राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 171

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 29 नवंबर 2019

पृष्ठ 16

एशियन चैंपियनशिप जीत कर दीपिका ने भारत को दिलाया ओलंपिक का कोटा

>> 14

रिलायंस बनी 10 लाख करोड़ वाली देश की पहली कंपनी

इस वर्ष का प्रदर्शन दमदार, किया आठ, नौ और 10 लाख करोड़ रुपये को पार

नई दिल्ली, प्रेट्र : एशिया के सबसे बड़े धनकुबेर मुकेश अंबानी के नियंत्रण वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) भारतीय इतिहास में 10 लाख करोड़ रुपये मूल्य का आंकड़ा छूने वाली पहली कंपनी बन गई है। शेयर बाजारों में पिछले दो कारोबारी सत्रों में कंपनी का प्रदर्शन दमदार रहा। इसके चलते गुरुवार को कारोबार के आखिर में बीएसई में रिलायंस का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 10,01,555.42 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा।

बीएसई में आरआइएल के शेयर गुरुवार को इंट्रा-डे में 0.90 प्रतिशत उछलकर 1,584 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। इस सप्ताह की शुरुआत से ही कंपनी के शेयर 10 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने को तैयार थी। कंपनी के शेयरों का इस वर्ष का प्रदर्शन इतना दमदार रहा है कि बीएसई ने जहां इस वर्ष अब तक लगभग 14 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, वहीं आरआइएल के शेयरों ने अपने निवेशकों को इससे करीब तीन गुना रिटर्न दिया है। पिछले महीने ही आरआइएल ने नौ लाख करोड़ रुपये बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार किया था। नौ लाख करोड़ रुपये से 10 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में रिलायंस ने महज 27 कारोबारी सत्र लिए। गौरतलब है कि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2019) के लिए 11,262 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया था।

रिलायंस ने ऐसे छुआ आसमान (पूंजीकरण करोड़ रु. में)

दिनांक	शेयर मूल्य	बाजार पूंजीकरण	कितने दिन लगे
02 अगस्त 2005	93.57	103321	–
16 अप्रैल 2007	364.44	203138	424
19 सितंबर 2007	543	302935	110
29 अक्टूबर 2007	707	411078	28
21 जुलाई 2017	793	515400	2410
01 नवंबर 2017	953	603207	70
19 जुलाई 2018	1105	700089	180
23 अगस्त 2018	1270	804533	24
24 अक्टूबर 2019	1437	910587	285
28 नवंबर 2019	1580	1000000	25

बड़ी भारतीय कंपनियों का बाजार मूल्य

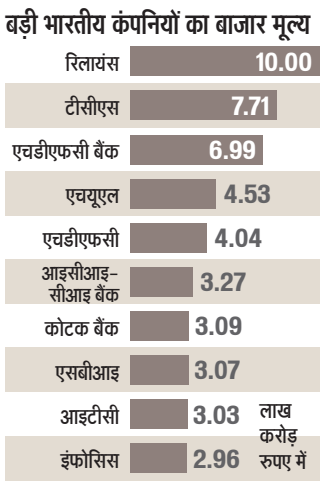

दुनिया की बड़ी पेट्रो कंपनियों का मूल्य

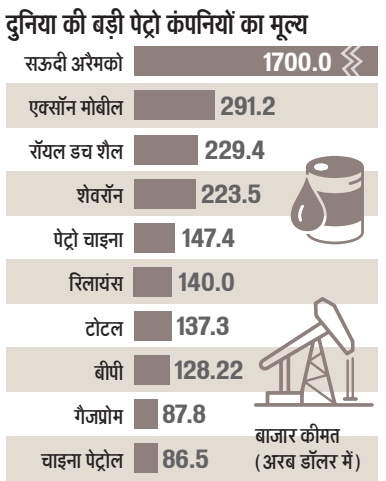

सरोकार

कोयले से लिखना सीखा, मिटा रहीं अशिक्षा की कालिख

जौनपुर : चूल्हे से निकले कोयले से लिखना सीखकर पढ़ाई शुरू करने वाली

मुन्नी बेगम जीवट के बूते परास्नातक तक पहुंचीं। अब तक पांच हजार महिलाओं को भी साक्षर कर चुकीं मुन्नी को उपराष्ट्रपति के हाथों एक्जांपल अवार्ड मिल चुका है। (पेज-10)

जागरण विशेष

गैस चूल्हे पर खाना पकाने के साथ मोबाइल भी करें चार्ज

लखनऊ : बर्नर की आंच को बर्बाद नहीं होने देगा यह 'एनर्जी अर्नर' डिवाइस। लखनऊ

के होनहार छात्र द्वारा तैयार किए गए मॉडल ने एशियन इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम में जीता पहला पुरस्कार। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

पीएमओ ने दिया रेल किराये में बढ़ोतरी का सुझाव

नई दिल्ली : रेलवे की नाजुक माली हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने रेल मंत्रालय से यात्री ट्रेनों का किराया बढ़ाने को कहा है। पीएमओ का कहना है कि स्थिति को देखते हुए रेलवे को एक-दो महीने में किराया बढ़ाना चाहिए और उससे पहले लोगों को इसका औचित्य बताना चाहिए। पीएमओ ने रेलवे को आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ नए उपाय अपनाने को भी कहा है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

सीबीआइ ने अब सेंगर को बताया हत्या का आरोपित

नई दिल्ली : उन्नाव कांड की जांच कर रही सीबीआइ ने पीड़िता के पिता की मौत के मामले में विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ अब हत्या का आरोप-पत्र दायर किया है, जबकि तीस हजारी अदालत पहले ही सेंगर के खिलाफ हत्या का आरोप तय कर चुकी है। सीबीआइ ने पूर्व में दायर आरोप-पत्र में सेंगर को हत्या का आरोपित नहीं माना था।

विश्वास. News

मधुमक्खी के जहर से संक्रमण ठीक होने का दावा फर्जी ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 10

उद्धव राज में माफ होंगे किसानों के कर्ज

ताजपोशी ▶ महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में संभाली कमान, सेक्युलर मूल्यों पर दृढ़ रहने का वादा

शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस से दो-दो मंत्रियों ने ली शपथ, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं पहुंचे

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

अपने संकल्प को पूरा करते हुए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आखिरकार गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वह महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के दो-दो मंत्रियों ने भी शपथ ली। खास बात यह रही कि न्योते के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समारोह में नहीं पहुंचे। शपथ ग्रहण से दो घंटे पहले तीनों पार्टियों ने सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी किया। इसमें किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी, नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 फीसद प्राथमिकता और सेक्युलर मूल्यों पर दृढ़ रहने का वादा किया गया है।

1995 का इतिहास दोहराते हुए दादर स्थित शिवाजी पार्क में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे (59) को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुहूर्त के अनुसार उद्धव ने शाम 6.42 बजे शपथ ग्रहण की। शपथ लेने से पहले उद्धव ने जहां मंच पर रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा को प्रणाम किया, वहीं शपथ लेने के बाद जमीन पर मत्था टेकते हुए जनता-जनार्दन को भी प्रणाम किया। इस शपथ ग्रहण समारोह का मंच उनके पिता शिवसेना संस्थापक बालासाहब ठाकरे के स्मृतिस्थल से चंद कदमों की दूरी पर बनाया गया था। 2013 में बालासाहब ठाकरे के निधन के बाद इसी शिवाजी पार्क में उनकी अंत्येष्टि की गई थी। इसी शिवाजी पार्क में बालासाहब हर साल दशहरे के दिन शिवसैनिकों की विशाल सभा को संबोधित करते आए थे। यही नहीं, 1995 में पहली बार बनी शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार ने भी इसी शिवाजी पार्क में शपथ ली थी। तब मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना के मनोहर जोशी और उपमुख्यमंत्री के रूप में भाजपा के गोपीनाथ मुंडे को शपथ दिलाई गई थी।

जयंत पाटिल हो सकते हैं उपमुख्यमंत्री : माना जा रहा है कि जयंत पाटिल नई सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की भूमिका निभाएंगे। लेकिन राकांपा से बगावत कर फड़नवीस के साथ उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजीत पवार की सरकार में भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है।

ये नेता रहे मौजूद : शपथ ग्रहण समारोह में इस गठबंधन सरकार के शिल्पकार शरद पवार के अलावा पूर्व सीएम देवेंद्र फड़नवीस, उद्योगपति मुकेश अंबानी और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी उपस्थित थे। कभी शिवसेना में बालासाहब ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे भी थे तो तमिलनाडु के राजनीतिक दल द्रमुक के नेता स्टालिन और मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ भी नजर आ रहे थे।

उद्धव की राह में बिछाए दो टन फूल पेज>>4

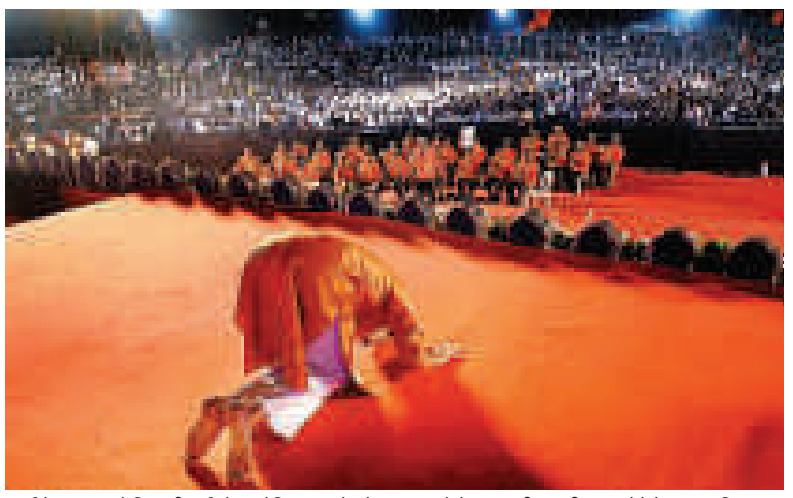

मुंबई में गुरुवार को शिवाजी पार्क में आयोजित समारोह में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उपस्थित जनसमूह का कुछ इस तरह अभिवादन किया। एएनआइ

> महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उद्धव ठाकरे जी को बधाई। मुझे विश्वास है कि वह महाराष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी लगन से काम करेंगे।
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

इन मंत्रियों ने ली शपथ

- एकनाथ शिंदे (शिवसेना)
- सुभाष देसाई (शिवसेना)
- जयंत पाटिल (राकांपा)
- छगन भुजबल (राकांपा)
- बालासाहब थोरात (कांग्रेस)
- नितिन राउत (कांग्रेस)

पहली कैबिनेट बैठक में रायगढ़ किले के लिए 20 करोड़ मंजूर

मुंबई, प्रेट्र : शपथ ग्रहण के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सहयाद्री गेस्ट हाउस में अपनी कैबिनेट की पहली बैठक की। बैठक के बाद उद्धव ने बताया, कैबिनेट ने पहला फैसला रायगढ़ किले के संरक्षण के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर करने का लिया है। रायगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी हुआ करती थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'हमें वास्तविकता पता हो तो हम बेहतर योजना बना सकते हैं। इसके लिए हमने मुख्य सचिव से जानकारियां मांगी हैं। किसानों को अब तक आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। हम किसानों को ठोस मदद मुहैया कराना चाहते हैं ताकि उनके हालात में सुधार हो सके। हम राज्य में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां कोई भी आतंकित महसूस न करे।'

न्यूनतम साझा कार्यक्रम

- नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 फीसद आरक्षण
- सरकारी पदों पर तुरंत भर्ती
- किसान बीमा योजना में सुधार
- 10 रुपये में भोजन की थाली योजना
- तालुका स्तर पर एक रुपया क्लीनिक
- गरीब कन्याओं को मुफ्त शिक्षा
- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल
- दो समन्वय समितियां बनेंगी

रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से प्रज्ञा ठाकुर बाहर

- भाजपा ने संसदीय दल की बैठक में भाग लेने पर रोक लगाई
- लोकसभा में राजनाथ बोले, गोडसे को देशभक्त बताने वाली सोच निंदनीय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा में दिए विवादित बयान को लेकर भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर चौतरफा घिर गई हैं। खुद उनकी पार्टी भाजपा ने संसदीय दल की बैठक में भाग लेने पर रोक लगाने के साथ ही रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से बाहर कर दिया है। वहीं दूसरी ओर संप्रग के विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। बैकफुट पर आई भाजपा ने खुद को प्रज्ञा ठाकुर के बयान से अलग कर लिया है। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे संसदीय इतिहास का दुखद दिन बताते हुए भाजपा-आरएसएस की सोच करार दिया है।

प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी देते हुए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी संसदीय दल की बैठक में उनके भाग लेने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर का बयान निंदनीय है और भाजपा ऐसे बयान और विचार का कभी समर्थन नहीं करती है। वहीं, लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाली किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं करती है और वे खुद ऐसी विचारधारा की निंदा करते हैं। लेकिन, असंतुष्ट विपक्षी सांसदों ने सदन का बहिष्कार किया। अपने विवादित बयानों को लेकर पार्टी की किरकिरी कराने वाली प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पार्टी इस बार कड़ी कार्रवाई पर विचार कर रही है। इस बीच प्रज्ञा ने सफाई देकर अपना बचाव करने की कोशिश की। उनका कहना था कि उन्होंने ऊधम सिंह को देशभक्त बताया था, नाथूराम गोडसे को नहीं।

वहीं, भाजपा की कार्रवाई और प्रज्ञा ठाकुर की सफाई से असंतुष्ट विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। संप्रग के सांसदों ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ लोकसभा में निंदा प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि पूरे सदन को इस बयान के लिए प्रज्ञा ठाकुर की निंदा करनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आतंकी प्रज्ञा ने आतंकी गोडसे को देशभक्त बताया। यह भारत के संसदीय इतिहास का एक दुखद दिन है। बाद में संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो भी कहा कि वह भाजपा और आरएसएस के दिल की बात है। कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से निकालने की मांग करते हुए कहा कि इसके लिए देश भाजपा को माफ नहीं करेगा।

प्रज्ञा ठाकुर। फाइल फोटो

साध्वी प्रज्ञा हैं कि मानती ही नहीं

भोपाल : यह पहला मौका नहीं है, जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के कारण भाजपा को जवाब देना मुश्किल हुआ हो। विवादों से उनका गहरा और पुराना नाता रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण के समय अपने विवादास्पद बयानों से साध्वी ने पार्टी को मध्य प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी परेशानी में डाल दिया था। (पेज-6)

वाट्सएप ने नहीं दी जासूसी पीड़ितों की जानकारी

- सरकार ने राज्यसभा में कहा, कंपनी ने अपनी कमजोर कड़ियां भी नहीं बताईं
- कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर के जवाब पर असंतोष जताया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वाट्सएप के सीईओ के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने अपने सिस्टम की सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियों जानकारी नहीं दी थी। इतना ही नहीं अभी तक वाट्सएप कंपनी पेगासस सॉफ्टवेयर का शिकार हुए लोगों के नामों तक की जानकारी नहीं दे पाई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार ने इस मामले में अनधिकृत तरीके से कोई दखलंदाजी नहीं की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजिटल कंपनियों को कड़ी सुरक्षा रखनी होगी अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

गुरुवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रसाद ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने इजरायली टेक्नोलॉजी कंपनी एनएसओ समूह को भी 26 नवंबर को एक नोटिस भेजा जिसमें मालवेयर के बारे में जानकारी और भारतीय उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव का विवरण मांगा गया था। उन्होंने कहा कि डिजिटल कंपनियों को यह स्वीकार करने और समझने की आवश्यकता है कि भारतीयों की संरक्षा और सुरक्षा वास्तव में महत्वपूर्ण है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करने चाहिए। इसमें विफल होने पर सरकार आइटी कानून के तहत उचित कार्रवाई भी कर सकती है।

प्रसाद ने कहा कि 5 सितंबर को वाट्सएप ने सर्ट इन (कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम) को मई में रिपोर्ट की गई सुरक्षा घटना के बारे में अपडेट प्रदान करते हुए लिखा और कहा कि यद्यपि इस हमले की पूरी सीमा कभी भी ज्ञात नहीं हो सकती, फिर भी वाट्सएप उपलब्ध सूचनाओं की लगातार समीक्षा करता रहा है। उपलब्ध लॉग डाटा के आधार पर वाट्सएप का मानना है कि हो सकता है हमलावरों ने भारत में लगभग 121 उपयोगकर्ताओं तक पहुंच बनाने का प्रयास किया हो। प्रसाद ने इस संबंध में सदन में रखे अपने विवरण पत्र में कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वाट्सएप ने खेद व्यक्त किया है कि वे उपयोगकर्ता की गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जांच एजेंसियां तय मानकों के अनुरूप ही इस मामले की जांच कर रही हैं।

इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के इस जवाब पर दिग्विजय सिंह ने असंतोष जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें यह स्पष्ट जवाब देना होगा कि सरकार या किसी एजेंसी ने पेगासस खरीदा है या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाट्सएप के मालिक फेसबुक के कुछ वरिष्ठ अफसरों से मुलाकात की थी और पेगासस को लेकर चर्चा की थी।

ट्रंप के हांगकांग बिल पर दस्तखत से चीन लाल

- राजदूत को तलब कर दी दुष्परिणामों की चेतावनी, कहा, हांगकांग के मामलों में अमेरिका दे रहा दखल

बीजिंग, रायटर : हांगकांग पर संसद के पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत से चीन भड़क उठा है। कानून में तब्दील इस दस्तावेज के मुताबिक हांगकांग को अमेरिका से मिले खास कारोबारी दर्जे की हर साल समीक्षा होगी, इसके बाद अगले साल के लिए उसे जारी रखा जाएगा। यह समीक्षा मानवाधिकारों के पालन को मानदंड बनाकर होगी। साथ ही मानवाधिकार उल्लंघन के चीन और हांगकांग के अधिकारियों को अमेरिका प्रतिबंधित करेगा। चीन ने कहा है कि इस कानून के लागू होने से दोनों देशों रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा और इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे।

ट्रंप ने चंद रोज पहले हांगकांग मसले पर संसद के पारित प्रस्ताव पर दस्तखत न करने के संकेत देने के बावजूद बुधवार को अचानक यह बड़ा कदम उठाया। ट्रंप ने संबंध बिगड़ने की चीन की पूर्व चेतावनी के बावजूद संसद के प्रस्ताव पर दस्तखत किए। अमेरिका ने यह कानून तब बनाया है जब उसकी चीन के साथ कारोबार में समझौते के लिए वार्ता महत्वपूर्ण दौर में है। हांगकांग का लोकतंत्र की मांग वाला छह महीने पुराना आंदोलन भी ठंडा पड़ने लगा है। लेकिन अमेरिका के इस कदम से आंदोलन में फिर गर्माहट पैदा होने के आसार हैं।

चीन ने कहा है कि अमेरिका के इस कदम से हांगकांग में मनमानी को बढ़ावा मिलेगा। अब इसको रोकने के लिए चीन जो कदम उठाएगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। चीन के उप विदेश मंत्री ली यूचेंग ने गुरुवार को अमेरिकी राजदूत टेरी ब्रांसटेड को तलब कर ट्रंप के कदम पर कड़ा विरोध जताया। अमेरिका को चीन के घरेलू मामलों में दखलंदाजी से बाज आने की चेतावनी दी। कहा, इससे दोनों देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। जबकि हांगकांग की चीन समर्थित सरकार ने कहा है कि अमेरिकी कानून का आंदोलनकारियों के बीच गलत संदेश गया है। अमेरिका के समर्थन में लिए गए बड़े कदम के बावजूद गुरुवार को हांगकांग में शांति बनी रही। कोई बड़ा आंदोलन न होने की खबर है। इस बीच 100 पुलिसकर्मियों ने सादे कपड़ों में पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय के भीतर जाकर वहां हिंसक आंदोलनकारियों के खिलाफ सुबूत एकत्रित किए। ये अपने साथ कई हस्तनिर्मित हथियार लेकर आए हैं जिनमें पेट्रोल बम और तीर-धनुष शामिल हैं।

डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)। रायटर

कारगर कदम

जम्मू-कश्मीर में अगस्त से अक्टूबर तक सिर्फ 16 युवाओं ने पकड़ी आतंक की राह, सुरक्षा बलों की मुहिम से भी टूट रहा है आतंकी संगठनों का मनोबल

इंटरनेट पर पाबंदी से जिहादी दुष्प्रचार पर शिकंजा

नवीन नवाज, जम्मू

जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी का असर जिहादी दुष्प्रचार पर भी साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि राज्य के पुनर्गठन के फैसले के बाद से आतंक के दलदल में फंसने वाले युवाओं की संख्या में काफी कमी आई है। सुरक्षा एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त से अक्टूबर तक मात्र 16 युवाओं ने आतंकियों और ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओडब्ल्यूजी) के दुष्प्रचार में फंसकर हथियार उठाए हैं। सुरक्षा बलों की मुहिम का असर भी आतंकी संगठनों के मनोबल को तोड़ रहा है। वहीं, इस साल करीब 110 युवा अमन के पथ से भटककर आतंकी बने हैं। यह संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले करीब आधी है।

जानकारी के अनुसार, एक जनवरी 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर में 447 स्थानीय लड़के आतंकी बने हैं। सबसे ज्यादा 209 युवकों ने पिछले साल आतंक की राह पकड़ी। इस दौरान यह बात सामने आई थी कि अधिकतर युवा सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकी संगठनों के दुष्प्रचार का शिकार हुए थे। पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का प्रस्ताव लाने से पूर्व पूरे जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था। वादी में फोन सेवा भी बंद थी। हालांकि अब मोबाइल सेवा करीब एक माह पहले बहाल की जा चुकी है, लेकिन इंटरनेट सेवा अब भी चुनिंदा सरकारी कार्यालयों में ही कड़ी निगरानी के बीच उपलब्ध है। इंटरनेट सेवाओं पर रोक का असर कानून व्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है। हिंसक प्रदर्शनों में लगातार कमी आ रही है।

प्रतीकात्मक

सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा था जहर : जम्मू-कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों से जुड़े एसएसपी इम्तियाज हुसैन मीर के अनुसार बीते छह वर्षों में सोशल मीडिया के दुष्प्रचार ने सबसे अधिक युवाओं के दिमाग में जहर भरा है। इसके अलावा सक्रिय ओजीडब्ल्यू भी युवाओं को अपने जाल में फंसाते हैं। सोशल मीडिया पर पाबंदी से इस दुष्प्रचार पर रोक लगी है। साथ ही राज्य के पुनर्गठन के साथ आतंकियों का एजेंडा भी समाप्त हो गया है।

सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उपलब्ध सूचनाओं के मुताबिक इस अगस्त से अक्टूबर तक सिर्फ 16 लड़के ही आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं। अगस्त में सिर्फ दो लड़कों के आतंकी बनने की पुष्टि हुई थी। अलबता, वर्ष 2018 के अगस्त माह में 17, सितंबर में 13 और अक्टूबर माह में 14 युवाओं ने आतंक का रास्ता पकड़ा था। इस वर्ष हिजबुल मुजाहिदीन से 46, जैश से 34 और लश्कर से 22 युवा जुड़े हैं। दक्षिण कश्मीर अब भी आतंक की नर्सरी बना हुआ है और इस वर्ष कुल 110 में से सबसे ज्यादा 36 युवक पुलवामा से आतंकी बने हैं। बीते साल भी पुलवामा से ही सबसे ज्यादा 94 युवा आतंकवाद की राह पर फिसल गए थे।

कश्मीर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंक की राह पकड़ने वाले युवाओं की घर वापसी के लिए सुरक्षा बलों ने विशेष अभियान छेड़ रखा हैं। सेना का ऑपरेशन मां काफी चर्चा में है। ऐसे करीब 70 युवाओं को बचाने में सफलता मिली है।

अब कश्मीरी नेताओं को विदेश जाने की अनुमति

जम्मू : जम्मू-कश्मीर में बने राजनीतिक शून्य को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न स्तरों पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। पांच अगस्त को एहतियातन हिरासत में लिए गए कई नेताओं को जहां क्रमानुसार रिहा किया जा रहा है। वहीं, कई नेताओं को विदेश जाने की अनुमति दी है ताकि वह संबंधित पक्षों से जुड़े लोगों से संपर्क कर राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली का रास्ता खोल सकें। घरों में नजरबंद किए गए नेताओं को आपात परिस्थितियों में जम्मू या दिल्ली जाने की छूट भी दी गई है। हालांकि वादी में उन्हें नजरबंद रखा जाएगा। (पेज-6)

झारखंड के मतदान दल के 18 लोगों को छत्तीसगढ़ में छोड़ गया हेलीकॉप्टर

नईदुनिया, अंबिकापुर

झारखंड के नक्सल प्रभावित लातेहार जिले के आठ पोलिंग बूथों पर तैनात मतदान दल के 18 अधिकारियों-कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर भैंसामुंडा स्थित सत्तीपारा के खुले मैदान में उतार कर वापस चला गया। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों की पहल पर घंटों बाद पोलिंग पार्टियों को वापस ले जाने हेलीकॉप्टर आया।

जानकारी के अनुसार झारखंड में 30 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए आठ पोलिंग पार्टियों को दोपहर करीब 12 बजे लातेहार से सेना के हेलीकॉप्टर से मनिका विधानसभा क्षेत्र के चटकपुर इलाके में स्थित अलग-अलग मतदान केंद्रों के लिए भेजा गया था। लेकिन, हेलीकॉप्टर भटक कर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला स्थित प्रतापपुर भैंसामुंडा से लगे सत्तीपारा के खुले मैदान में उतरा। पायलट को लगा कि इसी स्थान पर उन्हें उतारना है। हेलीकॉप्टर उतरता देख मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। पोलिंग पार्टियों को जब पता चला कि वे झारखंड के अपने पोलिंग सेंटर को छोड़ छत्तीसगढ़ इलाके में उतर गए हैं तो अफरातफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी जानकारी सूरजपुर कलेक्टर दीपक सोनी को दी। कलेक्टर ने तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी। इसकी जानकारी झारखंड राज्य के निर्वाचन आयोग तक भेजी गई। दोपहर करीब दो बजे हेलीकॉप्टर लातेहार (झारखंड) से वापस आया और मतदान दल को लेकर वापस लौटा।

झारखंड के मतदान दल के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर भैंसामुंडा क्षेत्र में उतारकर चला गया हेलीकॉप्टर। नईदुनिया

22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा दिल्ली का गुरुवार को। यह सामान्य से चार डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से छह डिग्री अधिक है।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 29 नवंबर 2019

नर्सरी में दाखिले की दौड़ आज से

मिशन एडमिशन ▶ दिल्ली के 1750 निजी स्कूलों में करीब डेढ़ लाख हैं सीटें

ज्यादातर स्कूलों ने वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नर्सरी, केजी और कक्षा-एक में दाखिले के दौड़ शुक्रवार से राजधानी के 1750 निजी स्कूलों में शुरू हो रही है। इन स्कूलों में करीब डेढ़ लाख सीटें हैं। ज्यादातर स्कूलों ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। कुछ स्कूलों में वहां जाकर आवेदन करना होगा।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को 28 नवंबर तक निदेशालय की वेबसाइट पर दाखिले के लिए निर्धारित प्वाइंट अपलोड करने का समय दिया था। देर शाम नौ बजे तक 1485 स्कूलों ने प्वाइंट अपलोड कर दिए हैं। जिन स्कूलों ने गुरुवार तक ऐसा नहीं किया, निदेशालय उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। उन्हें दो से तीन दिन का समय दिया जाएगा। जवाब न देने पर उन स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया रोक दी जाएगी। निदेशालय ने सभी उप शिक्षा निदेशकों को इन नियमों का पालन कराने का निर्देश दिया है। उप शिक्षा निदेशक ही स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजेंगे।

स्कूल के नजदीक है घर तो मिलेंगे ज्यादा अंक : ज्यादातर स्कूलों ने अभिभावकों के घर नजदीक होने के सबसे ज्यादा अंक दिए हैं। कुछ स्कूलों ने अभिभावकों के घर तीन किलोमीटर के दायरे में होने पर 50 से 100 अंक तक निर्धारित किए हैं। कुछ स्कूलों ने चार किलोमीटर तक के लिए 50 अंक, कुछ स्कूलों ने 3.1 से छह किलोमीटर के लिए 45 अंक, 6.1 से 14 किलोमीटर तक के लिए 40 अंक निर्धारित किए हैं। जिस स्कूल में आवेदन किया है, यदि उसमें पहला बच्चा भी पढ़ता है तो नर्सरी दाखिले के लिए 30 अंक मिलेंगे। अभिभावक स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं तो उनके बच्चे को 10 अंक मिलेंगे।

नर्सरी दाखिला की फाइल फोटो।

बच्चों की उम्र सीमा
नर्सरी – 31 मार्च 2020 तक उम्र चार साल से कम होनी चाहिए
केजी– 31 मार्च 2020 तक उम्र चार साल से कम होनी चाहिए
कक्षा–1 – 31 मार्च 2020 तक उम्र छह साल से कम होनी चाहिए
नर्सरी दाखिले के लिए ये दस्तावेज एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्य होंगे
अभिभावकों (माता–पिता) के नाम पर राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड
अभिभावकों के पास आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए
अभिभावकों का वोटर आइडी कार्ड
बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट अभिभावक के नाम होना चाहिए
अभिभावकों का आधार कार्ड

इन तारीखों का रखें ध्यान

29 नवंबर : नर्सरी दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी और इसके लिए फॉर्म मिलने लगेंगे

27 दिसंबर : नर्सरी दाखिले के लिए फॉर्म जमा कराने की अंतिम तारीख

10 जनवरी 2020 : दाखिले के लिए आवेदन करने वाले बच्चों की जानकारी स्कूल देंगे

17 जनवरी : प्वाइंट सिस्टम के अधीन स्कूलों को बच्चों के अंकों को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा

24 जनवरी : नर्सरी, केजी और कक्षा–1 में दाखिले के लिए चयनित बच्चों की पहली सूची जारी की जाएगी

27 जनवरी से तीन फरवरी तक : बच्चों को स्कूल द्वारा दिए गए प्वाइंट को लेकर अभिभावक ईमेल व पत्र के जरिये स्कूलों से बात कर सकते हैं

12 फरवरी : नर्सरी दाखिले के लिए चयनित बच्चों की दूसरी सूची जारी की जाएगी

13 से 19 फरवरी : बच्चों को स्कूल द्वारा दिए गए प्वाइंट को लेकर अभिभावक ईमेल व पत्र से स्कूलों से बात कर सकते हैं

06 मार्च : चयनित बच्चों के दाखिले की कोई सूची है तो वह जारी की जाएगी

16 मार्च : नर्सरी दाखिला प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी

स्कूलों पर रहेगी नजर : सभी उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिले में स्कूलों पर नजर रखें। अभिभावकों की शिकायतों को सुनें। इस पर ध्यान दें कि स्कूल प्वाइंट सिस्टम का पालन कर रहे हैं कि नहीं।

मानहानि मामले में मनोज तिवारी समेत छह के खिलाफ समन

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर किए गए मानहानि मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत छह के खिलाफ समन जारी किया है। राउज एवेन्यू के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पहूजा ने मनोज तिवारी, सांसद हंसराज हंस, सांसद प्रवेश वर्मा, हरीश खुराना, मनविंदर सिंह सिरसा और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ समन जारी किया। अदालत ने सभी को 18 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है।

सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण में भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाने के मामले में मनोज तिवारी समेत अन्य के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली के सरकारी स्कूल के निर्माण में दो हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। सिसोदिया ने कहा था कि भाजपा नेताओं द्वारा संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से उन पर झूठे और मानहानि वाले आरोप लगाए गए थे, ताकि उनकी छवि को खराब किया जा सके। सिसोदिया का आरोप है कि सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में झूठे और मानहानि वाले बयान दिए गए।

जल्द ही परिवहन व्यवस्था पर गर्व करेंगे दिल्लीवासी : केजरीवाल

राजघाट डिपो पर नई क्लस्टर बस का अवलोकन करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। जागरण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार दोपहर राजघाट डिपो से 100 नई बसों को रवाना किया। इन सभी बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस समेत अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी का दिन है कि आज से 100 बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। पिछले कुछ माह में काफी बसें दिल्ली की सड़कों पर आई हैं। आने वाले समय में और भी बसें आएंगी। जिस तरह से दिल्ली को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है, उसी तरह परिवहन व्यवस्था भी अति आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर की बनेगी। आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को भी अपनी परिवहन व्यवस्था पर गर्व होगा।

इस तरह की हैं सुविधाएं : ऑरेंज कलर की ये नई बसें 37 सीटों वाली हैं। सभी बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिससे दिव्यांग जनों को बस में सवार होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हर साइड में सात-सात पैनिक बटन हैं। साथ ही तीन सीसीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं।

प्याज की कीमत कम होने में लगेंगे दस दिन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

70 से लेकर 100 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा खुदरा बाजारों में प्याज

मंडी में थोक में प्याज 60 रुपये प्रति किलो तक बिका। (फाइल)

अगले दस दिनों में प्याज की कीमतों में कमी आ सकती है। इसकी वजह यह है कि दस दिनों में राजधानी की मंडियों में प्याज की नई फसल की आवक शुरू हो जाएगी। मौजूदा समय में केवल राजस्थान से ही प्याज की आवक हो रही है। मांग के अनुरूप आवक कम होने से इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। गुरुवार को आजादपुर मंडी में 200 टन प्याज भी नहीं पहुंच सका। इस कारण से प्याज की थोक कीमत में कोई गिरावट नहीं आई। मंडी में प्याज थोक में प्रति किलो न्यूनतम 30 रुपये तो अधिकतम 60 रुपये प्रतिकिलो तक बिका। इसका असर खुदरा बाजारों में भी दिखा, जहां प्याज 70 से लेकर 100 रुपये प्रति किलो की दर से बिकते देखा गया। हालांकि छोटे प्याज की कीमत कम रही।

आजादपुर मंडी के प्याज के आढ़तियों ने बताया कि नवंबर के पहले हफ्ते में ही प्याज का थोक मूल्य 60 से 80 के बीच हो गया था। इस कारण खुदरा बाजार में प्याज का दाम 100 रुपये प्रति किलो को भी पार कर गया था। बीच में आवक थोड़ी बढ़ी तो थोक कीमत नीचे उतर कर 50 रुपये तक हो गई थी। लेकिन महाराष्ट्र, कनार्टक आदि राज्यों में हुई बारिश के कारण आवक में कमी आ गई और मौजूदा समय में केवल राजस्थान से ही प्याज आ रहा है। ऐसे में मांग के अनुपात में आवक कम होने से कीमतों में तेजी बनी हुई है।

आजादपुर स्थित चौधरी हीरा सिंह सब्जी मंडी में प्याज के आढ़ती मोहम्मद रफीक ने बताया कि अब अन्य राज्यों में प्याज की नई फसल तैयार हो गई है। आगामी दस दिनों में मंडी में इसकी आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। इसके बाद ग्राहकों को राहत मिलने लगेगी। आढ़ती मोहम्मद रफीक ने बताया कि बारिश के कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में प्याज की फसल खराब होने से अभी मांग के अनुरूप डेढ़ गुना कम आवक हो रही है।

महंगे प्याज पर इमरान हुसैन ने पासवान को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में बिक रहे महंगे प्याज को लेकर भी आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। प्याज के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को चिट्ठी लिखी है। इसमें महंगे प्याज को लेकर इमरान हुसैन ने पासवान से पूछा है कि आखिर 60 रुपये किलो वाली प्याज सरकार खरीदे तो खरीदे कैसे? उन्होंने यह भी कहा कि नैफेड केंद्रीय भंडार के माध्यम से दिल्ली सरकार को प्याज मुहैया करा रहा है।

अभी तक नैफेड प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड (पीएसएफ) के तहत 15 रुपये 60 पैसे प्रति किलो की दर से दिल्ली सरकार को प्याज सप्लाई कर रहा था, जिसे दिल्ली सरकार 23 रुपये 90 पैसे की खुदरा दर पर दिल्ली की जनता को मुहैया करा रही थी। दिल्ली सरकार ने मोबाइल गाड़ियों के अलावा दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन (डीएससीएससी) और खाद्य और आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को भी प्याज के वितरण के काम में लगाया है। इसके बावजूद एक समीक्षा बैठक में नैफेड ने बताया कि पीएसएफ के तहत मुहैया कराए जा रहे प्याज की सप्लाई रोक दी गई है। ऐसा केंद्र सरकार के कहने पर किया गया है।

नैफेड ने यह भी बताया कि वह दिल्ली सरकार को अलवर की मंडी से प्याज मुहैया करवा सकता है और इसके बाद मिस्र से आयात किए जाने वाले प्याज की खेप से भी दिल्ली में प्याज की आपूर्ति की जाएगी। हालांकि इस प्याज को मौजूदा खरीद रेट पर दिया जाएगा और इस पर ढुलाई लागत भी देनी होगी।

कोर्ट ने दोषियों की फांसी पर जेल प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

जासं, नई दिल्ली : वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से दोषियों की फांसी पर रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने पूछा कि दोषियों ने दया याचिका दायर की है या नहीं? इस मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई होगी। पीड़िता की मां ने अदालत में अर्जी दायर कर कहा था कि दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन सजा की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। दोषियों को जल्द फांसी दी जानी चाहिए।

गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2012 की रात छात्रा के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। कुछ दिनों बाद पीड़िता ने इलाज के दौरान सिंगापुर में दम तोड़ दिया था। इस मामले के एक दोषी ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य नाबालिग को कोर्ट ने तीन साल के लिए बाल सुधार गृह में भेजा था। चार अन्य दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई है। दोषियों ने फांसी की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दया याचिका दायर की थी। उनकी याचिका को खारिज कर फांसी की सजा बरकरार रखा गया था।

'नियमितीकरण में देरी के लिए केजरीवाल जिम्मेदार'

अनधिकृत कॉलोनियों का मामला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का विधेयक लोकसभा में सर्वसम्मिति से पारित हो गया। विपक्षी दलों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विधेयक लाने पर सवाल जरूर उठाए, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। दिल्ली से भाजपा सांसदों समेत शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने अनियमित कालोनियों को नियमित करने में देरी के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

अनधिकृत कॉलोनियों के मामले को लंबे समय तक लटकाने को लेकर सरकार और विपक्ष के आरोपों-प्रत्यारोपों को दरकिनार करते हुए पुरी ने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली के विकास में योगदान दिया। लेकिन दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने में हुई देरी के लिए सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। उनके अनुसार, 2017 में शहरी विकास मंत्री बनने के तत्काल बाद उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात की थी। उनके बीच हुए पत्राचार के दस्तावेजी सुबूत मौजूद हैं। केजरीवाल ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी ने 2017 और 2019 में केंद्र सरकार द्वारा केजरीवाल सरकार को लिखे दो पत्र पढ़े, जिनमें दिल्ली सरकार ने अनियमित कॉलोनियों की मैपिंग में देरी का हवाला देते हुए दोनों बार दो-दो साल के लिए समय मांगा था।

हरदीप पुरी ने मुख्यमंत्री के तीन दिन के भीतर सभी रजिस्ट्री पूरी कराने के बयान पर चुटकी ली

हरदीप पुरी ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि विधेयक चुनाव को देखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी काम करो, कोई न कोई चुनाव आ रहा होगा। एक बार चुनाव करा दीजिए तो समस्या समाप्त हो जाएगी। उनके अनुसार, केजरीवाल सरकार द्वारा दोबारा दो साल का समय मांगे जाने के बाद ही केंद्र ने खुद इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव के पहले ही इसके लिए कैबिनेट नोट बनकर तैयार हो गया था। पुरी ने केजरीवाल के तीन दिन के भीतर सभी रजिस्ट्री पूरी कराने के बयान पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री का काम दिल्ली सरकार के मातहत आता है। एक दिन में रजिस्ट्रार कितनी रजिस्ट्री कर सकता है, उसका अंदाजा होने के बाद केजरीवाल को खुद अपना बयान बदलना पड़ सकता है।

विपक्ष ने अनधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर शुल्क लेने पर सवाल उठाया और इसमें रहने वाले गरीबों को ध्यान में रखते हुए उसे मुफ्त करने की सलाह दी। लेकिन पुरी का कहना था कि अनधिकृत कॉलोनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद यह फीस रखी गई है, जो न के बराबर है। विधेयक में पॉश इलाकों की अनधिकृत कॉलोनियों को बाहर रखे जाने पर उन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें नियमित करने की कोशिश की जाएगी। हरदीप पुरी ने केजरीवाल पर रोज नए बयान देकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हर दिन नया बयान देने वाले केजरीवाल सावधान हो जाएं। वे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली को धोखा दे रही है, जो सरासर गलत है। पुरी ने दावा किया कि जो 11 साल में नहीं हुआ, उसे 30 दिन में पूरा करेंगे।

एक बार नियमित हो जाने के बाद इन कॉलोनियों के विकास की रूपरेखा बताते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि इनमें सामाजिक आधारभूत संरचना केंद्र सरकार बनाएगी। यही नहीं, रजिस्ट्री से मिलने वाले शुल्क को एक फंड में रखा जाएगा और उसी कॉलोनी के विकास में लगाया जाएगा।

50 फीसद सीटों पर महिला व युवा चेहरों पर दांव लगाएगी कांग्रेस

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

महज दो से ढाई महीने में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में 50 फीसद सीटों पर कांग्रेस महिला एवं युवा चेहरों पर दांव लगाएगी। शेष 50 फीसद सीटों पर अच्छी छवि वाले दिग्गजों को चुनावी रण में उतारा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।

पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के निधन के बाद काफी समय तक निष्क्रिय पड़ी रही कांग्रेस की दिल्ली इकाई अब चुनावी मोड़ में आ चुकी है। अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ एवं अनुभवी नेता सुभाष चोपड़ा की नियुक्ति के साथ ही तमाम वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हो गए हैं और आए दिन धरना-प्रदर्शन, कार्यकर्ता सम्मेलन और बैठकों के जरिये अपनी उपस्थिति भी बखूबी दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी ने अब विधानसभा चुनाव की बिसात के लिए अपने मोहरे भी बैठाने शुरू कर दिए हैं।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक, पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को पूरी मुस्तैदी और मजबूती से लड़ना चाहती है। इसीलिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर विचार-विमर्श एवं मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। पहले चरण में तय किया गया है कि 50 फीसद सीटों पर नए चेहरों को टिकट दिया जाए। इनमें महिलाएं और नौजवान दोनों ही शामिल रहेंगे। इससे पार्टी को बड़ा फायदा यह होगा कि जो कार्यकर्ता पार्टी से छिटक रहे हैं, वह वापस लौटेंगे। आम आदमी पार्टी एवं भाजपा की नए चेहरों पर दांव खेलने की नीति को ध्यान में रखते हुए भी कांग्रेस के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है।

आधी सीटों पर पार्टी दिग्गजों का भी साथ छोड़ना नहीं चाह रही। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद समेत कई नेता जिनकी अपने विधानसभा क्षेत्र में ठीक- ठीक छवि है, उनको टिकट दिया जाएगा। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर वह भी चुनाव लड़ गए तो बाकी सीटों पर ध्यान दिया जाना संभव नहीं रह जाएगा।

> उम्मीदवारों का चयन तो समय आने पर ही किया जाएगा, लेकिन यह तय है कि 35 सीटों पर महिला एवं युवा लड़ेंगे जबकि 35 सीटों पर पुराने नेता। टिकटों के वितरण में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। जहां तक मेरा सवाल है तो मेरे लिए चुनाव लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पार्टी को मजबूत करना व चुनाव में उसे विजय दिलाना।
>
> **-सुभाष चोपड़ा, अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस**

किसके हाथ लगेगा जेवर एयरपोर्ट, आज उठेगा पर्दा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए शुक्रवार का दिन बेहद अहम है। आज यह तय हो जाएगा कि जेवर एयरपोर्ट की बाजी किसके हाथ लगेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) के ग्रेटर नोएडा स्थित कार्यालय में दोपहर बाद तीन बजे फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। एयरपोर्ट की दौड़ में चार कंपनियां शामिल हैं। बिड प्रक्रिया पूरी होने के बाद दो दिसंबर को प्रदेश की परियोजना निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति (पीएमआइसी) की होने वाली बैठक में चयनित कंपनी की जानकारी दी जाएगी।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिड प्रक्रिया शुक्रवार को अंतिम पड़ाव पर होगी। छह नवंबर को खोली गई तकनीकी बिड में सभी चार कंपनियां सफल घोषित की गई थीं। इसमें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, अडानी इंटरप्राइजेज, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी शामिल हैं। इन कंपनियों की फाइनेंशियल बिड शुक्रवार को खोली जाएगी। एयरपोर्ट की कंपनी चयन के लिए मुख्य शर्त सरकार को प्रति यात्री मिलने वाला राजस्व है। जो कंपनी प्रति यात्री अधिकतम राजस्व सरकार को देगी, वह जेवर एयरपोर्ट की बिड में सफल होगी। फाइनेंशियल बिड में चयनित कंपनी की जानकारी दो दिसंबर को लखनऊ में होने वाली पीएमआइसी की बैठक में दी जाएगी।

आइएस के वीडियो से सीखा था बम बनाना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- असम से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में खोले राज
- स्थानीय लड़की से दोस्ती के बाद लोगों ने किया था जमील का विरोध
- पुलिस में शिकायत की तो खुलकर कट्टरपंथ का प्रचार-प्रसार करने लगा

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा असम के ग्वालपाड़ा से गिरफ्तार आइएस (इस्लामिक स्टेट) से प्रभावित संदिग्ध आतंकियों ने पुलिस की पूछताछ में कई राज खोले हैं। इन आतंकियों में शामिल जमील जमान ने असम में एक स्थानीय लड़की को अपने जाल में फंसा उससे दोस्ती गांठ ली थी। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और पुलिस में शिकायत की तो खुलकर कट्टरपंथ का प्रचार-प्रसार करने लगा। उसने समूह के प्रमुख रंजीत अली से संपर्क किया था और आइएस की विचारधारा के प्रसार में जुट गया था। उसने आइएस के बम बनाने वाले वीडियो से बम बनाना सीखा था। आरोपित सोशल मीडिया पर लगातार आइएस, इस्लाम और उसके नाम से लोगों को जोड़ रहे थे।

2017 में उज्जैन में ट्रेन में जिस तरह की पाइप आइईडी बम से धमाका किया गया था। उसी तरह की आइईडी आतंकियों के पास से भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जमील जमान असम के कृष्णोई इलाके में रह रहा था। उसने करीब सात महीने पहले बहला फुसला कर एक स्थानीय लड़की से दोस्ती कर ली थी। इसका स्थानीय स्तर पर काफी विरोध हुआ था। स्थानीय लोगों के बीच जब यह खबर फैली तो उन्होंने इसके विरोध में लव जिहाद को लेकर इलाके में पोस्टर लगाए थे। यह पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। जमील की शिकायत लोगों ने स्थानीय पुलिस में भी की थी।

बताया जाता है कि इस घटना के बाद जमील खुलकर आइएस का प्रचार-प्रसार करने लगा। आतंकियों के लिए दिल्ली में रेकी करने वाले दिल्ली तीन युवक भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संपर्क में आए थे। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने असम पुलिस के साथ मिलकर असम के ग्वालपाड़ा से गत दिनों आइएस प्रभावित तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनकी साजिश स्थानीय रास मेला में बड़ा हमला करने की थी। रास मेला कृष्ण मेला होता है। असम में धमाका करने के बाद इनकी अगली साजिश दिल्ली-एनसीआर में हमला करने की थी। इससे पहले ही पुलिस ने लुइत जमील जमान, मुकादिर इस्लाम व रंजीत इस्लाम को दबोच लिया था। तीनों संदिग्ध आइएस के बांग्लादेश मॉड्यूल से प्रभावित हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसका कहना है कि आतंकियों के के मददगारों को पता लगाया जा रहा है। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

समस्या

करीब दो घंटे के दौरान 15 बार ट्रायल करना पड़ा बंद, एक दिसंबर से खेड़कीदौला टोल प्लाजा पर महाजाम लगने की आशंका

दस मिनट में फेल हो गया फास्टैग का ट्रायल, लगा जाम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे स्थित खेड़कीदौला टोल प्लाजा पर गुरुवार को चार लेन पर फास्टैग का ट्रायल दस मिनट में ही फेल हो गया। लगभग डेढ़ से दो किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। इस वजह से करीब दो घंटे के दौरान 15 बार ट्रायल बंद किया गया। ऐसी स्थिति में एक दिसंबर से खेड़कीदौला टोल प्लाजा पर महाजाम लगने की आशंका है। केंद्र सरकार ने एक दिसंबर से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। खेड़कीदौला टोल प्लाजा से प्रतिदिन 80 से 85 हजार वाहन निकलते हैं। इनमें से पिछले दस दिनों के दौरान टोल प्लाजा के नजदीक सात हजार फास्टैग बन पाए हैं। इसका नतीजा गुरुवार को ट्रायल शुरू होने के साथ ही सामने आ गया।

दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे जयपुर की तरफ से ट्रायल शुरू किया गया। लगभग दस मिनट के भीतर ही जाम रामपुरा फ्लाईओवर के नजदीक पहुंच गया। इससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। लगभग ढाई बजे तक ट्रायल किया गया। जाम न लगे इसके लिए लगभग 15 बार ट्रायल बंद किया गया। जाम में कई एंबुलेंस भी फंस गई थीं। ट्रायल की वजह से जाम में फंसे लोगों ने एक सुर से कहा कि पहले तैयारी की जाए फिर फास्टैग अनिवार्य किया जाए।

टोल प्लाजा प्रबंधन के कर्मचारियों ने भी दबी जुबान से कहा कि ट्रायल से साबित हो गया है कि एक दिसंबर से काफी मुश्किल होगा। लचर व्यवस्था का आलम यह है कि एनएचएआइ से संबंधित इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आइएचएमसीएल) की ओर से फास्टैग उपलब्ध कराने का काम गुरुवार तक भी शुरू नहीं हुआ था। पेटीएम के साथ ही कई बैंकों की ओर से फास्टैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कुल पांच काउंटर हैं, जबकि प्रतिदिन सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। दो-दो घंटे उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि फास्टैग के लिए पूरे जिले में सभी प्रमुख स्थानों पर काउंटर लगाए जाएं। खेड़कीदौला टोल प्लाजा पर कम से कम दस काउंटर होने चाहिए।

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे स्थित खेड़कीदौला टोल प्लाजा पर फास्टैग ट्रायल के दौरान लगा जाम। जागरण

आज से शहर के कई स्थानों पर होंगे काउंटर: खेड़कीदौला टोल प्लाजा पर ट्रायल का निरीक्षण करने पहुंचे एनएचएआइ के निदेशक (प्रोजेक्ट) एके शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फास्टैग के लिए साइबर सिटी में भी काउंटर चालू किए गए हैं। शुक्रवार से शहर के विभिन्न इलाकों में काउंटर चालू हो जाएंगे। पेटीएम के साथ बैंकों से कहा गया है कि वे काउंटरों की संख्या अधिक से अधिक करें ताकि लोगों को आसानी हो। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कहीं से भी लोग फास्टैग ले सकते हैं। बैंकों की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है।

सरकार ने एक दिसंबर से फास्टैग अनिवार्य किया है, उसका पालन किया जाएगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। लोगों से अपील है कि वे जल्द से जल्द फास्टैग ले लें ताकि उन्हें जाम का सामना न करना पड़े।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर भी लागू होगा फास्टैग

जासं, ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेस-वे पर भी फास्टैग व्यवस्था लागू होगी। प्राधिकरण ने इसके लिए जेपी इंफ्राटेक को पत्र भेजा है। एक्सप्रेस-वे की दोनों ओर की एक-एक लाइन फास्टैग के लिए रिजर्व होंगी। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर फास्ट टैग के लिए पहले ही करार हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग की व्यवस्था एक दिसंबर से लागू हो जाएगी। फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है। टोल प्लाजा पर फास्टैग के लिए वाहन चालकों की लाइन लग रही हैं। यमुना प्राधिकरण ने एक्सप्रेस-वे पर भी फास्टैग व्यवस्था लागू करने के लिए जेपी इंफ्राटेक को निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने कंपनी को इस संबंध में पत्र भेजा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जेपी इंफ्राटेक इसे लेकर जल्द ही एमओयू कर सकती है। ईस्टर्न पेरिफेरल को यमुना एक्सप्रेस-वे से इंटरचेंज के जरिये जोड़ना प्रस्तावित है।

ईडी ने अटैच की 8.82 करोड़ की संपत्ति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों की ठगी के मामले में नोएडा की मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी वेबवर्क ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अनुराग गर्ग व संदेश वर्मा की 8.82 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। इनमें कई बैंक खाते व एफडी शामिल हैं। ईडी इससे पूर्व आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

ईडी ने इससे पहले कंपनी की करीब 27.66 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी। नोएडा की कंपनी वेबवर्क ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड, ऐड्स बुक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड व वेबवर्क डॉट इन के जरिये सितंबर 2016 में निवेशकों को घर बैठे उनकी रकम को कई गुना किए जाने का झांसा दिया गया था। कंपनी ने लोगों को एक क्लिक पर रकम देने का झांसा देकर जाल में फंसाया था। हजारों लोगों ने कंपनी में 250 करोड़ से अधिक का निवेश किया था। ठगे जाने पर निवेशकों ने 12 फरवरी 2017 को नोएडा के सेक्टर 20 थाने में कंपनी के निदेशक अनुराग गर्ग व संदेश वर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

48 सरकारी वेबसाइट हैक हुए हैं इस साल अक्टूबर तक। इनमें केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के वेबसाइट भी शामिल हैं। पिछले वर्ष यह संख्या 110 थी। यह जानकारी प्रौद्योगिकी एवं सूचना मंत्रालय के राज्यमंत्री संजीव धोत्रे ने गुरुवार को राज्यसभा में दी।

श्रीलंका के साथ आर्थिक व रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने को तैयार भारत

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

पहले विदेश दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे

पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति के बीच वार्ता आज

पिछले हफ्ते श्रीलंका में आम चुनाव के संपन्न होते ही भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि अब वह अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे को बधाई दी, बल्कि उनके शपथ लेने के दिन ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर को कोलंबो भेज दिया। अब शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और गोतबाया के बीच पहली बैठक की तैयारियों में विदेश मंत्रालय जुटा है। इस बात के संकेत दिए गए हैं कि भारत अपने इस पड़ोसी देश के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला।

गोतबाया गुरुवार देर शाम अपनी पहली विदेश यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक, सत्ता संभालने के बाद राष्ट्रपति गोतबाया का भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती व महत्व को दर्शाता है।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, मोदी के साथ होने वाली उनकी बैठक का एजेंडा काफी व्यापक है। यह एक तरह से भारत व श्रीलंका के भावी सहयोग का एजेंडा तय करेगा। दोनों नेताओं के बीच भारतीय मछुआरों से जुड़े मुद्दों से लेकर आतंक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग तक पर बात होगी। साथ ही भारत की मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं की समीक्षा भी होगी। उम्मीद है कि भारत की तरफ से श्रीलंका के लिए कुछ नए आर्थिक सहयोग की घोषणा भी की सकती है।

नई दिल्ली में गुरुवार को हवाई अड्डे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे की अगवानी केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने की। एएफपी

सनद रहे कि नेपाल में जब केपी शर्मा ओली की सरकार बनी थी तब भी भारत ने उन्हें सबसे पहले यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। ओली के दौरे पर भारत ने नेपाल को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने की योजना का खुलासा किया था। ओली की छवि भी भारत से ज्यादा चीन के प्रति झुकाव रखने वाले की रही है। गोतबाया के बारे में भी यही माना जाता है कि वह चीन के प्रति ज्यादा झुकाव रखते हैं।

गोतबाया और मोदी के बीच होने वाली मुलाकात में भारत की मदद वाली वहां की ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा भी होनी है। भारत वहां कुछ परियोजनाएं अपने बूते और कुछ जापान की मदद से चलाने को तैयार है। वर्ष 2018 में जब जापान के पीएम एबी शिंजो भारत दौरे पर आए थे तो दोनों देशों ने यह मंशा जताई थी कि वे श्रीलंका समेत अन्य देशों में बिजली, रेल, बंदरगाह परियोजनाएं साथ-साथ चलाना चाहते हैं। श्रीलंका की पूर्ववर्ती सरकार इसको लेकर काफी उत्साहित थी। अब देखना है कि गोतबाया क्या रुख दिखाते हैं।

जानकारों की मानें तो गोतबाया ने अपने चुनाव प्रचार में भले ही चीन के प्रति ज्यादा सकारात्मक भाव दिखाया हो लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने एक बार भी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है जिससे भारत को उनकी भावना के प्रति कोई शंका हो। हो सकता है कि जिस तरह से इस क्षेत्र के कुछ दूसरे देश चीन और भारत के बीच बेहतर सामंजस्य बिठाते हुए दोनों से ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग हासिल करने की रणनीति अपना रहे हैं, श्रीलंका भी उसी का अनुसरण करे। भारत की भावी रणनीति के लिए श्रीलंका की भूमिका काफी अहम होगी। जिस तरह से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की जगह भारत बिम्सटेक (बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार व थाइलैंड की सदस्यता वाला संगठन) को बढ़ावा दे रहा है उसमें श्रीलंका की भूमिका काफी अहम होगी। इसके अलावा भारत यह भी सुनिश्चित करना चाहेगा कि श्रीलंका चीन की बढ़ती गतिविधियों का अड्डा नहीं बने। सुरक्षा विशेषज्ञ पहले ही चीन की तरफ से वहां विकसित किए जा रहे पोर्ट को लेकर काफी चिंता जता चुके हैं।

चिट फंड संशोधन विधेयक को मिली संसद की मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 को संसद की मंजूरी मिल गई है। चिट फंड की मौद्रिक सीमा को तीन गुना बढ़ाने तथा 'फोरमैन' के कमीशन को सात फीसद करने के प्रावधान वाले इस विधेयक को गुरुवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को 20 नवंबर को पारित कर चुकी है। 'फोरमैन' का आशय उस व्यक्ति से है, जो चिट फंड चलाता है।

एक व्यक्ति या चार साझीदारों से कम द्वारा चलाए जाने वाले चिट फंड की मौद्रिक सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है। चार या इससे ज्यादा साझीदारों द्वारा चलाए जाने वाले वाले चिट फंड की मौद्रिक सीमा छह लाख रुपये से बढ़ाकर 18 लाख रुपये कर दी गई है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पोंजी और चिट फंड में अंतर है। पोंजी अवैध होता है, जबकि चिट फंड वैध कारोबार है।

इस कानून में ग्राहकों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये भी पैसे निकालने की सुविधा दी गई है। इसको लेकर विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए ठाकुर ने कहा कि पैसे की निकासी के समय सभी ग्राहकों को उपस्थित रहना पड़ेगा। लेकिन, यदि कुछ सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं, तो उनसे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये संपर्क किया जा सकता है। ठाकुर ने कहा कि चिट फंड के ग्राहक बीमा का विकल्प भी चुन सकते हैं, लेकिन सरकार इसे अनिवार्य नहीं कर सकती है।

विचाराधीन कैदियों के मामलों की जल्द सुनवाई के पक्ष में केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा को बताया कि उन्होंने सभी 25 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से विचाराधीन कैदियों के मामलों की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है। प्रस्तावित सजा का 50 फीसद पूरा कर चुके विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का भी आग्रह किया है। प्रश्नकाल के दौरान प्रसाद ने कहा कि विचाराधीन कैदियों की रिहाई जेलों में भीड़ कम करने की सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2016 में जेलों में बंद कैदियों में से 67 .7 फीसद विचाराधीन थे।

औद्योगिक संबंध संहिता बिल पेश करने पर लोस में विपक्ष का हंगामा

रखी बात ▶ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों ने बिल को बताया श्रमिक विरोधी

विधेयक को व्यापक चर्चा के लिए स्थायी समिति को भेजने की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार की ओर से संसद में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक पेश किए जाने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस तथा वाम सदस्यों समेत विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि विधेयक श्रमिक विरोधी है और इसमें श्रमिकों के अधिकारों की उपेक्षा की गई है। लिहाजा इसे व्यापक चर्चा के लिए स्थायी समिति को भेजा जाए।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे श्रमिकों के अधिकारों का हनन होता हो। हालांकि बाद में सदन में बिल पेश हो गया। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि किसी श्रम संगठन ने इस बिल की मांग नहीं की थी। यह बिल फिक्की और सीआइआइ की मांग पर लाया गया है। इसमें कर्मचारियों के अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि कौन यूनियन अध्यक्ष हो सकता है और कौन नहीं। हम कई यूनियनों के अध्यक्ष हैं। कर्मचारी हमें चुनते हैं। इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि बिल में हड़ताल और तालाबंदी पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया गया है। ये श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन है।

संतोष गंगवार फाइल फोटो

कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बिल में विसंगतियों के साथ-साथ विवादास्पद प्रावधान हैं। सरकार स्थायी रोजगार के बजाय कारपोरेट सेक्टर के 'जब चाहे रखो और जब चाहे निकालो (हायर एंड फायर) सिद्धांत' को अमल में लाना चाहती है। इस सरकार ने श्रमिकों को कोई सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की है। बिल में 'सामूहिक सौदेबाजी' का कोई उल्लेख नहीं है। जबकि यह श्रमिकों का बुनियादी अधिकार है। इसमें अर्धन्यायिक अधिकारों वाले ट्रिब्यूनलों को असीमित अधिकार दिए गए हैं। इसका उपबंध 75 आंख में धूल झोंकने वाला है क्योंकि इसमें फैक्ट्री बंद होने की दशा में कामगारों को क्षतिपूर्ति नहीं देने के कई बहाने दिए गए हैं।

हड़ताल पर जाने के लिए देना होगा 14 दिन का नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : औद्योगिक संबंध संहिता बिल में सरकार ने हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए 14 दिन का अनिवार्य नोटिस देने का प्रस्ताव किया है। इसकी जानकारी संतोष गंगवार ने खुद बुधवार को राज्यसभा में दी थी।

आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि बिल में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान की यूनियन के पंजीकरण के लिए उसके पदाधिकारियों के उस कारखाने का कर्मचारी होने की शर्त रखी गई है जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। इसके अनेक प्रावधान समवर्ती सूची में आते हैं। लेकिन संबंधित राज्यों से परामर्श नहीं किया गया है। विपक्ष की आशंकाओं का जवाब देते हुए श्रम राज्यमंत्री गंगवार ने कहा कि बिल को सारे श्रम संगठनों, नियोक्ताओं और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही पेश किया गया है। आप चर्चा करें। बहस के बाद जो निर्णय लेंगे उसे माना जाएगा। बता दें कि औद्योगिक संबंध संहिता बिल पुराने 44 श्रम कानूनों को चार संक्षिप्त श्रम संहिताओं में बदलने की सरकार की मुहिम का हिस्सा है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 नवंबर को मंजूरी प्रदान की थी।

सीआइसी में 13 हजार से अधिक मामले एक साल से ज्यादा समय तक लंबित

आरटीआइ कानून लागू करने में सुधार के लिए कदम उठा रही है सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) में 13 हजार से अधिक मामले एक वर्ष से ज्यादा समय तक लंबित हैं। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीआइसी में एक साल से अधिक समय तक लंबित मामलों की कुल संख्या 13,453 है। मंत्री ने बताया कि सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में सुधार के लिए कदम उठा रही है।

पहले सुरक्षा बाद में उत्पाद का सूत्र अपना रहे हैं : उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का उत्तर देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के सभी परमाणु बिजली संयंत्र साइबर हमले के खतरों से पूरी तरह सुरक्षित हैं। कुडनकुलम संयंत्र के प्रशासनिक नेटवर्क में 'वायरस हमले' की शिकायत मिलने के बाद इस तरह के जोखिम से निपटने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, 'हम पहले सुरक्षा, बाद में उत्पादन सूत्र को अपना रहे हैं।' सिंह के पास प्रधानमंत्री कार्यालय का भी प्रभार है।

3000 से ज्यादा पेंशनरों से शिकायतें मिलीं : जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में बताया कि इस साल नवंबर में पेंशनरों से 3000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। मुख्य जवाबदेही रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की मंजूरी देना है। इसके साथ ही जहां से वे रिटायर हो रहे हैं उस संबंधित विभाग या संगठन से जुड़ी शिकायतों का समाधान करना होता है।

राज्यसभा में सवालों का जवाब देते कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह। एएनआइ

96 भ्रष्ट अधिकारियों को समय से पहले दी गई सेवानिवृत्ति : एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले पांच साल में करीब 96 भ्रष्ट अधिकारियों को जनहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई। उन्होंने कहा कि जुलाई, 2014 से अक्टूबर 2019 तक सत्यनिष्ठा पोर्टल पर अपलोड सूचना के मुताबिक, विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के कुल 96 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

अश्लील सामग्री वाली करीब 377 वेवसाइटों को हटाया गया : महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में कहा कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री वाली करीब 377 वेबसाइटों को हटा दिया गया है। बाल उत्पीड़न के संबंध में 50 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। शून्यकाल के दौरान अन्नाद्रमुक सदस्य विजिला सत्यानंद ने इंटरनेट पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री का मुद्दा उठाया था। केंद्रीय मंत्री ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए जवाब दिया।

जनजातीय बहुल प्रखंडों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे : अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। जनजातीय मामलों की राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि जिन प्रखंडों की 50 फीसद से ज्यादा आबादी हो वहां ऐसे स्कूल खोले जाएंगे। जनजातीय समुदाय के कम से कम 20,000 व्यक्ति जिन प्रखंडों में होंगे सरकार वहां भी 2022 तक ये स्कूल खोलेगी।

लाभ-हानि रहित है सीबीएसई परीक्षा शुल्क में वृद्धि : मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों को छोड़ सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा शुल्क में लाभ-हानि रहित सिद्धांत के आधार पर वृद्धि की है। सीबीएसई ने सभी श्रेणी के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है।

भ्रष्टाचार, आतंकवाद में अलग-अलग सजा पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : उच्चतम न्यायालय उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें भ्रष्टाचार तथा आतंकवाद के मामलों में एक साथ कैद के बजाय एक के बाद एक सजा का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। अमेरिका जैसे देश में किसी अपराधी को अलग-अलग मामलों में एक साथ सजा देने के बजाय एक के बाद एक सजा भुगतनी होती है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और सूर्य कांत की तीन सदस्यीय पीठ ने भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की इस दलील को स्वीकार किया कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।

अदालत ने इस साल मार्च में ही केंद्र को इस मामले में नोटिस जारी किया था। उपाध्याय ने कहा कि याचिका पर केंद्र का जवाब आ गया है और अब यह मामला सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। अतः इसे शीघ्र सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

याचिका में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधान के तहत दोषी व्यक्ति अलग-अलग अपराधों के लिए एक साथ सजा काट सकता है, लेकिन यह प्रावधान नृशंस अपराधों के लिए लागू नहीं होना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, भ्रष्टाचार रोकथाम कानून, बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध कानून, मनी लांड्रिंग एक्ट, विदेशी योगदान (विनिमय) कानून, कालाधन एवं कर चोरी कानून और भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून जैसे विशेष अधिनियमों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

अमेरिका जैसे देश में अपराधियों को एक के बाद एक भुगतनी होती है सजा

सीआरपीसी के तहत अलग-अलग जुर्मों के लिए एक साथ सजा काट सकता है अपराधी

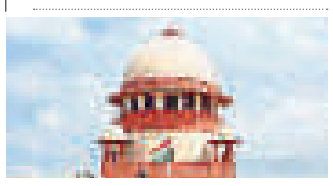

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

याचिका में कहा गया है कि समाज में आतंकवाद फैलाकर धन कमाना संगठित अपराधियों का उद्देश्य है। इसलिए जघन्य अपराध के दोषियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। मकोका में तीन से 10 साल सजा का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकता था। सीआरपीसी की धारा 31 में प्रावधान है कि विभिन्न अपराधों के तहत अलग-अलग सजा दी जा सकती है। लेकिन, यदि कोर्ट विशेष रूप से इसका उल्लेख नहीं करता है, तो सजा साथ-साथ चलती है।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा-जेल से भी गवाहों को प्रभावित कर रहे चिदंबरम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आइएनएक्स मीडिया केस

जमानत पर बहस पूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

ईडी ने कहा-16 देशों में हैं पूर्व वित्त मंत्री से संबद्ध बेनामी संपत्तियां

आइएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि चिदंबरम प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह हिरासत में रह कर भी गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इस संबंध में दस्तावेज भी पेश कर सकते हैं। कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस आर.भानुमती की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को ईडी को सीलबंद लिफाफे में मामले से संबंधित दस्तावेज देने की छूट देते हुए चिदंबरम की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम की भारत के बाहर भी बेनामी संपत्तियां हैं। 16 कंपनियां मनी लांड्रिंग में शामिल रहीं और उनके शेयर होल्डिंग के तरीकों में तब्दीली की गई। 12 विदेशी बैंक खातों और 12 विदेशी संपत्तियों की पहचान हो गई है। 16 देशों की इन संपत्तियों का ताल्लुक चिदंबरम से हो सकता है।

ध्यान रहे कि चिदंबरम पिछले सौ दिन से जेल में हैं। मनी लांड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। गत बुधवार को चिदंबरम की ओर से जमानत की मांग करते हुए कहा गया था कि उनके खिलाफ एक भी सुबूत नहीं है। ऐसे में उन्हें जेल में रखना ठीक नहीं।

ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध भी गंभीर प्रकृति के होते हैं। ऐसे अपराधों से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि व्यवस्था से लोगों का भरोसा भी डिगता है। आर्थिक अपराध समाज पर असर डालता है। उन्होंने कहा कि चिदंबरम प्रभावी व्यक्ति हैं। वे हिरासत में जेल में रहें या बाहर रहें, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। मेहता ने कहा कि एक गवाह ने चिदंबरम से आमना-सामना करने से मना कर दिया। उसने चिदंबरम के सामने आकर पुष्टि करने से भी मना कर दिया। इस दलील का विरोध करते हुए चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम जब बाहर थे तब उन्होंने किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं किया और अब ईडी कह रही है कि वह जेल में रह कर गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। इस पर मेहता ने कहा कि उनके पास ये दिखाने के लिए दस्तावेज हैं।

मेहता बोले, क्या रंगा बिल्ला जैसे अपराध पर ही कार्रवाई हो : सिब्बल की ओर से बुधवार को चिदंबरम की जमानत से इन्कार करने के हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए दलील दी गई थी कि चिदंबरम क्या रंगा बिल्ला जैसे अपराधी हैं जो उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। गुरुवार को इस दलील का जवाब देते हुए तुषार मेहता ने कहा कि क्या रंगा बिल्ला जैसा अपराध किए जाने पर ही कार्रवाई होनी चाहिए।

कोर्ट की रोक हटते ही कार्ति भी गिरफ्तार होंगे : मेहता ने कहा कि पी. चिदंबरम के बेटे और आरोपित कार्ति चिदंबरम मनी लांड्रिंग मामले में जमानत पर नहीं हैं। वह भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ की जांच पर जमानत पर हैं। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। कोर्ट की रोक हटते ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कार्ति ने पीएमएलए कानून के कुछ प्रावधानों को कोर्ट में चुनौती दे रखी है।

डीआरटी का आदेश, पीएनबी को 7030 करोड़ रुपये लौटाए नीरव

मुंबई, आइएएनएस : कर्ज वसूली अधिकरण (डीआरटी-1) ने पीएनबी घोटाले में आरोपित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को 7030 करोड़ रुपये की राशि पंजाब नेशनल बैंक को ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही मोदी और उनके अन्य आरोपित सहयोगियों को बकाया राशि के साथ कुल राशि का 14.30 प्रतिशत ब्याज भी चुकाने को कहा है। यह पूरी राशि 30 जून, 2018 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा रिकवरी की 1.75 लाख रुपये की रकम भी 15 दिनों के अंदर ही वसूली जाएगी।

डीआरटी-1 का विगत 22 नवंबर को दिया आदेश नीरव मोदी और मामले के अन्य आरोपितों को दिया गया है। मोदी और उनके नजदीकी रिश्तेदारों एमि एन.मोदी, नीशाल डी. मोदी, अनन्या एन.मोदी, अपाशा एन.मोदी और पूर्वी मयंक मेहता को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा, समूह की कंपनियों को भी नोटिस जारी किया गया है। यह कंपनियां स्टेलर डायमंड्स, सोलर एक्सपोर्ट्स, डायमंड आरयूएस, फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड और उसकी मुंबई, गुजरात और राजस्थान में स्थित 13 शाखाओं को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा, एएनएम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस दिया गया है। नीरव मोदी को नोटिस उनके मुंबई स्थित आवास ग्रोस वेनोस हाउस और दुबई स्थित शेरा टावर्स में भेजा गया है। मोदी के एक रिश्तेदार नेहाल डी. मोदी को उनके न्यूयार्क के पते पर नोटिस भेजा गया है। डीआरटी-पुणे के आदेश के चार महीने बाद मुंबई स्थित डीआरटी ने भी ऐसा ही आदेश दिया है।

नीरव मोदी। फाइल

इससे पहले नीरव मोदी को सिंगापुर उच्च न्यायालय ने झटका देते हुए ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में पंजीकृत पवेलियन प्वाइंट कॉर्प कंपनी के खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया था। इस खाते में 44.41 करोड़ रुपये मौजूद हैं। इस खाते के लाभकारी मयंक मेहता और पूर्वी मोदी हैं, जो नीरव मोदी के बहन-बहनोई हैं।

गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने 27 जून को नीरव मोदी और उसकी बहन के चार स्विस खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी थी। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी थी। भारत में नीरव मोदी के खिलाफ चल रहे मनी लांड्रिंग मामले के तहत यह कार्रवाई की गई थी।

सलाह

पहली तिमाही में रेलवे की कम कमाई को देखते हुए पीएमओ आया आगे, आमदनी बढ़ाने के लिए रेलवे को कुछ और नए उपाय करने को कहा

प्रधानमंत्री कार्यालय का रेल किराये में बढ़ोतरी का सुझाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे की नाजुक माली हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने रेल मंत्रालय से यात्री ट्रेनों का किराया बढ़ाने को कहा है। पीएमओ का कहना है कि स्थिति को देखते हुए रेलवे को एक-दो महीने में किराया बढ़ाना चाहिए और उससे पहले लोगों को इसका औचित्य बताना चाहिए।

पीएमओ ने ये निर्देश रेलवे की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए दिए हैं। दरअसल इस वर्ष रेलवे की यातायात से कमाई कम, जबकि खर्च ज्यादा हो गए हैं। अप्रैल से अक्टूबर की तिमाही में रेलवे को यात्री और माल यातायात से मात्र 99 हजार करोड़ से कुछ अधिक की कमाई हुई है। जबकि लक्ष्य एक लाख 18 हजार करोड़ की कमाई का था। इसके विपरीत खर्च बढ़कर एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। जबकि खर्च को 96 हजार करोड़ रुपये पर सीमित रखने का लक्ष्य था। हालांकि इस स्थिति के लिए अर्थव्यवस्था में सुस्ती और मांग कम होना प्रमुख वजह बताई जाती है, जिससे रेलवे की माल ढुलाई पर बुरा असर पड़ा है। ढुलाई बढ़ाने के लिए रेलवे पहले ही अक्टूबर-मार्च के व्यस्त मौसम के लिए स्टील छोड़ बाकी वस्तुओं की माल-भाड़ा दरों में 20 फीसद की रियायत देने का एलान कर चुका है। जबकि खाली चल रही चुनिंदा प्रीमियम ट्रेनों को भरने के लिए उनके किराए भी कम किए गए हैं। इनमें कुछ रूटों पर चलने वाली शताब्दी गाड़ियां शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार पीएमओ इतने से संतुष्ट नहीं है। वह चाहता है कि रेलवे बोर्ड इसी महीने किराया वृद्धि का निर्णय ले और उसे अगले वर्ष एक जनवरी से लागू करे। ताकि चालू वित्तीय वर्ष के आखिरी तीन महीनों यानी जनवरी-मार्च के दौरान ही इसका लाभ रेलवे को मिल सके और एक फरवरी को पेश होने वाले अगले आम बजट में इसका उल्लेख किया जा सके।

किराया बढ़ोतरी के अलावा पीएमओ ने रेलवे को आमदनी बढ़ाने के कुछ और नए उपाय करने को कहा है। और इस बाबत कुछ सुझाव भी रेलवे को दिए हैं। मसलन, उसने लखनऊ-दिल्ली-लखनऊ 'तेजस एक्सप्रेस' की तर्ज पर कुछ और प्राइवेट ट्रेनें जल्द शुरू करने को कहा है। इसके जिस प्रकार एनएचएआइ टोल सड़कों के 'टीओटी' ठेके देकर एकमुश्त रकम जुटा रहा है। उसी भांति आइआरसीटीसी और क्रिस की वेबसाइटों के चुनिंदा अधिकार निजी कंपनियों को देकर उनसे एकमुश्त रकम जुटाने का सुझाव भी दिया गया है। पीएमओ ने रेलवे से टूरिस्ट ट्रेनों से संबंधित पैकेजों को और आकर्षक बनाने तथा हेल्थ टूरिज्म में भागीदारी की योजना तैयार करने को भी कहा है।

सीबीआइ ने रेलटेल निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने रेलटेल के निदेशक आशुतोष वसंत और निजी कंपनी यूनाइटेड टेलीकॉम के साथ ही अमेरिकी कंपनी इनफिनेरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि 2012 में अधिकारियों की अमेरिका यात्रा के दौरान उनके कथित आपराधिक कदाचार के लिए यह मामला दर्ज किया गया है। वसंत पर आरोप है कि उन्होंने 2012 में सैन फ्रांसिस्को होते हुए शिकागो की अपनी आधिकारिक यात्रा के लिए एयर इंडिया में बिजनेस श्रेणी की टिकट बुक की थी। अधिकारियों ने बताया कि सैन फ्रांसिस्को से शिकागो जाते हुए उन्होंने अमेरिका एयरवेज की इकोनॉमी श्रेणी की टिकट का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वसंत के अनुरोध और इनवॉयस एवं ई-टिकट दिखाने के बाद ट्रैवल एजेंसी को भुगतान किया था। अधिकारियों के मुताबिक, वसंत ने इकोनॉमी क्लास में सफर किया, लेकिन बिल बिजनेस क्लास का

निजी कंपनी यूनाइटेड टेलीकॉम और अमेरिकी कंपनी इनफिनेरा के खिलाफ भी मामला दर्ज

दिया। सीबीआइ ने कहा कि उन्होंने धोखाधड़ी को छिपाने के लिए यात्रा संबंधी दस्तावेज नहीं पेश किया था।

रेलटेल की स्थापना 2000 में एक मिनीरत्न कंपनी के तौर पर हुई थी। यह ट्रेन नियंत्रण परिचालन और भारतीय रेलवे के सुरक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड, टेलीकम्युनिकेश एवं मल्टीमीडिया नेटवर्क का संचालन करता है। एजेंसी ने कहा कि यूनाइटेड टेलीकॉम ने वसंत के होटल बिलों का भुगतान किया, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने एक हलफनामा बनवाया कि उन्होंने नकद में कंपनी को पैसा वापस चुका दिया। सीबीआइ ने कहा कि वसंत और अन्य दो अधिकारियों की अनुशंसा पर, रेलटेल ने यूटीएल और इनफिनेरा कंपनी को एक टेंडर के लिए चुना था।

कह के रहेंगे माधव जोशी

1966 में बनी शिवसेना ने कई मौकों पर कांग्रेस का साथ दिया है। 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल और 2012 के चुनाव में प्रणव मुखर्जी की उम्मीदवारी का समर्थन किया था।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 29 नवंबर 2019

मुंबई में गुरुवार को शिवाजी पार्क में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पत्नी रश्मि से हाथ मिलाकर खुशी जताते उद्धव ठाकरे। प्रेट्र

सरकारी विभागों में खाली पदों को जल्द भरने का किया वादा

महाविकास अघाड़ी ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम की घोषणा की

राज्य ब्यूरो, मुंबई

मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण से पहले महाविकास अघाड़ी ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) की घोषणा की। शिवसेना अपनी स्थापना के दौर से ही रोजगार में स्थानीय लोगों अर्थात भूमिपुत्रों को प्राथमिकता देने की हिमायती रही है। उसकी इसी नीति की छाप साझा कार्यक्रम में भी दिखाई थी। इसी वजह से किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी के साथ-साथ सीएमपी में नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 फीसद आरक्षण और विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पदों पर तुरंत भर्ती का वादा किया गया है।

शपथ ग्रहण समारोह से करीब दो घंटे पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे, राकांपा के जयंत पाटिल व नवाब मलिक और कांग्रेस नेताओं ने एक साथ आकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम की घोषणा की। इसमें किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर रखते हुए हाल की बेमौसम अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों को तुरंत राहत देने का वादा किया गया है। किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी देने के अलावा उनके लिए किसान बीमा योजना में भी सुधार करने की बात कही गई है। उद्धव ठाकरे चुनाव के दौरान भी किसान बीमा में गड़बड़ी की बात उठाते रहे हैं। किसानों की समस्याओं के अलावा शिवसेना द्वारा चुनाव के दौरान किए गए 10 रुपये में भोजन की थाली के वादे को भी पहले ही दिन पूरा करने की घोषणा की गई। बता दें कि इस तरह के सस्ते भोजन की योजनाएं तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत में काफी लोकप्रिय होती रही हैं। महाराष्ट्र में भी 1995 में बनी शिवसेना-भाजपा गठबंधन की पहली सरकार में झुणका-भाखर योजना शुरू की गई थी।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी काफी ध्यान दिया गया है। तालुका स्तर पर हर प्रकार के टेस्ट के लिए एक रुपया क्लीनिक की घोषणा की गई है, जहां मरीजों को एक रुपये का पर्चा बनाकर उनका इलाज किया जाएगा और उन्हें सभी प्रकार के टेस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी। गरीब कन्याओं को मुफ्त शिक्षा और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलने की बात भी कही गई है। महिलाओं की सुरक्षा को भी विशेष प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सेक्युलर मूल्यों पर दृढ़ रहने का वादा करते हुए साझा सरकार में विवादों से बचने के लिए दो समन्वय समितियां बनाने का भी प्रस्ताव है। इनमें से एक समन्वय समिति सरकारी कामकाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए होगी तो दूसरी तीनों पार्टियों के बीच। इसके अलावा भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में मुंबई में शुरू की गई कई मेट्रो परियोजनाओं में तेजी लाने की बात भी कही गई है। झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत झुग्गी में रहने वालों को वर्तमान में 300 वर्गफीट के स्थान पर 500 वर्गफीट के घर किराये पर देने का वादा किया गया है।

मुंबई में गुरुवार को शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राकांपा प्रमुख शरद पवार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस नेता अहमद पटेल और मनसे नेता राज ठाकरे। एपी

कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने शुभकामना पत्र भेजकर दी उद्धव को बधाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **सोनिया ने असाधारण परिस्थितियों का हवाला देकर शिवसेना से गठबंधन को ठहराया जरूरी**

शिवसेना के साथ सत्ता की साझेदार बनने के बावजूद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहा। शिवसेना से अचानक दोस्ती को लेकर हिचकिचाहट ही रही कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उद्धव को महाराष्ट्र की कमान संभालने का शुभकामना पत्र तो भेजा, मगर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए।

उद्धव को भेजे शुभकामना पत्र में सोनिया ने यह कहकर गठबंधन के फैसले को सही ठहराया कि बेहद असाधारण परिस्थितियों में कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना को साथ आना पड़ा है। इसलिए उम्मीद है कि इन हालात में तीनों दलों की नई सरकार महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। उद्धव ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बुलाने के लिए अपने विधायक बेटे आदित्य को खुद सोनिया, मनमोहन और राहुल को आमंत्रित करने के लिए दिल्ली भेजा था।

सोनिया गांधी ने उद्धव से कहा कि आदित्य ने न्योता दिया था मगर वह शपथ ग्रहण समारोह में आने में असमर्थ हैं और इसके लिए उन्हें खेद है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने असमर्थता की कोई वजह नहीं बताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा है कि देश का राजनीतिक वातावरण जहरीला हो गया है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और किसान परेशान हैं। ऐसे में कांग्रेस-राकांपा और शिवसेना ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय किया है और उन्हें विश्वास है कि तीनों पार्टियां इस वादे को पूरी भावना के साथ कार्यान्वित करेंगी। सोनिया ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र की जनता गठबंधन से समावेशी, जवाबदेह और पारदर्शी शासन की उम्मीद करती है और हम सभी का सामूहिक प्रयास इसे पूरा करने पर केंद्रित होना चाहिए।

मनमोहन ने उद्धव को शुभकामनाएं भेजते हुए उनके मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बताया। वहीं, राहुल गांधी ने भी शपथ में शामिल नहीं होने पर खेद जताते हुए उद्धव को नई सियासी जिम्मेदारी संभालने के लिए शुभकामना पत्र भेजा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने इसमें फड़नवीस को शपथ दिलाए जाने के घटनाक्रम की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक उदाहरण है।

उन्होंने इस बात पर खुशी भी जताई कि शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा के महाविकास अघाड़ी ने साथ आकर लोकतंत्र को कुचलने के भाजपा के प्रयासों को परास्त कर दिया। राहुल ने यह उम्मीद भी जताई है कि अघाड़ी एक स्थायी, धर्मनिरपेक्ष और गरीब हितैषी सरकार देगा।

उद्धव की राह में बिछाए दो टन फूल

प्रथम पृष्ठ से आगे

उद्धव के शपथ ग्रहण को लेकर गुरुवार सुबह से शिवसेना की मजबूती वाले इलाकों में खासा उत्साह देखा जा रहा था। शाम को शपथ ग्रहण से ठीक पहले शिवसैनिकों के एक समूह ने दो टन गेंदे के फूल उद्धव के शिवाजी पार्क पहुंचने के मार्ग में बिछा दिए थे। बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रचार अभियान में उद्धव बार-बार अपने पिता के सपनों का जिक्र करते हुए मंत्रालय पर भगवा फहराने और किसी शिवसैनिक को ही मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का संकल्प दोहरा रहे थे। लेकिन तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह स्वयं इस पद की शपथ ले सकते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद परिस्थितियां ऐसी बदलीं कि 105 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी भाजपा को दरकिनार कर 56 सीटों वाली शिवसेना ने अपने विरोधी दल कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला कर लिया। इन चुनावों में राकांपा को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें हासिल हुई हैं।

'पीएम-गृह मंत्री के निर्देश पर महाराष्ट्र की घटना'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सोनिया गांधी फाइल

- **संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, राज्यपाल के जरिये लोकतंत्र कुचलने का प्रयास**
- **आर्थिक मंदी, जासूसी व एनआरसी पर भी सरकार पर बोला हमला**

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़नवीस को चुपके-चुपके शपथ दिलाने की घटना को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। राज्यपाल के इस फैसले को निंदनीय करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक ही नहीं कि पीएम और गृह मंत्री के निर्देश पर गवर्नर ने लोकतंत्र को कुचलने का शर्मनाक प्रयास किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने जम्मू-कश्मीर के हालात और अर्थव्यवस्था की खस्ताहाली पर भी सरकार पर तीखे हमले किए।

गुरुवार को संसद के शीत सत्र में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम के सहारे सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की सूबे में सरकार न बने इसके लिए भाजपा नेतृत्व ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिये तीनों दलों ने भाजपा के प्रयासों का पर्दाफाश कर दिया। उनका कहना था कि स्पष्ट हो गया है कि मोदी-शाह की सरकार में राजनीतिक शिष्टाचार जैसी कोई चीज नहीं और न ही देश की गंभीर समस्याओं के समाधान का गुर है।

सोनिया ने कहा कि मोदी सरकार लोगों का ध्यान बुनियादी समस्याओं से हटाने के लिए विभाजनकारी नीतियों को आगे बढ़ाती है। असम में एनआरसी की खामियों से पैदा हुई गंभीर चुनौती के बाद भी गृह मंत्री का पूरे देश में एनआरसी लागू करने का एलान इसी रणनीति का हिस्सा है। सरकार का यह कदम जाहिर तौर पर लोगों में खौफ और बेचैनी पैदा करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसी तरह अनुच्छेद 370 हटाते समय सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में इसी तरह नई शुरुआत का झूठा वादा किया, मगर हालत यह है कि लोगों की मुश्किलें और हताशा कहीं ज्यादा बढ़ गई है। सूबे के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब भी हिरासत में नजरबंद रखा गया है। राहुल गांधी की अगुआई में राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर गया तो उसे एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया, जबकि एक संदेहास्पद एनजीओ की पहल पर यूरोपीय संघ के सांसदों को वहां की यात्रा कराने का सरकार ने शर्मनाक काम किया।

लोगों की जासूसी मूल अधिकारों पर प्रहार : वाट्सएप जासूसी कांड पर सोनिया ने इजरायली कंपनी के साफ्टवेयर पेगासस के जरिये सरकार के सुर से अलग बात करने वाले लोगों की जासूसी कराने के मुद्दे पर भी हमला बोला। उनका कहना था कि सरकार का यह कृत्य लोगों के संवैधानिक मूल अधिकारों पर प्रहार है। आर्थिक मंदी पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विकास दर लगातार नीचे जा रही है। व्यापार-कारोबार की हालत बेहद खराब है। चौतरफा लोगों को मुश्किलों से रूबरू होना पड़ रहा है। रोजगार और नौकरियों का संकट बेहद गंभीर होता जा रहा है। वहीं, किसानों की चुनौती का समाधान नहीं निकाला जा रहा। सोनिया गांधी ने चुनावी बांड में भारी गड़बडी के तथ्यों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने केवल अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक की आपत्तियों को भी दरकिनार कर दिया।

शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने किया इन्कार

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया। हाई कोर्ट ने सवाल किया कि विवाह कानून में तलाक की अवधारणा क्या नई है? खुद को भाजपा समर्थक बताने वाले लोगों के एक समूह की ओर से दायर इस याचिका में भाजपा और शिवसेना को चुनावपूर्व गठबंधन में बने रहने और सरकार गठन करने का निर्देश देने की मांग की गई है। समूह की ओर से पेश अधिवक्ता मैथ्यू नेदुम्परा ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए हाई कोर्ट की दो अलग-अलग पीठों से संपर्क किया, लेकिन दोनों ही पीठों ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया। जस्टिस एससी धर्माधिकारी और आरआइ चगला की खंडपीठ ने कहा कि उनके पास समय नहीं है। इसके बाद नेदुम्परा ने मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ से याचिका पर सुनवाई का अनुरोध किया। नेदुम्परा ने कहा कि उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण असंवैधानिक और अमान्य है। पीठ के इसका कारण पूछने पर नेदुम्परा ने कहा कि भाजपा और शिवसेना ने मतदाताओं के भरोसे को छला है। इस पर मुख्य न्यायाधीश नंदराजोग ने कहा, 'विवाह कानून में क्या तलाक की अवधारणा नई है? जब उचित पीठ पहले ही याचिका पर आज सुनवाई से इन्कार कर चुकी है तो हम इस पर सुनवाई क्यों करें?'

झारखंड में पहले चरण का थमा चुनावी शोर कल पड़ेंगे वोट

- **सुदूर मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गईं पोलिंग पार्टियां**
- **चुनाव के अंतिम दिन सभी दलों व प्रत्याशियों ने लगाया जोर**

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए 13 विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार शाम तीन बजे से प्रचार थम गया। अंतिम दिन सभी दलों और उम्मीदवारों ने पूरा जोर लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अंतिम दिन चतरा और गढ़वा में जनसभाएं कीं। अन्य दलों की भी कई जनसभाएं हुईं। अब उम्मीद्वार डोर टू डोर कैंपेन में लग गए हैं।

पहले चरण की इन 13 सीटों पर शनिवार सुबह सात बजे से शाम तीन बजे तक वोट पड़ेंगे। इसे लेकर पोलिंग पार्टियां गुरुवार को ही सुदूर व संवेदनशील-अतिसंवेदनशील बूथों पर हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गईं। 1,269 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। शेष मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टियां शुक्रवार को सुबह रवाना होंगे। पहले चरण की सीटों पर कुल 189 प्रत्याशियों के लिए वोट पड़ेंगे जिनमें 15 महिला हैं।

इन विस क्षेत्रों में होगा मतदान : चतरा, गुमला, बिशुनपुर, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डालटनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, गढ़वा, हुसैनाबाद तथा भवनाथपुर।

नक्सलियों को जमीन के 20 फुट अंदर दफन कर देंगे : अमित शाह

महासमर
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

जेएनएन, गढ़वा

- **पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गृह मंत्री ने गढ़वा और चतरा में कीं सभाएं**
- **कहा- झारखंड में ओबीसी के आरक्षण का बढ़ाया जाएगा कोटा**

झारखंड के गढ़वा में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रेट्र

झारखंड के गढ़वा और चतरा में आयोजित चुनावी सभाओं में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर जोरदार हमला किया। वह बोले, नक्सली विकास में बाधा हैं। इसलिए इनका समूल नाश आवश्यक है। पलामू और चतरा नक्सलवाद से दहल रहे थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने इस पर नकेल कसी। नक्सली अपनी खैर मना लें। फिर भाजपा की सरकार आने वाली है। नक्सलवाद को 20 फुट जमीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा।

पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गढ़वा में आयोजित जनसभा में लोगों से कहा कि बंदूक से नहीं बल्कि बुलेट से राज्य का विकास हो सकता है। इसके लिए पीएम मोदी और सीएम रघुवर दास के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार को दोबारा चुनें। वहीं, चतरा में उन्होंने कहा कि झारखंड में ओबीसी की आबादी काफी अच्छी है। इसे सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भाजपा झारखंड में ओबीसी का कोटा बढ़ाना चाहती है। चुनाव बाद एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण के कोटे को बढ़ाने का निर्णय होगा। इसके लिए अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी।

भाजपा अध्यक्ष ने सभा में उपस्थित लोगों का समर्थन मांगते हुए कहा कि प्रदेश में दोबारा भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएं, ताकि अगले पांच वर्ष में झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार किया जा सके। झारखंड राज्य को भाजपा की देन बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में 70 वर्ष तक राज करने वाली कांग्रेस ने कभी इसकी चिंता नहीं की। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस के हाथों का खिलौना बना रहा।

रघुवर सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का बखान करते हुए शाह ने कहा कि पिछले पांच वर्ष के दौरान राज्य में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, उद्योग व रोजगार के क्षेत्र में काफी बेहतर काम हुआ है। सरकार ने 30 लाख घरों में बिजली पहुंचाई है। 2024 तक राज्य के सभी घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम पूरा किया जाएगा। देवघर में एम्स तथा रांची में कैंसर अस्पताल की स्थापना होने जा रही है। हजारीबाग, पलामू में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने वाली है।

मुलाकात...

मुंबई में गुरुवार को शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता का अभिवादन करते भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फड़नवीस। प्रेट्र

सियासत

मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और झामुमो में, छोटे दलों की कोशिश सरकार की चाभी उनके हाथ लग जाए

किंग से ज्यादा किंग मेकर के लिए प्रतिस्पर्धा

आशुतोष झा, रांची

महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद एक तरफ जहां झारखंड विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं, वहीं खुद झारखंड एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहा है जहां किंग से ज्यादा किंग मेकर की लड़ाई है। मैदान में सिर्फ दो योद्धा हैं, भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री रघुवर दास और विपक्षी गठबंधन की ओर से झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) के हेमंत सोरेन। 81 विधानसभा सीटों वाले राज्य में सुदेश महतो का ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू), बाबूलाल मरांडी का झारखंड विकास मोर्चा समेत जनता दल यू, लोजपा, झारखंड पार्टी ही नहीं, कई छोटे-छोटे समूहों ने अपना दावा ठोक दिया है। दरअसल, झारखंड का 2014 से पहले का राजनीतिक इतिहास देखते हुए हर दल ही नहीं इक्की-दुक्की सीटों पर लड़ने वाले नेता भी सोच रहे हैं कि कहीं सरकार की चाभी उन्हीं के हाथ न लग जाए।

झारखंड के चुनावी समर में उम्मीद्वारों की भरमार है। सबसे ज्यादा चर्चा आजसू की है, जो अब तक भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ती और सरकार चलाती रही है, लेकिन इस बार लगभग आधी सीटों पर भाजपा से अलग चुनाव लड़ रही है। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो हालांकि अपने निर्णय के पीछे महाराष्ट्र को कारण नहीं मानते हैं और भाजपा सरकार से सैद्धांतिक मतभेद को कारण बताते हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक विश्लेषक यह मानने को तैयार नहीं है। दरअसल, आजसू को लगता है कि ज्यादा सीटों पर लड़कर आधा दर्जन सीटें जीतने में भी कामयाब रहे तो सरकार किसी की भी बने, दबदबा रहेगा।

ध्यान रहे कि राज्य के लगभग 20 साल के इतिहास में पहली बार 2014 में स्थायी सरकार बनी तो थी, लेकिन शुरुआत में बहुमत नहीं था और आजसू के समर्थन से ही सरकार बनी थी। उससे पहले 14 साल के इतिहास में सात मुख्यमंत्री बने। एक बार तो निर्दलीय मुख्यमंत्री भी बना है।

पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी पिछली बार नतीजों के कुछ महीनों तक भी वह अपने विधायकों का कुनबा समेट कर नहीं रख सके थे। यह भी पता है कि जब कांग्रेस, झामुमो और खुद उनके बीच आदिवासी नेतृत्व की दावेदारी की प्रतिस्पर्धा हो तो अकेले दम बड़ी बाजी नहीं मारी जा सकती है, लेकिन फिर भी इस बार गठबंधन से अलग रहकर 80 सीटों पर खम ठोक दिया है। जदयू का झारखंड में बड़ा समर्थक वर्ग नहीं है, लेकिन लगभग चार दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया है। लोजपा ने भी दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रहे एनोस एक्का, कभी शिबू सोरेन को हराने वाले राजा पीटर जैसे कई लोगों ने दावेदारी की है।

दरअसल, झारखंड एक छोटा राज्य है। कुछ सीटों का हेरफेर भी बड़े बदलाव की गुंजाइश छोड़ देता है। इसलिए छोटे दलों को लगता है कि चार-पांच सीटों पर भी हाथ जम जाए तो किंग मेकर बन सकते हैं। आखिर मधु कोड़ा सरकार में तो एक-एक सीट जीतकर आए निर्दलीय भी किंग मेकर थे। एक विश्लेषक का मानना है कि अलग-अलग लड़ रहे दल ही नहीं हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ रही कांग्रेस की भी यही आस है। पहले की तरह इस बार मुख्यमंत्री पद की कोशिश छोड़ दी। संयम दिखाते हुए झामुमो का नेतृत्व सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन मजबूत उम्मीदवार न होते हुए भी लगभग दो दर्जन सीटों पर दावा इसीलिए ठोका है ताकि उसकी अहमियत बनी रहे। ध्यान रहे कि पिछले दिनों में कांग्रेस के तीन प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू, सुखदेव भगत और अजय कुमार अलग-अलग दलों का दामन थाम चुके हैं।

बुलेट की रफ्तार पर सियासत का ग्रहण!

14 सितंबर 2017
पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के पीएम एबी शिंजो के साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी

कभी भाजपा की हमकदम रही शिवसेना सियासत में साथी के बदलते ही प्राथमिकताएं भी बदल रही है। पार्टी प्रवक्ता मनीष कायदे ने कहा है कि शिवसेना बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा की तरह गंभीर नहीं है। राहुल गांधी पहले ही बुलेट ट्रेन पर सवाल उठा चुके हैं। दुनिया के अधिकांश देश समय की महता को समझते हुए आवागमन के साधनों में तेजी लाने पर जोर दे रहे हैं और बुलेट ट्रेन जैसे माध्यमों को अपना रहे हैं। ऐसे में हर भारतीय के स्वाभिमान से जुड़े इस प्रोजेक्ट के प्रति यह सोच कतई राष्ट्रहित में नहीं है। ऐसे में इस अहम परियोजना पर डालते हैं एक नजर:

पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। जापान के साथ 2015 में समझौता किया। इसके निर्माण में जापान आसान शर्तों पर वित्तीय मदद दे रहा है। 2016 में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का गठन हुआ।

कहीं देर न हो जाए

बुलेट ट्रेन चलाने के लिए अगस्त 2022 का लक्ष्य है। हालांकि 2022 में प्रोजेक्ट का एक छोटा हिस्सा ही पूरा होगा। मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन में बैठने का सपना आगामी वर्षों में ही पूरा हो सकेगा। उस पर महाराष्ट्र की सत्ता में शिवसेना के आगमन से बुलेट ट्रेन अपने निर्धारित लक्ष्य को पाने में और दूर हो सकती है। सरकार ने इसी साल जुलाई में संसद में कहा था कि बुलेट ट्रेन के लिए 1380 हेक्टेयर में से 548 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। फिलहाल आधी जमीन ऐसी है जिसका अधिग्रहण नहीं हो सका है।

आंकड़ों के आईने में बुलेट ट्रेन

- **508 किमी** लंबा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट
- **21 किमी** लंबी सुरंग बोइसर से बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स के बीच
- **2 घंटे** पूरा करेगी सफर
- **320 किमी/घंटे** रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन
- **35 फेरे** एक दिन में एक तरफ से होंगे
- **₹1.08 लाख करोड़** परियोजना की लागत
- **₹3000** करीब होगा किराया
- **7 किमी** समुद्र के अंदर से गुजरेगी
- **12** स्टेशनों के बीच दौड़ेगी ट्रेन
- **24 ट्रेनों** शुरुआत में होगा इस्तेमाल

6 हजार रुपये पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार तीन तलाक पीड़िताओं को देने जा रही है। हिंदू परित्यक्ताओं को भी सरकार यह पेंशन प्रदान करेगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग व समाज कल्याण विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है। शीघ्र ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

न्यूज गैलरी

उप्र में एक लीटर दूध में पानी मिलाकर 81 छात्रों को पिलाया

सोनभद्र : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मिड डे मील (मध्याह्न भोजन) में धांधली का मामला सामने आया है। यहां चोपन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सलईबनवा में 81 बच्चों में एक लीटर दूध बांटा गया। प्राथमिक जांच में घटना सही पाई गई, लेकिन इसमें शिक्षामित्र की साजिश भी सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है। एक लीटर दूध में एक बाल्टी पानी मिलाकर 81 बच्चों को पिलाने के इस मामले में सोनभद्र के डीएम ने कहा, जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ विभागीय व विधिक कार्रवाई की जाएगी। (जासं)

मुस्लिम देशों के साथ हेल्थ टूरिज्म पर उप्र सरकार का जोर

लखनऊ : मुस्लिम देशों के साथ मिलकर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने का उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है। इसके लिए बंगलुरू में आयोजित ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज में गुरुवार को राज्य सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने इस्लामिक देशों के हेल्थ टूरिज्म सेंटर के साथ सरकार ने समझौते किए। ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज में उप्र का प्रतिनिधित्व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया। (राब्यू)

महाराष्ट्र के आदर्श घोटाले में नई जांच नहीं : ईडी

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि महाराष्ट्र के आदर्श घोटाला मामले में उसने कोई नई जांच शुरू नहीं की है। जांच एजेंसी का यह बयान मीडिया में आई उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि ईडी के दस्ते ने पैमाइश और संबंधित काम के लिए आदर्श सोसायटी का दौरा किया है। ईडी ने कहा है, 'मीडिया में आई रिपोर्ट निराधार है। यह केवल अनुमान पर आधारित है। आदर्श घोटाले में कोई नहीं जांच शुरू नहीं की गई है।' यह घोटाला दक्षिणी मुंबई के कोलाबा इलाके में 1999 के कारगिल युद्ध के वीरों और सैनिकों की विधवाओं के लिए 31 मंजिले आदर्श अपार्टमेंट में फ्लैटों के आवंटन में अनियमितता से संबंधित है। (प्रेट्र)

उल्फा पर लगे प्रतिबंध को पांच वर्षों के लिए बढ़ाया

नई दिल्ली : केंद्र ने असम के उग्रवादी संगठन उल्फा पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के अनुसार प्रतिबंध के दौरान भी उल्फा हत्या, अपहरण और फिरौती मांगने जैसे अपराधों को अंजाम देता रहा है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि अवैध और हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए उल्फा ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उल्फा अलग असम के देशविरोधी उद्देश्य के तहत काम करता है। (प्रेट्र)

बंगाल में तृणमूल और उत्तराखंड में भाजपा की जीत

दोनों राज्यों में विधानसभा के उप चुनाव में सत्ताधारी दलों का ही रहा दबदबा

जागरण न्यूज नेटवर्क, कोलकाता

बंगाल और उत्तराखंड में हुए विधानसभा उप चुनाव में सत्ताधारी दलों का दबदबा रहा। बंगाल में जहां तृणमूल कांग्रेस ने तीनों सीटों पर विजय पाई, वहीं उत्तराखंड में भाजपा ने अपनी सीट पर कब्जा बरकरार रखा। तृणमूल जिन तीन सीटों पर विजयी रही है, उनमें से दो पर विपक्षी दलों का कब्जा था, जिनसे वह सीट छीनने में कामयाब रही। तीनों सीटों पर दूसरे नंबर पर भाजपा रही।

बंगाल के कलियागंज, खड़गपुर सदर और करीमपुर में तृणमूल के उम्मीदवारों को जीत मिली है। कालियागंज में तृणमूल के तपन देब सिंघा ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के कमलचंद्र सरकार को 2414 मतों से मात दी है, जबकि करीमपुर में बिमलेंद्र सिन्हा राय ने भाजपा के जयप्रकाश मजूमदार को 24073 और खड़गपुर सदर में प्रदीप सरकार ने भाजपा के ही प्रेमचंद्र झा को 20853 मतों के अंतर से हराया। गौरतलब है कि कलियागंज सीट पर कांग्रेस, खड़गपुर सदर सीट पर भाजपा और करीमपुर सीट पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा था। खड़गपुर सदर और करीमपुर के विधायक गत लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने से ये सीटें खाली हो गई थीं। कालियागंज के विधायक के निधन से यह सीट रिक्त पड़ी थी।

बंगाल में एनआरसी के खिलाफ जनादेश : ममता

जागरण संवाददाता, कोलकाता

ममता बनर्जी फाइल

विधानसभा उप चुनाव में जीत से गदगद तृणमूल प्रमुख व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे ऐतिहासिक जनादेश करार दिया है। साथ ही कहा है कि जनता ने भाजपा के अहंकार का जवाब दिया है। बनर्जी ने कहा कि 'धर्मनिरपेक्षता और एकता' के पक्ष में और 'एनआरसी' के खिलाफ जनादेश है, क्योंकि भाजपा ने अपने अहंकार से राज्य के लोगों को अपमानित करने का काम किया, जिसका वह परिणाम भुगत रही है।

ममता ने यह भी कहा कि वह 2021 (बंगाल विधानसभा) की बात कर रहे थे, जबकि 2019 में ही मामला समाप्त है, क्योंकि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा को नहीं सोचना चाहिए कि देश के लोग बहुमत (भाजपा के पास) नहीं होने के बावजूद राज्यों में सरकार गठन के उसके धौंस जमाने वाले तौर तरीकों को स्वीकार कर लेंगे।

कुल तीन सीटों पर हुए उपचुनाव में कालियागंज व खड़गपुर सदर सीट पर जीत तृणमूल के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अस्तित्व में आने के बाद से अब तक तृणमूल को यहां जीत नहीं मिली थी। यह जीत पार्टी को 21 साल बाद नसीब हुई है।

एक न्यूज चैनल से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मां, माटी, मानुष के प्रति आभारी हूं। कतार में खड़े होकर लोगों ने मतदान किया। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यह जाति, धर्म, संस्कृति के नाम पर लोगों को बांटने वालों को करारा जवाब है, जिसे वही महसूस कर सकता है, जिसने जनता के हित में कोई उपलब्धि हासिल की हो।

भाजपा की मदद कर रहे वाम मोर्चा-कांग्रेस : विपक्षी माकपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोग खुद को मजबूत करने के बजाय राज्य में भाजपा की मदद कर रहे हैं। सभी ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है, यह बड़ी बात है, भले ही यह उपचुनाव ही क्यों न रहे हों।

भाजपा ने भी माना-एनआरसी की वजह से हारे

बंगाल में एनआरसी लागू करने को लेकर ममता बनर्जी एवं केंद्र सरकार के बीच छिड़ी रार का नुकसान भाजपा को विधानसभा उप चुनाव में उठाना पड़ा। भाजपा नेताओं ने भी यह बात स्वीकार की है कि राज्य में एनआरसी को लेकर जनता में किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति है, जिसके कारण हार हुई। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जिस बंगाल की 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसी राज्य में पार्टी को उपचुनाव में एक भी सीट नहीं मिल सकी। इस परिणाम पर कलियागंज सीट से भाजपा उम्मीदवार कमल चंद्र सरकार ने एनआरसी को जिम्मेदार ठहराया।

भाजपा ने कब्जा रखा बरकरार : पथौरागढ़ : उत्तराखंड में पिथौरागढ़ सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रा पंत ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अंजू लुंठी को 3267 मतों से पराजित किया। चंद्रा पंत को 26086 और अंजू लुंठी को 22819 मत मिले। चंद्रा पंत के पति प्रदेश के वित्त मंत्री रहे प्रकाश पंत के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। जीत पर भाजपाइयों ने जश्न मनाया।

बंगाल में भाजपा जिलाध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा के घर पर हमला

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल में करीमपुर विधानसभा सीट पर उप चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर 24 परगना की भाजपा जिलाध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा के घर पर हमले की घटना प्रकाश में आई है। हमलावरों ने उनके घर के सामने खड़े वाहनों और अन्य सामान की तोड़फोड़ की। वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मारपीट की। फाल्गुनी ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भाजपा के बागियों को जिम्मेदार ठहराया है।

घटना के संदर्भ में फाल्गुनी की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। फाल्गुनी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उप चुनाव में मिली जीत से अति उत्साहित तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मेरे घर और वाहनों में तोड़फोड़ की। जब पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका तो हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा महिला नेता के लगाए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तृणमूल ने बेवजह झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान पर बखेड़ा, 14 विधायक निलंबित

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ में दो दिन बाद धान खरीद शुरू होनी है, लेकिन केंद्र से सेंट्रल पूल में धान खरीद का कोटा घटाए जाने का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है। इस बीच विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धान पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। गुरुवार को विपक्ष ने धान खरीद और धान का रकबा घटाने के सरकारी प्रयास पर जमकर बवाल किया। विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ने पर विपक्ष के 14 विधायक वेल में आ गए, जिन्हें निलंबित कर दिया गया।

प्रश्नकाल में भाजपा विधायक धान खरीद की दर को लेकर मंत्री से सवाल कर रहे थे। हर बार मंत्री अमरजीत भगत की ओर से यही जवाब आ रहा था कि केंद्र ने समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए हमें बाध्य किया है। हम 25 सौ रुपये प्रति क्विंटल किसानों को देना चाहते हैं। विपक्ष इस सवाल पर अड़ा रहा कि एक दिसंबर से किस दर पर खरीद होगी, यह बताया जाए। इसी बात को लेकर भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जकांछ) के 14 विधायक वेल में आ गए। नियमानुसार वेल में आने वाले विधायक स्वतः निलंबित हो जाते हैं। निलंबन के बाद विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि धान का रकबा कम करने के लिए मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को फरमान जारी किया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि रकबे में अनावश्यक कटौती करने का कोई निर्देश कलेक्टरों को नहीं दिया गया है।

रांची में विधि छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, 12 लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रांची

- पिस्टल दिखा कर अगवा कर सुनसान ईंट भट्टे में ले गए
- तीन घंटे तक छात्रा और उसके दोस्त को बनाए रखा बंधक

झारखंड में कांके स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से पिस्टल के बल पर 12 बदमाशों ने मंगलवार देर रात दुष्कर्म किया। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक पिस्टल और कट्टा बरामद हुआ है। छात्रा जमशेदपुर की रहने वाली है।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ऋषभ कुमार झा ने पत्रकारवार्ता कर मामले की जानकारी दी। पीड़ित छात्रा मंगलवार शाम अपने दोस्त के साथ बीआइटी मेसरा से संग्रामपुर के रास्ते लॉ यूनिवर्सिटी स्थित हॉस्टल लौट रही थी। संग्रामपुर बस स्टॉप के पास दोनों बातचीत कर रहे थे। तभी अलग-अलग बाइक से छह युवक पहुंचे। इन्होंने हथियार दिखा कर जबरन छात्रा को बाइक पर बैठाया और उसे सुनसान जगह पर ले जाने लगे। इस बीच उनकी बाइक खराब हो गई तो फोन कर बदमाशों ने कार मंगवाई। अन्य बदमाश सैंट्रो कार लेकर पहुंचे। इसके बाद कार में जबरन छात्रा को बैठा लिया। विरोध करने पर दोस्त की पिटाई की और उसे भी साथ ले गए। इस हाथापाई और मारपीट के दौरान एक बदमाश का मोबाइल छात्रा के दोस्त के पास रह गया था। जो आरोपितों की गिरफ्तारी में मददगार बना। बदमाशों ने दोनों को करीब तीन घंटे तक बंधक बनाकर रखा। संग्रामपुर गांव के ही एक ईंट भट्ठे में ले जाकर छात्रा से दुष्कर्म किया गया।

दूसरे दिन पीड़िता पहुंची पुलिस के पास

घटना के दूसरे दिन बुधवार को पीड़िता परिजन के साथ कांके थाना पहुंची। पुलिस के मुताबिक संग्रामपुर कांके निवासी सुनील मुंडा, कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, अमन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव और ऋषि उरांव को बुधवार रात ही गिरफ्तार कर लिया गया।

सेटेलाइट से जुटाए जा सकेंगे प्रदूषण के आंकड़े

जागरण संवाददाता, नैनीताल : आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज की ओर से वायु प्रदूषण पर आयोजित कार्यशाला में वर्तमान हालात पर चिंता जताई गई। गुरुवार को इस्टरलीन में आयोजित तीन दिनी कार्यशाला के पहले दिन सेटेलाइट से आंकड़े जुटाना और वायु प्रदूषण की जांच को लेकर ईजाद किए जा रहे अत्याधुनिक उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में 15 देशों के वैज्ञानिक और शोधार्थी भाग ले रहे हैं। जापान से आए वैज्ञानिक डॉ. हिरोशी तनिमोटो ने कहा कि पर्यावरण को बचाना है तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए वैज्ञानिक उपायों के साथ ही लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। सिंगापुर से आए डॉ. डेविड कोह ने कहा कि अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके स्थिति पर नजर रखकर जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। एरीज के वैज्ञानिक डॉ. मनीष नाजा ने कहा कि विकासशील देशों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के अत्याधुनिक तकनीक ईजाद करने की जरूरत है। विकसित देशों की तर्ज पर हमें भी इस दिशा में कार्य करने होंगे। इस मौके पर वायु प्रदूषण को लेकर दुनिया में ईजाद अत्याधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण दिया गया।

निर्देशक मृणाल सेन का आशियाना बेचा जाएगा

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- सेन के बिस्तर को ले गए वाममोर्चा अध्यक्ष विमान बोस
- बेटे ने पिता की कृतियों को किया लंदन समेत अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों के सुपुर्द

मृणाल सेन भारत के उन चुनिंदा निर्देशकों में शामिल रहे, जो देशी सिनेमा को सरहद पार लेकर गए। उनकी फिल्मों ने देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में नाम कमाया। ढेर सारे अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। मृणाल ने नील अक्षर नीचे, भुवन शोम, इंटरव्यू, कोलकाता 71, मृगया और एक दिन अचानक जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। लेकिन, कोलकाता के पद्मोपुकुर स्थित जिस फ्लैट में बैठकर उन्होंने इन फिल्मों की पटकथा लिखी आज वहीं फ्लैट बिक्री के कगार पर है।

फ्लैट की बिक्रे के पीछे वजह बताई जा रही है कि इसका सुनियोजित रखरखाव करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में इसे बेचना ही एकमात्र विकल्प है। साथ ही उनकी फिल्मों की पांडुलिपि व अन्य रचनाओं को लंदन सहित विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए उनके सुपुर्द कर दिया गया, ताकि विश्व उनकी कृति से लाभान्वित हो सके। उनके पुत्र कुणाल सेन ने बताया कि समयाभाव व उचित रखरखाव न हो पाने के कारण उन्होंने दक्षिण कोलकाता के 38, पद्मोपुकुर स्थित फ्लैट को बेचने का फैसला किया है। जिस बिस्तर पर मृणाल सेन ने अंतिम सांस ली थी, उसे पिछले सप्ताह पीपुल्स रिलीफ कमेटी के अध्यक्ष व वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बोस लेकर चले गए। गौरतलब है कि उनके पुत्र कुणाल विदेश में रहते हैं और उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वे फ्लैट व अन्य चीजों की देखभाल कर सकें। यही कारण है कि आखिरकार उन्होंने इस फ्लैट को बेचने का फैसला किया है।

सफाईकर्मी के 549 पदों पर 7,000 इंजीनियरों व स्नातकों का आवेदन

कोयंबटूर, प्रेट्र : तमिलनाडु के कोयंबटूर नगर निगम में सफाईकर्मी पद के लिए सात हजार इंजीनियरों, स्नातकों और डिप्लोमाधारियों ने आवेदन किया है। नगर निगम ने 549 पदों पर भर्ती निकाली है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, 'ग्रेड-1 सफाईकर्मियों की भर्ती के लिए साक्षात्कार, सर्टिफिकेट की जांच आदि की तीन दिवसीय प्रक्रिया में सात हजार आवेदक शामिल हुए। प्रक्रिया बुधवार को शुरू हुई। 70 फीसद आवेदक एसएसएलसी की न्यूनतम अर्हता ही पूरी कर पाए हैं। इनमें ज्यादातर इंजीनियर, स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमाधारक हैं।' कुछ मामलों में पाया गया कि आवेदक पहले से ही निजी कंपनियों में काम कर रहे थे। लेकिन, सरकारी नौकरी और 15,700 रुपये की शुरुआती वेतन ने उन्हें आकर्षित किया। कुछ तो 10 साल से अनुबंध के आधार पर सफाईकर्मी की नौकरी कर रहे थे। उन्होंने स्थायी नौकरी के लिए आवेदन किया है। योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिलने के कारण स्नातक आवेदक शहर में छह से सात हजार रुपये मासिक की नौकरी करते हैं और 12 घंटे ड्यूटी देते हैं। दूसरी तरफ, सुबह और शाम तीन-तीन घंटे सफाईकर्मी के काम में 20 हजार रुपये मिल जा रहे हैं।

पत्नी घर से चली गई तो पंचायत ने पति, बेटा-बेटी को समाज से किया बेदखल

नईदुनिया, गुना : मध्य प्रदेश में गुना जिले के ग्राम मोहरी में एक महिला के घर से चले जाने पर बंजारा समाज की पंचायत ने उसके पति, बेटे और बेटी को समाज से बेदखल कर दिया। उन पर कुएं से पानी भरने पर भी रोक लगा दी है।

मोहरी निवासी प्रहलाद पुत्र रामा बंजारा (43) के मुताबिक, चार नवंबर की रात उसकी पत्नी समरीबाई मधुसूदनगढ़ जाने का कहकर गई थी। तबसे घर नहीं लौटी। इस पर बंजारा समाज की पंचायत ने हमें समाज से बेदखल कर हुक्का पानी बंद कर दिया। समाज के किसी भी कार्यक्रम में आने-जाने पर रोक लगा दी। गांव के कुएं से हमें पानी लेने पर रोक लगा दी। मजबूरी में हमें नदी से पानी भरकर लाना पड़ता है। पंचायत ने फरमान सुनाया है कि अगर पत्नी घर लौटी तो हर्जाने के रूप में 60 हजार रुपये देने होंगे। तब फिर से समाज में शामिल किया जाएगा। बंजारा समाज के नायक भंवरलाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पंचायत ने इन्हें समाज से बाहर कर दिया है। समाज में इनके आने-जाने पर रोक लगाई है।

शिकायत नहीं मिली : थाने में इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। महिला अगर लापता है तो उसको ढूंढने के लिए प्राथमिकता से प्रयास किए जाएंगे।

अपराध की रोकथाम पुलिस का पहला और घटना का राजफाश दूसरा कदम : बेदी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

'पुलिस तकनीक के सहारे कितने ही कदम आगे बढ़ा ले, लेकिन बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए बीट पुलिसिंग का कोई विकल्प नहीं है। बीट प्रणाली ही पुलिस की रीढ़ है। देश भर में इसकी सख्त जरूरत है। अधिकारियों को बीट पुलिसिंग में सीधी भागीदारी करनी चाहिए। बीट के सिपाही को अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी होती है। वीआइपी मूवमेंट व कानून-व्यवस्था के चलते भी बीट पुलिसिंग को नहीं छेड़ना चाहिए। अपराध की रोकथाम पुलिस का पहला कदम है। किसी घटना का राजफाश दूसरा कदम है।' पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट जनरल डॉ.किरण बेदी ने गुरुवार को इस गुरुमंत्र के साथ पुलिस बल के उस अस्सी फीसद हिस्से की क्षमता पर विश्वास जताया, जो सिपाही व हेडकांस्टेबल के रूप में लोगों के बीच होते हैं और पुलिस का मान बढ़ाते हैं।

47वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस-2019 का शुभारंभ करने के बाद देश भर से आए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से रूबरू देश की पहली महिला आइपीएस अधिकारी डॉ.बेदी ने बात अपने अनुभव से शुरू की। पुलिस मुख्यालय के अवनि सभागार में आयोजित समारोह में डॉ.बेदी ने बताया कि बतौर डीसीपी जिले में अपनी पहली तैनाती के दौरान 1980 में तत्कालीन एसीपी केके छाबड़ा से उन्होंने बीट पुलिसिंग का गुर सीखा था और फिर हमेशा सिपाही व हेडकांस्टेबल को केंद्र में रखकर कानून-व्यवस्था की बागडोर संभाली। डॉ.बेदी ने कहा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शाम की फुट पेट्रोलिंग पर जोर देते हैं, जो बेहद जरूरी है।

लखनऊ में गुरुवार को गोमती नगर विस्तार में स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस को संबोधित करतीं पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी। जागरण

उप्र पुलिस की प्रशंसा

डॉ.बेदी ने अयोध्या प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश में शांति-व्यवस्था बनाओ रखने व कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए पुलिस की प्रशंसा की। उन्होंने 29 शोधपत्रों की पुस्तिका का विमोचन भी किया। उद्घाटन सत्र में प्रमुख रूप से अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, डीजीपी ओपी सिंह, डीजी वीएस कौमुदी मौजूद रहे। आयोजन सचिव एडीजी रेणुका मिश्रा ने सभी आभार जताया।

ईडी ने मांगी सना की हिरासत, कहा-पूछताछ के लिए जरूरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मीट कारोबारी मोईन कुरैशी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले को रद करने की मांग को लेकर दायर व्यवसायी सतीश बाबू सना की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि सना ने गोलमोल तरीके से बयान दिया है। लिहाजा उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है।

स्टैंडिंग काउंसल अमित महाजन के माध्यम से हाई कोर्ट में दायर जवाब में ईडी ने कहा कि मनी लांड्रिंग मामले में जांच अभी चल रही है और यह सीबीआइ जांच से अलग है। सना से पता लगाना है कि 1.5 करोड़ के भुगतान का स्रोत कौन है? सतीश सना ने याचिका दायर कर खुद और मोईन कुरैशी के खिलाफ दायर मनी लांड्रिंग मामला रद करने की मांग की है। हैदराबाद स्थित व्यवसायी सना को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और बाद में 50 लाख रुपये के शेयरों की कथित खरीद से संबंधित मामले में निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।

सतीश सना ने ईडी द्वारा 18 और 25 जुलाई को मनी लांड्रिंग की धारा-50 के तहत जारी किए गए समन को भी रद करने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ के कॉलेज में पबजी प्रतियोगिता को लेकर बखेड़ा

नईदुनिया, रायपुर

रायपुर की समता कॉलोनी में संचालित महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज (मैक) में पबजी (प्लेयर्स अननोंस बैटल ग्राउंड्स) गेम को लेकर प्रस्तावित प्रतियोगिता पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। बताया जाता है कि स्कूली बच्चों को प्रतिस्पर्धा में शामिल कराने की तैयारी थी। मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को मिलने के बाद उन्होंने इस पर आपत्ति की। लिहाजा प्रतियोगिता को निरस्त कर दिया गया है। हालांकि अब कॉलेज प्रबंधन इस तरह के किसी भी गेम को आयोजित करने की तैयारी से ही इन्कार कर रहा है।

सूत्रों की मानें तो गुपचुप तरीके से यहां पबजी गेम को लेकर प्रतियोगिता कराने की तैयारी थी। जिसके लिए छात्रों का पंजीयन भी चल रहा था। वह भी तब जबकि गृह मंत्रालय ने पबजी गेम से खतरे को लेकर आगाह कर रखा है। बता दें कि ऑनलाइन मोबाइल फोन से खेला जाने वाला पबजी गेम एक बीमारी की तरह है। जो भी इसे खेलता है, इसी में डूबा रहता है। इससे गेमिंग डिसार्डर जैसी गंभीर बीमारी होने की संभावना होती है।

> कोई भी गेम यदि स्कूली बच्चों के साथ कराया जा रहा है तो इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को देनी चाहिए। गेम का क्या स्वरूप होगा, यह जानकारी भी देनी चाहिए। यदि बिना जानकारी के कोई भी स्कूल बच्चों को ऐसे गेम में शामिल करता है तो शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
> **-जीआर चंद्राकर, डीईओ, रायपुर**

प्रबंधक ने कहा- पबजी गेम का स्वरूप अलग था : महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज (मैक) रायपुर के प्राचार्य डॉ. ज्योति जनस्वामी ने कहा कि पबजी गेम की कोई प्रतियोगिता नहीं होनी थी बल्कि पबजी बल्कि बच्चों को मार्केट का फंडा बताने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी। मार्केट का फंडा एक थीम थी, जिसमें एक टॉपिक था। उसमें बताना था कि किस तरह पबजी ने अपना मार्केट फैलाया, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पहलू हैं। हालांकि कमेटी ने इस कार्यक्रम को निरस्त किया है।

रखी बात

50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (इफ्फी) के समापन पर गोवा के राज्यपाल ने किया आह्वान

समाज की विसंगतियों को उजागर करें फिल्मकार : सत्यपाल मलिक

स्मिता श्रीवास्तव, पणजी

फिल्मों से सीखने को मिलता है। मैं फिल्मों से जुड़ी कई चीजें नहीं भूला हूं। मैं दिलीप कुमार की गंगा-जमुना और वहीदा रहमान की तीसरी कसम नहीं भूला हूं। जितना असर फिल्मों का होता है, उतना न किताब का होता है न किसी और चीज का। मेरा फिल्मकारों से आग्रह है कि आप समाज की विसंगति को उजागर कीजिए। ये बातें गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (इफ्फी) के समापन कार्यक्रम में गुरुवार को कहीं।

उन्होंने कहा, 'देश में पहली फिल्म वर्ष 1913 में बनी थी। 1936 में बनी संत तुकाराम को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली। अब तक फिल्म उद्योग लंबा सफर तय कर चुका है। हिंदुस्तान में अब भी गुरबत है, बेरोजगारी है। शहरों में पीठ पर बैग लादे हजारों लड़के रोजी-रोटी की तलाश में पैदल घूमते रहते हैं। यही हाल किसानों का है। जवानों का हाल मैं देख कर आया हूं।'

राज्यपाल ने कहा, 'देश में ऐसे लोग हैं, जिनके पास 14 मंजिले मकान हैं। एक मंजिल पर कुत्ता रहता तो दूसरे पर ड्राइवर, लेकिन एक पैसा हिंदुस्तान की फौज, शिक्षा या युवाओं के लिए दान नहीं देते। जबकि, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक समेत कई नामी हस्तियां अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा दान करती हैं। मैं अपने यहां के उन अमीरों को सड़े आलू की बोरी मानता हूं, जिनकी जेब से एक पैसा नहीं निकलता। मैं फिल्मकारों का आह्वान करता हूं कि इस वर्ग पर हमला करें। शायद उनसे कुछ निकले। नौजवानों, किसानों की मदद कीजिए। उसका समाज पर असर होगा।' इस दौरान राज्यपाल अभिनेता प्रेम चोपड़ा को प्राण चोपड़ा कह गए।

जम्मू-कश्मीर पुलिस पर फख्र है : मलिक ने कहा कि अभी मुझे कश्मीर से गोवा आए तीन सप्ताह हुए हैं। लिहाजा वहां की बातों को जरूर साझा करूंगा। हर रात जब मैं सोने जाता था तो मीना कुमारी अभिनीत फिल्म पाकिजा का गाना 'आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे' की आखिरी लाइन 'आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे' जरूर याद आती थी। उन्होंने कहा, 'अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद फौज को एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी। मैं अस्पताल, बाजार सब जगह गया। एक लड़के ने यहां तक कहा कि चलिए आपको लाल चौक पर चाय पिलवाता हूं। लोगों के मिजाज में फर्क आ गया है। चेतावनी दी गई थी कि जब अनुच्छेद 370 हटेगा तो पुलिस भी विद्रोह कर देगी। मुझे जम्मू-कश्मीर की पुलिस पर फख्र है कि ईद के मौके पर एक भी सिपाही ने छुट्टी नहीं मांगी।' मलिक ने कहा, 'मैंने हथियार उठाए नौजवानों से सार्वजनिक तौर पर कहा कि आप मेरे घर आइए। खाना खाइए और समझाइए कि कैसे आप 250 लोग सुपरपावर इंडिया को हरा देंगे। वह कहते थे कि न उन्हें हिंदुस्तान से मुहब्बत है, न पाकिस्तान से, न हुर्रियत से। न दोनों पार्टियों से। हमारी बर्बादी का कारण यही हैं। अब हमें मौलवी सिखाते हैं कि मरोगे तो जन्नत मिलेगी। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको दो जन्नत दे सकता हूं। एक वह जहां जहांगीर ने घोड़े से उतर कर कहा था कि दुनिया में कहीं जन्नत है तो यहीं हैं।

पणजी में गुरुवार को 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (इफ्फी) के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और मशहूर निर्देशक रमेश सिप्पी ने मलयालम फिल्म 'जल्लीकट्टू' के लिए लिजो जोस पेल्लिसरी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया। प्रेट्र

76 देशों की 190 फिल्मों का प्रदर्शन, 'पार्टिकल्स' सर्वश्रेष्ठ फिल्म

20 नवंबर को शुरू हुए इफ्फी में 76 देशों की 190 फिल्में प्रदर्शित हुईं। 90 भारतीय फिल्मों का भी प्रीमियर हुआ। अंत में मार्गी एंड हर मदर फिल्म दिखाई गई। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फिल्म 'पार्टिकल्स' को दिया गया। पुरस्कार के तहत निर्देशक और निर्माता को गोल्डन पीकॉक अवार्ड और 40 लाख रुपये नकद प्रदान किए गए। समापन समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सांसद बाबुल सुप्रियो व रूपा गांगुली, संगीतकार इलैयाराजा, निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी व रमेश सिप्पी, प्रेम चोपड़ा, दक्षिण के अभिनेता विजय देवरा कोंडा, रकुल प्रीत आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कुणाल कपूर और सोनाली कुलकर्णी ने किया।

सत्यजीत रे पर केंद्रित होगा अगले साल का फेस्टिवल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने कहा कि अगला साल सत्यजीत रे का जन्मशताब्दी वर्ष होगा। अगला फेस्टिवल उन्हीं पर केंद्रित होगा।

सर्वश्रेष्ठ फिल्म	पार्टिकल्स
बेस्ट डेब्यू फिल्म	मांस्टर
इफ्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड	जू जॉर्ज (मैरीगेला)
इफ्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड	उषा जाधव (माई घाट, क्राइम नंबर 103/2005)
इफ्फी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार	लीजो जोस पेलीसेरी (जलीकट्टू)
स्पेशल ज्यूरी अवार्ड	बैलून
स्पेशल मेंशन अवार्ड	हीलारो
आइसीएफटी यूनेस्को स्पेशल मेंशन	बहत्तर हूरें
आइसीएफटी गांधी मेडल	रवांडा

50 बख्तरबंद वाहन जीपीएस व अत्याधुनिक उपकरणों से लैस शामिल किए जाएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के बेड़े में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक हजार करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 29 नवंबर 2019

सेटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी

सरहद पार बैठे आकाओं से चार सेटेलाइट फोन और रेडियो सेट से कर रहे संपर्क

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- पुलिस, सीआरपीएफ और सेना संभावित इलाकों में ले रही तलाशी
- इस समय कश्मीर में चार इसी तरह के सेटेलाइट फोन सक्रिय हैं

कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर रोक से हताश आतंकी अब सरहद पार बैठे आकाओं से संपर्क बनाने के लिए फिर सेटेलाइट फोन और उच्च क्षमता वाले रेडियो सेट इस्तेमाल करने लगे हैं। इस समय कश्मीर में चार सेटेलाइट फोन हैं। इनमें श्रीनगर के आंचर सौरा इलाके में एक, दो अन्य दक्षिण कश्मीर में और एक उत्तरी कश्मीर में है। हालांकि, राज्य पुलिस ने सीआरपीएफ और सेना के साथ संभावित इलाकों में घर घर तलाशी भी ली है, लेकिन सफलता नहीं मिली है।

दो फोन हो चुके हैं बरामद : इस साल कश्मीर में सुरक्षाबल दो सेटलाइट फोन बरामद कर चुके हैं। पहला सेटलाइट फोन 13 जनवरी को बांडीपोर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सरफराज से पकड़ा गया था। दूसरा करीब एक पखवाड़े पहले सोपोर में मारे गए आतंकियों के पास से मिला था। दोनों सेटलाइट फोन थुरैया कंपनी के हैं। सरफराज से मिला सेटलाइट फोन इसी माह बरामद हुए फोन से अत्याधुनिक था। वह स्मार्ट फोन जैसी सुविधाओं से लैस था।

प्रतीकात्मक

आंचर सौरा में हुई थी सबसे अधिक हिंसा : श्रीनगर के उत्तरी जोन के एसपी सज्जाद शाह ने कहा कि आंचर सौरा इलाके में कुछ दिनों के दौरान एक-दो बार सेटेलाइट फोन होने का पता चला, लेकिन उसकी सही लोकेशन का पता नहीं चला। हमने एक इलाके को चिह्नित करते हुए घेराबंदी कर घर-घर तलाशी भी ली, कुछ नहीं मिला। एक संदिग्ध युवक को जरूर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।

यह वही इलाका है जहां अगस्त में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के बाद सबसे ज्यादा हिंसक और राष्ट्रविरोधी प्रदर्शन हुए थे।

1998 से शुरू हुआ था इस्तेमाल

कश्मीर में आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड नेटवर्क द्वारा सेटलाइट फोन का इस्तेमाल कोई नया नहीं है। एसएसपी सिक्योरिटी इम्तियाज हुसैन मीर ने बताया कि कश्मीर में आतंकियों ने सेटलाइट फोन का इस्तेमाल 1998 में शुरू किया था। वर्ष 2003 तक खूब इस्तेमाल होता था। मोबाइल फोन सेवा के शुरू होने के बाद आतंकियों की इस पर निर्भरता कम हो गई।

किसी की पकड़ में नहीं आते

इंटरनेट यह एक सस्ता और सुरक्षित विकल्प है। इंटरनेट पर वॉयस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआइपी) पर बातचीत कर वह किसी की पकड़ में नहीं आते और न उनकी बातचीत को आसानी से सुना जा सकता है। कश्मीर में पांच अगस्त से इंटरनेट और प्रीपेड मोबाइल फोन बंद हैं। ऐसे में सेटलाइट फोन और रेडियो सेट ही उनके लिए आपस में संपर्क बनाए रखने का जरिया है। वह इस समय ह्यूमन इंटेलीजेंस नेटवर्क भी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं।

सरकारी कर्मियों को परिवहन व बच्चों के लिए मिलेगा शिक्षा भत्ता

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- जम्मू-कश्मीर में वेतनमान के अनुरूप 900 से 7200 रुपये प्रति माह परिवहन भत्ता मिलेगा, दो बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रति बच्चा 2250 के हिसाब से अलाउंस

राज्य सरकार के अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों और कर्मियों के लिए खुशखबरी है। राज्य प्रशासन ने परिवहन भत्ते के साथ दो बच्चों की 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी को मंजूरी देने की घोषणा की है।

परिवहन भत्ता : राज्य सरकार के अधीनस्थ प्रत्येक कर्मी को उसके वेतनमान के अनुरूप 900 से 7200 रुपये प्रति माह परिवहन भत्ता मिलेगा, बशर्ते संबंधित सेवा नियमों और शर्तों को पूरा करता हो। पहले से सरकारी परिवहन सेवा का लाभ लेने वाले अधिकारी परिवहन भत्ते से वंचित रहेंगे।

उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के निर्देशानुसार वित्त विभाग के वित्तायुक्त अरुण कुमार मेहता ने 31 अक्टूबर से प्रभावी परिवहन व महंगाई भत्ते के संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें राज्य से बाहर भी भत्ता देय होगा। दिव्यांग कर्मियों को सामन्य दरों से दोगुने दर पर परिवहन भत्ता देय होगा जो किसी सूरत में 22501 रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होगा।

शिक्षा भत्ता व छात्रावास सब्सिडी

केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को 12वीं कक्षा तक के स्कूलों में दो बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रति बच्चा 2250 रुपये के हिसाब से हर माह 4500 रुपये का अलाउंस मिलेगा। इसके साथ हॉस्टल में पढ़ाने के लिए 6750 रुपये की हॉस्टल सब्सिडी भी मिलेगी। दिव्यांग बच्चे के लिए सरकारी कर्मचारी को सामान्य से दोगुना 4500 रुपये का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। सामान्य बच्चों के लिए 12वीं तक अलाउंस देने की अधिकतम आयु सीमा 20 तो दिव्यांग बच्चों के लिए यह 22 वर्ष है। साल में एक बार संबंधित शिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र लेना होगा।

हिजबुल के हैं अनंतनाग में हमला करने वाले दोनों आतंकी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : अनंतनाग में गांव की ओर कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को हुए आतंकी हमले में शामिल हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकियों की पहचान हो गई है। यह जानकारी केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर राज्य पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने गुरुवार को दी। उन्होंने कहा कि ये आतंकी जल्द ही कानून के शिकंजे में होंगे। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में हुई उच्चस्तरीय बैठक में घाटी में मौजूदा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य की जानकारी ली। बैठक में आइजीपी आर्म्ड विजय कुमार, आइजीपी कश्मीर जोन एसपी पाणि, डीआइजी सेंट्रल कश्मीर रेंज, एसएसपी श्रीनगर, एसएसपी सिक्योरिटी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। दिलबाग सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए हाल की आतंकी घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आतंकी इस समय सरहद पार बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए जम्मू-कश्मीर में हालात बिगाड़ने की हर संभव साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार को अनंतनाग के हाकूरा में भी इसी साजिश के तहत आतंकियों ने हमला किया था।

भारत एक दिन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनेगा : जयशंकर

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने विश्वास जताया कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का एक दिन स्थायी सदस्य बन जाएगा। इस दिशा में देश कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्थाई सदस्यता के लिए लंबी अवधि और धीरज भरे प्रयास की आवश्यकता होती है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को उच्च सदन को बताया कि मुझे जल्द ऐसा होने की उम्मीद है। हम इसके लिए अपने प्रयास, धैर्य और प्रेरणा में कहीं भी कम नहीं हैं। यह हमें एक दिन मिलना ही है। मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने यह जवाब अन्नाद्रमुक की विजिला सत्यानंत के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

उन्होंने राज्यसभा को यह भी बताया कि रीजनल काम्प्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) समझौते से उसके मौजूदा स्वरूप के चलते संबद्ध नहीं हो सका। चूंकि इसमें देश के लिए अहम मुद्दों और चिंताओं पर गौर नहीं किया गया था। इसके बावजूद सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के छह महीनों में पड़ोसी देशों के साथ ही खाड़ी, दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीकी देशों से संबंध प्रगाढ़ कर लिए हैं। जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता चुके हैं कि आर्थिक साझेदारी के समझौते में भारत ने बहुत गंभीरता से शिरकत की। लेकिन खुद को इससे जोड़ नहीं सके। सरकार ऐसे सभी समझौतों में अपने हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसलिए भारत ने आर्थिक साझेदारी के इस समझौते से किनारा कर लिया।

अब कश्मीरी नेताओं को विदेश जाने की अनुमति

मिली छूट ▶ राजनीतिक निष्क्रियता खत्म करने के लिए केंद्र के प्रयास

नजरबंद नेताओं को जम्मू और दिल्ली जाने की भी मिली इजाजत

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर में बने राजनीतिक शून्य को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न स्तरों पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। पांच अगस्त को एहतियातन हिरासत में लिए गए कई नेताओं को जहां क्रमानुसार रिहा किया जा रहा है। वहीं, कई नेताओं को विदेश जाने की अनुमति दी है ताकि वह संबंधित पक्षों से जुड़े लोगों से संपर्क कर राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली का रास्ता खोल सकें। घरों में नजरबंद किए गए नेताओं को आपात परिस्थितियों में जम्मू या दिल्ली जाने की छूट भी दी गई है। हालांकि वादी में उन्हें नजरबंद रखा जाएगा।

रिहाई का क्रम शुरू : प्रशासन ने प्रशासनिक पाबंदियों में राहत के साथ ही राजनीतिक लोगों की रिहाई का क्रम शुरू किया ताकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की बहाली के लिए राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो। गैर भाजपा दलों द्वारा मौजूदा हालात में किसी तरह से राजनीतिक गतिविधियों में रुचि नहीं दिखाई जा रही है। सभी चाहते हैं कि उनके प्रमुख नेताओं पर लगी सभी पाबंदियां हटाने के साथ राज्य के दर्जे की बहाली की दिशा में ठोस पहलकदमी हो। ब्लॉक विकास परिषदों के गठन की प्रक्रिया से नेकां, पीडीपी, कांग्रेस समेत गैर-भाजपा दल पूरी तरह दूर रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि इस समय कांग्रेस, नेकां और पीडीपी के अलावा पीपुल्स कांफ्रेंस के 35 बड़े नेता एहतियातन हिरासत में हैं। इन दलों के तीन दर्जन अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं को उनके घरों में नजरबंद रखा है। केंद्र विभिन्न स्तरों पर इन दलों के नेताओं के साथ लगातार संवाद-सपंर्क की प्रक्रिया में है। इसलिए इनके कई प्रमुख नेताओं को गत दिनों रिहा किया है।

दुबई में हैं पीडीपी के पूर्व मंत्री

पीडीपी से निष्कासित पूर्व शिक्षामंत्री अल्ताफ बुखारी जिनका नाम कई बार कथित तौर पर हवाला लेन-देन में आ चुका है, को केंद्र ने दुबई जाने की अनुमति दे दी है। बुखारी नेकां, पीडीपी, कांग्रेस और भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों में अच्छे संबंध रखते हैं। वह एक सप्ताह से दुबई में हैं। कुछ दिनों में शारजाह जाने वाले हैं। कहा जाता है कि केंद्र ने उन्हें कश्मीर में अमन बहाली और राजनीतिक प्रक्रिया बहाली के लिए दुबई स्थित कुछ खास लोगों से जो अब्दुल्ला, मुफ्ती और लोन परिवार के करीबी हैं से संपर्क के लिए भेजा है।

राजनीतिक गतिविधियों की खुली छूट

उन्होंने बताया कि राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली के लिए केंद्र ने कांग्रेस, नेकां, पीडीपी समेत अन्य राजनीतिक दलों को जम्मू प्रांत में अनुच्छेद 370 पर किसी तरह की बयानबाजी न करने की हिदायत के साथ अन्य मुद्दों पर राजनीतिक गतिविधियां करने की छूट दे रखी है। एक माह के दौरान जम्मू में इन दलों की बैठकें और रैलियां हो रही हैं।

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अशांति फैलाना चाहते थे आतंकी

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम में सोमवार को गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकी अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में अशांति फैलाना चाहते थे। सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिये इन लोगों ने बम बनाना सीखा और असम तथा दिल्ली में धमाके की साजिश रच रहे थे।

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने गुरुवार को विधानसभा में शून्य काल के दौरान बताया, '25 नवंबर को गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपित आतंकी संगठन आइएस से प्रेरित थे। वे असम के ग्वालपाड़ा जिले में चल रहे स्थानीय उत्सव में विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे। सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों की निगरानी के बाद सुरक्षा एजेंसी ने पुष्ट की कि तीनों आइएस के प्रति निष्ठा रखते हैं।'

अगप विधायक प्रबींद्र डेका व प्रदीप हजारिका के नोटिस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'ये लोग अयोध्या फैसले के बाद अशांति फैलाने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने एक आइईडी बनाई थी और असम के दूधनोई रास उत्सव में विस्फोट कराना चाहते थे।' पटवारी ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की ओर से कहा, इन लोगों ने दिल्ली में भी इसी तरह के धमाकों की साजिश रची थी। सोनोवाल के पास गृह विभाग का भी प्रभार है। मंत्री ने बताया कि दो आरोपितों के घरों से आइईडी बनाने की चीजें भी जब्त की गई हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली और असम पुलिस के एक संयुक्त अभियान में रंजीत अली, मुकद्दीर इस्लाम और लुइत जमील जमान को गिरफ्तार किया गया था।

जमीन पर प्रभुराम चिकित्सालय बनवाएगा शिया वक्फ बोर्ड

जागरण संवाददाता, अयोध्या

- जमीन मिली तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा भी बनेगा
- इस संबंध में बोर्ड की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा

शिया वक्फ बोर्ड पांच एकड़ जमीन पर प्रभु राम चिकित्सालय बनवाएगा। इस चिकित्सालय में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा भी बनाया जाएगा। इस संबंध में बोर्ड की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बोर्ड के सदस्य अशफाक जिया ने गुरुवार को अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय व गोसाईंगंज के विधायक इंद्रप्रताप तिवारी उर्फ खब्बू से भेंट कर प्रस्ताव के बारे में चर्चा की। इस दौरान अशफाक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लखनऊ में बुधवार को हुई शिया वक्फ बोर्ड की बैठक के बारे में भी महापौर व विधायक को जानकारी दी। मंदिर बनाने के फैसले का स्वागत किया। बोले, वक्फ बोर्ड इस आदेश के विरुद्ध रिव्यू नहीं दायर करने का निर्णय ले चुका है। यह भी तय किया गया कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड पांच एकड़ जमीन नहीं लेता है तो शिया वक्फ बोर्ड सरकार से इस जमीन की मांग करेगा, जिसमें प्रभुराम चिकित्सालय व सर्वधर्मस्थान बनाया जाएगा।

अयोध्या में पांच नहीं, दस एकड़ जमीन मिले: खान: मुस्लिम कारसेवक मंच: मुस्लिम कारसेवक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर मुहम्मद आजम खान गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एवं मणिरामदासजी की छावनी के महंत नृत्यगोपाल दास को पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। महंत नृत्यगोपालदास ने मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने मांग की है कि अयोध्या में मुस्लिम समाज को पांच एकड़ जमीन की जगह 10 एकड़ जमीन दी जाए, जिसमें एक भव्य शिक्षा के मंदिर का निर्माण हो सके और उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय। आजम ने कहा, मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की पुनर्विचार याचिका राजनीति के सिवा और कुछ नहीं है, ओवैसी जैसे लोगों की राजनीति सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त हो गई है। यह भी कहा कि 1992 में विस्थापित मुस्लिम परिवारों को पुनः स्थापित किया जाए। मस्जिद निर्माण में साधु-संतों का योगदान हो और मंदिर निर्माण के बाद मंदिर आंदोलन से जुड़े मुस्लिम भाइयों के नाम का शिलापट लगवाया जाए। मस्जिद निर्माण के बाद निर्माण में सहयोगी साधु-संतों के नाम का शिलापट वहां लगवाया जाए।

पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सीबीआइ ने सेंगर को बताया हत्यारोपित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उन्नाव कांड

- कोर्ट ने लगाई फटकार, पूछा अब इसकी क्या जरूरत
- अदालत विधायक पर पहले ही तय कर चुकी है हत्या का आरोप

उन्नाव कांड की जांच कर रही सीबीआइ ने पीड़िता के पिता की मौत के मामले में विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ अब हत्या का आरोप-पत्र दायर किया है, जबकि तीस हजारी अदालत पहले ही सेंगर के खिलाफ हत्या का आरोप तय कर चुकी है। सीबीआइ ने पूर्व में दायर आरोप-पत्र में सेंगर को हत्या का आरोपित नहीं माना था।

पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत और उन पर झूठा केस दर्ज करने के मामले में सीबीआइ ने पहले दायर आरोप-पत्र में सेंगर को आरोपित नहीं बनाया था। जब तीस हजारी अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो पीड़ित पक्ष के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने दलील दी थी कि पीड़िता के पिता पर झूठा केस सेंगर के कहने पर दर्ज हुआ। पिता को हिरासत में पीटा गया, जिससे उनकी मौत हो गई।

यह पूरा प्रकरण सेंगर के कहने पर हुआ तो वह आरोपित कैसे नहीं है? इस पर अदालत ने दोनों मामलों को जोड़कर एक कर दिया और कुलदीप सेंगर सहित 10 आरोपितों के खिलाफ हत्या के आरोप तय कर दिए थे।

कुलदीप सेंगर। फाइल

सूत्रों के मुताबिक सीबीआइ को जब यह आभास हुआ कि जब कुलदीप सेंगर के खिलाफ अदालत ने खुद ही हत्या के आरोप तय कर दिए हैं तो जांच एजेंसी को लगा कि आरोपपत्र दायर करना बेहतर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्नाव कांड से जुड़े दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या सहित सभी मामलों की सुनवाई तीस हजारी कोर्ट में सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत में चल रही है।

सीबीआइ को लगाई फटकार

आरोप-पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सीबीआइ को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ पहले किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। जब अदालत ने दोनों मामलों को जोड़कर हत्या के आरोप तय कर दिए तो उसने भरपाई के लिए अतिरिक्त आरोप-पत्र दायर कर दिया। अब सीबीआइ मांग कर रही है कि आरोपित विधायक को समन जारी कर ट्रायल किया जाए। जब अदालत 13 अगस्त को ही सेंगर सहित अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप तय कर चुकी है तो अब आरोपित को फिर समन करने की क्या जरूरत रह जाती है? इस अतिरिक्त आरोप-पत्र पर कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं रह जाती है।

पीएम की शैक्षणिक डिग्री के मामले में सुनवाई स्थगित

जासं, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री की जानकारी की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई 28 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या मामला है। मेहता ने बताया कि पूरा मामला किसी से जुड़ी निजी जानकारी मांगे जाने से संबंधित है जो जनहित में नहीं है और निजी सूचना किसी और को नहीं दी जा सकती। याचिका में यही मांग की गई है। इसके बाद पीठ ने सुनवाई 28 जनवरी के लिए स्थगित कर दी। मालूम हो कि सूचना के अधिकार के तहत प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी मांगी गई है। इसके खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाई में याचिका दायर कर दलील दी थी कि आरटीआइ मजाक बनकर रह गया है। इसके माध्यम से पीएम के साथ ही वर्ष 1978 में बीए परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के बारे में जानकारी मांगी गई है, जबकि किसी की निजी जानकारी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती।

बढ़ी ताकत : मध्य प्रदेश में सेना ने किया टैंक भेदी 'स्पाइक' मिसाइल का सफल परीक्षण

आइएएनएस, नई दिल्ली: भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के समीप महू के इंफैंट्री स्कूल में टैंक भेदी दो 'स्पाइक एलआर' (लांग-रेंज) मिसाइल का बुधवार को सफल परीक्षण किया। इससे सेना की युद्ध क्षमता में और इजाफा होगा। स्पाइक एलआर चार किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के टैंक पर अचूक निशाना साध सकेगी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत व कई कमांडर इस परीक्षण के साक्षी बने।

चौथी पीढ़ी की मिसाइल : सैन्य अधिकारियों ने बताया कि स्पाइक एलआर चौथी पीढ़ी की मिसाइल है, जिसे हाल ही में सेना में शामिल किया गया है। जनरल रावत महू स्थित इंफैंट्री स्कूल में सैन्य कमांडरों की सालाना बैठक में भाग लेने आए थे। इसी दौरान यह परीक्षण किया।

हवा में बदल सकेगी लक्ष्य : सैन्य अधिकारियों ने बताया कि स्पाइक एलआर 'मारो और भूलो' की क्षमता के साथ ही 'दागो, देखो और फिर निशाना साधो' (फायर, ऑब्जर्व एंड अपडेट) तकनीक से भी लैस है। यह हवा में ही लक्ष्य बदलने की क्षमता रखती है। इसे ऊंचे या कम ऊंचाई वाले परिपथ से दागा जा सकता है।

विश्व भर में 5000 स्पाइक दागी गईं, 95 फीसद अचूक : अब तक विश्व भर में 5000 से ज्यादा स्पाइक मिसाइलें दागी गई हैं। उनमें से 95 फीसद ने लक्ष्य साधने में कामयाबी पाई है। भारतीय सेना ने इसका डीआरडीओ के जरिये देश में निर्माण का फैसला किया है। तब तक तात्कालिक जरूरतें पूरी करने के लिए सीमित मात्रा में ये हासिल की गई हैं। इसके साथ ही भारत इन मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाला 33वां देश बन गया है।

- चार किलोमीटर दूर तक लगाएगी अचूक निशाना, सफल परीक्षण के साक्षी बने सेना प्रमुख रावत

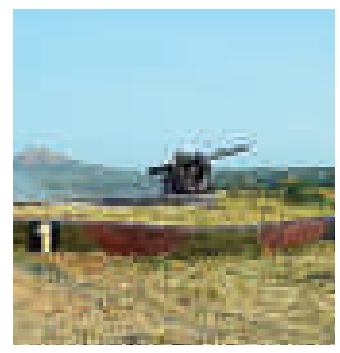
मध्य प्रदेश के महू में टैंक भेदी 'स्पाइक' मिसाइल का परीक्षण करते हुए। एएनआइ

नौसेना ने क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया

नई दिल्ली, एएनआइ: नौसेना ने 290 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गुरुवार को अरब सागर में इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पोत, विमान या जमीन से लांच किया जा सकता है। इसी वर्ष सितंबर में भारतीय प्रपल्सन प्रणाली, एयरफ्रेम, पावर सप्लाई एवं अन्य स्वदेशी अवयवों वाली मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इससे पहले मई में भारतीय वायुसेना ने एसयू-30 एमकेआइ लड़ाकू विमान से इसके एयर वर्जन का परीक्षण किया था। एयर-लांच ब्रह्मोस मिसाइल 2.5 टन की हवा से सतह पर मार करने वाली है। यह मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 22 नवंबर 2017 को भारतीय वायुसेना ने समुद्र में लक्ष्य को निशाना बनाया था। इसके बाद भारतीय वायुसेना 2.8 मैक सर्फेस अटैक मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली वायुसेना बन गई थी।

बड़ा मामला

भाजपा सांसद का विवादों से रहा पुराना नाता, पार्टी के नेता चाहते हैं कड़ी कार्रवाई हो प्रज्ञा पर

कई बार मिली हिदायत पर साध्वी प्रज्ञा हैं कि मानती ही नहीं

नईदुनिया, भोपाल

यह पहला मौका नहीं है, जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के कारण भाजपा को जवाब देना मुश्किल हुआ हो। विवादों से उनका गहरा और पुराना नाता रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण के समय अपने विवादास्पद बयानों से साध्वी ने पार्टी को मध्य प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी परेशानी में डाल दिया था। इस बार जब मामला सिर से ऊपर निकल गया, तब पार्टी को कड़े कदम उठाने पड़े।

लोकसभा में बुधवार को हुए घटनाक्रम पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा सफाई के लिए किए गए ट्वीट को पढ़कर कहीं यह नहीं लगता कि वे नाथूराम गोडसे को लेकर क्या कहना चाह रही हैं। उन्होंने लिखा कि 'कभी-कभी झूठ का बवंडर इतना गहरा होता है कि दिन में भी रात लगने लगती है, किंतु सूर्य अपना प्रकाश नहीं खोता। पल भर के बवंडर में लोग भ्रमित न हों, सूर्य का प्रकाश स्थायी है। सत्य यही है कि कल मैंने उधम सिंहजी का अपमान नहीं सहा, बस।' इससे पहले जब लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, तब पार्टी के दबाव के चलते उन्होंने तत्काल खेद भी जता दिया था।

साध्वी प्रज्ञा। फाइल

इस बार लगता है कि पार्टी ने कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि सीधा एक्शन ले लिया। सूत्रों की मानें तो पार्टी के अनेक नेता साध्वी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के पक्षधर हैं।

साध्वी प्रज्ञा पहले भी कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान साध्वी ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को 'देशभक्त' तक करार दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान फिल्म अभिनेता कमल हासन के गोडसे को लेकर आए बयान पर जब साध्वी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा था कि गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। उनके इस बयान पर जब बवाल मचा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक सभा में यह कहना पड़ा था कि मैं दिल से उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बाद में अनुशासन समिति ने उन्हें नोटिस भी दिया था।

हेमंत करकरे की शहादत को लेकर भी दिया था विवादित बयान : इसके पहले साध्वी प्रज्ञा ने मुंबई में आतंकवादियों की गोली से शहीद हुए एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की शहादत को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने मालेगांव बम धमाके के मामले में हुई गिरफ्तारी के दौरान हेमंत करकरे को दिए गए श्राप का जिक्र किया था। इसकी भी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और भाजपा को बैकफुट पर आकर यह कहना पड़ा था कि यह साध्वी के निजी विचार हैं।

अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने को लेकर दिए गए बयान पर प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव आयोग ने मामला भी दर्ज किया है। प्रज्ञा ने विवादित ढांचे को गिराए जाने को गर्व का विषय बताया था। यह भी नहीं भूलना होगा कि साध्वी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भोपाल दिग्विजय सिंह को आतंकवादी बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छता अभियान को लेकर भी उन्होंने सीहोर में विवादित बयान दिया था जिस पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाकर हिदायत दी थी।

प्रज्ञा को लेकर कांग्रेस विधायक ने दिया विवादास्पद बयान

नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश के ब्यावरा (राजगढ़) से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। भोपाल सांसद द्वारा दिए बयान के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों ने भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर का पुतला दहन किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में विधायक ने कहा कि पूरा पुतला नहीं, प्रज्ञा ठाकुर कभी आई तो साथ-साथ जला भी देंगे। दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया ने विधायक से उनके बयान पर बात की तो बोले-अन्यथा नहीं लेना, ऐसे शब्द निकल गए।

साध्वी पर भाजपा की कार्रवाई दिखावटी: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया कि उनकी बड़ी गलती की सजा काफी छोटी है। यदि भाजपा ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान को गलत मान उन्हें दोषी माना है और उनके बयान को वो निंदनीय बता रहे हैं तो उनके इस आचरण पर उनकी सदस्यता समाप्ति की कार्रवाई होना चाहिए।

कल्पना की जन्म व कलाम के मृत्यु की गलत तारीख पढ़ाई जा रही

नईदुनिया, भोपाल

- मध्य प्रदेश में आठवीं और 12वीं कक्षा की किताबों में गड़बड़ी
- पांच माह से गलत पढ़ रहे बच्चे, जानकारी होने पर भी गलती नहीं सुधारी

मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की दो किताबों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आठवीं कक्षा की अंग्रेजी की किताब में अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जन्मतिथि तो 12वीं कक्षा की सामान्य हिंदी की किताब में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय में निधन की तारीख गलत छपी है। यह गलती 2019-20 के पाठ्यक्रम के लिए छापी गई किताबों में हुई है।

गौरतलब है कि जुलाई में यह किताबें विद्यार्थियों को बांट दी गई थीं। शिक्षकों को गलती भी पता चल गई थी। शिक्षा विभाग को भी इस बारे में जानकारी है। बावजूद इसके अब तक दोनों किताबों में सुधार नहीं किया गया। राज्य शिक्षा केंद्र के पास जानकारी पहुंची तो संशोधन के लिए पत्र जारी किया गया, फिर भी सुधार नहीं हुआ।

2015 के बदले 1915 छाप दिया: पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत 27 जुलाई 2015 को हुआ था, लेकिन किताब में 1915 छाप दिया गया है। वहीं, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म एक जुलाई 1961 को हुआ था, लेकिन किताब में 17 मार्च 1962 छाप दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम के निधन की तिथि की यह गलती सिर्फ 2019-20 के पाठ्यक्रम की किताबों में ही नहीं की गई है, बल्कि 2017-18 में उनके निधन का वर्ष ही नहीं छापा गया था। पाठ को पढ़ने पर ऐसा लगेगा जैसे अब भी वे जीवित हैं।

> आठवीं और 12वीं की किताब की छपाई में गड़बड़ी हुई है। इसे संज्ञान में लेकर तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए हैं।
> -डॉ. प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश

1.78 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी मिली है कैलाशा एंटरटेनमेंट के लिए उत्तराखंड में। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर की मैसर्स कैलाशा इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा केदारनाथ आपदा पर बनाए गए धारावाहिक की एवज में ये रुपये शेष थे।

पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश

बढ़ी ठंड ▶ उत्तराखंड के बदरीनाथ और केदारनाथ में तीन से चार फीट बर्फ की चादर

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रहा बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंसी

जेएनएन, नई दिल्ली

दिल्ली और एनसीआर में लगातार दूसरे दिन की बारिश से पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई है। तेज रफ्तार ठंडी हवा शीत लहर जैसा एहसास करा रही है। अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जबकि न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता हल्की पड़ने के कारण शुक्रवार को बारिश होने की संभावना नहीं है। शुक्रवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 24 और 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

पहाड़ों पर हुई खूब बर्फबारी : उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बुधवार से तल्ख मौसम के तेवर गुरुवार को भी नहीं बदले। इस दौरान उत्तराखंड के बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही पहाड़ों में हिमपात हुआ तो मैदानों में रुक-रुक कर बारिश का क्रम जारी है। मसूरी के पास धनोल्टी और नागटिब्बा की पहाड़ियों पर मौसम का पहला हिमपात हुआ है। भारी हिमपात से उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सराज हलके के छतरी में बर्फबारी के बाद बर्फ से लकदक हुई एचआरटीसी की बस व अन्य वाहन। जागरण

वहीं, हिमाचल में चोटियों पर बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश राहत के साथ दिक्कतें लेकर आई है। तापमान में गिरावट से प्रदेश में शीतलहर तेज हो गई है। बर्फबारी के कारण प्रदेश में कई सड़कों पर यातायात बाधित रहा। इस कारण कई पर्यटक व स्थानीय लोग परेशान हुए। किन्नौर जिले के कल्पा व लाहुल-स्पीति के केलंग में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है।

इसके अलावा कश्मीर में लगातार तीसरे दिन रुक-रुक कर हुई बर्फबारी और बारिश से जवाहर टनल के आसपास भूस्खलन के बाद बुधवार शाम से बंद हुआ जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग गुरुवार को भी बंद रहा। इसके चलते सैकड़ों गाड़ियां राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसी हुई हैं।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ओलावृष्टि से खेती को नुकसान

दो दिन से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से जहां ठंड अचानक से बढ़ गई है। वहीं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फसलों को भी नुकसान हुआ है। मेरठ क्षेत्र में बुधवार रात झमाझम बारिश के बाद गुरुवार को भी रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहा। देहात क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हुई। शुक्रवार को भी बारिश के आसार हैं। हालांकि इससे वायु प्रदूषण का प्रकोप भी कम हुआ है। वहीं, बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हैं।

गेहूं, गन्ना और सरसों की फसल प्रभावित

मेरठ क्षेत्र में गत दो दिनों से बारिश हो रही है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश और ओलावृष्टि से सरसों की फसल को ज्याद नुकसान हुआ है। गेहूं की बुआई भी प्रभावित हुई है। वहीं, गन्ने की कटाई का काम भी रुक गया है। वहीं, हरियाणा में भी बारिश और ओलावृष्टि के चलते सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है।

नोएडा की कंपनी की 8.82 करोड़ की संपत्तियां जब्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पोंजी स्कीम घोटाले में नोएडा स्थित मार्केटिंग कंपनी की आठ करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

वेबवर्क ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड की इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था। मामला वर्ष 2017 का है। नोएडा पुलिस ने कंपनी और उसके निदेशकों अनुराग गर्ग, संदेश वर्मा व अन्य के खिलाफ ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा जमाकर्ताओं को धोखा देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। ईडी ने पुलिस की इस कार्रवाई पर संज्ञान लेते हुए पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

जांच एजेंसी के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति में फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, अचल संपत्तियों व गहनों की बिक्री के बाद कंपनी के खातों में जमा राशि आदि शामिल हैं। इनका मूल्य 8.82 करोड़ रुपये है।

ईडी ने कहा, 'वेबवर्क ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ऑनलाइन पोर्टल एड्डसबुक डॉट कॉम व वेबवर्क डॉट इन के जरिये लोगों को लाभकारी योजनाओं का झांसा देकर उनके साथ धोखाधड़ी की। जांच में पता चला कि कंपनी के उत्तराधिकारी के तौर पर सिटी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, विजया बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और एक्सिस बैंक आदि में कई खाते खोले और बंद किए गए। बहुत कम समय में इस मार्केटिंग कंपनी ने विभिन्न बैंकों में खोले गए अलग-अलग लोगों और कंपनियों के खाते में बड़ी राशि जमा की।'

▶ **कुर्क की गई संपत्ति में फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, अचल संपत्तियों व गहनों की बिक्री के बाद कंपनी के खातों में जमा राशि आदि शामिल**

फाइल

पूर्व में फ्रीज हो चुकी हैं कंपनी की 27.66 करोड़ की संपत्तियां

ईडी की तरफ से कंपनी के खिलाफ की गई यह दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले एजेंसी कंपनी की 27.66 करोड़ रुपये की संपत्तियों को फ्रीज कर चुकी है। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि वह इस मामले में लखनऊ स्थित पीएमएलए अदालत में पिछले ही साल आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। अब मामले की सुनवाई चल रही है।

राष्ट्रपति के रिश्तेदार को परिवार संग बम से उड़ाने की धमकी

जागरण संवाददाता, कानपुर : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर आगमन से पहले उनके रिश्तेदार और नमो सेना इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार को परिवार समेत बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी गुरुवार दोपहर पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से वाट्सएप कॉल के जरिए दी गई। फोन करने वाले ने नमो सेना संगठन को छोड़ने के लिए भी कहा। पीड़ित राजीव ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस सर्विलांस व साइबर सेल की मदद से जांच कर रही है। बता दें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 नवंबर को कानपुर पहुंचेंगे।

गुरुवार दोपहर करीब 2.01 बजे राष्ट्रपति के भतीजे पंकज के गूबा गार्डन सिद्धार्थनगर निवासी साले राजीव कुमार के पास पाकिस्तानी नंबर से वाट्सएप कॉल आई।

उन्होंने नंबर पर गौर नहीं किया और कॉल रिसीव कर ली। फोन करने वाले ने उन्हें धमकाया कि नमो सेना छोड़ दे, वरना तुझे और तेरे परिवार को आरडीएक्स से उड़ा देंगे। राजीव ने फोन करने वाले से नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया। घटना से सहमे राजीव ने अपने रिश्तेदारों को जानकारी दी। पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा मांगी। सीओ अजय कुमार ने बताया कि वाट्सएप कॉलर ने उनसे नमो सेना छोड़ने के लिए कहा है। वह कोई जानकार भी हो सकता है। +92 पाकिस्तान का आइएसडी कोड है, लेकिन यह कॉल स्पूफिंग का भी मामला हो सकता है। साइबर सेल व सर्विलांस टीम की मदद से जांच चल रही है।

कृष्णानंद राय हत्याकांड के आरोपितों को मिली जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : भाजपा नेता कृष्णानंद राय की वर्ष 2005 में की गई हत्या के मामले में निचली अदालत से बरी सभी आरोपितों को दिल्ली हाई कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने साथ ही निचली अदालत को मामले से जुड़े दस्तावेज हाई कोर्ट लाने का निर्देश दिया।

कृष्णानंद की पत्नी अलका राय की तरफ से दायर चुनौती याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर को सभी पक्षों को नोटिस जारी कर विधायक मुख्तार अंसारी और छह अन्य लोगों से जवाब मांगा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सांसद अफजल अंसारी अदालत में मौजूद रहे।

अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से दिल्ली की निचली अदालत में स्थानांतरित किया गया था। कृष्णानंद वर्ष 2002 में मोहम्मदाबाद क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। 29 नवंबर 2005 को उनकी छह लोगों के साथ हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी पर हत्या और अपहरण सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

'वृंदावन के कण-कण में प्रेम का संदेश'

जागरण संवाददाता, मथुरा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को मथुरा में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के चैरिटेबल हॉस्पिटल के शारदा ब्लॉक को रोगियों के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि वृंदावन के कण-कण में प्रेम और शांति का संदेश है। जिस तरह भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी लीलाओं के जरिए लोगों को अत्याचारियों से मुक्ति दिलाई थी। ठीक उसी तरह रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम का शारदा ब्लॉक लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति दिलाने का काम करेगा। नर सेवा ही नारायण सेवा का भाव रखने वाले स्वामी विवेकानंद ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है।

राष्ट्रपति गुरुवार को करीब चार घंटे के अंतराल में यहां विभिन्न कार्यक्रमों में मौजूद रहे। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए बनाए गए शारदा ब्लॉक के लोकार्पण समारोह में राष्ट्रपति बोले, मुझे विश्वास है कि शारदा ब्लॉक के कैंसर वार्ड, कैंसर ऑपरेशन, महिला सर्जिकल वार्ड, नवजात वार्ड से रोगियों की सघन देखभाल हो सकेगी। भक्ति और आध्यात्म में रमे नजर आए राष्ट्रपति बोले, मैं योगीराज श्रीकृष्ण की लीलास्थली आया हूं, लोग यहां आध्यात्मिक और मानसिक सुख-शांति पाने आते हैं। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में कहा कि मानव कल्याण का इससे बड़ा कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। सच कहूं तो यही ईश्वर सेवा भी है। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद, बेटी श्वेता कोविंद, बेल्लूर मठ के महासचिव तत्वविदानंद महाराज, संस्थान सचिव स्वामी सुप्रकाशानंद व उप सचिव कृष्णकालीचंद भी मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश के मथुरा में गुरुवार को अक्षयपात्र फाउंडेशन में बच्चों को भोजन परोसते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी सविता कोविंद, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एएनआइ

बच्चों को परोसा भोजन : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांकेबिहारी जी मंदिर भी गए। ठाकुर जी का विधिविधान से पूजन किया। उन्होंने निकुंजवन आश्रम में संत विजय कौशल महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद अक्षयपात्र फाउंडेशन में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने परिषदीय स्कूल के बच्चों को अपने हाथ से भोजन परोसा और उनके साथ फोटो खिंचवाए।

केरल की महिला ने आइएस में शामिल अपने दामाद को पहचाना

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : इस्लाम धर्म कबूल करने वाली निमिषा फातिमा की मां बिंदु ने बुधवार को कहा कि उन्होंने अपने दामाद और नातिन की पहचान की है। ये उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने हाल में अफगानिस्तान में आत्मसमर्पण किया है। निमिषा और उसके पति पर तीन साल पहले आइएस में शामिल होने का संदेह है।

बिंदु ने टीवी चैनलों को बताया कि केरल के लापता लोगों, जिनके आइएस में शामिल होने का संदेह है, के मामले की तहकीकात कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने आत्मसमर्पण करने वाले लोगों की कुछ तस्वीरें भेजी हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दामाद पलक्कड़ जिले के ईसा उर्फ बेंसन विन्सेंट और नातिन को पहचान लिया है। बिंदु ने पत्रकारों से कहा, 'मेरी नातिन बुर्का पहनी महिला की गोद में बैठी हुई है। यह महिला मेरी बेटी हो सकती है।' उन्होंने कहा, 'मेरे खयाल से यह महिला मेरी बेटी होगी, जिसने 2016 में आइएस में शामिल होने के लिए अपने पति के साथ घर छोड़ दिया था।' बिंदु ने कहा कि उन्होंने तस्वीरों को अपने दामाद की मां ग्रेसी को भेजा है और उन्होंने भी अपने बेटे को पहचान लिया है। उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले एनआइए ने कुछ तस्वीरें भेजी थीं। उसमें मैंने अपने दामाद को देखा।

झूठ बोलने पर सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने को राजी नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **वैवाहिक विवाद के केस में चार साल से लंबित याचिका की खारिज**

▶ **पति ने तलाक की डिक्री रद करने के हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती**

अदालत में की गई गलतबयानी कितनी भारी पड़ती है, इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने चार साल से लंबित याचिका को अदालत में बोले गए झूठ के कारण सुनने से इन्कार कर दिया। यह मामला वैवाहिक विवाद का था जिसमें लखनऊ के एक प्रमुख डॉक्टर ने तलाक की डिक्री रद किए जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका स्वीकार करते हुए तलाक की डिक्री मंजूर करने का निचली अदालत का 21 फरवरी, 2006 का आदेश रद कर दिया था और फरवरी 1989 को हुई शादी बहाल कर दी थी। इसी आदेश के खिलाफ डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वह महिला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी जिससे डॉक्टर ने दूसरी शादी कर ली थी। यह महिला डॉक्टर के अस्पताल की कर्मचारी थी।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरएफ नरीमन, अनिरुद्ध बोस और वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने डॉक्टर पति और दूसरी पत्नी दोनों की याचिकाएं अदालत में झूठ बोले जाने के कारण खारिज कीं। चार साल से लंबित याचिकाएं खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने झूठ बोला है और ऐसे में यह अदालत अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की इजाजत देने के अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगी।

यह मुकदमा एक जाने-माने डॉक्टर दंपति का था। पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। पति नामीगिरामी डॉक्टर और लखनऊ में एक बड़े निजी अस्पताल के संचालक एवं मेडिकल कॉलेज में फार्मोकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। दोनों की शादी 15 फरवरी, 1989 को कानपुर में हुई थी। पत्नी उस वक्त सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी, पति शादी के वक्त एमबीबीएस एमडी थे और अपनी निजी प्रैक्टिस करते थे। बाद में उन्होंने लखनऊ में एक नर्सिंग होम शुरू किया जो आज एक बड़ा अस्पताल है। करीब 13 साल बाद 26 अक्टूबर, 2002 को पति ने पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए पारिवारिक अदालत में तलाक का मुकदमा दाखिल किया। इस बीच दंपति के तीन संतानें हो चुकी थीं। तलाक मांगते हुए पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी उसके साथ मारपीट और बुरा व्यवहार करती है। पारिवारिक अदालत ने 21 फरवरी, 2006 को पति की अर्जी मंजूर करते हुए तलाक की डिक्री पारित कर दी थी। पत्नी ने तलाक की डिक्री को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने छह नवंबर, 2015 को पत्नी की याचिका स्वीकार कर पारिवारिक अदालत का तलाक देने का फैसला रद कर दिया और शादी बहाल कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट फाइल

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने एक अर्जी दाखिल कर पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था। पति ने आरोपों को गलत बताते हुए हलफनामा दाखिल कर दूसरी शादी से इन्कार किया। हलफनामा देखने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि मुकदमा लंबित रहने तक दोनों पक्ष शादी नही कर सकते। बाद में डॉक्टर पति ने हाई कोर्ट में दूसरी शादी का सार्टिफिकेट पेश किया। हाई कोर्ट में दिए गए ये विरोधाभासी बयान और हलफनामा ही सुप्रीम कोर्ट में पति की याचिका पर सुनवाई की बाधा बना। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की गलतबयानी पर सख्त रुख अपनाते हुए पति और दूसरी पत्नी की याचिका पर विचार करने से मना करते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं। इसका परिणाम यह है कि 1989 में हुई पहली शादी बहाल है। पहली पत्नी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह तथ्य रखा गया था कि पति की ओर से हाई कोर्ट में कहा गया था कि दूसरी शादी नहीं की है और हाई कोर्ट ने इस शपथपत्र को देखने के बाद शादी करने पर रोक लगा दी थी, ऐसे में वह दूसरी शादी का आधार लेकर हाई कोर्ट के फैसले का विरोध कैसे कर सकते हैं? पहली पत्नी का आरोप था कि अस्पताल में काम करने वाली महिला कर्मचारी से उनके पति के संबंध थे। इसका विरोध करने पर ही उनके खिलाफ क्रूरता के झूठे आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा दाखिल किया गया था।

असम के पूर्व एनआरसी संयोजक हजेला पर मुकदमा

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम पब्लिक वर्क्स (एपीडब्ल्यू) ने सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) में एनआरसी के पूर्व राज्य संयोजक प्रतीक हजेला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन पर राज्य में एनआरसी प्रक्रिया के दौरान सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है।

एपीडब्ल्यू ने ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) प्रक्रिया शुरू करने के लिए मूल याचिका दाखिल की थी। एसीबी में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में एपीडब्ल्यू ने एनआरसी के राज्य संयोजक हजेला व उनके करीबियों के खिलाफ भ्रष्टाचार या सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। एपीडब्ल्यू के सदस्य राजीव डेका की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एनआरसी प्रक्रिया के लिए राज्य संयोजक के माध्यम से धन उपलब्ध कराया था। रिपोर्ट के अनुसार, 'जहां तक हमारी जानकारी है करीब 1,600 करोड़ रुपये अब तक जारी हो चुके हैं। हम आपसे इस पूरी प्रक्रिया और इसके अलग-अलग मदों में हुए खर्च की जांच का आग्रह करते हैं।' मीडिया को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट की प्रति में दावा किया गया है, 'हजेला ने अपने सलाहकार के तौर पर कई पूर्व सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया था। उन्हें अच्छा वेतन के साथ-साथ नई गाड़ी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इन सलाहकारों ने क्या काम किया। न ही खर्च का सीएजी ने ऑडिट किया है।'

▶ **एपीडब्ल्यू ने सीबीआइ की एसीबी में दर्ज कराई रिपोर्ट, सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप**

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि एनआरसी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त किया गया। उन्हें अब तक एक रुपया भी नहीं दिया गया, जबकि रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि शिक्षकों को बड़ी राशि का भुगतान किया गया है। एनआरसी के लिए 45,500 रुपये की दर से हजारों लैपटॉप खरीदे गए, जबकि ये बाजार में 22,500 रुपये की दर से उपलब्ध हैं। इस प्रकार की और भी कई अन्य अनियमितताएं हैं, जिनकी जांच जरूरी है।

बिलासपुर व नागपुर में रेलवे दफ्तरों में सीबीआइ की छापेमारी

नईदुनिया, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर सेंट्रल इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (सीबीआइ) की टीम ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर व नागपुर स्थित वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक (सीनियर डीओपी) कार्यालय में छापेमारी की। सीबीआइ टीम ने भर्ती घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। दोनों स्थानों पर एक ही समय पर कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार रेलवे के सतर्कता विभाग ने लोको निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा के दौरान जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसे लेकर शुरुआत से ही गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी। विभागीय कर्मचारियों ने गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर रेलवे के आला अधिकारियों के साथ ही विजिलेंस विभाग से भी शिकायत दर्ज कराई थी। विभागीय स्तर पर जब कुछ नहीं हुआ तब पुलिस में भी इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई । पुलिस के आला अधिकारियों ने भी इस मामले में जांच पड़ताल करना उचित नहीं समझा । इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सघन जांच करने के लिए सीबीआइ को निर्देशित करने की गुहार कर्मचारियों ने लगाई थी।

आनंद भवन के गृहकर की माफी को लेकर फंसा पेच

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

प्रयागराज के आनंद भवन के गृहकर में छूट को लेकर पेच फंस गया है। नगर निगम ने जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड (ट्रस्ट) के अधीन आने वाले आनंद भवन, संग्रहालय और तारामंडल पर ब्याज समेत 4.36 करोड़ रुपये बकाया गृहकर का नोटिस दिया है। इसके जवाब में गृहकर माफ करने को लेकर ट्रस्ट ने नगर निगम को जो दस्तावेज सौंपे हैं, उससे यह पुष्टि नहीं हो रही है कि आनंद भवन चैरिटेबल ट्रस्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट होने की स्थिति में ही आनंद भवन का गृहकर माफ हो सकता है। ऐसे में नगर निगम दस्तावेजों की दोबारा जांच कर रहा है।

नगर निगम की ओर से बकाया गृहकर का नोटिस दिए जाने के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी से दोबारा मुलाकात की और उन्हें ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेजों की प्रतिलिपि सौंपी। ट्रस्ट कब बनाया गया? ट्रस्ट की कार्यशैली क्या है? पदाधिकारियों की जानकारी दस्तावेज में है, लेकिन आनंद भवन के चैरिटेबल ट्रस्ट होने के स्पष्ट कागजात नहीं हैं। संस्था कैसे चैरिटी कर रही है, इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र का कहना है कि ट्रस्ट की ओर से दोबारा दिए गए दस्तावेज की भी गहन जांच की जा रही है। इसकी संपूर्ण रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने पर उसका अध्ययन करने के बाद निगम की ओर से आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि सिर्फ ट्रस्ट होने भर से गृहकर माफ करने का कोई प्राविधान नहीं है।

> ट्रस्ट द्वारा अभी तक जो दस्तावेज दिए गए हैं, उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि आनंद भवन चैरिटेबल ट्रस्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट होने पर गृहकर माफ हो सकता है। वैसे ट्रस्ट 600 रुपये वार्षिक गृहकर जमा कर रहा है।
>
> **-अभिलाषा गुप्ता नंदी, महापौर, प्रयागराज**

परंपरा

नहीं चलेगी चीन की, तीन दिवसीय तिब्बती धार्मिक सम्मेलन के दूसरे दिन 800 साल पुरानी तिब्बती परंपराओं का ही निर्वहन किए जाने पर चर्चा

दलाईलामा ही चुनेंगे अपना उत्तराधिकारी

जागरण संवाददाता, धर्मशाला

15वें दलाईलामा के चयन के लिए धर्मशाला में प्रस्ताव पारित कर बौद्ध लामाओं ने चीन सरकार के दलाईलामा के पुनर्जन्म पर अधिकार के दावे को खारिज कर दिया है। अब दलाईलामा ही अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। तय किया गया कि इस मामले में चीन की नहीं चलेगी और 800 साल पुरानी तिब्बती परंपराओं का ही निर्वहन किया जाएगा।

इस बाबत धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार के धर्म एवं संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे तीन दिवसीय तिब्बती धार्मिक सम्मेलन के दूसरे दिन भी चर्चा हुई। शुक्रवार को अंतिम दिन आयोजन में दलाईलामा भाग लेंगे और उपस्थित बौद्ध लामाओं को संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इसी साल अक्टूबर में मैक्लोडगंज में तिब्बती समुदाय का विशेष अधिवेशन हुआ था और इसमें निर्णय लिया था कि दलाईलामा ही उत्तराधिकारी चुनें और इस मामले में चीन का हस्तक्षेप सहन नहीं होगा। वर्ष 1969 के बाद से ही दलाईलामा के पुनर्जन्म की चर्चाएं शुरू हुई थीं। इस मामले में दलाईलामा का भी हमेशा यही रुख रहा है कि यह तिब्बती समुदाय का ही मामला है। यदि चीन सरकार अपना दलाईलामा घोषित करती है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

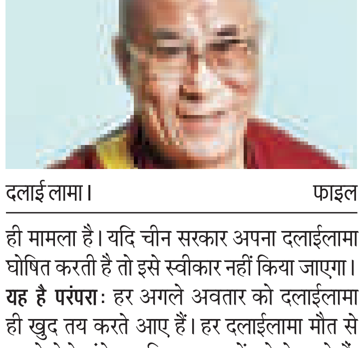

दलाई लामा। फाइल

यह है परंपरा: हर अगले अवतार को दलाईलामा ही खुद तय करते आए हैं। हर दलाईलामा मौत से पहले ऐसे संकेत वरिष्ठ लामाओं को दे जाते हैं, जिनसे उनके अगले अवतार की पहचान आसानी से की जा सकती है। मौजूदा समय में यह परंपरा 14वें दलाईलामा तक पहुंची है। वर्तमान दलाईलामा ने कुछ साल पहले यह कहा था कि इस विषय में वे लिखित निर्देश छोड़कर जाएंगे।

क्या है दलाईलामा : दलाईलामा मंगोल भाषा का शब्द है और इसका सामान्य अर्थ है ज्ञान का महासागर। दलाईलामा कोई नाम नहीं, बल्कि यह दलाईलामा के अवतार के रूप में जन्म लेने वाले को मिलने वाली एक पहचान है। दलाईलामा की पदवी सबसे पहले तिब्बत के तीसरे सबसे सर्वोच्च धर्मगुरु सोनम ग्याछो को मिली थी।

2011 में लिया था बड़ा फैसला : वर्ष 2011 में मौजूदा दलाईलामा ने बड़ी परंपरा को तोड़ दिया था। पहले दलाईलामा ही तिब्बत के सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख होते थे। यानी राजनीति से धर्म तक सभी निर्णय दलाईलामा ही लेते थे, लेकिन 29 मई, 2011 को उन्होंने राजनीतिक अधिकार एक प्रक्रिया के तहत निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख को सौंप दिए थे।

> तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति चीन की शत्रुता हमें स्वीकार नहीं है। इसी तरह, हम पुनर्जन्म प्रक्रिया में चीन के हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं। यह तिब्बती समुदाय व दलाईलामा को ही तय करना है कि उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा।
>
> **-डॉ. लोबसांग सांग्ये, अध्यक्ष केंद्रीय तिब्बतियन प्रशासन**

मप्र में छात्राओं को डंडों से पीटा, 100 उठक-बैठक लगवाईं, आठ भर्ती

नईदुनिया, टीकमगढ़

मध्य प्रदेश के मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र के गोर गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में होमवर्क नहीं करने पर छात्राओं से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इसमें 8 छात्राओं को अतिथि शिक्षिका ने डंडों से पीटा और 100 से ज्यादा उठक-बैठक लगवाई। मारपीट के कारण छात्राओं की हालात इतनी बिगड़ गई कि उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। भर्ती छात्राओं ने अधीक्षिका पर छुआछूत का आरोप भी लगाया है। इस बीच अतिथि शिक्षिका को हटा दिया गया है।

जानकारी के अनुसार गोर गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में पदस्थ अतिथि शिक्षिका मोना सोनी ने कक्षा सात की छात्राओं को एप्लीकेशन याद करने के लिए कहा था। बुधवार को देर शाम शिक्षिका ने छात्राओं से पूछना शुरू किया तो 8 छात्राएं नहीं बता सकीं। छात्राओं का आरोप है कि इसी बात को लेकर शिक्षिका ने पहले तो छात्राओं को डंडे से जमकर पीटा और 100 से ज्यादा उठक-बैठक लगवाईं। गुरवार को जब मामला खुला तो छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती छात्राओं में विनीता चढ़ार, श्री यादव, मोना घोष, शिवानी घोष, अंजना रजक, मुस्कान यादव, शिवानी अहिरवार और गीता चढ़ार हैं। अधीक्षिका उपासना दुबे ने बताया कि छात्राएं जब स्कूल के लिए छात्रावास से निकलने लगी, तब छात्राएं ठीक से चल नहीं पा रहीं थीं। मारपीट की जानकारी लगते ही तत्काल अतिथि शिक्षिका मोना सोनी को हटा दिया गया है।

> शिक्षक और छात्राओं के बीच पढ़ाई-लिखाई का मामला है। इसमें अतिथि शिक्षिका ने अतिउत्साह में आकर छात्राओं को दंड दे दिया, लेकिन यह कानूनी रूप से ठीक नहीं है। इस बात को लेकर डीपीसी के माध्यम से वार्डन और सहायक वार्डन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। जवाब संतोषजनक न होने या न देने की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
>
> **- सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर टीकमगढ़**

शिवसेना प्रमुख के खिलाफ शिकायत

जासं, वाराणसी : गुरुवार को अदालत में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे तथा वरिष्ठ नेता संजय राउत के खिलाफ प्रार्थना पत्र (परिवाद पत्र) दायर किया गया। कमलेश चंद्र त्रिपाठी की ओर से दाखिल आवेदन पर एसीजेएम (षष्ठम) की अदालत ने सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है। आरोप है कि उद्धव ने हिंदुओं के साथ छल कर वोट लिया और फिर भगवा आतंकवाद कहने वालों के साथ मिलकर सरकार बना ली। इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।

जनमत मुद्दा

क्या मूल अधिकारों की रक्षा जितना ही कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति भी सबका संकल्प होना चाहिए?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। MUDDA लिखें, स्पेस देकर YES या NO लिखकर 57272 पर भेजें।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 29 नवंबर 2019

दैनिक जागरण

चिंता भरा एक दिन काम भरे एक दिन से ज्यादा थकाने वाला होता है

खतरनाक अभिव्यक्ति

भाजपा को भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के कारण जिस तरह फजीहत का सामना करना पड़ रहा है उससे यही साबित होता है कि राजनीतिक फायदे के लिए जिस-तिस को गले लगाने के क्या दुष्परिणाम होते हैं? यह पहली बार नहीं है जब प्रज्ञा ठाकुर ने भाजपा को असहज किया हो। वह इसके पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी हैं। समझना कठिन है कि जब उन्हें पहले भी नाथूराम गोडसे के महिमामंडन के कारण शर्मसार होकर अपना बयान वापस लेना पड़ा था तब फिर उन्होंने वही गलती दोबारा क्यों की और वह भी संसद में? साफ है कि वह प्रधानमंत्री के इस कथन को भूल गईं कि वह उन्हें मन से माफ नहीं कर पाएंगे? क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि जब मोदी सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जोर-शोर से मना रही है तब प्रज्ञा ठाकुर को यह समझ नहीं आ रहा कि उन्हें उनके हत्यारे नाथूराम के बारे में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं? उन्हें शायद इससे मतलब ही नहीं कि मोदी सरकार गांधी जी को किस तरह हर स्तर पर प्राथमिकता दे रही है? यह भी हो सकता है कि उन्हें इसका आभास ही न हो कि उनकी सोच कितनी क्षुद्रता भरी है?

भाजपा को इससे चिंतित होना चाहिए कि प्रज्ञा ठाकुर जैसे कुछ और ऐसे लोग पार्टी में हैं जो दबे-छिपे स्वर में गोडसे का महिमामंडन करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाने का काम दृढ़ता से किया जाना चाहिए, ताकि यह साफ संदेश जाए कि यदि कोई गांधी जी की नीतियों से असहमत भी है तो भी उसे उनके हत्यारे के गुणगान का अधिकार नहीं। ऐसा करना तो एक तरह से अतिवाद को समर्थन देना है। किसी अतिवादी तत्व का गुणगान एक खतरनाक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। वास्तव में कैसा भी अतिवाद हो उसके विरोध की अपेक्षा हर भारतीय से की जाती है, क्योंकि यही भारत का स्वभाव है और वह इसी के लिए जाना जाता है। इसमें संदेह है कि प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा संबंधी संसदीय समिति से हटाने और संसद के इस सत्र से बाहर रखने के फैसले से उस क्षति की भरपाई हो सकती है जो उनके घोर आपत्तिजनक बयान से भाजपा और सरकार को पहुंची है। भाजपा को यह आभास होना चाहिए कि प्रज्ञा ठाकुर सरीखे नेता केवल उसकी छवि पर पानी ही नहीं फेरते, बल्कि राजनीतिक विरोधियों को हमले का अवसर भी प्रदान करते हैं। बेहतर हो कि भाजपा इस पर गंभीरता से चिंतन-मनन करे कि राजनीतिक लाभ के लिए हर तरह के तत्वों को अपनाना कहां तक उचित है?

उप चुनाव की कसौटी

बंगाल की तीन सीटों कलियागंज, करीमपुर और खड़गपुर सदर सीटों का उप चुनाव किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था। यह चुनाव 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए लिटमस टेस्ट भी था और राजनीतिक दलों के प्रति जनता का रुझान का आकलन भी। नतीजों ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है, क्योंकि तीनों सीटें सत्ताधारी तृणमूल के खाते में चली गई हैं। लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर विजयश्री हासिल कर भाजपा बंगाल में मजबूत समीकरण बन गई थी, लेकिन छह माह बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। यहां तक कि बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के सांसद बनने से रिक्त हुई खड़गपुर सदर सीट भी हार गई। गौर करें तो लोकसभा चुनाव में भाजपा के व्यापक उभार से तृणमूल की नींद उड़ गई थी। खिसकते जनाधार को वापस पाने की तृणमूल के सामने चुनौती थी। अपने को नए सिरे से आजमाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उपचुनाव को ही हथियार बनाया। वह पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरीं और इसके पहले ही उनकी पूरी सेना बंगाल की जनसमस्याओं को हल करने में जुट गई। विशेष रूप से इन तीनों क्षेत्रों में अभियान चलाकर जन समस्याओं को हल किया गया। इसमें सर्वाधिक कारगर नुस्खा बना एनआरसी का मुद्दा। ममता ने भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह को सीधे चुनौती देकर दावा कर दिया कि वह बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। आरोप-प्रत्यारोप के बीच तो यही लगा कि शाह पर पलटवार कर ममता सिर्फ जुबानी जंग लड़ रही हैं, लेकिन सही मायने में वह बांग्लादेश से घुसपैठ कर यहां जमे हुए लोगों को मजबूती से अपना बना रही थीं। करीमपुर और कलियागंज विधानसभा क्षेत्र की सरहदें बांग्लादेश को छूती हैं और दोनों जगह बांग्लादेशी मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतों में बिखराव हुआ था, लेकिन इस उप चुनाव में माकपा और कांग्रेस गठबंधन को जिस तरह मतदाताओं ने समेट दिया उससे यह साफ हो गया कि भाजपा के खिलाफ ममता अपने परंपरागत मतदाताओं के साथ ही मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण में कामयाब हो गईं। एक बात और भी है। भाजपा ने यह आरोप लगाया है कि ममता ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। चुनाव में जिस तरह हिंसक घटनाएं हुईं उससे चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हुए। करीमपुर के भाजपा उम्मीदवार जयप्रकाश मजूमदार पर हुए हमले ने इस आरोप को बल भी दिया। हालांकि तृणमूल के लोग इसे नकारते हैं। इस टकराव के बीच यह संकेत मिल गया है कि 2021 में तृणमूल और भाजपा की सीधी टक्कर होगी।

सत्ता के लिए विचारधारा को तिलांजलि

डॉ. एके वर्मा

आखिर जो कांग्रेस भाजपा को अपना धुर वैचारिक विरोधी मानती है वह उसके उग्र संस्करण शिवसेना से हाथ कैसे मिला सकती है?

महाराष्ट्र में अंततः उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन ही गई। यह भारतीय राजनीति में विचारधारा के अंत का ही नहीं, वरन विचारधारा पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वर्चस्व का भी ज्वलंत उदाहरण है। कल तक शिवसेना और कांग्रेस-राकांपा विचारधारा के दो ध्रुवों की तरह थे। शिवसेना जहां कट्टर हिंदुत्ववादी यानी दक्षिणपंथी पार्टी के रूप में जानी जाती थी वहीं कांग्रेस और राकांपा वामपंथी-मध्यमार्गी के रूप में। दोनों में गंभीर वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन आज सत्ता के लालच में दोनों ही ध्रुवों ने वैचारिक मतभेद भुलाकर एक-दूसरे का हाथ थाम लिया। समय ही बताएगा कि यह प्रयोग कितने दिनों चलेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि इसका खामियाजा इन तीनों ही दलों को उठाना पड़ेगा। ऐसा ही प्रयोग कुछ समय पूर्व कांग्रेस ने कर्नाटक में जद-एस के साथ और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ किया था। इसके परिणाम उसके लिए घातक ही रहे थे। इसी की पुनरावृत्ति 2019 में उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा ने लोकसभा चुनाव में की और उसमें दोनों को ही नुकसान हुआ।

ऐसा माना जाता है कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है, लेकिन उसकी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं होती कि राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों की गंभीर गलतियों को भूल जाए। इसीलिए चुनावों में सरकारें अक्सर बदल जाया करती हैं। विचारधारा राजनीति की आत्मा होती है। जिन राजनीतिक दलों का भारतीय लोकतंत्र में पराभव हुआ है या हो रहा है उन्हें यह समझना चाहिए कि उनसे गलती कहां हो रही है? आखिर जनता को एक दल और दूसरे दल में फर्क करने का कोई तो ठोस आधार चाहिए। शिवसेना को आज यह नहीं समझ में आ रहा कि भविष्य में उसे अपनी वैचारिक जमीन छोड़ने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? जो लोग शिवसेना के साथ हैं वे जरूर असहज होंगे, क्योंकि जो सैद्धांतिक लड़ाई उन्होंने कांग्रेस और राकांपा के खिलाफ दशकों से लड़ी, आज उस पर पानी फिर गया। आखिर ऐसे लोग क्यों न भाजपा की ओर आकृष्ट हों? यहां वे वैचारिक रूप से अपने को ज्यादा सहज पाएंगे। शिवसेना जैसा हश्र कांग्रेस का भी होगा।

महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार में सम्मिलित होकर पार्टी ने देश में क्या कुछ नहीं खोया? आखिर जो कांग्रेस भाजपा को अपना धुर वैचारिक विरोधी मानती है वह उसके उग्र-संस्करण शिवसेना से हाथ कैसे मिला सकती है? या तो कांग्रेस पहले गलत थी या अब गलत है? शिवसेना तो एक प्रादेशिक पार्टी है, उसका हित तो सीमित है, लेकिन कांग्रेस को तो अपने वृहद राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना चाहिए था। क्या आगामी चुनावों में कांग्रेस के पास वैचारिक स्तर पर भाजपा के विरोध का कोई आधार होगा? यदि एक विचारधारा है तो नीतियां भी एक जैसी होंगी, निर्णय और

अवधेश राजपूत

कार्यक्रम भी एक जैसे होंगे। फिर जनता को पार्टी बदलने से क्या बदलाव मिलेगा?

हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विद्वान डेनिएल बेल ने अपनी पुस्तक 'विचारधारा के अंत' में कहा था कि किसी भी देश के उन्नत आर्थिक-सामाजिक ढांचे की संरचना में विकास की अहम भूमिका होती है, विचारधारा की नहीं। विभिन्न राजनीतिक विषयों जैसे लोक कल्याणकारी राज्य, शक्ति विकेंद्रीकरण, मिश्रित अर्थव्यवस्था और बहुलवाद पर सभी विचारधाराओं में मतैक्य है। एक अन्य अमेरिकी विद्वान फ्रांसिस फुकुयामा ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा था कि ऐसा नहीं कि विचारधाराओं का अंत हो गया है, वरन विचारधाराओं के संघर्ष में दक्षिणपंथी विचारधारा ने स्थाई रूप से पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है और यही विचारधारा मानवता को भविष्य में निर्देशित करती रहेगी। एक तरह से देखा जाए तो दक्षिणपंथी शिवसेना द्वारा बहुत कम सीटें प्राप्त होने के बाद भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना डेनियल बेल और फुकुयामा की भविष्यवाणियों को प्रमाणित करता है।

महाराष्ट्र के घटनाक्रम से भाजपा ने भी कुछ खोया है। भाजपा को अपनी विचारधारा के लिए जाना जाता है। भारतीय राजनीति में भाजपा का जिस तरह अभ्युदय हुआ वह फुकुयामा की थीसिस को सही साबित करता है। जब धीरे-धीरे केंद्र और राज्यों में भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही थी तब महाराष्ट्र में भाजपा को इतनी अधीरता क्यों दिखानी चाहिए थी कि भोर में शपथ ग्रहण हो जाए? देवेंद्र फड़नवीस ने सरकार न बनाने की बात कहकर स्वच्छ राजनीति का जो उदाहरण शुरू में दिया और जनता की सहानुभूति बटोरी उसे बेमतलब गंवाने का कोई कारण नहीं था।

कभी पूरे देश में मध्यमार्गी-वामपंथी विचारधारा का पर्याय रही और केंद्र और राज्यों में एकक्षत्र राज्य करने वाली कांग्रेस को आज एक पिछलग्गू पार्टी की भूमिका में क्यों आना पड़ा? इसका कारण यही है कि कांग्रेस ने 1960 के दशक से या उससे भी पहले अपनी वैचारिक आधारशिला को तोड़ना शुरू कर दिया था। केरल में 1959 में नंबूदरीपाद की विधिवत निर्वाचित वामपंथी सरकार को प्रधानमंत्री नेहरू ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी के आदेश पर भंग कर इसका संकेत दे दिया था। इंदिरा गांधी ने 1969 में कांग्रेस का विभाजन कर इसे आगे बढ़ाया। 1975 में देश को आपातकाल में झोंक कर इंदिरा गांधी ने उसे और पुख्ता किया। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नरसिंह राव ने समाजवादी लीक से हटकर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहल पर देश को 'उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण' की ओर ले जाकर उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि को और कमजोर किया। आज कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं जो भाजपा से अलग हो। इसके चलते जनता और मतदाता को भाजपा और कांग्रेस में कोई वैचारिक फर्क नहीं दिखता। जब दोनों दलों में फर्क करने के लिए नेतृत्व सामने आता है तब भाजपा बाजी मार ले जाती है। आज भले ही कांग्रेस को शिवसेना से वैचारिक धरातल पर कोई परहेज न हो, लेकिन यदि उसने अपने को वैचारिक धरातल पर अलग नहीं किया और नेतृत्व के स्तर पर कोई गंभीर आकर्षक विकल्प नहीं दिया तो पार्टी का भविष्य संदिग्ध है। राहुल गांधी हों या सोनिया गांधी, ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी से बड़े नहीं हो सकते। राजनीति कोई 'शार्ट-टर्म' गेम नहीं, राजनीतिक दलों को लंबी रेस के घोड़े तैयार करने होंगे। जो दल राजनीति में विचारधारा और महत्वाकांक्षा का बेहतर समिश्रण कर सकेंगे, भविष्य उन्हीं का है। महाराष्ट्र में यह समिश्रण नहीं हो पाया। चूंकि यहां विचारधारा को तिलांजलि देकर महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया गया इसलिए इस प्रयोग की सफलता संदिग्ध है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)

response@jagran.com

राजनीतिक विमर्श का सिमटता दायरा

गिरीश्वर मिश्र

संसद और विधानसभाओं का उदार वैचारिक माहौल बिगड़ते जाना गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए

भारत की विचार-परंपरा में स्वतंत्र चिंतन की जड़ें अत्यंत प्राचीन और गहरी हैं। दर्शन के क्षेत्र में विभिन्न प्रश्नों को लेकर वाद-विवाद एक आम सी बात है। यहां वाद-विद्या अपने आप में ज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुई थी। भिन्न मतों के बीच शास्त्रार्थ की कथाएं भी प्रसिद्ध हैं। निकट अतीत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी लोक जीवन में विभिन्न मुद्दों पर विमर्श के दौर चलते रहे। संविधान सभा में भी भिन्न विचार वालों को शामिल किया गया था। कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र का जन्म एक उत्कृष्ट किस्म के राजनीतिक विमर्श की परिणति है। अपने निजी अनुभवों और विभिन्न देशों के विचारों का लाभ उठाते हुए संविधान सभा ने बाबा साहब डॉ. आंबेडकर के सहयोग से भारत के लिए जिस संविधान का निर्माण किया वह एक उच्चकोटि दस्तावेज है। संविधान सभा में भारत के सामाजिक, धार्मिक और वैचारिक विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल थे। निजी और दलगत विचार भिन्न होते हुए भी उन्होंने एक नए राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का खाका तैयार किया और गहन तथा खुले मन से किए गए विचार-विमर्श के बाद सहमति पर पहुंचे।

स्वतंत्रता मिलने के पहले और बाद के कुछ वर्षों तक भारतीय संसद में विभिन्न मुद्दों को लेकर उच्च स्तर का विचार-विमर्श होता था। यदि कोई सांसद अच्छा वक्तव्य देता था तो पार्टी लाइन से हट कर उसकी तारीफ भी की जाती थी। आलोचनाओं को सुनना और उनको गुन कर अपने में बदलाव लाना अस्वाभाविक नहीं था। धीरे-धीरे संसद और विधानसभाओं का उदार वैचारिक माहौल बिगड़ने लगा। इन संस्थाओं के कार्य दिवसों की संख्या घटती गई है। इस स्थिति के चलते बहुत से काम-काज बिना आवश्यक विचार किए फटाफट निपटा दिए जाते हैं। बिहार, हरियाणा और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं में लगभग बिना विचार किए बिल प्रस्तुत करने और तत्काल पास करने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। संसदीय समितियां की कार्यप्रणाली भी बहुत संतोषजनक नहीं है। आवश्यक संसाधनों, तत्परता की कमी और विशेषज्ञता के अभाव से वे ठीक ढंग से काम नहीं निपटा पातीं। आजकल कुछ ही सांसद प्रबुद्ध और विशेषज्ञ होते हैं। केवल वे ही चर्चा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जो जातिबल, बाहुबल या धनबल की बदौलत संसद में पहुंचते हैं वे बहस में कोई योगदान नहीं करते। उनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो पूरे कार्यकाल में कोई सवाल भी नहीं पूछते। ज्यादातर सांसद पार्टी की बात को दोहराना ही अपना धर्म मानते हैं। संप्रग शासन के दौर में पार्टी नेता सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह संसद में बहुत कम बोलते थे। वे मीडिया से भी दूर रहते थे। वे अपनी अच्छी नीतियों के लिए भी जन-समर्थन नहीं जुटा पाते थे। मोदी सरकार इस दृष्टि से मुखर तथा सक्रिय है। संसदीय कार्य की दृष्टि से भी उसकी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं।

राजनीतिक विमर्श के लिए संस्थाओं के मानकों की रक्षा और भरपूर आदर होना चाहिए। उदाहरण के लिए राज्य और शासन भिन्न और परस्पर संबंधित संस्थाएं हैं। पूरे समाज के प्रतिनिधित्व का दायित्व होने के कारण राज्य को हर तरह के भेद-भाव से ऊपर उठ कर निष्पक्ष और तटस्थ रूप से जनहित की बात सोचनी चाहिए। शासन तंत्र और न्यायालय आदि के लिए निष्पक्षता, नियम पालन आदि बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक हित और देशहित के बीच संतुलन बनाना जरूरी होता है। आज सत्ता के लिए हर तरह के समझौते हो रहे हैं। एक राजनीतिक दल और उसकी सरकार के बीच का अंतर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि सरकार पूरे देश के लिए होती है, जबकि पार्टी का दायरा सीमित होता है। सरकारी तंत्र का पार्टी के लिए दुरुपयोग किसी भी तरह न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। समानता, समता और बंधुत्व जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार को खुले मन से सबके लिए और सबके साथ मिलकर कार्य करना जरूरी होता है।

विमर्श का एक आयाम नीतियों के लिए परामर्श या संसद में चर्चा करना भी है। कई बार सरकार द्वारा व्यापक महत्व के अंतरराष्ट्रीय करार और दूरगामी व्यापारिक फैसले बिना संसद में बहस के ले लिए जाते हैं। दूसरी ओर शिक्षा जैसा सामाजिक दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण विषय कभी भी गंभीर चर्चा का विषय ही नहीं बन पाता। पांच साल से शिक्षा नीति का मसौदा बन रहा है। अभी भी यह पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने वर्षों से शिक्षा पर 'सेस' लगा रखा है, परंतु जमीनी हकीकत यह है कि शिक्षा के लगभग हर स्तर पर अध्यापकों की कमी बनी हुई है। संसाधनों का अभाव है। कुशलता के अभाव में शिक्षा रोजगार दिलाने में असफल हो रही है। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रश्न इस राष्ट्र के सामने ज्यों का त्यों मुंह बाए खड़ा है। शिक्षा के अनियंत्रित निजीकरण की अपनी कहानी है। शायद सरकारी सोच यह है कि यदि और सब ठीक हो जाएगा तो शिक्षा खुद ठीक हो जाएगी, जबकि बात ठीक उल्टी है। यदि शिक्षा ठीक हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। शिक्षा पूरे देश के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। शिक्षा के प्रति उदासीनता आज घातक सिद्ध हो रही है।

लोकतंत्र में विमर्श के स्वरूप को निर्धारित करने में मीडिया की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ थोड़ी-सी अच्छी पत्रिकाओं के अलावा दैनिक समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे सामने एक मिश्रित चित्र प्रस्तुत करते हैं। कुछ तो अच्छे हैं, पर ज्यादातर प्रबुद्ध पाठक या दर्शक को निराश करते हैं। फैशन और संभ्रांत जनों पर मीडिया द्वारा अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि गरीबों, गावों और उपेक्षितों पर बहुत कम नजर पड़ती है। फलतः विरोध और प्रतिकार का जरूरी पक्ष दबा ही रहता है। ऐसे में विचारों की सिकुड़ती परिधि और सघन विचार की परंपरा दुर्बल होने के साथ देश की नैतिक और राजनीतिक संस्कृति में क्षरण के लक्षण दिखने स्वाभाविक हैं। कुल मिलाकर उच्च आर्थिक छलांग के लिए तत्पर आज के भारत में राजनीतिक आचार, नैतिकता और लोकतंत्र की रक्षा तथा विकास की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसके लिए लोक में विमर्श की संस्कृति को पुष्ट करना ही होगा।

(लेखक पूर्व प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अवसर की महिमा

जीवन को श्रेष्ठतर, स्मरणीय एवं उदाहरण प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को जीवनरूपी सुंदरतम उपवन दिया। साथ ही प्रसूनरूपी दुर्लभ अवसर भी। शुभ अवसरों की गंगा प्रभु क्षण-क्षण हमारे चहुंओर प्रवाहित करते रहते हैं। आवश्यकता केवल उन दुर्लभ अवसरों को सहेजने की है। सही समय पर सही अवसर का सदुपयोग जीवन को स्मरणीय उप्लब्धियों की मंजिल तक पहुंचने में कोर-कसर नहीं छोड़ता। इसके विपरीत अनमने भाव से प्रभु कृपा से इतर दुर्भावनापूर्ण अवसर का दामन थाम आने वाला कल कष्टमय सिद्ध हो सकता है।

अवसर जीव से सकारात्मकता एवं कर्मठता की मांग करता है। कहा भी गया है कि अवसर उसकी मदद कभी नहीं करते जो अपनी मदद नहीं करते। जीवन में प्रभु की कृपा से कोई दुर्लभ अवसर प्राप्त होने पर भी अज्ञान, अहंकार, विपरीत परामर्श, पद का प्रदर्शन दैव-अनुकंपा में मिली उस दुर्लभ अवसर रूपी पूंजी को पल में धूल-धूसरित करने का कारक बन सकते हैं। फिर उसके पश्चात का पश्चाताप जीवन में क्षण-क्षण मरने के लिए पर्याप्त है।

कोई भी शुभ अवसर प्रभु द्वारा मनुष्य को केवल शुभ कार्य, समाज को समुचित न्याय एवं मानवता के कल्याण के लिए ही प्रदान किया जाता है, लेकिन सत्ता पाते ही जो सद्मार्ग एवं प्रभु निर्देशों की अवहेलना का दुस्साहस जुटाता है तो उसका पतन अवश्य होता है। वस्तुतः प्रभु-प्रदत्त अवसर किसी के ज्ञान, सूझबूझ, संयम, संस्कार, परमार्थ, निष्पक्षता, शक्ति, भक्ति, मर्यादा, सहिष्णुता, धैर्य एवं जीवन दर्शन का परीक्षण भी करता है। प्रभु कृपा के शुभ संकल्पों से अनुबंधित व्यक्ति अपने दुर्लभ-अवसर अवधि के स्वर्णिम काल को अविस्मरणीय भी बना सकता है। इसके विपरीत चलनेवाला स्वयं एवं अपने वरिष्ठ जनों की स्थापित कुलीन आदर्श परंपरा को प्रश्नचिह्नित भी कर सकता है। अच्छा हो इन दुर्लभ अवसरों की महिमा समझ, इनसे स्वयं एवं जगत के कल्याण के सुखद मार्ग खोजे।

प्रो. दिनेश चमोला 'शैलेश'

खुद से करें भ्रष्टाचार रोकने की शुरुआत

देवेंद्रराज

हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा, जहां भ्रष्टाचार के असुर ने अपने पंजे न गड़ाए हों

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ताजा सर्वे के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में भारत इस साल 79वें पायदान पर है। हालांकि भारत की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले तीन पायदान सुधरी है। पिछले साल देश 81वें क्रम पर था। इस साल रिश्वत देने वालों की संख्या 51 प्रतिशत है, जबकि पिछले साल यह संख्या 56 प्रतिशत थी। रिपोर्ट के अनुसार पासपोर्ट और रेल टिकट जैसी सुविधाओं को केंद्रीकृत और कंप्यूटराइज्ड करने से भ्रष्टाचार में कमी आई है।

हालांकि सरकारी दफ्तर रिश्वतखोरी का बड़ा अड्डा बने हुए हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी राज्य सरकारों के ऑफिसों में होती है। गौरतलब है कि सर्वे में 1.90 लाख लोगों को शामिल किया गया। इसमें 64 प्रतिशत पुरुष और 36 प्रतिशत महिलाएं शामिल हुईं। सर्वे में 48 प्रतिशत लोगों ने माना कि राज्य सरकार या स्थानीय स्तर पर सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। लोगों ने 2017 में हुई नोटबंदी की वजह से भी भ्रष्टाचार में गिरावट को कारण माना है। ऐसे लोग जो यह मानते हैं कि रिश्वत के बिना काम नहीं हो सकता, उनकी संख्या पिछले साल के मुकाबले 36 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई। जो रिश्वत को महज एक सुविधा शुल्क समझते हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 2018 में 22 प्रतिशत के मुकाबले ऐसे मानने वाले लोगों की संख्या 26 प्रतिशत हो गई है। जहां तक बात रिश्वत लेने वाले दफ्तरों की है तो जमीन से जुड़े मामलों में सबसे अधिक रिश्वत दी गई। 26 प्रतिशत लोगों ने इस विभाग में रिश्वत दी, जबकि 19 प्रतिशत ने पुलिस विभाग में रिश्वत दी।

भ्रष्टाचार हमारी व्यवस्था को खोखला कर रहा है। बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार आचरण दोष का ही परिणाम है। हर दिन भ्रष्टाचार के काले करनामे उजागर हो रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार को मिटाकर सभी नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकार का धर्म है, लेकिन आजादी से लेकर अब तक देश की सरकारें भ्रष्टाचार को मिटाने में विफल रही हैं। दरअसल जब तक भ्रष्टाचार की राजनीतिक बुनियाद पर चोट नहीं की जाती, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी मुहिम तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच सकती।

भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रचलित रूप रिश्वतखोरी है। लोगों में रिश्वत देकर काम निकलवाने की प्रवृत्ति घर करती जा रही है। जनमानस में यह धारणा बैठ गई है कि रिश्वत देने से हर कठिन काम सरल हो जाता है। सरकारी दफ्तरों में रिश्वत लेने का सिलसिला बहुत पुराना है। रिश्वतखोरी रोकने के लिए सर्वप्रथम हमें खुद को बदलना होगा, क्योंकि रिश्वत देकर परेशानियां खड़ी करने वाले भी हम ही हैं और बाद में सरकार को कोसने वाले भी हम ही हैं। अगर भ्रष्टाचार से निजात पाना है तो हमें खुद से ही शुरुआत करनी होगी, रिश्वत न देने का संकल्प लेना होगा। फिर मतदाता के तौर पर भी हम भ्रष्टाचार से लड़ने में काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही सरकारों को अपने भ्रष्टाचार विरोधी वादों को पूरा करने के लिए ज्यादा प्रयास करने होंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

कहां गई है साख?

प्रदीप सिंह का आलेख 'सत्ता के साथ साख भी गई' पढ़ा। उन्होंने भाजपा की जो तीन गलतियां बताई हैं उससे मैं असहमत हूं। वे कहते हैं कि भाजपा को रह-रहकर कोसने वाली शिवसेना से गठबंधन करना पहली गलती थी। यह ठीक है कि शिवसेना यदा-कदा भाजपा को गरियाती रहती थी, किंतु भाजपा का जो कोर मतदाता है, वह अपनी हिंदुत्व निष्ठा के कारण दोनों में संबंध-विच्छेद उस समय-बिंदु पर कतई पसंद नहीं करता। वैसे भी जहां तक शिवसेना के नेताओं के कथनों का प्रश्न है तो केवल दो माह पहले सितंबर 2019 में उद्धव ने सोनिया-राहुल को जेल भेजने की मांग की थी। जाहिर है किसी न किसी को कोसते रहना शिवसेना नेताओं का स्वभाव है। लेखक ने दूसरी गलती बताई है, उन शरद पवार को ईडी का नोटिस भिजवाना, जिन्होंने 2014 में भाजपा की सरकार को सदन में बचाया था। यदि नोटिस न भेजा जाता तो भाजपा इस आरोप को निमंत्रण देती कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी शून्य-सहनशीलता की घोषणा खोखली है। यह आरोप भाजपा की यूएसपी का खात्मा कर उसे ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाता। तीसरी बड़ी गलती बताई गई है भाजपा का सत्ता के लिए उतावलापन! मुझे आश्चर्य है। क्या लेखक सोशल मीडिया पर दृष्टि नहीं डालते। इस तीसरी कथित गलती को कितना सराहा गया है वहां। भाजपा के पक्ष में एक बड़ा जन-समर्थन का ज्वार इस कथित सत्ता की जल्दबाजी ने खड़ा किया है। लेखक का कहना है कि इस सारे प्रकरण ने शरद पवार का कद बढ़ा दिया है, तो यह तो भाजपा के हित में ही है। शरद कांग्रेस पर और अधिक हावी होंगे, और नौसिखिए नेताओं की मारी कांग्रेस और अधिक नतमस्तक होती चली जाएगी। यह परिदृश्य राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक राजनीति में लोगों को नजर आ रहा है। कहीं ये मोदी-पवार का मिला-जुला खेल तो नहीं, इस अनुमान का सही उत्तर निकट भविष्य में ही मिल जाना चाहिए।

अजय मित्तल, मेरठ

प्रकृति से खिलवाड़

आज जिसे देखो वही प्रकृति का दोहन करने में लगा है। पहाड़ों में पानी रोका जा रहा है, बांध बनाए जा रहे हैं तथा वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप भूस्खलन हो रहे हैं। कहीं जरूरत से ज्यादा बाढ़ और कहीं सूखा पड़ रहा है। पर्यटक पहाड़ों में गंदगी और प्लास्टिक कचरा फैला रहे हैं। हमारे इस प्रकृति के दोहन के कारण वो समय-समय पर कुपित होकर हमें सबक सिखाकर अपनी श्रेष्ठता साबित करती रहती है, लेकिन हम फिर भी बाज नहीं आते। धरती का तापमान बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। भविष्यवाणी की जा रही है कि 2050 तक तटवर्ती शहरों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। प्रकृति के साथ ये मानवीय खिलवाड़ एक भयानक विनाश को आमंत्रित कर रहा है।

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

सिद्धांतविहीन राजनीति

महाराष्ट्र की राजनीति से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि राजनीतिक दलों में विचारधारा का महत्व नगण्य हो चुका है। दूसरी तरफ अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में नेतागण जनमत का अपमान करने से भी नहीं चूकते। हालांकि एक राजनीतिक दल का उद्देश्य सत्ता पाना होता है, किंतु सिद्धांतविहीन राजनीति कतई उचित नहीं है। ऐसे उदाहरण भारतीय लोकतंत्र को स्थिरता एवं मजबूती तो प्रदान नहीं करते, अपितु इसके उलट संवैधानिक मूल्यों की बलि देते प्रतीत होते हैं। इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है कि बहुमत ना मिलने की स्थिति में जनमत की स्वाभाविक अभिव्यक्ति शासन में किस प्रकार से हो।

अंजन मिश्रा, दिल्ली

ऐसे करें पर्यावरण की रक्षा

देश में तीव्रगति से वनों की कटाई से इसका सीधा प्रभाव वातावरण और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इन समस्याओं का एक सीधा उपाय पौधरोपण है। इसका तरीका यह भी हो सकता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों की शादी में निमंत्रण पत्र स्वरूप एक पौधा लगा गमला भेंट करे तो भारत में प्रतिदिन कई लाख नए पौधों की शुरुआत हो सकती है।

gaganbansal12345@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

2.74 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे थे भूटान वर्ष 2018 के दौरान जिनमें से 1.8 लाख पर्यटक भारतीय थे। यानी पर्यटक के तौर पर भूटान जाने वालों में लगभग दो-तिहाई संख्या भारत के लोगों की है।

आजकल

क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करता भारत

पर्यटन को अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एक अहम क्षेत्र माना जाता है। भूटान ने अपने पर्यटक स्थलों की मुद्रा अर्जन क्षमता को समझते हुए एक नई पर्यटन नीति को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। भूटान ने निर्णय किया है कि अभी तक जिन प्रमुख दक्षिण एशियाई देशों, खासकर भारत और बांग्लादेश से भूटान में पर्यटन शुल्क नहीं वसूला जा रहा था, उन्हें अब यह रियायत नहीं दी जाएगी और इन देशों के नागरिकों को भी भूटान के पर्यटक स्थलों का भ्रमण करने पर एक निश्चित शुल्क चुकाना होगा

विवेक ओझा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

भारत, बांग्लादेश और मालदीव से भूटान जाने वाले पर्यटकों से किसी तरह का शुल्क नहीं वसूला जाता है। लेकिन पर्यटकों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए भूटान अब इन देशों के पर्यटकों पर भी शुल्क लगाने की तैयारी में है। भूटान का मंत्रिमंडल अगले महीने पर्यटन नीति के मसौदे को अंतिम रूप दे सकता है। इस संबंध में नई दिल्ली में भूटान के विदेश मंत्री तांदी दोरजी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाल ही में मुलाकात भी की है। इस मसौदे को भूटान की पर्यटन परिषद (टीसीबी) ने तैयार किया है। टीसीबी के महानिदेशक दोरजी धराधुल ने स्पष्ट किया कि पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी है, जो भूटान की नीति के लिए ठीक नहीं है। वर्ष 2018 में 2.74 लाख पर्यटक भूटान गए थे, जिनमें से 1.80 लाख भारतीय थे। यानी भूटान जाने वाले पर्यटकों में भारतीय लगभग दो-तिहाई संख्या में रहे। नई पर्यटन नीति के अनुसार अब इन पर्यटकों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस और परमिट फीस देनी होगी।

नई पर्यटन नीति के तहत अब दक्षिण एशियाई देशों- भारत, बांग्लादेश और मालदीव से भूटान आने वाले पर्यटकों को अन्य देशों के विदेशी यात्रियों के समान ही प्रति यात्री 250 डॉलर (18 हजार रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से अदा करना होगा जिसमें प्रतिदिन 65 डॉलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी और 40 डॉलर वीजा शुल्क भी शामिल है। भारी मात्रा में पर्यटकों के भूटान आगमन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

दरअसल भूटान सरकार क्षेत्रीय पर्यटकों को बहुत कम दर पर रहने योग्य यात्री निवास की सुविधा के उपयोग को रोकने के पक्ष में है, क्योंकि इससे भूटान में अनियंत्रित गेस्ट हाउसों और होम स्टे को बढ़ावा मिला है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में भूटान को पर्यटन से प्राप्त कुल राशि 85.41 मिलियन डॉलर थी। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि भूटान पर्यटकों के लिए भीड़-भाड़ वाली जगह बनता जा रहा है। साथ ही जो लोग ज्यादा पैसा खर्च करके यहां आते हैं उन्हें भी शिकायत रहती है कि ज्यादा पैसे देने के बावजूद उन्हें यहां होटल समेत अन्य कई प्रकार की पर्यटक सुविधाएं मिलने में दिक्कत होती है। वहीं भारत, मालदीव और बांग्लादेश के पर्यटकों को होटल सस्ते दामों में आसानी से मिल जाते हैं।

दक्षिण एशियाई पर्यटकों पर शुल्क लगाने का औचित्य : भूटान दुनिया का पहला देश है जिसने राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक (हैप्पीनेस इंडेक्स) अपना रखा है और अपने सकल घरेलू उत्पाद में नागरिकों की प्रसन्नता के स्तर का भी मापन करता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरे इस देश में पर्यटकों की संख्या का लगातार बढ़ना इसके सतत विकास के लिए चुनौती माना गया है। यही कारण है कि चौथे भूटान वेतन आयोग की रिपोर्ट में भी इस बात की सिफारिश की गई है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय पर्यटकों को एक न्यूनतम ही सही, लेकिन सस्टेनेबल डेवलेपमेंट शुल्क देने को कहा जाए। संबंधित वेतन आयोग का यह भी कहना था कि 500 नगुलट्रम (भूटानी मुद्रा) का शुल्क लगाकर इसकी शुरुआत की जा सकती है जिससे 425 मिलियन नगुलट्रम (4.25 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्ति होगी। सभी देशों के पर्यटकों को शुल्क के दायरे में लाकर इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की सिफारिश भी वेतन आयोग द्वारा की गई थी।

भूटान की भौगोलिक दशा : भूटान एक लैंडलॉक्ड यानी स्थलरुद्ध देश है। उसके व्यापारिक साधन सीमित हैं। वह पनबिजली को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को आधार देता आया है। भूटान में द्रक न्यामरुप शोग्पा (डीएनटी) पार्टी की सरकार ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह भारत को निर्यात की जाने वाली पनबिजली पर भूटान की अत्यधिक निर्भरता घटाना चाहती है। उसके घोषणापत्र में कहा गया था, 'हम अपनी अर्थव्यवस्था में पनबिजली क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करते हैं, लेकिन चूंकि यह जलवायु के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है और भविष्य में इससे भू-जलवायु नुकसान हो सकते हैं, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को केवल इसी क्षेत्र के सहारे रखना बुद्धिमानी नहीं होगी।' इस बयान से भूटान की सरकार की मंशा पता चलती है और अर्थव्यवस्था में विविधता के इस सवाल का जवाब चीन हो सकता है। हालांकि चीन के साथ भूटान के व्यापारिक एवं आर्थिक रिश्ते बेहद सीमित हैं। चीन से भूटान को केवल 161 करोड़ रुपये और भूटान से चीन को तो महज 14.6 लाख रुपये का निर्यात होता है। लेकिन भूटान में होने वाले वस्तुओं के आयात में एक तिहाई हिस्सा चीनी उपभोक्ता वस्तुओं का है। स्पष्ट है कि चीन भूटान के साथ व्यापार के मामले में पांव जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन इस हिमालयी साम्राज्य में अपना दखल बढ़ाने के लिए संस्कृति और पर्यटन जैसी सॉफ्ट पावर की कूटनीति का प्रयोग कर रहा है।

टूरिज्म काउंसिल ऑफ भूटान की एक रिपोर्ट के अनुसार भूटान की यात्रा करने वाले चीनियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। वर्ष 2016 में चीन से यहां 9,220 पर्यटक आए। हालांकि डोकलाम संघर्ष के बाद संख्या गिरकर 6,421 ही रह गई, लेकिन इसके कई अन्य कारण भी रहे। चीनी पर्यटकों को वे आर्थिक बढ़त के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पनबिजली के बाद भूटान की जीडीपी में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी पर्यटन की ही है और यह वहां का सबसे तेज बढ़ता उद्योग है। भूटान में बड़ी संख्या में चीनी सैलानियों के आने से दोनों देशों की जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा संपर्क होगा और दोनों के बीच सकारात्मक रिश्ते पनपेंगे।

भारत पर क्या होगा भूटान के पर्यटन शुल्क बढ़ाने के फैसले का असर

भूटान के इस निर्णय का असर भारत भूटान संबंधों पर किस रूप में पड़ेगा, इसकी समीक्षा भी की जानी शुरू हुई है। यहां सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भूटान दक्षिण एशिया में भारत का सबसे विश्वसनीय मित्र देश है जो भारत के द्वारा उसके विकास के लिए किए गए अहम योगदान की कद्र करता है, लेकिन कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती, राजस्व प्राप्ति के वैकल्पिक साधनों की तलाश और पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाता ही है।

भूटान ने बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वेहिकल एग्रीमेंट से बाहर निकलने का निर्णय भी जब लिया तब भी यह तर्क दिया गया था कि वाहनों की आवाजाही की मुक्त प्रणाली पर हामी भरने से भूटान के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इन सबके बावजूद भारत ने भूटान के विकास में योगदान अब तक किया है, उससे यह स्पष्ट है कि भूटान को कोई भी नया निर्णय भारत को असहज करने के लिए नहीं लिया जा रहा है। भारत ने भूटान के सामाजिक आर्थिक नियोजन और सशक्तीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1961 में भारत की वित्तीय मदद से भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई और तब से लेकर आज 2019 में भूटान अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर 2018 को नवनिर्वाचित भूटानी प्रधानमंत्री डॉ. लोतेय शेरिंग भारत की यात्रा पर आए थे और यहां भारतीय प्रधानमंत्री ने भूटान की बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपये की मदद देने की घोषणा की थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी भारत ने इतनी धनराशि भूटान को दी थी।

भूटान भारत का ऋणी है और ऐसा वह कहता है कि 1971 में भारत के प्रयास से ही उसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिली थी। इसके साथ ही भारत भूटान का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी प्रतिनिधित्व करता है। भारत भूटान संबंधों की नींव वर्ष 1949 में मैत्री और सहयोग संधि के जरिये रखी गई थी जिसमें कहा गया है कि भूटान आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र होगा, लेकिन विदेश मामलों में भारत के मार्गदर्शन और निर्देशन में काम करेगा। वर्ष 2007 में इस संधि की समीक्षा कर भूटान को स्वतंत्र विदेश नीति भी संचालित करने के लिए भारत ने बढ़ावा दिया। दोनों देशों के बीच 1968 से कूटनीतिक संबंध हैं जो आज भी मजबूत स्थिति में हैं। दक्षिण एशिया में भूटान ही एकमात्र देश है जिसका चीन के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है, ना ही चीन का दूतावास है और ना ही कांस्युलेट ऑफिस। भूटान अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तरह चीन के 'वन बेल्ट वन रोड' पहल का हिस्सा भी नहीं है, ना ही 'मैरीटाइम सिल्क रूट' और 'मोतियों की लड़ी की नीति' का हिस्सा है।

भारत को असहज करने की नेपाल की कोशिश

हाल ही में नेपाल की एक अदालत ने यह फैसला लिया है कि भारत की तिपहिया गाड़ियां नेपाल में नहीं चलेंगी। नेपाल की इस अदालत ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से अनेक तिपहिया वाहन कानून का उल्लंघन करते हुए सीमा पार से यात्रियों को लेकर आ रहे हैं, और ऐसे वाहन देश के कानून के मुताबिक कस्टम ड्यूटी भी नहीं दे रहे हैं। नेपाल में संबंधित अदालत का यह आदेश नेपाल के ट्रांसपोर्ट उद्यमियों द्वारा दाखिल याचिकाओं के बाद आया है जिसमें उन्होंने भारत के तिपहिया वाहनों का मुद्दा उठाया था।

वास्तव में हाल के समय में नेपाल ने भारत के साथ सौदेबाजी वाली राजनीति से प्रेरित होकर दबाव बनाना शुरू किया है। यह सर्वविदित है कि चीन इसके पीछे एक जिम्मेदार कारक है। नेपाल ने आर्थिक- व्यापारिक लाभों, पर्यटन, सुरक्षा मुद्दों, पनबिजली परियोजनाओं, भू-स्वामित्व विवाद आदि मामलों में भारत पर दबाव बनाना शुरू किया है। एक लैंड लॉक्ड देश के रूप में नेपाल का शेष विश्व के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारत के दो बंदरगाहों- हल्दिया और विशाखापत्तनम के जरिये होता है। फरवरी 2019 में नेपाल के पोखरा में हुई भारत नेपाल के प्रतिनिधियों की बैठक में नेपाल ने भारत से अपने व्यापार के लिए दो और नए भारतीय बंदरगाहों गुजरात के मुंद्रा और ओडिशा के धामरा के प्रयोग और पहुंच की अनुमति मांगी है। ऐसा तब हुआ जब सितंबर 2018 में चीन ने नेपाल को चार चीनी बंदरगाहों तक पहुंच देने का निर्णय किया था।

हाल के समय में कालापानी, लिपुलेख, टनकपुर और मेंची जैसे क्षेत्रों में भू सीमा विवाद उभरते रहे हैं। नेपाल के मधेसियों की समस्या भारत नेपाल के बीच विवाद खड़े करते रही है। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों की लंबी फेहरिस्त है। अमेरिकी विदेश विभाग की हालिया जारी एक रिपोर्ट 'कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2018' में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) ने भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए नेपाल को अपना सबसे बड़ा अड्डा बना लिया है। उसने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हरकत उल-जिहादी इस्लामी से भी गठजोड़ कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आइएम का पहला मकसद भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना है। इसी के तहत उसने अपना दायरा बढ़ाते हुए भारत के पड़ोसी देश नेपाल को अपना सबसे बड़ा केंद्र बना लिया है।

इसके अलावा आठ नवंबर 2016 को भारत में एक हजार रुपये और पांच सौ रुपये के उस समय प्रचलित नोटों पर पाबंदी लगाने के बाद जारी किए गए पांच सौ रुपये और दो हजार रुपये के नए नोटों को नेपाल में वर्ष 2018 में गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था। नेपाल में भारत के दो हजार, पांच सौ और दो सौ रुपये के नोट प्रतिबंधित करने के फैसले का असर नेपाल के पर्यटन पर पड़ेगा और इससे भारतीय पर्यटकों को भी काफी असुविधा होगी, लेकिन नेपाल ने देश हित के नाम पर अपने इस कदम को जायज ठहराया था। भारत को इन चुनौतियों से निपटने के लिए यथार्थवादी रणनीति और कूटनीति से काम लेना होगा, क्योंकि दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति भारत के सामरिक हितों की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

खरी-खरी

राज्यस्तरीय लोकतंत्र की हत्या

विजी श्रीवास्तव

सर, आप कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या हुई? 'हां, देखते नहीं। क्या हुआ है महाराज्य में?' लेकिन सर, अब तो वहां हालात बदल गए हैं। सर, पहले भी आप कहते रहे हैं कि क, ख, ग, च राज्य में लोकतंत्र की हत्या हुई?

हां, हमने कहा होगा। जहां भी सरकार बनाने के लिए जोड़-तोड़ की जाती है, वहां लोकतंत्र की हत्या होती है।

'वो भी कई बार कहते रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या आपने की है?'

वे झूठ बोलते हैं। लोकतंत्र के असली हत्यारे वे हैं।

सर, लोकतंत्र की हत्या जब पहले ही हो चुकी, तो बार-बार कैसे हो सकती है?

वो दूसरे राज्यों की बात है। इस वाले राज्य में लोकतंत्र की हत्या अभी हुई थी।

सर, सुनते हैं कि लोकतंत्र घायल हो गया, लोकतंत्र को कुचला गया, उसकी मर्यादा को तार-तार कर दिया गया। क्या लोकतंत्र का सही तरीके से उपचार नहीं किया जा सकता?

देखो, पहले लोकतंत्र के पास मूल्य थे। अब मूल्यों के अभाव में इलाज तो संभव है नहीं। फिर सरकारी अस्पतालों के लिए पहले सरकार होना चाहिए। सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र जरूरी है। बीमार लोकतंत्र सरकार नहीं बना सकता। लोकतंत्र की हत्या होना बताता है कि सरकार बनने वाली है।

'लोकतंत्र की हत्या हो रही है! इसका अनुमान आपको कैसे होता है?'

हम लोकतंत्र की नब्ज गिनना जानते हैं। हमें थमती सांसों, रुकती धड़कनों, सिसकती आहों और गुम होती चेतना से पता चल जाता है कि लोकतंत्र के प्राण निकाले जा रहे हैं।

'मतलब, दूसरी पार्टी सरकार गठन का जुगाड़ करे, इससे लोकतंत्र मरता है?'

तब तो बिकने वाले हत्या के दोषी हैं?

वो हमारे लोगों को चुरा लेते हैं।

यह तो चोरी हुई?

स्थानाभाव में लोकतंत्र का दम घुट जाता है।

'यह तो दुर्घटना हुई। लोकतंत्र की हत्या कहां हुई? साजिशों के कारण लोकतंत्र खुद ही आत्महत्या कर लेता है।'

लेकिन लोकतंत्र के मरने की बात ही क्यों होती है। इसे तो जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन कहा जाता है।

लोकतंत्र कल्पना है। कल्पना से ही लोकतंत्र है। कल्पना के मरने की कल्पना भर की जा सकती है। पर वास्तव में कल्पना कभी मरती नहीं है। लोकतंत्र इसीलिए मरकर भी नहीं मरता।

ट्वीट-ट्वीट

अगर भाजपा अपनी साख बचाना चाहती है तो उसके पास एकमात्र विकल्प यही है कि वह प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाने के लिए माफी मांगे, उन्हें पार्टी से निकाले, सांसद पद से हटने को कहे और नए उम्मीदवार के साथ भोपाल में नया लोकसभा सदस्य बनाने के लिए चुनाव कराए।

श्रीनिवासन जैन@SreenivasanJain

कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में ना तो कुछ खोने को था और ना ही उसने कुछ खोया। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में जाने को लेकर हिचकिचाहट दिखाकर वह यह मैसेज देने में कामयाब रही कि साथ चुनाव लड़ने की वजह से वह एनसीपी के दबाव में है और शिवसेना का साथ देकर उसने भाजपा को सत्ता में आने से रोका है तो उसका वोटर भी नाराज नहीं होगा।

अनुराग मुस्कान@anuraagmuskaan

बिना किसी महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास के अपनी राजनीतिक महत्ता और सत्ता में भागीदारी बनाए रखने में कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व का कोई मुकाबला नहीं है।

प्रशांत किशोर@PrashantKishor

प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

झारखंड डायरी

बढ़ी राजनीतिक कटुता, अब जनता की बारी

झारखंड की कुर्सी किसे हासिल होगी? यह जानने के लिए तो 23 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सत्ता के लिए 'राजनीतिक संघर्ष' अपने चरम पर पहुंच चुका है। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी महागठबंधन के साथ ही अलग-अलग ताल ठोक रही आजसू पार्टी और झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। आरोप-प्रत्यारोप से राजनीतिक कटुता निरंतर बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री रघुवर दास और विपक्षी महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और दोनों ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं।

इस बीच कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के महानाटक का पटाक्षेप अब हो चुका है। राजनीतिक दल ना सही, शायद मतदाता जरूर इससे कुछ सबक ले सकते हैं, क्योंकि अब उनकी बारी आ चुकी है। पांच चरण में होने जा रहे राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 13 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। बीते सप्ताह दो और बड़ी बातें हुईं। पहली बार गृहमंत्री अमित शाह और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का परोक्ष रूप से ही सही, पूरा श्रेय लिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए इस मामले को लटकाए रखा था, लेकिन हमने अपना वादा पूरा कर दिया।

इस पर विपक्ष ने हो-हल्ला भी मचाया। खैर, अब यह मतदाता को तय करना है। दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल को छोड़ दें तो पहले चरण में कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं ने झारखंड से दूरी ही बनाए रखी। वह भी तब जब पहले और दूसरे चरण में ही कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी संभावनाएं हैं और अभी तक राहुल, प्रियंका और सोनिया में से किसी ने राज्य का दौरा नहीं किया है। बड़े नेताओं में भूपेश बघेल जरूर राज्य को मथ रहे हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री रघुबर दास और भाजपा के अन्य नेता।

चुनावी रैली संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।

वहीं दूसरी ओर राज्य के क्षत्रप दिन-रात एक किए हुए हैं। सभी एक-दूसरे को घेर तो रहे हैं, लेकिन मतदान बाद की गुंजाइश भी रख रहे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता की साझीदार रही आजसू पार्टी पर हमले से बच रही है, वहीं सुदेश भी सीधे सरकार को घेरने से गुरेज करते दिख रहे हैं। वह मुद्दे तो उठा रहे हैं, लेकिन सीधे रघुवर पर हमला नहीं कर रहे। बाबूलाल मरांडी की झाविमो को तो झामुमो और कांग्रेस भाजपा की ही बी टीम बता रहे हैं। पूर्व में झाविमो के विधायक टूटकर भाजपा में मिलते रहे हैं। विपक्षी महागठबंधन मतदाताओं को बार-बार यह याद दिला रहा है। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए जो नाटक चला, झारखंड में ऐसा कई बार हो चुका है। यहां इकलौते निर्दलीय मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बेशक, रघुवर दास की पहली स्थिर सरकार है जो पांच वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, फिर भी यहां मतदान बाद के समीकरणों पर भी अभी से खूब चर्चा हो रही है।

राजनीतिक गलियारे में यही सवाल सबसे बड़ा है कि यदि किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो कौन किसके साथ जाएगा? मतदाता अभी चुप हैं। अब उनकी बारी आ गई है। सभी दलों के संकल्प पत्र (घोषणापत्र) आ चुके हैं। पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने और आदिवासियों आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाए जाने वाले खास कानून को लगभग सभी दलों ने प्रमुखता दी है। तमाम ऐसे वादे भी हैं जो हर संकल्प पत्र में होते हैं, लेकिन वह कभी धरातल पर उतर नहीं पाते।

चुनाव आयोग और पुलिस-प्रशासन के लिए शांतिपूर्ण मतदान कराना एक बड़ी चुनौती है। नक्सल प्रभावित इलाके मतदान में तैनात कर्मियों से लेकर सुरक्षा बलों की कड़ी परीक्षा लेते हैं। वैसे पिछले पांच वर्ष में राज्य में नक्सलियों की कमर लगभग टूट चुकी है, फिर भी ठीक चुनाव से पहले वह बड़ी वारदात कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की फिराक में रहते हैं। इस बार भी दो-तीन वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें चार जवान शहीद हो चुके हैं। राजनीतिक अवसरवादिता से लेकर नक्सलियों तक को सबक सिखाने के लिए मजबूत सरकार चुनने की जिम्मेदारी अब मतदाताओं की है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या चुनाव पूर्व और चुनाव बाद राजनीतिक गठबंधन को लेकर कानून बनाना चाहिए?

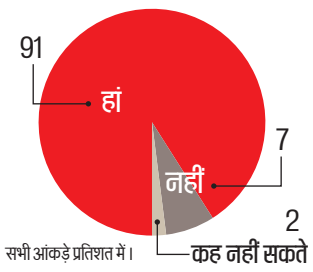

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आप वित्त मंत्री के इस कथन से सहमत हैं कि देश में मंदी जैसी स्थिति नहीं है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

आई है सरकार तो करिए बढ़िया काम,
रोशन करिए काम से पूज्य पिता का नाम।
पूज्य पिता का नाम काम से अगर डुबोया,
तो समझो सर्वस्व आपने अपना खोया।
इधर कुआं है और उधर है गहरी खाईं,
शरद-सोनिया साथ आज जो सत्ता आई।

-ओमप्रकाश तिवारी

कूटनीति

भारतीय विचारों को समृद्ध करते मोदी

देश-दुनिया में भारतीय विचारों के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से तमाम मसलों पर लोगों से संवाद करते नजर आ रहे हैं, वह निश्चित रूप से उन्हें भारतीय विचारों के विश्व संचारक के तौर पर प्रतिष्ठापित करता है

डॉ. अनिल सौमित्र
राजनीतिक विश्लेषक

देशहित से जुड़े अनेक मसलों के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी बात देश-दुनिया के लोगों तक 'मन की बात' के जरिये पहुंचाते हैं। अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से उन्होंने देश में कई तरह के बदलाव की शुरुआत की है। हालांकि नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अभी अनेक परिवर्तनों की अपेक्षा है, किंतु आगे के कार्यकाल के दौरान और कुछ उल्लेखनीय न भी हुआ तो भी उनके नाम अनेक उपलब्धियां दर्ज हो चुकी हैं।

तब का नरेंद्र संन्यासी के रूप में भारत का विश्व संचार कर रहा था, लेकिन आज का नरेंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, प्रचारक और प्रधानमंत्री के रूप में भारत का विश्व संचार कर रहा है। अमेरिका, चीन, रूस समेत फ्रांस, इजराइल आदि देशों की मोदी की प्रत्येक विदेश यात्रा भारत का संदेश देने वाली सिद्ध हुई है। उनकी अनेक राष्ट्रों की यात्रा ना सिर्फ आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामरिक, सांस्कृतिक और राजनय की दृष्टि से भी मील का पत्थर है। उल्लेखनीय है कि अनेक देशों की संस्कृति और परंपरा भारत की सनातन जीवन परंपरा से प्रभावित रही है। अनेक राष्ट्र आज भी भारत को सांस्कृतिक तौर पर अपना गुरु, मित्र और बड़ा भाई मानते हैं। भारत के शासक या राष्ट्राध्यक्ष से दुनिया को इसी भूमिका की अपेक्षा है, किंतु दुर्भाग्यवश अभी तक अंग्रेज द्वारा अनुशंसित गांधी-नेहरू मॉडल ही प्रचलित रहा। चाहे पंचशील का सिद्धांत हो, गुट-निरपेक्षता का व्यवहार या 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' का नारा, भारत को एक दमित, शोषित, पिछलग्गू और विपन्न राष्ट्र के रूप प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है। पहले इंग्लैंड, फिर सोवियत रूस और बाद में अमेरिका से पोषित राष्ट्र की छवि वाला भारत दुनिया की नजरों में रहा है।

इतिहास गवाह है कि अमेरिका और सोवियत रूस अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सशस्त्रीकरण करते रहे और पूरी दुनिया के लिए निःशस्त्रीकरण का सिद्धांत रचते रहे। भारत इन दोनों राष्ट्रों के हितों का ही पोषण करता रहा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक कमोबेश यही चला। लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी इस संबंध में अपवाद कहे जा सकते हैं। ये दोनों कुछ करना चाहते थे, लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण असफल रहे। अतः कह सकते हैं कि 1947 के बाद अभी तक भारत में जितने भी राजपुरुष हुए हैं, उनमें से सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर भारत का पक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन भारत का स्वतंत्र और समग्र प्रतिनिधित्व करने वाला पक्ष किसी प्रधानमंत्री ने नहीं रखा। यह मोदी का संचार कौशल ही है कि अयोध्या, धारा-370, तीन तलाक और नागरिकता पंजीयन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी देश के मुसलमानों और अनेक ईसाई- इस्लामिक राष्ट्रों के नेताओं का समर्थन कांग्रेसी- कम्युनिस्ट मिथक का खंडन-मंडन है। विरोधी देश भी अब भारत के साथ स्वाभाविक सांस्कृतिक संबंधों से जुड़ने को लालायित हो रहे हैं।

नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के अनुसार, 'नरेंद्र भाई दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इससे उनके व्यक्तित्व, कार्यों या नेतृत्व पर कोई असर नहीं पड़ा है। वे आज भी वैसे ही हैं जैसा वे मुख्यमंत्री बनने से पहले थे। उनका सबसे बड़ा गुण यह है कि जैसी जरूरत होती है, उसी के अनुरूप वे काम करते हैं।'

ऐसा नहीं है कि संघ, भाजपा या अन्य संगठनों के कार्यकर्ता- पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी बात से असहमत नहीं होते। मोदी से अनेक असहमतियां हैं। भिन्न-भिन्न भूमिकाओं और वैचारिक प्रतिबद्धताओं के कारण मतभेद या असहमति स्वाभाविक और आवश्यक है, किंतु मोदी के बारे में उनके आलोचक भी मानते हैं कि जानते-बूझते हुए वे भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। संभव है उनके प्रयासों में नीतिगत या व्यवहारगत कमी या दोष हो, पर नीयत में लेशमात्र भी खोट नहीं।

मोदी समर्थक उनके आडंबररहित एवं प्रभावी प्रशासन शैली और उनकी करिश्माई भाषण शैली के कायल हैं। मोदी की लिखी और मोदी पर लिखी गई किताबें बेस्ट सेलर हो रही हैं। उनकी पुस्तकें उनके भाषणों की तरह शक्तिशाली, अंतर्दृष्टिपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं।

नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व उनके अनुभवों का प्रतिबिंब है, उनके संघर्ष और सफलता की कहानी है। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए, विकास योजनाओं को लागू किया, उससे भारत में या फिर वैश्विक परिदृश्य में अनेक रिकॉर्ड कायम हुए हैं। ये वो रिकॉर्ड हैं, जिनसे पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। विदेशी भूमि पर नरेंद्र मोदी का खड़ा होना भारत का अपने ओज-तेज, पराक्रम और वैभव के साथ विश्व पटल पर खड़ा होना है।

जैसाकि शुरू में उल्लेख किया गया कि मोदी एक कुशल, श्रेष्ठ और आदर्श संचारक हैं, वे विविध रूपों और आयामों में भारतीयता के विश्वसंचारक सिद्ध हुए हैं। मोदी एक स्वयंसेवक, प्रचारक, राजपुरुष, वक्ता आदि के रूप में देश-दुनिया से संचार कर रहे हैं। वे संचार के तमाम प्रारूपों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों और माध्यमों का उपयोग करते हैं।

संचारक के रूप में यदि देखा जाए तो चुनाव के समय मोदी त्रि-आयामी (थ्री-डी) आभासी मोदी बन जाते हैं। मोदी टेक्नोक्रेट नहीं, टेक्नोसेवी हैं।

2021 तक धरती के औसत तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई गई है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ते तापमान की एक मुख्य वजह है।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 29 नवंबर 2019

कुनो में मिले 200 प्रजाति के पक्षी शेर को लाने के दिखे अच्छे संकेत

नईदुनिया, भोपाल

22 से 24 नवंबर तक पार्क में कराई गई पक्षियों की गिनती

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयन (बब्बर शेर) के लिए अनुकूल वातावरण के साक्ष्य पक्षी गणना में भी मिले हैं। पार्क में 22 से 24 नवंबर तक कराए गए इस सर्वेक्षण में 200 प्रजाति के पक्षियों की उपस्थिति का पता चला है। यह पार्क का पहला पक्षी सर्वे था। इसमें देशभर से 65 वन्यप्राणी विशेषज्ञ, प्रकृति प्रेमी व 80 से अधिक वन कर्मचारी-अफसर शामिल हुए। सर्वे टीमों को पार्क में शाकाहारी जानवरों की अच्छी उपस्थिति देखने को मिली है।

गुजरात के गिर अभयारण्य के शेरों के लिए कुनो पालपुर पार्क पूरी तरह से तैयार है। गुजरात सरकार भले ही आइयूसीएन (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर) की गाइडलाइन के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने का हवाला देकर शेर देने से इन्कार करती रही हो, लेकिन पार्क में पक्षियों की इतनी अच्छी संख्या शेरों के लिए पार्क में अनुकूल वातावरण होने के संकेत दे रहा है। वनमंडल अधिकारी ब्रजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सर्वेक्षण के लिए 150 लोगों की 45 टीमें बनाकर गणना करने का प्रशिक्षण दिया गया था। इन टीमों ने पूरे पार्क में 22 रास्ते पर सर्वेक्षण किया। वन विभाग की टीम में मुख्य वन संरक्षक

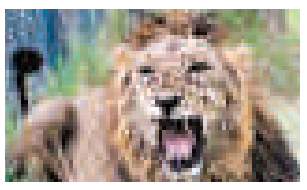

बब्बर शेर फाइल

से लेकर चौकीदार स्तर तक के अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे। सर्वेक्षण में राज्य पक्षी दूधराज, फ्लाईकेचर, पैराकीट, नाईटजार, बारबलर्स, वुड पेकर, किंगफिशर आदि के साथ गिद्धों की पांच प्रजातियां भी मिलीं हैं। उद्यान में प्रवासी पक्षियों का आना भी शुरू हो रहा है। बता दें कि 27 साल पुरानी सिंह परियोजना के तहत बब्बर शेरों की शिफ्टिंग के लिए पालपुर कुनो नेशनल पार्क 2003 से तैयार है। 15 अप्रैल, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और केंद्र सरकार को छह माह में शेरों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आइयूसीएन की गाइड लाइन के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने का हवाला देकर गुजरात सरकार शेर देने को तैयार नहीं है। वर्तमान में गिर अभयारण्य में 600 से कम शेर बचे हैं। यह शेर देश में सिर्फ गुजरात में ही हैं। यह परियोजना शेरों की इस प्रजाति को महामारी से बचाने के लिए बनाई गई थी।

मप्र में दूसरी नदियों में छोड़े जाने के लिए 25 घड़ियाल रहेंगे रिजर्व

मुरैना, नईदुनिया

मध्य प्रदेश में चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षण का प्रयोग सफल रहा है। नदी में लगातार घड़ियालों की संख्या बढ़ रही है। अब चंबल दूसरी नदियों में घड़ियालों की वृद्धि में योगदान दे रही है। नदी से पंजाब की व्यास और सतलज नदियों में घड़ियाल जा चुके हैं। इस बार भी वन विभाग ने यहां रिलीजिंग के लिए तैयार 147 घड़ियालों में से 25 को दूसरी नदियों में छोड़ने के लिए रोका है। इसके लिए पंजाब वन विभाग ने भी डिमांड भेज रखी है। वहीं, 14 साल से केन नदी में घड़ियाल न छोड़े जाने के चलते विशेषज्ञों ने केन में भी घड़ियाल छोड़ने की अनुशंसा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मध्य प्रदेश से की है।

चंबल नदी में हर साल की तरह इस बार 147 घड़ियालों को नदी में छोड़ने को लेकर वन विभाग ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कार्यालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन मध्य प्रदेश व देश के अन्य राज्यों की दूसरी नदियों में चंबल के घड़ियालों की डिमांड और विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते

घड़ियाल फाइल

हमने 147 घड़ियालों को छोड़ने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हमें करीब 25 घड़ियालों को रोककर रखे जाने के निर्देश मिले हैं। इन्हें किसी दूसरी नदी में छोड़ा जाएगा। कहां यह अभी तय नहीं है। फिलहाल 122 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा जाएगा। इसके लिए कैलेंडर तैयार करेंगे।

– पीडी गेब्रियल, डीएफओ मुरैना

हुए, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कार्यालय ने इनमें से सिर्फ 122 घड़ियालों को नदी में छोड़ने की अनुमति दी है। करीब तीन साल पहले चंडीगढ़ की छटवीर जू सहित पंजाब की व्यास और सतलुज नदी में 50 के करीब घड़ियाल भेजे गए थे। इसके बाद वन विभाग पंजाब ने वन विभाग मध्य प्रदेश से कुछ और घड़ियाल मांगे थे, जो अभी भी विचाराधीन हैं।

कोयले से लिखना सीखा, अब मिटा रहीं अशिक्षा की कालिख

शिक्षा का अधिकार ▶ अब तक पांच हजार महिलाओं को बना चुकीं साक्षर, मिले अनेक पुरस्कार और सम्मान

शशि कुमार गुप्त, जौनपुर

- बाहर रह रहे पति के पत्रों का जवाब देने में आती थी दिक्कत तो पढ़ने-लिखने की ठानी
- जीवटता के बल पर बेटे से एक साल बाद पूरी की पढ़ाई, शिक्षिका और जिला पंचायत सदस्य बनीं, शुरू किया महिलाओं को साक्षर बनाने का काम

हौसला और जज्बा हो तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। ऐसा ही कार्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर के हटिया गांव की मुन्नी बेगम ने कर दिखाया है। अनपढ़ मुन्नी बेगम ने अपनी राह में कभी शिक्षा को रोड़ा नहीं बनने दिया। आलम यह रहा कि चूल्हे से निकले कोयले से लिखना सीखकर इन्होंने पढ़ाई शुरू की। जीवटता का आलम यह रहा कि बेटे के स्नातकोत्तर पूरा करने के एक साल बाद इन्होंने भी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की।

सुशिक्षित समाज

अब तक पांच हजार महिलाओं को भी साक्षर कर चुकीं मुन्नी को उपराष्ट्रपति के हाथों एक्जांपल अवार्ड मिल चुका है। महराजगंज विकास खंड के पहाड़पुर में 1971 में जन्मी मुन्नी की शादी 12 वर्ष की उम्र में रामनाथ हटिया गांव में कर दी गई। शादी के दौरान वह पूरी तरह निरक्षर थीं। पति

गुजरात में नौकरी करते थे। पति के पत्र का जवाब न दे पाने के कारण परेशान मुन्नी ने पढ़ने लिखने की ठानी। घर के बाहर चूल्हे से निकले कोयले से मिट्टी पर व बच्चों द्वारा फेंकी गई रफ कॉपी पर लिखने का अभ्यास करके सफलता पाई।

सम्मान पत्रों-पदकों के साथ उत्तर प्रदेश के जौनपुर की निवासी मुन्नी बेगम। जागरण

प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1997 में हाईस्कूल और 99 में इंटर, 2004 में बीए, 2017 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। पति की बीमारी के बाद 1994 में जब घर चलाना मुश्किल हो गया तो एक प्राइवेट विद्यालय में 500 रुपये प्रतिमाह पर अध्यापन प्रारंभ किया। वर्ष 2000 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने वार्ड से जिला पंचायत सदस्य चुनी गईं। इसके साथ सामाजिक कार्य प्रारंभ हो गया।

तरुण चेतना सामाजिक संस्था से जुड़कर उन्होंने साक्षरता एवं महिला सशक्तीकरण अभियान चलाया, जिसके लिए जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने पुरस्कृत किया। 2015 में जिलाधिकारी जौनपुर ने भी महिला साक्षरता एवं सुरक्षा के लिए 'मैं भी मलाला हूं' पुरस्कार से सम्मानित किया। 2018 में उपराष्ट्रपति ने एक्जांपल अवार्ड से सम्मानित किया। पति की मौत के बाद एकमात्र बेटे के सहारे अपने भावी जीवन का ताना-बाना बुन रही 50 वर्षीय मुन्नी बेगम आज भी शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण के काम में जुटी हुई हैं। हजारों महिलाओं को साक्षर बनाने के अलावा उन्हें सिलाई कढ़ाई आदि स्वरोजगार का प्रशिक्षण भी देती हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

गैस चूल्हे पर खाना पकाने के साथ मोबाइल भी करें चार्ज

जागरण विशेष ▶ बर्नर की आंच को बर्बाद नहीं होने देगा यह 'एनर्जी अर्नर' थर्मो इलेक्ट्रिक स्टोव जेनरेटर

लखनऊ के होनहार छात्र के शोध ने जीता एशियन इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम में पहला पुरस्कार

आशुतोष मिश्र, लखनऊ

गैस चूल्हे पर खाना पकाते वक्त बर्नर की आंच बर्तन को गर्म करती है, लेकिन काफी मात्रा में यह बर्तन के इर्द-गिर्द यूं ही व्यर्थ हो जाती है। या कह सकते हैं कि इस आंच का पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाता। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक स्कूली छात्र ने आंच का शतप्रतिशत सदुपयोग करने वाला उपकरण विकसित कर दिखाया है। इसके जरिये बची ऊर्जा से मोबाइल भी चार्ज किया जा सकता है। इस शोध को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। नेशनल इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भी यह आविष्कार पुरस्कृत हुआ है।

दरअसल, लखनऊ के होनहार छात्र प्रांजल श्रीवास्तव ने 'एनर्जी अर्नर' नामक थर्मो इलेक्ट्रिक स्टोव जेनरेटर तैयार किया है। यह उपकरण बर्नर की आंच को बिलकुल भी बर्बाद नहीं होने देगा। इस मॉडल ने हालही एशियन इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम में पहला पुरस्कार जीता है। लखनऊ के जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल के छात्र प्रांजल यह पुरस्कार जीतकर फिलीपींस से लौटे हैं। उन्होंने दैनिक जागरण से कहा, दरअसल यह उपकरण खाना पकाने के

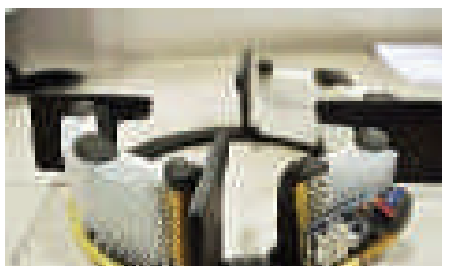

'एनर्जी अर्नर' मॉडल। जागरण

दौरान बर्बाद होने वाली आंच को संजोने का काम करता है और इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। अब वह इसका पेटेंट कराने की तैयारी में हैं।

ऐसे आया विचार : लखनऊ में तैनात फूड सेफ्टी ऑफिसर पिता शैलेंद्र श्रीवास्तव और गृहणी नीमा श्रीवास्तव के बेटे प्रांजल को इस आविष्कार की प्रेरणा तब मिली जब वह दो साल पहले अपने मऊ स्थित गांव ढड़वल गए थे। वहां अक्सर बिजली गुल रहती थी। महिलाएं खाना बनातीं तो बर्नर के किनारों से निकलती लौ का उजाला देख जेहन में इसके इस्तेमाल का खयाल आया। प्रांजल कहते हैं, 'आंच को संजोने की तरकीब तलाशने के लिए मैंने इंटरनेट के साथ ही स्कूल की लाइब्रेरी में काफी ढूंढ़ा। तब मुझे सीबैक थ्योरी का पता चला। मतलब यह कि अगर कोई धातु एक तरफ गर्म की जाए और दूसरी ओर ठंडी, तो इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर तेजी से बहते हैं। इनकी इस गति से बिजली पैदा होती है। मैंने इसी सिद्धांत पर अपना थर्मो इलेक्ट्रिक स्टोव जेनरेटर तैयार कर डाला।'

400 रुपये में किया तैयार : प्रांजल श्रीवास्तव बताते हैं, 'मैंने 250 रुपये कीमत वाले पांच पेल्टियर मॉड्यूल ऑनलाइन ऑर्डर देकर मंगाए। कंप्यूटर की खराब पड़ी सीपीयू (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) से इतनी ही एल्युमिनियम हीट सिंक्स निकालीं। इसे बर्नर पर फिट होने वाले लोहे के ढांचे पर सेट किया। फिर ग्लॉस वूल से कवर्ड तार के जरिये इन्हें सुपर कैपिसिटर से जोड़ दिया। सुपर कैपिसिटर में स्टोर एनर्जी को बक बूस्टर से जोड़कर यूएसबी पोर्ट के सहारे मोबाइल चार्ज करने या एलईडी लाइट जलाने लायक बना दिया। इसमें महज 400 रुपये की लागत आई।

इस सफलता ने नया हौसला दिया है। शोध-अनुसंधान की बातें हमेशा से आकर्षित करती रही हैं। अब यह आकर्षण और बढ़ गया है। आगे चलकर इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) में जाने का अरमान है। इस सफलता के बाद लगने लगा है कि मैं अपना सपना जरूर साकार कर लूंगा।

– प्रांजल श्रीवास्तव, लखनऊ निवासी युवा आविष्कारक

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

'एनर्जी अर्नर' मॉडल और पुरस्कार के साथ प्रांजल श्रीवास्तव। जागरण

ठंड में भी जमीन से क्रूड ऑयल निकालने में मददगार साबित होगा आइएसएम का पॉलीमर

शशिभूषण, धनबाद

- ठंड में कच्चे तेल के जमने या गाढ़ा हो जाने के कारण उसे बाहर निकालना होता है मुश्किल
- गहन शोध के बाद फैटी एसिड ईस्टर पॉलीमर एडिटिव बनाने में कामयाब हुए वैज्ञानिक

जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे से निकलने वाले क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) से हमें पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। सर्दियों में क्रूड ऑयल के अधिक गाढ़ा होने या जमने के कारण धरती से बाहर निकालना बेहद कठिन हो जाता है। अक्सर तेल कंपनियों को इस कारण काम भी बंद करना पड़ता है। इसका समाधान धनबाद आइआइटी आइएसएम (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस) के वैज्ञानिकों ने तलाश लिया है।

पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. विकास महतो ने गहन शोध के बाद ऐसा पॉलीमर (कई अणुओं से मिलकर बना विशेष रसायन का बड़ा अणु) बना लिया है, जो ठंड में क्रूड ऑयल को न तो अत्यधिक गाढ़ा होने देगा न ही जमने देगा। इस पॉलीमर का प्रयोग कर ठंड में भी आराम से क्रूड ऑयल निकाला जा सकेगा। इस तकनीक को पेटेंट कराया गया है।

प्रो. महतो ने बताया कि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम होने के साथ ही कच्चा तेल गाढ़ा होने लगता है। ठंड में यह जम तक जाता है। तापमान जब 15 डिग्री से कम होने लगता है तब पाइप लाइन से इसे ऊपर लाना बेहद कठिन

आइएसएम धनबाद वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया पॉलीमर। जागरण

होता है। जमीन के अंदर गहराई के साथ तापमान बढ़ता है पर ऊपर आने के साथ यह घटता है। उनका कहना है कि कच्चे तेल को निकालने के लिए कई कंपनियां पाइप गर्म कर उसे निकालने का काम करती हैं, पर यह विधि बहुत अधिक कारगर नहीं है। इसमें ऊर्जा की काफी बर्बादी होती है और साथ ही लागत भी बढ़ जाती है। वहीं, इस नई तकनीक में 10 लाख मिली क्रूड ऑयल को बाहर निकालने में महज एक मिलीग्राम पॉलीमर की जरूरत होती है। इससे ऊर्जा और धन दोनों की बचत हो सकेगी।

ऐसे काम करेगी यह तकनीक : प्रो. महतो ने बताया कि कई परीक्षणों के बाद फैटी एसिड ईस्टर पॉलीमर एडिटिव बनाने में सफलता मिली है। कई अणुओं के संयोजन से इसे बनाया गया है। इस पॉलीमर के प्रयोग से तेल जहां से बाहर निकाला जाना है, वहां का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंचाया जा सकता है। इससे कच्चा तेल जब ऊपर लाया जाएगा तब अनुकूल ताप के कारण वह नहीं जमेगा। प्रो. महतो का कहना है कि तेल जमने के कारण ठंडे मौसम में अक्सर कंपनियां काम बंद करती हैं, तब उनको कई बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। यह तकनीक उनके नुकसान को बचाएगी।

गुणवत्ता पर असर नहीं : इस पॉलीमर के उपयोग से क्रूड ऑयल की क्वालिटी पर असर नहीं पड़ेगा। हल्दिया रिफाइनरी में इससे संबंधित परीक्षण किए गए। उनमें यह पॉलीमर पास हो गया। प्रयोगों से पता चला कि पॉलीमर के प्रयोग से कच्चे तेल की गुणवत्ता पर लेशमात्र भी असर नहीं हुआ है।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

मधुमक्खी के जहर से संक्रमण ठीक होने का दावा फर्जी

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

विश्वास न्यूज, जेएनएन: फेसबुक पर वायरल हो रही एक पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि मधुमक्खी के जहर वाली थेरेपी (इलाज) से सेल्यूलाइटिस संक्रमण ठीक हो सकता है। इस पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी साझा की गई है, जिसमें इलाज से घाव में सुधार होते भी दिखाया गया है। विश्वास न्यूज की पड़ताल में यह दावा फर्जी साबित होता है।

पड़ताल : विश्वास न्यूज की टीम ने मधुमक्खी जहर थेरेपी को इंटरनेट पर सर्च कर अपनी पड़ताल शुरू की। टीम को अमेरिका के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गनाइजेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक, 'इस थेरेपी में जीवित मधुमक्खियों का सीधे मरीजों पर इस्तेमाल किया जाता है। हिप्पोक्रेट्स (प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक) ने मधुमक्खियों के जहर के चिकित्सीय इस्तेमाल के बारे में बताया था। कई मधुमक्खी पालक मानते हैं कि इनका डंक रूमेटाइड अर्थराइटिस के इलाज में फायदेमंद है। हालांकि, यह परंपरागत रूप से माने जाने वाली बात है। यह डंक थेरेपी पुरानी, असाध्य बीमारियों में लाभ पहुंचाती है। मल्टीपल स्केरोसिस और रूमेटाइड अर्थराइटिस के कुछ पीड़ितों का यकीन है कि यह थेरेपी मदद करती है। हालांकि इसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद टीम को बीबीसी मॉनिटरिंग के वेबसाइट पर एक रिपोर्ट मिली। यह एक 55 साल की स्पैनिश औरत के मामले से जुड़ी रिपोर्ट है। महिला दो सालों से मधुमक्खी-डंक थेरेपी ले रही थी और उसे गंभीर रिएक्शन हो गया, जिससे उसकी मौत भी हो गई। इस अध्ययन को करने वाले शोधकर्ताओं ने मधुमक्खी डंक थेरेपी को 'असुरक्षित और अस्वीकार्य' बताया है। मेडिसिन साइंस इंटरनेशनल मेडिसिन जर्नल की एक केस रिपोर्ट के मुताबिक, 'मधुमक्खी के डंक से हुए रिएक्शन को दो ग्रुप, शुरुआती और बाद में बांटा जाता है। शुरुआती रिएक्शन 14 मिनट से 4 घंटे के बीच में शुरू होता है। इससे तेज एलर्जी होती है और मौत भी हो सकती है।' इसके मुताबिक, देर से होने वाले रिएक्शन 7-10 दिन बाद शुरू होता है। बाद में चलकर यह मायस्थेनिया ग्रेविस, मायोकार्डिटिस, पोलिसोमाइलाइटिस, पेरिफेरियल न्यूरिटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वास्कुलिटिस जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। टीम ने इस संबंध में एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के नेशनल प्वाइजन इंफॉर्मेशन सेंटर के डॉक्टर थॉमस से बात की। उन्होंने कहा, 'हम मधुमक्खी के जहर से इलाज को प्रोत्साहित नहीं करते, क्योंकि इससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है।' मधुमक्खी के जहर को मुख्य रूप से एंटी-इंफ्लेमेंट्री और दर्दनिवारक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कुछ देशों में अर्थराइटिस और दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए मधुमक्खी के डंक का इस्तेमाल एपिथेरेपी करने वालों द्वारा होता है। हालांकि, अभी इसकी पुष्टि के लिए काफी सबूतों की जरूरत है।

क्या है वायरल पोस्ट में?

Intuitive Apitherapy नाम के फेसबुक पेज पर इस पोस्ट को शेयर किया है। यह पोस्ट अंग्रेजी में है, जो कि हिंदी में कुछ इस प्रकार है, 'घाव ठीक नहीं हो रहा है? मधुमक्खी जहर थेरेपी से सेल्युलाइटिस संक्रमण ठीक हो सकता है। यह तस्वीर इस थेरेपी के पहले और बाद की है। इस दौरान कोई एंटीबॉयोटिक दवा नहीं ली गई है।

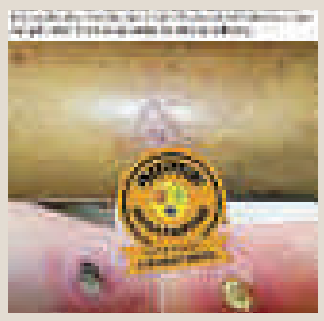

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें:
9205 270 923

बदलाव

अंग्रेजों के जमाने से विभाग में रही है उर्दू-फारसी भाषा की प्रधानता, एफआइआर व जीडी के ऑनलाइन होने से बदली भाषाई व्यवस्था

उप्र में टूट रहीं पुलिस महकमे की भाषाई बेड़ियां

आलोक मिश्र, लखनऊ

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिसिया तहरीर में उर्दू और फारसी शब्दावली से निजात पाने के लिए कहा है, हालांकि उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। अब बीए, एमए, पीएचडी से लेकर कंप्यूटर कोर्स करने के बाद पुलिस सेवा में आए युवाओं ने उर्दू-फारसी के ऐसे शब्दों के चक्रव्यूह से खुद को निकालना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन एफआइआर के सिस्टम ने तो थानों में लिखा-पढ़ी की परंपरागत शैली की रीढ़ ही तोड़ दी है। एडीजी (अभियोजन) आशुतोष पांडेय कहते हैं, 'यह समय की मांग है। इसके बिना हम मित्र पुलिस बन ही नहीं सकते। अदालतें भी अब सहज शब्दों को ही पसंद करती हैं। अभियोजन विभाग में भी लिखा-पढ़ी सरल हिंदी व अंग्रेजी भाषा में ही की जा रही है।'

अंग्रेजों ने बोई थी भाषा की यह फसल : अंग्रेजों के जमाने से पुलिस महकमे में उर्दू-फारसी भाषा की प्रधानता रही है। थाने के सबसे अहम दस्तावेज रजिस्टर नंबर आठ (ग्राम अपराध रिकार्ड पुस्तिका) में पहले सबकुछ उर्दू में ही दर्ज होता था। भाषाई गुलामी का आलम यह था कि किसी मुल्जिम के

प्रतीकात्मक

हवालात में खाना खाने से मना करने पर मुंशी लिखते थे कि 'मुल्जिम मुनकिर है। हश्त ख्वाहिश खुराक दी जाएगी'। इसका आशय यह था कि 'आरोपित ने खाना खाने से मना कर दिया, मांगने पर उसे भोजन दिया जाएगा।' 1965 के बाद थाने के ऐसे दस्तावेज में हिंदी भाषा का चलन बढ़ा। पुलिस में उच्च शिक्षा हासिल युवाओं की भर्तियों ने भी 2000 के बाद तस्वीर को तेजी से बदलना शुरू किया। इन युवाओं में अधिकांश को उर्दू आती भी नहीं थी।

कंप्यूटरीकरण ने दिलाई जटिल शब्दों से मुक्ति : 2011 में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम (सीसीटीएनएस) की अवधारणा के बाद थानों को कंप्यूटरीकृत करने की दिशा में कदम बढ़े। उत्तर प्रदेश में 2014 में पहली बार कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती हुई। कंप्यूटर ऑपरेटर के 2106 पद सृजित किए गए थे। वर्तमान में करीब 1900 कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं और करीब 650 की भर्ती इसी साल की गई है, जो जल्द पुलिस का हिस्सा होंगे। एडीजी (तकनीकी सेवाएं) असीम अरुण का कहना है कि उत्तर प्रदेश के सभी थानों को सीसीटीएसएन से जोड़ा जा चुका है और 2016 से एफआइआर रजिस्ट्रेशन, केस डायरी व जीडी की लिखा-पढ़ी कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन की जा रही है। इसकी भाषा हिंदी व अंग्रेजी है।

यह कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को (गत 25 नवंबर) को एक जनहित याचिका पर अहम टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था, एफआइआर दर्ज करने में उर्दू व फारसी शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। रिपोर्ट आसान भाषा में दर्ज की जानी चाहिए।

1995 से उर्दू अनुवादकों की भर्ती नहीं : पुलिस में पहले उर्दू अनुवादकों की भर्ती बेहद अहम थी। हालांकि, समय के साथ इनकी उपयोगिता कम होती चली गई। 1995 में अंतिम बार पुलिस में उर्दू अनुवादकों की भर्ती हुई थी।

यह थे पुलिसिया दस्तावेज के अनिवार्य शब्द

अदम तामील	सूचित न होना
अदम तकमीला	अंकन न होना
अदम मौजूदगी	बिना उपस्थिति
अहकाम	महत्वपूर्ण
गोस्वारा	नक्शा
फर्दअफराद	एक व्यक्ति
मालमसरूका	लूटी अथवा चोरी गई संपत्ति
मजरूब	पीड़ित
मुजामत	झगड़ा
मुचलका	व्यक्तिगत पत्र
रोजनामचाआम	सामान्य दैनिक
रोजनामचाखास	अपराध दैनिक
सफीना	बुलावा पत्र
हाजा	स्थान अथवा परिसर
नकल रपट	किसी लेख की नकल
नकल चिक	एफआइआर की प्रति
बाइस्तवा	शक
तरमीम	बदलाव करना अथवा बदलना

डीएनए बताएगा लद्दाख के द्रोपा मूल आर्यवंशी हैं या नहीं

सुमन सेमवाल, देहरादून

आर्य पहले भारतीय हैं या वह बाहर से आए, इस मुद्दे पर इतिहासकार भी भले ही एकमत न हों, लेकिन खुद को शुद्ध आर्यवंशी बताने वाले द्रोपा समुदाय के लोगों से इस रहस्य को सुलझाने में मदद मिल सकती है। भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (एएनएसआइ) विभाग ने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। एएनएसआइ के मानवविज्ञानियों ने खुद को मूल आर्यवंशी होने का दावा करने वाले द्रोपा समुदाय के लोगों के डीएनए सैंपल लिए हैं, ताकि स्पष्ट किया जा सके कि उनका मूल कहां से जुड़ा है।

एएनएसआइ के देहरादून स्थित उत्तरी केंद्र प्रमुख डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि लद्दाख के हनु गांव में रह रहे द्रोपा समुदाय के लोगों की डीएनए जांच के साथ ही उनके ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर आदि की भी जांच की जा रही है। इस समुदाय को डीएनए जांच के लिए इसलिए भी चुना गया, क्योंकि यहां के लोग मूल आर्यवंशियों के दावे के अनुरूप किसी अन्य समुदाय के साथ संबंध कायम नहीं करते हैं। जिस तरह से आर्यों के भारत के साथ संबंध को लेकर बहस कायम है, डीएनए जांच के बाद उससे भी पर्दा उठ जाएगा।

डीएनए जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि एक ही समुदाय में विवाह करने पर द्रोपा समुदाय के लोगों के जीन में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। विज्ञान कहता है कि वैवाहिक संबंध समुदाय से जितने भिन्न लोगों के साथ रखे जाएंगे, आगे की संतति के जीन की विविधता उतनी ही अधिक होगी, जबकि एक ही समुदाय में विवाह करने पर जीन में विकार उत्पन्न हो सकते हैं।

आर्यों के इतिहास पर यह हैं मत : इतिहासकारों का एक वर्ग यह कहता है कि भारतीय सभ्यता यहीं से निकली है और आर्य इसी का हिस्सा हैं। यही आर्य भारत से निकलकर एशिया व यूरोप के बड़े हिस्सों में फैल गए थे और इन्हीं से इंडो-यूरोपियन भाषाओं का विस्तार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार व शोध यह बताते हैं कि पिछले 10 हजार सालों में दो बार में बड़ी संख्या में लोग भारत आए।

दैनिक जागरण

सबरंग

प्लान वीकेंड के

नई दिल्ली, शुक्रवार, 29 नवंबर, 2019

सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com

https://www.facebook.com/jagransabrang/

इस बार यहां चलें

राह्ता में देखें अनोखे रंग

कैनवस पर खिंची लाइनें महज एक कलाकार की सोच भर नहीं है, अपितु ये दुनिया का नेतृत्व करती है। राह्ता में 35 कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। ये कलाकृतियां प्रकृति, मानवीय संवेदनाओं समेत रोजमर्रा की जिंदगी को संजीदगी से दर्शाती है।

- **कहां** : ऑल इंडिया फाइन एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
- **कब** : 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक, सुबह दस से शाम सात बजे तक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

कला साक्षी में दिखेगी रचनात्मकता

युवा कलाकारों को बढ़ावा देती यह प्रदर्शनी युवाओं के नजरिए से दुनिया को देखती है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए कॉलेज छात्रों की रचनात्मकता भी दिखेगी। कला साक्षी वर्कशॉप और प्रदर्शनी उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

- **कहां** : संस्कृति केंद्र, आनंदग्राम, एमजी रोड, नई दिल्ली। **कब** : 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक। **प्रवेश**-निश्शुल्क।

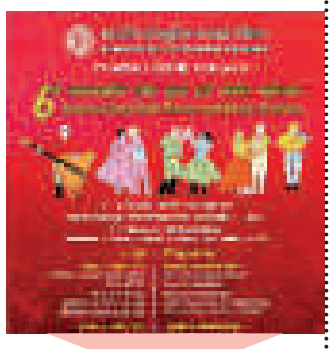

लोक नृत्य और संगीत समारोह

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आइसीसीआर) द्वारा आयोजित 6वां अंतरराष्ट्रीय लोक नृत्य और संगीत महोत्सव का आगाज होने वाला है। महोत्सव में कजाकिस्तान, हंगरी, तुर्कमेनिस्तान, लातविया, आर्मेनिया, दक्षिण अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, मोरक्को, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान के समूह भाग लेंगे।

- **कहां** : कमानी ऑडिटोरियम, मंडी हाउस, नई दिल्ली। **कब** : 2-4 दिसंबर, शाम साढ़े छह बजे। **प्रवेश** : निमंत्रण द्वारा।

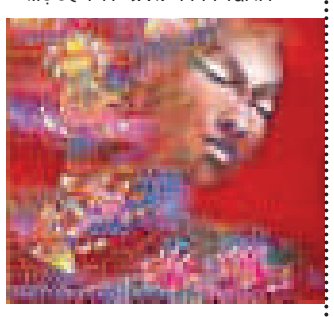

स्वयं की करें खोज

यह एक समकालीन कला शो है, जिसमें कलाकारों की रचनात्मकता और प्राकृतिक पूर्णता दिखती है। जो उन्हें बनाती है कि वे कौन हैं। इसे इस तरह से क्यूरेट किया गया है कि कोई भी इसका उपयोग स्वयं की खोज के लिए कर सकता है। लिविंग अनबाउंड विविध विषयों और स्वरूपों में दर्शकों से मुखातिब होता है।

- **कहां** : मॉर्डन आर्ट गैलरी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। **कब** : 30 नवंबर तक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

मैरो मार्ग स्थित हस्तशिल्प संग्रहालय में पेंटिंग बनाते दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट के छात्र-छात्राएं। जागरण

प्रदर्शनी

मन मस्त मगन
रंगों में घुला जाए रे...

रंगों का मिलन कराती है कूची...और इस मिलन का साक्षी बनता है कैनवस पर कोई विषय...इस सब को गढ़ने वाला...रूप रेखा देने वाला होता है कलाकार...। हस्तशिल्प संग्रहालय में ऐसे ही बहुत सारे कलाकार प्रकृति के आंगन में बैठ कुछ इसी तरह रंगों का मिलन करा रहे हैं...जिन रंगों में प्रकृति का सौंदर्य झलकता है...सबरंग के इस अंक में रंगों की ऐसी ही जीवंत दुनिया से रूबरू करा रहे हैं संजीव कुमार मिश्र :

दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट की छात्राएं...कोई अपनी पेंटिंग दिखा रही है और कोई शिद्दत के साथ रंगों को कैनवस पर सजा रही है। जागरण

हर रंग कुछ कहता है...प्रकृति के गीत कुछ यूं सुनाता है। जागरण

कौन आ रहा है कौन जा रहा है...कौन तुम्हे देख रहा है...कोई सुध बुध नहीं रहती इन युवाओं को बस मगन रहते हैं प्रकृति के हर सौंदर्य को अपने कैनवस पर सतरंगी रंगों में सजाने में। छात्रों की यह उत्सुकता दिखती है क्राफ्ट म्यूजियम के परिसर में चबूतरे पर चारों ओर समूहों में बैठे युवाओं में। मस्त मगन रंगों में घुले...हर कोई कैनवस पर सब कुछ उतार लाना चाहता है। कुछ जुदा कर जाने की चाह में कभी कैनवस ठीक करते हैं। कभी रंगों को सहेजते हैं कभी दिल्ली की बदली-बदली फिजाओं को महसूस करते हैं...मानो बदलते मौसम और आसमां के रंगों को कैनवस पर उतार लेना चाहते हैं। प्रकृति के विविध रूप उनकी आंखों में हैं जो बस कुछ ही देर में कैनवस पर उतर जाते हैं। और कैनवस पर रंगों के संगम में समाई प्रकृति को देख हर कोई आश्चर्य करता है...इस अप्रतिम सौंदर्य का मुरीद हो जाता है। और सबसे खास...दृश्य वो होता है जब दर्शक चकित रह जाते हैं सभी कैनवस पर सजे दृश्यों को एक साथ देखते हैं तो प्रकृति के विविध रूप संयुक्त होकर अलग ही आकर्षक दृश्यों को प्रस्तुत करते हैं। कैनवस पर जो तस्वीर उभरती है उसमें पेड़-पौधों से इतर एक चेहरा होता है...प्रकृति का चेहरा जिसमें झोपड़ियां उसकी आंखें थीं। पेड़ उसकी नाक एवं पक्षी उसका मुख बनाते हैं। इसमें चबूतरा भी उसके चेहरे का हिस्सा होता है। दरअसल ये युवा दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट द्वारा आयोजित आउटडोर स्केचिंग सेशन के तहत अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। जिसमें प्रसिद्ध आर्ट गुरु अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी ने छात्रों, युवाओं को कला की बारीकियां, आउटडोर स्केचिंग भी सिखाई।

स्वतंत्र है कला : यह 20वां वर्ष है, जब आउटडोर स्केचिंग का आयोजन किया जा रहा है। एक सप्ताह तक होने वाले इस आयोजन में छात्रों को बंद कमरे से इतर दिल्ली की खूबसूरती का दीदार करवाया जाता है। जिसे छात्र अपनी कूची से कैनवस पर उकेरते हैं। अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी बताते हैं कि कला किसी एक आदमी की नहीं है। यह स्वतंत्र होकर बहती है। यह खुद को व्यक्त करती है। सभी सीमाओं और युक्तियों को परिभाषित करती है। विभिन्न कल्पनाओं को आसानी से अंगीकार कर लेती है। वर्तमान समय में जब मनुष्य मशीन होता जा रहा है। मशीनी युग में कला ही है जो आत्मा को मशीन बनने से रोक सकती है। उससे शांत कर सकती है। उसकी कल्पनाओं को संजोए रख सकती है और उसे उस आत्मिक खुशी से मिला सकती है जो सुकून का पर्याय है।

कला निखर जाती है : एक रचनात्मक दिमाग में सैंकड़ों विचार एक समय में उपजते हैं। कैनवस पर सैंकड़ों रेखाएं बनती हैं। फिर भी इसे सुकून नहीं मिलता। वो कला के जरिए संसार को देखना, जानना, सुनना चाहता है। इसमें उसकी सहचर बनती है प्रकृति। क्योंकि प्रकृति ही है जिसके आगोश में कलाकार अपने सपनों की दुनिया बसाता है। इसलिए आउटडोर स्केचिंग सेशन आयोजित किए जाते हैं। जिसमें घंटों छात्र प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। दिल्ली में आउटडोर स्केचिंग नेशनल गैलरी फॉर मार्डन आर्ट, सफदरजंग मकबरा, इंडिया गेट, हस्तशिल्प और कला संग्रहालय जैसे ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर की गई है। बकौल पृथ्वीवासी आउटडोर सेशन पिछले 500 साल से ज्यादा समय से चलन में है। आप क्लासिकल, यूरोपियन आर्ट देखें तो शुरू-शुरू में लैंडस्केप को पेंटिंग में नहीं माना जाता था। जॉन कांस्टेबल ने इसे लोकप्रिय बनाया। जॉन यूनाइटेड किंगडम के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो लैंडस्केप पेंटिंग बनाते थे। इसके बाद बहुत से कलाकारों ने लैंडस्केप पेंटिंग बनानी शुरू की। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि कला को स्टूडियों में बैठकर नहीं गढ़ा जा सकता। अगर प्रकृति को दर्शाना है तो प्रकृति के बीच जाना होगा। बाहर निकल प्रकृति के आंगन को 360डिग्री में महसूस करना होगा।

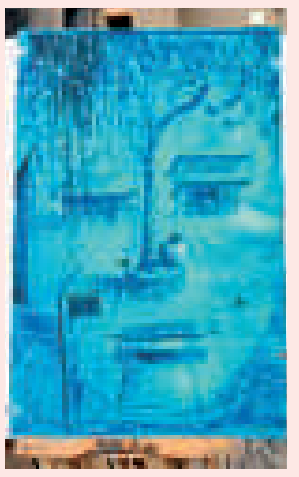

प्रकृति का खूबसूरत चेहरा

रेनू कहती हैं कि बंद कमरे में छात्र फोटो से पेंटिंग बनाते हैं। हम उन्हें बाहर लेकर आते हैं ताकि वो पेड़ पौधे, प्रकृति आदि के जरिए कला के विविध रूपों से रूबरू हों। यहां सेशन में पेंसिल, चारकोल, कलर से छात्रों को स्केचिंग करना बताया जा रहा है। छात्र यहां संग्रहालय के विविध हिस्से में जाकर विषयों की तलाश करते हैं एवं फिर उन्हें कैनवस पर उकेरते हैं। इसी कड़ी में छात्रों ने प्रकृति के विभिन्न रूपों को चुना। इसमें पेड़, पौधे, झोपड़ी आदि को चिन्हित किया एवं जब इन्हें एक कैनवस पर सेट किया तो एक चेहरा उभर कर सामने आया। जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर पेंटिंग गौर से देखें तो यह पेड़, चबूतरे, हरियाली, झोपड़ी यानी पर्यावरण के सम्मलित स्वरूप में मानव देखता है। यदि ऐसा सभी लोग मानने और जानने लगें तो पर्यावरण संरक्षण का संदेश चरितार्थ होगा। वहीं इसके पहले यानी रविवार को छात्रों ने चारकोल से संग्रहालय का जीवंत स्केच बनाया। बकौल रेनू यह लाइट एंड शैडो बनाया गया। जिसमें पेड़ों की छावं, झोपड़ी की श्वेत श्याम तस्वीर बनाई गई। वहीं सोमवार को सॉफ्ट पेस्टल माध्यम से ब्लैकशीट पर प्रकृति की खूबसूरती उभारी गई, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। रेनू की मानें तो यहां विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी पेंटिंग की बारिकियां सीखने आ रहे हैं। बच्चों ने इन विषयों को खूब पसंद किया। खुदको प्रकृति के करीब महसूस किया।

- **कहां** : हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम, भैरो सिंह मार्ग, प्रगति मैदान।
- **कब** : 1 दिसंबर तक, सुबह साढ़े ग्यारह से शाम चार बजे तक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।
- **नजदीकी मेट्रो स्टेशन** : प्रगति मैदान।

सबसे जुदा है तरुण का फूड फ्यूजन

शेफ अरुण सिबल। जागरण

जायका

जैसे-जैसे भौगोलिक-सांस्कृतिक परिवर्तन आते गए। अलग-अलग प्रांत के लोग शहर...राज्यों की सीमाओं से निकल दूसरी जगहों पर बसने लगे तभी से खानपान के प्रयोग भी निरंतर बढ़ गए। स्वाद की भी बेड़ियां टूटने लगीं। अब जरूरी नहीं बिहार का खाना वहीं के निवासियों को पसंद आए...वो दिल्ली को भी भाता है। अपने नए आइडियाज के साथ फूड इंडस्ट्री में आ रहे लोग इसे और बेहतर बना रहे हैं। ऐसे ही एक शेफ हैं तरुण सिबल। तरुण विभिन्न भारतीय व विदेशी रेस्त्रां व होटल्स का अनुभव लेने के बाद व्यंजनों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। साधारण तरीके व हेल्दी सामग्री के साथ हेल्दी फूड बनाना उनकी प्राथमिकता है। दिल्ली में पूसा संस्थान से डिग्री करने के बाद इंडिया हैबिटेट सेंटर से अपने करियर की शुरुआत की और फिर फ्रेंच एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से इंटरनेशनल फूड और वेबरेज बोर्ड में काम किया। इसके अलवा आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया फूड बोर्ड में काम किया। देश-विदेश की यात्राओं के बाद नए-नए व्यंजनों पर काम किया और लोगों तक पहुंचाया। कोलाब्रेटिव क्यूजीन के नाम से व नई-नई डिशेज बना रहे हैं। कई रेस्त्रां के शेफ सलाहकार भी रहे हैं।

केटरिंग के पारिवारिक व्यवसाय के कारण जुड़ा किचन से नाता : केटरिंग के व्यवसायी परिवार से आने वाले तरुण खान-पान को लेकर बचपन से ही विशेष शौक रखते थे। उन्होंने शुरुआती दौर में ही सोच लिया था कि भारतीय लोगों तक बेहतरीन स्वाद पहुंचाया जाए। तमाम शोधों के बाद उन्होंने अपनी नई डिशेज क्रिएट की। खाने के लिए केवल डिग्री काफी नहीं थी, उन्होंने खूब भ्रमण किया और हर तरह की डिश के स्वाद चखा और उसमें बदलाव किए।

फ्यूजन से एक कदम आगे : दो डिशेज के मिक्चर से फ्यूजन डिशेज बनती है लेकिन तरुण फ्यूजन से कुछ अलग हटकर करते हैं। इसके लिए उन्होंने 'कोलाब्रेटिव क्यूजीन' का कॉन्सेप्ट इजाद किया है। वे भारतीय लोगों के स्वाद को ध्यान में रखते हुए डिशेज को बनाते हैं। तरुण का कहना है कि फ्यूजन में दो प्रकार के डिशेज को इंफ्यूज किया जाता है जबकि वे अपनी डिशेज में एक क्यूजीन की बेसिक डिश लेकर अन्य क्यूजीन की डिशेज के साथ एक प्लेट पर लाते हैं। जैसे वे इंडियन बटर चिकन डिश के साथ इटालियन ब्रेड या मैक्सिकन रोटी के विकल्प के साथ परोसते हैं। इससे भारतीय स्वाद के साथ विदेशी जायका मिल सकता है। वन फाइन मील के निदेशक तरुण ने सर्दी के मौसम को देखते हुए विशेष डिशेज की रेसिपी बताई ताकि लोग इस मौसम में इन चीजों का स्वाद नए अंदाज में ले सकें

चार पत्तों का साग :सामग्री : सरसो पत्तों, बथुआ, पालक पत्तों का एक एक गुच्छा, एक कप कटे हुए मेथी के पत्ते, दो मध्यम आकार के प्याज, तीन मध्यम आकार के टमाटर, दो इंच का अदरक कटा हुआ, दो कटी हरी मिर्च, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हींग, दो से तीन कप पानी, दो चम्मच मक्के का आटा, नमक स्वादानुसार। इसके अलावा बारीक कटा हुए एक प्याज, एक से दो चम्मच तेल, तीन कटोरियां उबला साग लेते हैं।

घर भी ऐसे करें तैयार : सभी पत्तों को साफ करके काटकर धो लें। कुकर में मक्के केआटे के अलावा अन्य सभी चीजों को मिक्स कर लें कुछ देर पकांए। फिर इसे ठंडा होने पर मिक्सर में पीस लें। इसे अलग कड़ाही में डालकर 15 से बीस मिनट तक पकाएं। एक कड़ाही में तेल गरम करके तेल या घी डालकर गरम करें। इसमें साग डालकर बटर, अदरक और हरी मिर्च से सजाएं।

– प्रियंका दुबे मेहता

एवोकाडो टोस्ट

चिकन कॉर्न सूप

सामाग्री : ग्रिल्ड चिकन स्लाइस (250 ग्राम), दो अंडे, पांच ग्राम कटे प्याज, एक ग्राम लहसुन, पांच एमएल एलापीनो ब्राइन, बटर, नमक, काली मिर्च, फेनल पिकल, 200 ग्राम उबला हुआ ताजा कॉर्न।

विधि : ऑलिव ऑइल में कटे हुए प्याज व लहसुन को भुनें। इसमें ताजा कॉर्न, नमक, काली मिर्च, एलापीनो डालिए। अब इसे ठंडा होने दें। इसके बाद इसे पीस लें। इसे दोबारा से गरम करके इसमें बटर डालें। इसमें ग्रिल्ड चिकन को मिलाएं। और फ्राइड अंडे, फनल पिकल (नमक, चीनी, सिरका व नमक डालकर बनाया गया) डालें।

दिल्ली की गलियों में ही जिंदगी पली-बढ़ी

बातचीत

पद्म भूषण उस्ताद अमजद अली खान तहजीब और मौसिकी की मिसाल हैं। जब इनकी अंगुलियां सरोद के तारों की छूती हैं तो संगीत की एक नई धारा बह निकलती है। संगीत की अनूठी लयकारी और तंत्रकारी सुन दर्शक भी संगीत रस में डूबते जाते हैं। साहित्य कला परिषद द्वारा सुंदर नर्सरी में आयोजित शास्त्रीय संगीत महोत्सव की शुरुआत उनकी ऐसी ही बेमिसाल प्रस्तुति से हुई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उस्ताद को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबसे आखिर में प्रस्तुति का मौका मिलता था। दिल्ली समेत कला, संस्कृति से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में उस्ताद अमजद अली खान ने संजीव कुमार मिश्र से खुलकर बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :

• दिल्ली में आपने बहुत से कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी हैं, शुरुआती दिनों के अनुभव किस तरह के थे?

वैसे तो दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल हो चुका हूं, लेकिन पहली बार जब एक कार्यक्रम में शरीक हुआ तब मेरी उम्र 16 साल की थी। वह एक शैक्षणिक कार्यक्रम था, जिसमें मैंने पहली प्रस्तुति दी थी। शुरुआती दिनों में मुझे सबसे आखिर में प्रस्तुति का मौका मिलता था। उन दिनों एक से अधिक दिनों के फेस्टिवल होते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि सबसे आखिर में रात के दो बजे मुझे प्रस्तुति का समय मिला। मेरा नंबर आते आते दर्शक ही चले जाते थे। ऐसा काफी दिनों तक हुआ। बाद में एक आयोजक से मैंने कहा कि लोग मुझे देखने सुनने आते हैं, लेकिन मेरा नंबर सबसे आखिर होने के कारण उन्हें मायूसी हाथ लगती है। इसलिए कृपया मुझे समारोह में पहली प्रस्तुति का मौका दिया जाए।

• सुंदर नर्सरी में आपकी प्रस्तुति हुई। निजामुद्दीन से किस तरह की यादें जुड़ी हैं?

इसी इलाके के इर्द गिर्द तो हमारी जिंदगी पली-बढ़ी है। एक समय हम लोग निजामुद्दीन वेस्ट में रहते थे। मेरे पिता हजरत अमीर खुसरो के डिवोटी थे। पिता जी का सन् 1972 में स्वर्गवास हो गया। उनकी इच्छा थी कि खुसरो के आसपास ही उनकी समाधि बनाई जाए। निजामुद्दीन दरगाह के पास लोदी होटल के सामने जो मंदिर है उसके पीछे उनकी समाधि है। दरअसल, वो सूफी मत से बहुत प्रभावित थे। सूफी मत के लोग हर धर्म की इज्जत करते हैं। इसी कड़ी में एक बात और बताना चाहता हूं। मैं डेढ़ महीने बाद अमेरिका से दिल्ली लौटा हूं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में परिचर्चा हुई, जिसका विषय दुनियाभर में हो रही लड़ाईयां थीं। इस परिचर्चा में यह बात निकलकर सामने आई कि व्यक्ति दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करता। मैं अपने आप को इस मामले में खुशनसीब मानता हूं। मैं हर धर्म से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मेरे दर्शक हर जाति-धर्म के हैं। मैंने चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे, हर जगह प्रस्तुति दी है।

• दिल्ली के दर्शकों के बारे में क्या कहेंगे?

जहां तक मैंने महसूस किया है महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के दर्शक शास्त्रीय संगीत के प्रति बहुत गंभीर होते हैं। वे कार्यक्रम बड़ी तल्लीनता से देखते सुनते हैं। उनके मुकाबले दिल्ली के दर्शक अपेक्षाकृत कम गंभीर होते हैं। हालांकि कई बार कार्यक्रमों में बहुत अच्छे श्रोता भी मिल जाते हैं।

• हाल के वर्षों में दिल्ली को किस तरह बदलते देखा है?

इतिहास में मैंने इतना ज्यादा प्रदूषण नहीं देखा। दरअसल जो भी सरकारें आती हैं अपने एजेंडे में इतना उलझ जाती है कि पर्यावरण की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। प्लास्टिक हानिकारक है, लेकिन इसका उत्पादन आज भी हो रहा है। ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। प्रदूषण का सबसे बुरा असर तो छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। इसकी वजह से स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। लेकिन यह समाधान नहीं है। विदेश की तरह आर्टिफिशियल बारिश भी नहीं होती। प्रदूषण को रोकने के लिए रिसर्च करना होगा। इसे रोकने के लिए सरकार को हरसंभव कोशिश करनी होगी। इस संदर्भ में स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ करनी होगी कि प्रधानमंत्री की इस पहल से शहरों की सूरत बदल रही है।

• आप दिल्ली से जुड़े रहे हैं। यहां कहां घूमना या खाना पसंद है?

हमारी परवरिश तो मां के हाथों के पराठे, दूध, दही, रबड़ी खाकर हुई है। लेकिन मुझे पुरानी दिल्ली घूमना बहुत पसंद है। यहां बेडमी पूड़ी, आलू की सब्जी, हलवा और चाट अच्छे लगते हैं। करीम का लाजवाब जायका भी पसंद है। जामा मस्जिद के इर्द गिर्द खाने की कई अच्छी दुकानें हैं। अब तो हम कार्यक्रमों के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहते हैं। ऐसे में कई बार बर्गर, पिज्जा भी खा लेते हैं।

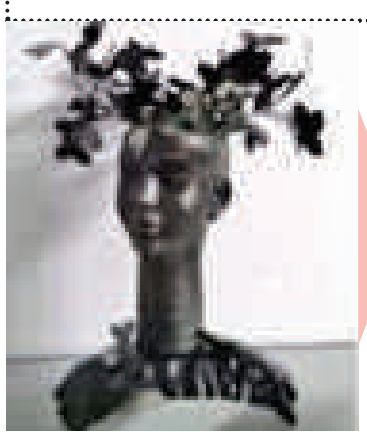

आत्मविश्वास एवं विनम्रता

सीमा सिंह दुआ की कलाकृतियां मानों जिंदगी का पन्ना पलटती हैं। वो रोजमर्रा की जिंदगी से चुनकर विचारों को कैनवस पर प्रदर्शित करती हैं। ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी इन कलाकृतियों के जरिए एक कहानी सुनाती है। आत्मविश्वास और विनम्रता को कलाकृतियां बड़ी संजीदगी से दर्शाती हैं।

- **कहां** : ललित कला अकादमी, मंडी हाउस, नई दिल्ली।
- **कब** : 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक, सुबह 11 से शाम सात बजे तक। **प्रवेश** : निश्शुल्क।

बैंड बाजा बरात

नॉर्थ इंडियन, चाइनीज और कांटिनेंटल का स्वाद चखने का मन हो तो बैंड बाजा बारात हो आएं। यहां पनीर टिक्का, दाल मखनी, गोल गप्पा, बटर चिकन, गुलाब जामुन, पालक पत्ता चाट, शाही टुकड़ा लाजवाब है। मेन्यू में कई और भी जायके हैं, जो ग्राहकों को दिल्ली-एनसीआर से यहां खींच लाते हैं।

- **कहां** : विशाल एंकलेव, राजौरी गार्डन, पश्चिमी दिल्ली। **कब** : दोपहर 12 से शाम चार, शाम सात से रात 12 बजे तक।
- **शुल्क** : 351 रुपये से शुरू।

भल्ला किंग

भल्ला किंग अपने क्वीक बाइट के लिए जाना जाता है। यहां स्ट्रीट फूड की वैरायटी ग्राहकों को लुभाती है। पाव भाजी, दही भल्ले, राज कचौरी, पालक चाट, देशी बर्गर, भल्ला पापड़ी और टिक्की की लोकप्रियता ऐसी है कि दूर दराज से भी लोग इसका सुस्वाद लेने आते हैं।

- **कहां** : सेंट्रल मार्केट, लाजपत नगर पार्ट 2, दक्षिणी दिल्ली।
- **कब** : सुबह दस से रात 12 बजे तक।
- **शुल्क** : प्रति दो व्यक्ति 150 रुपये से शुरू।

भारत में करीब पांच लाख करोड़ रुपये निवेश करेंगे सऊदी, यूएई

दुबई, एपी : सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भारत में 7,000 करोड़ डॉलर (करीब पांच लाख करोड़ रुपये) की योजना पर विचार कर रहे हैं। दोनों देश महाराष्ट्र में इस निवेश से एक पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। यह रकम इससे पहले घोषित 4,400 करोड़ डॉलर (करीब तीन लाख करोड़ रुपये) के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस बारे में बुधवार शाम को यूएई के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान और अबुधाबी के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन जायेद अल नाहयान के बीच बातचीत हुई।

हेल्थकेयर सेक्टर में पारदर्शिता और नैतिक आचरण की बेहद जरूरत है। हम मानते हैं कि इस बारे में एक कोड ऑफ एथिक्स होना ही चाहिए।
– सुदर्शन बल्लाल
चेयरमैन, मनीपाल हेल्थ इंटरप्राइजेज

सेंसेक्स	41,130.17 ▲ 109.56	निफ्टी	12,151.15 ▲ 50.45	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 38,535 ▼ ₹3	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 45,293 ▼ ₹91	$ डॉलर	₹ 71.62 ▲ ₹0.27	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 63.59

ठेका कर्मियों के वेतन के लिए बीएसएनएल जिम्मेदार नहीं

- टेलीकॉम मंत्री ने कहा – ठेका कर्मचारी अपने ठेकेदार से करें वेतन की मांग
- बीएसएनएल व एमटीएनएल को फिर बताया रणनीतिक संपत्ति

नई दिल्ली, आइएएनएस : बीएसएनएल और एमटीएनएल में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को अपनी चिंता खुद करनी पड़ेगी। आइटी व टेलीकॉम मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने गुरुवार को संसद में बताया कि इन दोनों कंपनियों में जो भी कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे हैं, उन्हें वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान करने की जिम्मेदारी ठेकेदारों की है, इन दोनों कंपनियों की नहीं। प्रसाद सरकारी टेलीकॉम कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

टेलीकॉम मंत्री ने दो-टूक कहा कि ठेका कर्मचारी उन ठेकेदारों के कर्मी हैं, जिन्हें बीएसएनएल या एमटीएनएल ने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति की जिम्मेदारी दी है। उनके ठेकों का नवीकरण कंपनी की जरूरतों पर निर्भर करता है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक उन कर्मियों को वेतन भुगतान की बात है, तो यह पूरी तरह से उन ठेकेदारों की जिम्मेदारी है।

प्रसाद ने बताया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की वीआरएस बेहतरीन है। यही वजह है कि अब तक बीएसएनएल के 79,000 कर्मी इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। एमटीएनएल के 20,000 में से 14,000 कर्मचारियों ने अब तक वीआरएस के लिए आवेदन दाखिल कर दिया है। एक अन्य सवाल के जवाब में प्रसाद ने दोहराया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल देश की रणनीतिक संपत्तियां हैं। इसलिए सरकार ने इनके पुनरोद्धार का फैसला किया है।

इस बीच, टेलीकॉम क्षेत्र के सूत्रों का कहना है कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) स्पेक्ट्रम नीलामी की योजना को अगले महीने अनुमोदन के लिए कैबिनेट के पास भेज सकता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 5-जी और अन्य स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वर्ष मार्च में लक्षित है।

दो दर्जन बड़ी एनबीएफसी को राहत की तैयारी

एनबीएफसी के एनपीए को एक विशेष कंपनी में ट्रांसफर करने की सरकार की योजना है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- घरेलू मांग बढ़ाने के उपायों पर सरकार व आरबीआइ के बीच चल रही मंत्रणा
- होम व ऑटो लोन की रफ्तार नहीं बढ़ने के पीछे एनबीएफसी का एनपीए भी एक बड़ा कारण

प्रतीकात्मक

सरकार खुलकर यह बात स्वीकार नहीं करती है कि घरेलू मांग की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। लेकिन वह जिन उपायों पर फिलहाल विचार कर रही है, वे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मांग में गिरावट की बात को सही माना जा रहा है। तभी वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के बीच इस बात के लिए जबरदस्त मंत्रणा चल रही है कि देश की 25 बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की फंसी परिसंपत्तियों यानी एनपीए को बचाया जाए। योजना यह है कि आरबीआइ एक विशेष कंपनी का गठन करे, जो देश की शीर्ष एनबीएफसी से उनकी समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों को खरीद सके। इस तरह से एनबीएफसी के सिर से एक बड़ा बोझ खत्म हो जाएगा और वे जनता या उद्योग को कर्ज उपलब्ध कराने के काम पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगी।

दरअसल, पिछले वर्ष के अंत में जब देश की बड़ी एनबीएफसी आइएलएंडएफएस में वित्तीय घोटाला सामने आया था, तभी से आरबीआइ के स्तर पर देश की सभी शीर्ष 50 एनबीएफसी की गतिविधियों और उनके वित्तीय मानकों की निगरानी की जा रही है। वैसे इस निगरानी के बावजूद एक और एनबीएफसी डीएचएफएल भी न केवल गहरी समस्या में समा चुकी है, बल्कि इसके प्रबंधन को भी आरबीआइ निरस्त कर चुका है।

बहरहाल, वित्त मंत्रालय और आरबीआइ के बीच देश के एनबीएफसी सेक्टर को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं उसमें यह बात सामने आई है कि अगर एक अलग कंपनी बनाकर बड़ी कंपनियों की सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों को एक जगह कर दिया जाए, तो भविष्य में इनका प्रबंधन आसान हो जाएगा। इसका दूसरा फायदा यह होगा कि एनबीएफसी के लिए बैंकों से कर्ज लेना और उसे होम व ऑटो लोन ग्राहकों को बांट पाना आसान हो जाएगा। अभी समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों के बोझ के चलते एनबीएफसी की समूची गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। इसकी वजह से ना तो वो बैंकों से कर्ज ले पा रहे हैं और ना ही कर्ज वितरण का काम सही तरीके से कर पा रहे हैं। ऑटो लोन और होम लोन की रफ्तार मनमाफिक नहीं बढ़ पाने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि एनबीएफसी की तरफ से ये कर्ज नहीं बांटे जा रहे हैं। इनकी तरफ से ज्यादा कर्ज बांटने से आवासीय इकाइयों और कारों की बिक्री बढ़ सकती है जो घरेलू मांग को बढ़ाने में सहायक साबित होंगी।

एनबीएफसी के लिए भविष्य में समस्या पैदा होने वाली परिसंपत्तियों को खरीदने की योजना का संकेत स्वयं आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में दिया था। अहमदाबाद में एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, 'आइएलएंडएफएस संकट और कुछ दूसरी कंपनियों की तरफ से अदायगी में आ रही दिक्कतें काफी चिंताजनक है। परिसंपत्तियों को लेकर नई चिंताएं सामने आ रही हैं। इससे एनबीएफसी के लिए तरलता संकट पैदा हो गया है। आरबीआइ इस संकट को दूर करने के लिए कई विकल्पों पर विचार रहा है ताकि एनबीएफसी की स्थिति को मजबूत किया जा सके और इसमें नियमन को भी बेहतर किया जा सके।'

आरबीआइ गवर्नर के इस बयान के कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने दिवालिया कानून में एक बड़ा बदलाव करते हुए एनबीएफसी को भी इसके तहत शामिल करने का फैसला किया था। इसके पहले केंद्रीय बैंक ने इस सेक्टर में फंड उपलब्धता से जुड़े जोखिम संबंधी नियमों को लेकर नया दिशानिर्देश जारी किया था। माना जा रहा है कि एक अलग नई कंपनी बनाकर उसमें समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों को ट्रांसफर करने का कदम इस दिशा में एक अहम एलान साबित होगा।

न्यूज गैलरी

यूपीआइ से होने वाले लेनदेन में 183 परसेंट का इजाफा

नई दिल्ली : चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) के माध्यम से 270 करोड़ लेनदेन हुए हैं। यह संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि से 183 परसेंट अधिक है। इस दौरान कुल 4.6 लाख करोड़ रुपये का मूल्य का लेनदेन हुआ है, जो कि पिछले वर्ष से 189 परसेंट अधिक है। (आइएएनएस)

सरकारी गैर-टेलीकॉम कंपनियां फोरम बनाने पर कर रहीं विचार

नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां एजीआर मामले में दूरसंचार विभाग के विरोध में फोरम बनाने पर विचार कर रही हैं। इस फोरम में पावर ग्रिड, रेलटेल, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड और डीएमआरसी शामिल होंगी। ये कंपनियां अपने सीमित टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाओं के लिए अतिरिक्त लाइसेंस नहीं लेना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एजीआर मामले में फैसला सुनाया था, जिसके बाद कंपनियों के ऊपर लाइसेंस फीस का भार है। (आइएएनएस)

एयरसेल का स्पेक्ट्रम, लाइसेंस रद ना करे डीओटी

मुंबई : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने एयरसेल के स्वामित्व वाला स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम लाइसेंस रद करने पर रोक लगा दी है। एनसीएलटी ने गुरुवार को कहा कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा एयरसेल से एजीआर मद में बकाये की मांग से ऐसा संदेश गया है कि विभाग कंपनी का टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम रद कर सकता है। इस अंदेशे के आधार पर एयरसेल ने रोक की याचिका दायर की है, जिस पर डीओटी को यह आदेश जारी किया जा रहा है। हालांकि एनसीएलटी ने यह भी कहा कि लाइसेंस और स्पेक्ट्रम सरकार की संपत्ति है, लिहाजा डीओटी दूरसंचार नियामक ट्राई या टेलीकॉम विवाद निपटान प्राधिकरण टीडीसैट में याचिका दायर कर सकता है। (प्रेट्र)

सोना लगभग सपाट, चांदी 91 रुपये फिसली

नई दिल्ली : गुरुवार के कारोबार में सोना तीन रुपये की मामूली गिरावट के चलते 38,535 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। चांदी को भी खरीदारों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की वजह से 91 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट का सामना करना पड़ा। कारोबार के आखिर में चांदी 45,293 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर स्थिर हुई। जानकारों का मानना था कि हांगकांग में लगातार चल रहे प्रदर्शनों और अमेरिका-चीन कारोबारी रिश्तों को लेकर असमंजस की स्थिति से भी विदेशी बाजारों में इस पीली धातु के भाव अस्थिर रहे हैं। (प्रेट्र)

जीएसटी में ई-इनवॉयसिंग से खुलेंगे एमएसएमई के लिए कर्ज के रास्ते

फायदा ▶ कारोबारियों की बढ़ेगी सहूलियत, अगले वर्ष से रिटर्न भरने में भी होगी आसानी

पहली जनवरी से 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य होगी

नितिन प्रधान, नई दिल्ली

अगले वर्ष पहली अप्रैल से हर कंपनी के लिए ई-इनवॉयसिंग अनिवार्य होगी। प्रतीकात्मक

अगले वर्ष की शुरुआत से जीएसटी में लागू हो रहे ई-इनवॉयसिंग सिस्टम से एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंकों से कर्ज लेना और आसान हो जाएगा। यह सिस्टम कर्ज देने के लिए बैंकों की आवश्यक कागजी प्रक्रिया को सीमित करेगा। बैंक ई-इनवॉयसिंग के जरिये लघु और मझोली इकाइयों की रेटिंग कर सकेंगे। सभी तरह की इकाइयों के लिए अप्रैल, 2020 से ई-इनवॉयसिंग की व्यवस्था लागू हो जाएगी।

छह महीने की तैयारी के बाद सरकार बिजनेस-टु-बिजनेस इनवॉयसिंग के लिए इस सिस्टम को लागू कर रही है। 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए पहली जनवरी, 2020 से ई-इनवॉयसिंग की व्यवस्था लागू करने जा रही है। हालांकि अभी यह स्वेच्छा से और प्रायोगिक आधार पर होगा। सौ करोड़ रुपये या इससे अधिक कारोबार वाली इकाइयां पहली फरवरी, 2020 से ई-इनवॉयसिंग कर पाएंगी। अप्रैल, 2020 से सभी कंपनियों के लिए लागू होने के बावजूद सौ करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली इकाइयों के लिए ऐसा करना स्वैच्छिक होगा।

जीएसटी के एक अधिकारी के मुताबिक ई-इनवॉयसिंग सिस्टम को लागू करने के पीछे दरअसल सरकार की मंशा जीएसटी करदाताओं की सहूलियतों में इजाफा करना और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था को और आसान बनाना है। इससे करदाताओं को रिटर्न भरने में सुविधा रहेगी, क्योंकि उन्हें रिटर्न तैयार अवस्था में मिलेगा। इससे समाधान संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी। ई-इनवॉयस के जरिये सरकार टेक्नोलॉजी की मदद से ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन की सुगमता और बिजनेस की भावना को मजबूती देना चाहती है।

कारोबारियों के लिहाज से इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इस सिस्टम में इनवॉयस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उपलब्ध होगा। इसे किसी भी सिस्टम पर पढ़ा जा सकेगा और सेंट्रल सिस्टम पर इसकी रिपोर्टिंग भी संभव हो सकेगी। अभी तक जीएसटी में इनवॉयसिंग को लेकर यही सबसे बड़ी दिक्कत थी कि अलग अलग फॉन्ट और सिस्टम में तैयार होने वाले इनवॉयस केवल उसी प्रकार के सिस्टम पर खोले जा सकते थे। लेकिन अब सभी एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नए ई-इनवॉयस को अपना सकेंगे।

नए सिस्टम में ई-इनवॉयस जनरेट करने की जिम्मेदारी कारोबारी अथवा करदाता की होगी जिसे जीएसटी के इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा। यह पोर्टल एक यूनिक इनवॉयस रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा और डिजिटल साइन वाले इनवॉयस के साथ क्यूआर कोड भी उपलब्ध कराएगा। सिस्टम के जरिये यह क्यूआर कोड इनवॉयस जनरेट करने वाले टैक्सपेयर के पास वापस आ जाएगा, जिसमें ई-इनवॉयस और रिटर्न की समस्त जानकारी होगी।

ई-इनवॉयसिंग अपनाने वाले छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए जीएसटीएन ने विशेष प्रबंध किए हैं। जिन कारोबारियों के पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा वे जीएसटीएन से सम्बद्ध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकेंगे। जीएसटीएन ने एकाउंटिंग और बिलिंग से संबंधित आठ सॉफ्टवेयर एम्पैनल किये हैं।

सरकार ने रखी 21,246 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा में मांग रखती सीतारमण। एएनआइ

- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए 8,820.62 करोड़ रुपये का प्रावधान
- आइडीबीआइ बैंक के रि-कैपिटलाइनजेशन के लिए 2,500 करोड़ रुपये की मांग

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने संसद से 21,246.16 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की मांग की है। इसमें 8,820.62 करोड़ रुपये की राशि हाल ही में गठित दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए है। इस आशय की अनुपूरक मांगें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश की। इसमें कुल 18,995.51 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

चालू वित्त वर्ष के लिए ये पहली अनुपूरक मांगें हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख इसी महीने नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। इससे पहले पूरे जम्मू-कश्मीर के लिए 14वें वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की थीं, बदली परिस्थितियों में उस गणना के हिसाब से अब इस केंद्र शासित प्रदेश को 8,820.62 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाना है। इसके अतिरिक्त रिकैपिटलाइजेशन बांड्स के जरिये आइडीबीआइ बैंक को 4,557 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जानी है। इसका प्रावधान भी पूरक मांगों में किया गया है। साथ ही 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान बीमा कंपनियों के पूंजीकरण के लिए किया गया है। केंद्र सरकार ने इस साल जुलाई में पेश बजट में 27.86 लाख करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया था। इसमें सरकारी कंपनियों का खर्च शामिल नहीं है।

अनुदान की पूरक मांगों की पहली किस्त में वित्त मंत्री ने सैन्य बलों के वेतन और भत्तों के अतिरिक्त खर्च की पूर्ति के लिए 1,500 करोड़ रुपये की मांग भी की है। इसके अलावा अंतरिक्ष विभाग के लिए अतिरिक्त 666 करोड़ रुपये का प्रावधान पूरक मांगों में किया गया है।

गृह मंत्रालय के मद में 3,387.46 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान पुलिस के वेतन और राशन की लागत के व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है। देश में गरीब परिवारों के लिए एलपीजी उपलब्ध कराने के व्यय को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की मांग रखी गई है।

जानकारों का कहना है कि टैक्स रेवेन्यू की धीमी रफ्तार के चलते सरकार को खर्च पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। अनुदान की पूरक मांगों के तहत सरकार इसी अतिरिक्त खर्च की मांग संसद से करती है। आमतौर पर सरकार दो किस्तों में पूरक मांगें रखती है।

इंडियाबुल्स के वित्तीय उल्लंघनों की पड़ताल कर रही सरकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आइबीएचएफएल) और इंडियाबुल्स वेंचर लिमिटेड (आइबीवीएल) में हुए उल्लंघन के संबंध में दो निरीक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा कथित वित्तीय अनियमितता को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस सी. हरिशंकर की पीठ के समक्ष हलफनामा दाखिल कर उक्त जानकारी दी।

गैर सरकारी संगठन सिटिजन व्हिसलब्लोअर फोरम की तरफ से दायर जनहित याचिका पर कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने यह भी बताया कि आबीवीएल एवं आइबीएचएफएल द्वारा उल्लंघन के संबंध में 19 नवंबर एवं 15 नवंबर को हुए निरीक्षण की रिपोर्ट मिल चुकी है, जबकि तीसरे निरीक्षण की रिपोर्ट अभी भी इंडियाबुल्स की तरफ से मंत्रालय को नहीं मिली है।

याचिका में आइबीएचएफएल द्वारा पांच कंपनियों को दिए गए जिस लोन का जिक्र किया गया है। उस पर निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार तीन कंपनियों को री-पेड लोन दिया गया, जबकि दो कंपनियों को दिए गए लोन को स्टैंडर्ड-एकाउंट बताया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि इसके अलावा रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। इससे पहले अक्टूबर माह में दाखिल किए गए शपथ-पत्र में मंत्रालय ने कहा था कि ग्रुप के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं और इसमें कुछ का निरीक्षण भी किया गया है।

नई टेक्नोलॉजी से मिलेगी ऑटोमोबाइल को गति

यशलोक सिंह, गुरुग्राम

- विशेषज्ञों ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बदलती जरूरतें पूरी करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को अहम बताया
- टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के माध्यम से ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भविष्य की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी

प्रतीकात्मक

आइएमटी मानेसर स्थित नेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव (आइकेट) में गुरुवार को न्यू जेन मोबिलिटी समिट-2019 के दूसरे दिन ऑटोमोबाइल क्षेत्र के दिग्गजों ने 'इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑटोनॉमस व्हीकल्स' विषय पर मंथन किया। इस दौरान ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए भविष्य की संभावनाओं एवं टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। जानकारों का कहना था कि विकसित देशों में आज के दौर में कार एक बड़ी स्मार्ट डिवाइस के तौर पर अपनी पहचान बना रही है। ईंधन की बचत, सर्विसिंग, दुर्घटना से बचाव और सुरक्षित चालन से संबंधित टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ती जा रही है। भारत में भी इनकी मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है।

आयोजन के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर वर्तमान में ऑटोमोबाइल क्षेत्र की चुनौतियां तेजी से बढ़ी हैं। इससे निपटने के लिए इस क्षेत्र की इंडस्ट्री को अपनी सोच और कार्यप्रणाली में बदलाव की बड़ी जरूरत है। टेक्नोलॉजी के बिना किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि भविष्य की सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक जरूरतों के अनुरूप टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को विकसित करने की जरूरत है। ऐसा होने पर ही यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा और मजबूती मिलेगी।

वक्ताओं ने कहा कि विकसित देशों द्वारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी का तेजी से इस्तेमाल बढ़ा है। इसलिए देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान जैसे देशों में ऑटोमोटिव क्षेत्र और टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल का रिवाज देखा जा रहा है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। जानकारों का यह भी कहना था कि वायु प्रदूषण के मामले में देश में स्थिति साल-दर-साल चिंताजनक होती जा रही है। ऐसे में पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों को लेकर परिवेश में तेजी से बदलाव हो रहा है। इलेक्ट्रिक इंजन वाले वाहनों की ओर से सरकार भी विशेष ध्यान दे रही है। ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजी के जरिए ही बदलाव संभव है। टेक्नोलॉजी के जरिए ही उत्पादकता एवं मुनाफा दोनों को बढ़ाया जा सकता है। आइकेट में समिट के दूसरे दिन 120 टेक्निकल पेपर्स का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा किया गया। समिट में एमएसआइएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डेलॉय, पोलारिस सहित कई नामी ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने टेक्नोलॉजी पर मंथन किया।

रौनक

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बिखेरा जलवा, 10 लाख करोड़ रुपये मूल्य की पहली कंपनी बनी, सेंसेक्स 110 अंक और निफ्टी 50 अंक चढ़कर बंद, दो दिनों में निवेशक मालामाल

रिकॉर्ड सफर पर बाजारों की उड़ान जारी, रिलायंस सब पर पड़ी भारी

मुंबई, प्रेट्र : घरेलू और विदेशी बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों के चलते बीएसई-सेंसेक्स और एनएसई-निफ्टी का रिकॉर्ड बनाने का सफर लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में भी जारी रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिकॉर्ड स्थापित करने वाले इस दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 109.56 अंक यानी 0.27 प्रतिशत उछलकर 41,130.17 अंकों के नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 50.45 अंक यानी 0.42 प्रतिशत चढ़कर कारोबार के आखिर में 12,151.15 अंक पर स्थिर हुआ। दिन के कारोबार में सेंसेक्स ने एक बार 41,163.79 अंक का स्तर भी छुआ था।

शेयर बाजारों में गुरुवार का दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) के नाम रहा। एशिया के सबसे बड़े धनकुबेर मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली आरआइएल भारतीय इतिहास में 10 लाख करोड़ रुपये मूल्य का स्तर पार करने वाली पहली कंपनी बन गई। कंपनी कारोबार के आखिर में इस रिकॉर्ड स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रही। पिछले दो-तीन सत्रों से आरआइएल इस मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करने के करीब रही थी।

महज एक महीने में रिलायंस ने नौ लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ पूंजीकरण हासिल कर लिया है। प्रतीकात्मक

दिन के कारोबार के बारे में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) की एक्सपायरी का दिन होने के बावजूद शेयर बाजारों का सकल रुख सकारात्मक रहा। निवेशक शुक्रवार को दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि निवेशकों को यह भी लगता है कि वैश्विक बाजारों में तरलता बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि बाजारों को हर गिरावट के बाद एक सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा कई क्षेत्रों को जरूरी आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जा रही है। इन सबका बाजार पर सकारात्मक असर दिख रहा है।

सेंसेक्स पैक में गुरुवार को सबसे ज्यादा 2.68 प्रतिशत की बढ़त इंडसइंड बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक के शेयरों में दर्ज की गई। यस बैंक, टाटा स्टील, एसबीआइ, टीसीएस, एलएंडटी और इन्फोसिस के शेयर भी उछाल के साथ बंद हुए। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी व एचडीएफसी बैंक, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी के शेयरों को गिरावट का सामना करना पड़ा।

एशिया और यूरोप के ज्यादातर प्रमुख बाजारों का रुख गुरुवार को मंद रहा। इसकी प्रमुख वजह यह रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के प्रदर्शनकारियों के पक्ष में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। इससे अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार खत्म करने की दिशा में पिछले दिनों जो प्रगति दिख रही थी, उस पर अब संदेह के बादल मंडराने लगे हैं।

इन शेयरों में रही गहमागहमी

आइसीआइसीआइ बैंक : निजी क्षेत्र के इस दिग्गज बैंक के शेयरों में गुरुवार को बीएसई पर 2.68 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बैंक पूर्व एमडी व सीईओ चंदा कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप मामले में सेबी के साथ लिस्टिंग डिस्क्लोजर मानकों के उल्लंघन के खिलाफ सुलह की एक याचिका दायर करने वाला है। बैंक ने यह खबर भी दी है कि उसने श्री बेंजोफेन इंडस्ट्रीज में अपनी 7.8 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब नौ लाख रुपये में बेच ली है।

सिप्ला : सिप्ला फार्मा लंका में शेष 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण संबंधी करार के चलते इस कंपनी के शेयर इंट्रा-डे में करीब दो प्रतिशत तक उछले। हालांकि कारोबार के आखिर में बीएसई पर कंपनी के शेयर 0.22 प्रतिशत चढ़कर 468.80 रुपये और एनएसई पर 469.20 रुपये पर बंद हुए।

निवेशकों की संपत्ति 1.87 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र : बुधवार और गुरुवार की बढ़त को मिलाकर बीएसई में निवेशकों की संपत्ति में 1.87 लाख करोड़ रुपये का उछाल दर्ज किया जा चुका है। इन दो कारोबारी सत्रों में बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का पूंजीकरण 1,87,370.56 करोड़ रुपये बढ़कर 1,55,57,484.14 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा। दिन के कारोबार में आरआइएल का बाजार पूंजीकरण एक लाख करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा उछल गया। इस बढ़त के दम पर कंपनी 10 लाख करोड़ रुपये बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली कंपनी बन गई। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर का कहना था कि कई क्षेत्रों को वित्तीय मदद देकर इकोनॉमी को गति देने की सरकार की कोशिशों का असर शेयर बाजारों पर दिख रहा है।

ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं सवा दो लाख भारतीय

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में सवा दो लाख से ज्यादा भारतीयों को परिवार प्रायोजित ग्रीन कार्ड का इंतजार है। इस कार्ड के मिलने से अमेरिका में स्थायी रूप से बसने और काम करने का अधिकार मिल जाता है। अमेरिकी संसद से हर साल महज दो लाख 26 हजार ही ऐसे कार्ड जारी करने की अनुमति मिली हुई है।

ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में परिवार प्रायोजित ग्रीन कार्ड पाने की कतार में करीब 40 लाख लोग हैं। इस सूची में सबसे बड़ी संख्या अमेरिका के दक्षिणी पड़ोसी देश मेक्सिको के नागरिकों की है। करीब 15 लाख मेक्सिको के नागरिकों को ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार है। ग्रीन कार्ड की इंतजार सूची में दूसरे स्थान पर भारत है। करीब दो लाख 27 हजार भारतीय इस कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। जबकि चीन इस मामले में तीसरे पायदान पर है। इसके करीब एक लाख 80 हजार नागरिकों को परिवार आधारित ग्रीन कार्ड का इंतजार है।

ये कर सकते हैं प्रायोजित : ग्रीन कार्ड पाने के इच्छुक लोगों में ज्यादातर अमेरिकी नागरिकों के भाई-बहन हैं। मौजूदा कानून के तहत विदेशी मूल के अमेरिकी नागरिक ग्रीन कार्ड के लिए अपने पारिवारिक सदस्यों और खून के रिश्तेदारों को प्रायोजित कर सकते हैं।

इस कार्ड से अमेरिका में स्थायी तौर पर बसने का मिलता है अधिकार

बच्चों के लिए मांग रहे हैं स्थायी वैध निवास

अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) के अनुसार, परिवार प्रायोजित ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे ज्यादातर भारतीयों में अमेरिकी नागरिकों के भाई-बहन हैं। ऐसे भारतीयों की संख्या एक लाख 81 से अधिक है। हजारों की संख्या में ऐसे भी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, जो अपने शादीशुदा बच्चों के लिए ग्रीन कार्ड यानी या स्थायी वैध निवास मांग रहे हैं।

ट्रंप खत्म करना चाहते हैं प्रावधान : मेरिट आधारित आव्रजन को बढ़ावा देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परिवार आधारित प्रावधान के खिलाफ हैं। वह इसे खत्म करना चाहते हैं। जबकि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी परिवार आधारित आव्रजन प्रणाली को खत्म किए जाने का जोर-शोर से विरोध करती है।

पाकिस्तान में जमात उद दावा के मदरसों में प्रशासक तैनात

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान में पंजाब सरकार ने 150 मदरसों में प्रशासक नियुक्त किए हैं। इनमें से ज्यादातर मदरसे मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) से संबंधित हैं। जेयूडी के नेटवर्क में कुल 300 मदरसे, स्कूल, अस्पताल, एक प्रकाशन और एंबुलेंस सेवा शामिल हैं। यह संगठन अपनी आतंकी गतिविधियों पर पर्दा डालने और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए स्कूल, अस्पताल और एंबुलेंस सेवा का इस्तेमाल करता है।

जेयूडी और उसकी तथाकथित समाजसेवी शाखा फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन में 50000 के करीब कार्यकर्ता हैं। इनमें से सैकड़ों लोगों को तनख्वाह भी दी जाती है। मार्च 2019 में पंजाब सरकार ने जेयूडी से संबंधित 180 मदरसों, दो कालेजों, चार अस्पतालों और 178 एंबुलेंस का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। पंजाब सरकार ने बताया कि करीब 150 मदरसों में प्रशासक तैनात किए गए हैं, जो शिक्षा विभाग के ग्रेड-17 के अधिकारी हैं। इसके पहले पंजाब सरकार पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के मुख्यालय में स्थित एक मदरसे और मस्जिद में प्रशासक नियुक्त कर चुकी है।

1.75 करोड़ के साथ दुनिया में सर्वाधिक हैं प्रवासी भारतीय

दुनिया भर में प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत सबसे आगे है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में दुनिया भर में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 1.75 करोड़ है। इसके बाद प्रवासियों की संख्या के मामले में मेक्सिको दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर हैं। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट, 2020 नामक इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेश से अपने देश में पैसे भेजने के मामले में भी भारतीय एक बार फिर सबसे आगे हैं। 2018 में प्रवासी भारतीयों ने 78.6 अरब डॉलर रकम भारत में भेजी है।

27 करोड़ : दुनिया में इस समय अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या यानी कुल प्रवासियों की संख्या दुनिया की आबादी का 3.5 फीसद है। इसका अर्थ यह है कि 96.5 फीसद लोग जिस देश में पैदा हुए हैं, उसी देश में रह रहे हैं।

16.1 करोड़ : कुल अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों में से आधे से ज्यादा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। इनमें से औसतन 52 फीसद पुरुष हैं और लगभग दो-तिहाई सभी प्रवासी काम की तलाश में हैं।

अपने देश में पैसा भेजने के मामले में कौन प्रवासी कितना आगे

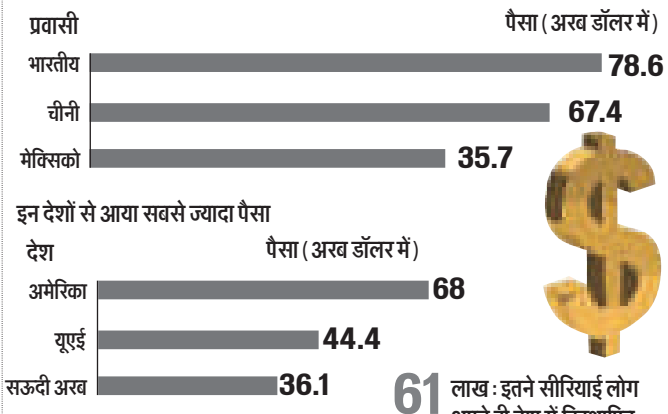

इन देशों से आया सबसे ज्यादा पैसा

दुनिया में शीर्ष तीन देशों के प्रवासी

देश	प्रवासी आबादी
भारत	1.75 करोड़
मेक्सिको	1.18 करोड़
चीन	1.07 करोड़

श्रम प्रवासियों की संख्या

रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में अस्थायी श्रम प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या खाड़ी देशों में है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है, जहां इनकी आबादी लगभग 90 फीसद है।

61 लाख : इतने सीरियाई लोग अपने ही देश में विस्थापित हुए। इसके बाद कोलंबिया (50.8 लाख) और कांगो (30 लाख) है।

आंतरिक विस्थापन

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, म्यांमार, दक्षिण सूडान, सीरिया और यमन ने पिछले दो वर्षों में बड़े पैमाने पर आंतरिक विस्थापन देखा है। कुल 4.13 करोड़ लोगों को 2018 के अंत में अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।

न्यूज गैलरी

नवाज शरीफ की सेहत में कोई सुधार नहीं

नवाज शरीफ। फाइल

इस्लामाबाद : लंदन जाकर इलाज करा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। यह जानकारी पूर्व पीएम के बेटे हुसैन नवाज ने दी है। बकौल हुसैन, 'डॉक्टरों की पुरजोर कोशिश के बावजूद मेरे पिता की सेहत में अभी तक कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। नवाज साहब की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है।' पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हुसैन ने देश की जनता से नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ करने की अपील की। परिवार के सदस्यों के अनुसार, नवाज शरीफ का इलाज लंदन के ब्रिज हॉस्पिटल में चल रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा काट रहे शरीफ की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें देश से बाहर जाकर इलाज कराने के लिए जमानत दी थी। (एएनआइ)

इराक में सुरक्षाबलों की फायरिंग में 28 प्रदर्शनकारियों की मौत

बगदाद : इराक के नासिरियाह शहर में गुरुवार को सरकार विरोध प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाबलों की फायरिंग में 28 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षाकर्मियों द्वारा यह कार्रवाई बीती रात उग्र प्रदर्शनकारियों द्वारा नजफ स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास को आग के हवाले कर देने की घटना के बाद की गई। आगजनी की घटना के बाद शिया समुदाय के पवित्र शहर नजफ में कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ भारी संख्या में इराकी जनता मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पिछले महीने से आंदोलन कर रही है। बीते एक अक्टूबर से शुरू देशव्यापी उग्र प्रदर्शनों में अब तक 350 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। (रायटर)

मोती के आतंकी होने के सुबूत पेश करें : ब्रिटिश कोर्ट

लंदन : ब्रिटिश कोर्ट में प्रत्यर्पण मामले में हो रही सुनवाई का सामना कर रहे जाबिर मोती पर आतंकवाद फैलाने का आरोप भी अमेरिका ने लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि मोती पर आतंकी होने के आरोप के पुख्ता सुबूत पेश किए जाएं। मोती अंडरवर्ल्ड सरगना और मोस्ट वांटेड आतंकी दाउद इब्राहीम का खास गुर्गा है, जो उसके आर्थिक मामलों को संभालता था। फायदा देखकर निवेश भी करता था। अमेरिका उस पर फिलहाल नशीले पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाकर उस पर मुकदमा चलाना चाहता है। (प्रेट्र)

बाजवा को मिला सिर्फ छह माह का सेवा विस्तार

बड़ा फैसला ▶ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख के तीन साल के एक्सटेंशन में की कटौती

इमरान सरकार को अदालत का निर्देश- इस संबंध में पारित करे जरूरी कानून

इस्लामाबाद, प्रेट्र : प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार को राहत देते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पाक सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को छह महीने का सेवा विस्तार दे दिया है। कोर्ट ने इमरान सरकार को इस संबंध में संसद से जरूरी कानून पारित कराने का निर्देश दिया है। इस फैसले से राहत महसूस कर रहे पीएम इमरान खान ने कहा कि इससे पाकिस्तान के बाहरी दुश्मनों और देश में मौजूद माफियाओं को बड़ी निराशा होगी।

चीफ जस्टिस आसिफ साईद खान खोसा की तीन सदस्यीय खंडपीठ में अन्य जजों में जस्टिस मजहर आलम खान मियांखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे। पहले पाकिस्तान सरकार ने बाजवा का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन गुरुवार को कोर्ट इस सेवा विस्तार को सिर्फ छह महीने के लिए मंजूरी दी है।

खंडपीठ ने अपने इस निर्णय में बाजवा के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने की बात कही है और सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में जल्दी ही जरूरी कानून लेकर आएं।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की फाइल फोटो। एपी

उल्लेखनीय है कि बाजवा का तीन साल का मूल सेवा विस्तार गुरुवार की मध्यरात्रि को ही खत्म हो गया। लिहाजा, नए फैसले से वह अगले छह महीने तक सेना प्रमुख के पद पर बने रहेंगे। इसलिए ऐसे समय पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इमरान खान की सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के कार्यकाल के विस्तार से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी। पुराने नियम के मुताबिक बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे थे। लेकिन अदालत के इस आदेश के बाद अब वह अगले छह महीने तक इस पद पर बने रह सकते हैं।

प्रधानमंत्री इमरान ने कहा- इस फैसले से बाहरी दुश्मनों और देश में मौजूद माफियाओं को होगी बड़ी निराशा

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब बाजवा के सेवा विस्तार से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगाई थी तो इस पर पीएम इमरान खान ने अपनी कैबिनेट के कानून मंत्री को फटकार लगाई थी। इसके बाद कानून मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।

हालांकि इसी साल 19 अगस्त को इमरान खान सरकार ने बाजवा को और तीन साल का एक्सटेंशन दिया था। अपने फैसले में पाकिस्तान सरकार ने 'क्षेत्रीय सुरक्षा के वातावरण' का हवाला देते हुए बाजवा के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। हालांकि सरकार ने अपना यह आदेश कोर्ट के दखल देने के बाद वापस ले लिया था और इस संबंध में एक अन्य अधिसूचना जारी की थी, जिसे बुधवार को निरस्त कर दिया गया था।

इमरान खान बोले-पेड़ रात में छोड़ते हैं ऑक्सीजन

नई दिल्ली, आइएएनएस : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने अल्पज्ञान का एक नया नमूना पेश किया है। उन्होंने एक समारोह में अपने भाषण में कहा कि पेड़ रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनकी इसी बात का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में इमरान खान को जनसभा में मंच से कहते सुना गया, '70 फीसद जो ग्रीन कवर था, दस सालों के अंदर वह कम हुआ। उसके नतीजे तो आने थे क्योंकि दरख्त हवा को साफ करते हैं। रात को ऑक्सीजन देते हैं। कार्बनडाइआक्साइड को सोख लेते हैं।'

पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान के इसी भाषण पर सोशल मीडिया में एक यूजर ने लिखा, 'पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम का ताजा ज्ञान है कि पेड़ रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइआक्साइड नहीं। मैं आप जैसे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप मेरे बेटे की सातवीं की बायोलॉजी का सबक पढ़ लें।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'शुक्र है खुदा का यह जनाब मेरे हिस्ट्री या जियोग्राफी

पाकिस्तानी पीएम अपने अल्पज्ञान पर सोशल मीडिया में जमकर ट्रोल हुए

इमरान खान। फाइल

के टीचर नहीं थे।' एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा कि उनके विचार से जर्मनी से लगे जापान बार्डर पर जो पेड़ लगाए गए हैं, वह संभवतः रात में ऑक्सीजन देते हैं। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े इस बंदे ने वाकई वहां से परीक्षा पास भी की है या नहीं। सोशल मीडिया पर एक भारतीय यूजर ने कटाक्ष करते हुए कहा, 'हो सकता है पाकिस्तान में ऐसा ही होता हो। लेकिन भारत और बाकी दुनिया में सामान्यतः पेड़-पौधे रात में ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं।'

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन को मनी लांड्रिंग में पांच साल की जेल

अब्दुल्ला यामीन की फाइल फोटो। रायटर

माले, एएफपी: मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लांड्रिंग के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर अपने एक बैंक खाते से 10 लाख डॉलर (लगभग सात करोड़, 15 लाख रुपये) का भुगतान करने का आरोप है। इस मामले की जांच के दौरान यामीन को पिछली फरवरी में गिरफ्तार कर लिया गया था।

अवैध रूप से धन लेने का आरोप लगने के बाद अधिकारियों ने यामीन के एक बैंक खाते को भी सील कर दिया है। जिस खाते को सील किया गया, उसमें 65 लाख डॉलर (लगभग 46.51 करोड़ रुपये) की राशि थी। जांच अधिकारियों का मानना है कि यामीन ने संभवतः करोड़ों की राशि विदेश में छिपा रखा है, जिन्हें वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यामीन ने अपने कार्यकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या फिर विदेश जाने के लिए मजबूर कर दिया था।

फेक अमेरिकी यूनिवर्सिटी दाखिले में 90 और विदेशी छात्र गिरफ्तार

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने फेक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के मामले में 90 और विदेशी छात्रों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए छात्रों में ज्यादातर भारतीय बताए जा रहे हैं। यह फर्जी यूनिवर्सिटी आव्रजन धोखाधड़ी को रोकने की कवायद के तहत खोली गई थी।

अमेरिका की प्रवर्तन एजेंसी इमीग्रेशन एंड कस्टम इंफोर्समेंट (आइसीई) ने फर्जी फार्मिंग्टन यूनिवर्सिटी मामले में अब तक कुल 250 से ज्यादा विदेशी छात्रों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने इस साल मार्च में 161 छात्रों को पकड़ा था। जबकि इस मामले में 90 और छात्रों की गिरफ्तारी हाल के महीनों में हुई। इसकी खबर गत मंगलवार को मीडिया में आई। आइसीई के प्रवक्ता के अनुसार, फर्जी यूनिवर्सिटी दाखिला मामले में गिरफ्तार किए गए 250 से ज्यादा छात्रों में से करीब 80 फीसद को अमेरिका से उनके देश भेजा जा चुका है। जबकि संघीय अभियोजकों का दावा है कि ये छात्र जानते थे कि यह फर्जी यूनिवर्सिटी थी। इसमें कोई पढ़ाई नहीं होती थी।

डेट्रायट में खुली थी यूनिवर्सिटी: अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की ओर से डेट्रायट शहर में फर्जी प्राइवेट फार्मिंग्टन यूनिवर्सिटी खोली गई थी। इसमें करीब 600 विदेशी छात्रों ने दाखिला लिया था। इन छात्रों में ज्यादातर भारतीय थे।

पकड़े गए छात्रों में ज्यादातर भारतीय, गत मार्च में भी हुई थी 161 की गिरफ्तारी

आव्रजन धोखाधड़ी रोकने को गृह विभाग ने खोली थी फर्जी यूनिवर्सिटी

रैकेट का हुआ था भंडाफोड़: विदेशियों को अमेरिका में अवैध रूप से रहने में मदद करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए यह यूनिवर्सिटी गोपनीय अभियान के तहत खोली गई थी। इस यूनिवर्सिटी के जरिये गत फरवरी में एक रैकेट का भंडाफोड़ कर आठ भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से सात ने अपना जुर्म मान लिया था।

ना शिक्षक थे, ना कक्षाएं चलीं: फार्मिंग्टन यूनिवर्सिटी में ना तो कोई शिक्षक था और ना ही कक्षाएं चलती थीं। इसके बावजूद ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए प्रति तिमाही 2500 डॉलर (करीब एक लाख 80 हजार रुपये) वसूला गया था।

पेट्रोकेमिकल प्लांट में भीषण विस्फोट

अमेरिका के टेक्सास राज्य के पोर्ट नेचेस में पेट्रोकेमिकल प्लांट में सिलसिलेवार विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। एक के बाद एक हुए विस्फोट इतने तीव्र थे कि आसपास के कस्बों में घरों की खिड़कियां और दरवाजों टूट गए। प्लांट के साढ़े छह किलोमीटर के दायरे में आने वाले चार कस्बों से 60 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। जेफरसन काउंटी के मुख्य कार्यकारी जेफ ब्रनिक ने कहा कि अभी विस्फोट के कारणों का पता नही चल सका है। इस प्लांट में रबर, नायलॉन, रेजिन और गैसोलीन का निर्माण किया जाता है। फिलहाल फायर फाइटरों की टीम आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी है। रायटर

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की बॉक्सर के रूप में अपनी तस्वीर

न्यूयॉर्क, एएनआइ: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक ऐसी तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें वह एक बॉक्सर के तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी इस तस्वीर के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी गहमागहमी के बीच ट्रंप ने यह फोटो क्यों शेयर की है? इसके जरिये वह क्या संदेश देना चाहते हैं? यह स्पष्ट नहीं किया गया है। वैसे कुछ लोग इस पोस्ट को उनकी सेहत को लेकर उड़ रही अफवाहों के बीच ट्रंप की सफाई के तौर पर देख रहे हैं। फोटो पर कमेंट में एक ने लिखा, ट्रंप लड़ाई को तैयार हैं।

ट्रंप ने अपनी जिस तस्वीर को ट्वीट किया है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि यह एक काल्पनिक बॉक्सर की फोटो है, जिसके चेहरे की जगह अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर लगाई गई है। यह तस्वीर 1982 में आई सुपर हिट फिल्म 'रॉकी 3' के प्रचार के लिए पोस्टर में इस्तेमाल हुई थी।

हाल ही में ट्रंप के अप्रत्याशित हेल्थ चेकअप के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैलने लगी थी। इसे दूर करने की कोशिश के तहत ट्रंप ने बीते मंगलवार को एक ट्वीट में मजाकिया अंदाज में लिखा था कि

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर, जिसमें वह एक बॉक्सर के रूप में नजर आ रहे हैं। एएफपी

चेकअप के वक्त उनसे कमीज हटाकर अपना गठीला शरीर दिखाने को कहा गया था। लोग शेयर किए गए फोटो को ट्रंप की इसी टिप्पणी के साथ जोड़कर देख रहे हैं।

ब्रिटेन में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों को रिकॉर्ड 30 हजार से ज्यादा मिले वीजा

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए बीते एक साल में भारतीय छात्रों को रिकॉर्ड 30,550 वीजा मिले। इससे पूर्व के वर्ष में 18,730 वीजा मिले थे। इस लिहाज से भारतीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने की अपनी नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने महज एक साल में भारतीय छात्रों को वीजा देने की संख्या में 65 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि की।

गुरुवार को ताजा आंकड़े जारी करते ब्रिटिश नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस (ओएनएस) ने बताया कि सितंबर 2019 में खत्म हुए वर्ष में टीयर 4 के अंतर्गत आने वाले भारतीय छात्रों को 30,550 वीजा जारी किए गए। जबकि इसके पूर्व के वर्ष में भारतीयों को 18,730 वीजा मिले थे। लगातार तीसरे साल भारतीय छात्रों की वीजा संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह हम दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये प्रतिभाशाली नौजवान आने वाले समय में दोनों देशों के बीच पुल का काम करेंगे। ये एक-दूसरे

पूर्व की तुलना में देश में इस बार 65 फीसद बढ़ी भारतीयों की संख्या

इससे पहले 18,730 भारतीय छात्रों को मिला था वीजा

ब्रिटेन में लगातार तीसरे साल बढ़ी है भारतीय छात्रों की संख्या। फाइल

की संस्कृति और विचारों को दोनों देशों में फैलाएंगे। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डॉमिनिक एस्क्विथ ने कहा कि आंकड़े दर्शा रहे हैं ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में भारतीयों की पढ़ाई की इच्छा बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार बीते दस साल में 2,70,000 भारतीय छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन का चयन किया।

भारत में ब्रिटिश काउंसिल की डायरेक्टर बारबरा वीखम ने कहा, छात्र संख्या में यह बढ़ोतरी भारत और ब्रिटेन के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सहयोग को दर्शाती है। यह दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रमुख क्षेत्र है। छात्र ही नहीं भारतीय पर्यटक भी समय बिताने के लिए ब्रिटेन जाना पसंद करते हैं।

बीते साल 5,12,000 भारतीय पर्यटक ब्रिटेन घूमने गए। यह उसके पूर्व के वर्ष की तुलना में नौ प्रतिशत ज्यादा है। पेशेवरों के लिए मिलने वाला ब्रिटिश वीजा पाने में भी भारतीय आगे हैं। बीते वर्ष में कुल 56,241 दक्ष पेशेवरों ने ब्रिटेन में काम करने का वीजा प्राप्त किया, जबकि इसके पूर्व के वर्ष में 55,136 लोगों को वीजा मिला था।

अफगानिस्तान में बम धमाके, 16 लोगों की मौत

काबुल, एपी : उत्तरी अफगानिस्तान में दो अलग-अलग बम धमाकों में 16 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं बताई जा रही हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहीमी ने बताया कि कुंदुज प्रांत में बुधवार रात बम धमाके में एक वाहन को निशाना बनाया गया। यह वाहन लोगों को लेकर एक शादी समारोह में जा रहा था। इसमें छह महिलाएं, छह लड़कियां और दो बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के कुछ घंटे बाद सर-ए-पोल प्रांत में एक जांच चौकी पर आतंकियों ने हमला किया। इसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई।

पुलिस प्रवक्ता मुहम्मद नूरघा फैजी ने बताया कि विस्फोटकों से लदे वाहन में कई आतंकी सवार थे। जांच चौकी पर रोके जाने पर उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसी दौरान आतंकियों ने विस्फोटक से लदे वाहन को रिमोट से उड़ा दिया। गृह मंत्रालय ने इन दोनों हमलों के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है। इस आतंकी संगठन का करीब आधे अफगानिस्तान पर नियंत्रण है।

ब्रिटेन में कंजरवेटिव पार्टी की सत्ता में वापसी के मजबूत संकेत

लंदन, रायटर : ब्रिटेन में होने वाले आम चुनाव में कंजरवेटिव पार्टी सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगी। वह 1987 जैसी बड़ी सफलता की ओर है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बड़े अंतर से अपना चुनाव जीत सकते हैं, जो उन्हें यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलगाव को प्रभावी बनाने के लिए नई ताकत देगा। 12 दिसंबर के चुनाव को लेकर यह दावा है यूगोव का। संस्था ने इससे पहले 2017 के चुनाव में 650 सीटों में से 359 पर जीत की भविष्यवाणी की थी, जो काफी हद तक सही साबित हुई थी। ताजा सर्वे से बाजार में सुधार हुआ है और पाउंड मजबूत हुआ है।

जॉनसन ने जनता से वादा किया है कि चुनाव जीतने की स्थिति में वह 31 जनवरी तक ब्रेक्जिट प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। यूरोपीय यूनियन से अलगाव की यह प्रक्रिया

बोरिस जॉनसन। फाइल

चार साल से लटकी हुई है। इससे पूरा ब्रिटेन अनिश्चितता की स्थिति में बना हुआ है। जुलाई में प्रधानमंत्री बनने के बाद जॉनसन ने चार महीने के भीतर ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच अलगाव की शर्तों का समझौता करा लिया। इस समझौते को ब्रिटिश संसद की स्वीकृति दिला दी। लेकिन संसद में एक संशोधन प्रस्ताव के पारित हो जाने की वजह से ब्रेक्जिट की प्रक्रिया 31 अक्टूबर को पूरी नहीं हो सकी, अब इसके लिए अगली तारीख 31 जनवरी तय की गई है।

यूगोव की सर्वे टीम के निदेशक एंटनी वेल्स के अनुसार 2019 के चुनाव को लेकर हमारा अभी का आकलन कंजरवेटिव पार्टी को बहुमत मिलने का है। वह सरकार बनाने जा रही है। 2016 के चुनाव की तुलना में वोटों का प्रवाह उसकी ओर ज्यादा है। इसके चलते संसद में उसके सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ब्रिटेन के बाजारों में सुधार आया, डॉलर की तुलना में पाउंड की कीमत भी मजबूत हुई। उल्लेखनीय है कि 1987 के चुनाव में कंजरवेटिव पार्टी ने मार्ग्रेट थैचर के नेतृत्व में चुनाव जीता था।

टीम के मैनेजर जोस मौरिन्हो के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। हम मिलकर टीम को आगे लेकर जाएंगे।
— हैरी केन, फुटबॉल खिलाड़ी, टॉटनहम

आइपीएल में भारतीय कोचों को मौके नहीं मिलने से द्रविड़ निराश

लखनऊ, एएनआइ : इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) में भारतीय कोचों को मौके नहीं मिलने को लेकर पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने निराशा जाहिर की है। द्रविड़ ने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे पास कुछ बेहद अच्छे कोच हैं। उनकी योग्यता में मेरा पूरा विश्वास है। जिस तरह हमारे पास क्रिकेट में काफी प्रतिभाएं हैं, उसी तरह से कोचिंग विभाग में भी बहुत सी प्रतिभाएं हैं। हमें उन पर कुछ विश्वास जताने की जरूरत है।

एमएसजी के दम पर बार्सिलोना अंतिम-16 में पहुंचा, डोर्टमंड को हराया, दिग्गज स्ट्राइकर लियोन ने बार्सिलोना के लिए खेला करियर का 700वां मैच

यूएफा चैंपियंस लीग

700वें मैच में मेसी का 613वां गोल

मैड्रिड, एएफपी: अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोन मेसी, लुइस सुआरेज और स्थानापन्न खिलाड़ी एंटोनी ग्रीजमैन (एमएसजी) के दम पर स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने बोरुसिया डोर्टमंड को 3-1 से हराकर यूएफा चैंपियंस लीग के अंतिम-16 में जगह बनाई। इस दौरान मेसी ने अपने क्लब के लिए 700वें मैच को यादगार बनाते हुए करियर का 613वां गोल दागा।

इस मैच में मेसी का प्रदर्शन कमाल का रहा है। उन्होंने एक गोल करने के अलावा दो खिलाड़ियों के गोल करने में मदद भी की। वहीं, सुआरेज ने भी एक गोल ठोकने के साथ एक गोल करने में सहायता की। इस जीत के साथ बार्सिलोना अपने ग्रुप-एफ में तीन जीत और दो ड्रॉ के साथ 11 अंक लेकर शीर्ष पर है। वहीं, डोर्टमंड दो जीत, दो हार और एक ड्रॉ के साथ सिर्फ सात अंक ही हासिल कर पाया। स्लोविया पराग पर 3-1 से जीत दर्ज करने वाले इंटर मिलान और जर्मनी के क्लब डोर्टमंड के एक समान सात-सात अंक हैं, लेकिन गोल अंतर के आधार पर पराग की टीम दूसरे नंबर पर काबिज है। इंटर मिलान के स्ट्राइकर रोमेलु लुकाकू ने अपने करियर के 250 गोल पूरे किए।

सुआरेज के 29वें मिनट में किए गए गोल की मदद से बार्सिलोना ने 1-0 की बढ़त बनाई। मेसी ने बॉक्स के बाहर से गेंद को सुआरेज को पास की और उन्होंने विपक्षी टीम के गोलकीपर को छकाकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाने में कोई गलती नहीं की। इसके चार मिनट बाद ही मेसी और सुआरेज की जोड़ी का एक बार फिर जलवा देखने को मिला। इस बार सुआरेज ने मेसी को गेंद बॉक्स के अंदर पास की और इस दिग्गज स्ट्राइकर ने अपने बायें पैर से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया। पहले हाफ तक बार्सिलोना की टीम 2-0 से आगे रही। दूसरे हाफ में भी बार्सिलोना की टीम का गोल करने का सिलसिला जारी रहा। इस बार मेसी ने बायें पैर से ग्रीजमैन की तरफ गेंद को भेजा और फिर ग्रीजमैन ने टीम की बढ़त 3-0 करने में कोई गलती नहीं की। इस चैंपियनशिप में ग्रीजमैन ने क्लब के लिए पहली बार कोई गोल दागा। डोर्टमंड के लिए 77वें मिनट में जाडोन सांचो के गोल ने हार के अंतर को कम किया।

लिप्जिग पहली बार अंतिम-16 में

लिप्जिग : आरबी लिप्जिग की टीम चैंपियंस लीग में पहली बार अंतिम-16 में पहुंची है। लिप्जिग ने यहां रेड बुल एरिना में ग्रुप-जी के इस मुकाबले में बेनफिका को 2-2 से बराबरी पर रोक दिया। एक समय लिप्जिग की टीम मैच हारने की कगार पर थी, लेकिन एमिल फोर्सबर्ग ने 90वें मिनट में पेनाल्टी पर गोल करके टीम का मैच में खाता खोल दिया। फिर इसके छह मिनट बाद ही फोर्सबर्ग ने एक और गोल करके अपनी टीम को हारने से बचा लिया। बेनफिका के लिए दो गोल पिज्जी (20वां मिनट) और कार्लोस विनिसियस (59वां मिनट) ने किए। लिप्जिग की टीम अपने ग्रुप में 10 अंकों के साथ शीर्ष पर रही जबकि बेनफिका चार अंक लेकर अंतिम चौथे स्थान पर रहा। वहीं, जेनित सेंट पीटर्सबर्ग ने ल्योन को 2-0 से हरा दिया।

वेलेंसिया ने चेल्सी से खेला ड्रॉ

वेलेंसिया : वेलेंसिया क्लब ने चेल्सी को 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। ग्रुप-एच में खेले गए इस मैच में वेलेंसिया के लिए कार्लोस सोलर ने 40वें मिनट में गोल करके उसे 1-0 से आगे कर दिया। इसके एक मिनट बाद ही माटेओ काविक ने गोल दागकर चेल्सी को 1-1 की बराबरी दिला दी। चेल्सी ने इसके बाद क्रिस्टियन पुलिसिक के गोल की मदद से 50वें मिनट में अपनी बढ़त को दोगुना कर दिया लेकिन 82वें मिनट में वेलेंसिया ने बराबरी हासिल कर ली। वेलेंसिया के लिए यह गोल डेनियल वास ने दागा। इस ड्रॉ के बाद ग्रुप-एच में चेल्सी और वेलेंसिया दोनों पांच-पांच मैचों में आठ-आठ अंकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर है।

लोवरेन ने लिवरपूल को हार से बचाया

लिवरपूल : देजान लोवरेन (65वां मिनट) ने दूसरे हाफ में किए हेडर के जरिये गोल की मदद से अपनी टीम लिवरपूल को यहां ग्रुप-ई के मैच में नापोली के खिलाफ हार से बचा लिया। दोनो टीमों के बीच यह मैच 1-1 से बराबरी पर खत्म हुआ। इसके साथ दोनों टीमों ने चैंपियंस लीग के अंतिम-16 में अपनी जगह पक्की की। इस मैच के बाद लिवरपूल (10 अंक) और नापोली (09 अंक) ग्रुप में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे। ड्राइस मर्टेंस ने 21वें मिनट में गोल करके नापोली को मैच में 1-0 से बढ़त दिलाई थी। ग्रुप के अन्य मैच में सल्जबर्ग ने रेसिंग जेंक को 4-1 से शिकस्त दी।

बार्सिलोना के लिए मेसी के गोल

700	मैच क्लब के लिए खेले	01	बार एक मैच में पांच गोल किए
613	गोल किए	218	बार एक मैच में एक गोल किया
237	बार अन्य खिलाड़ियों की गोल करने में मदद की		
34	बार चैंपियन टीम के सदस्य रहे		
05	बार एक मैच में चार गोल दागे		
125	बार एक मैच में दो गोल किए		

16 वीं बार लगातार बार्सिलोना की टीम ने यूएफा चैंपियंस लीग के नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई है

» लियोन मेसी ● रायटर

34 अलग-अलग टीमों के खिलाफ गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोन मेसी। मेसी से पहले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और स्पेन के राउल ने 33 टीमों के खिलाफ गोल किए थे

700 मैच बार्सिलोना के लिए खेलने वाले इस स्पेनिश क्लब के दूसरे खिलाड़ी हैं मेसी। क्लब के लिए सबसे ज्यादा मैच जावी (767) ने खेले हैं। तीसरे नंबर पर आंद्रे इनिस्ता (674) हैं

मेसी शानदार है। उसने दमदार प्रदर्शन किया। हम इस चैंपियनशिप के सबसे मुश्किल ग्रुप में शामिल थे और अब हम अगले दौर में पहुंच गए हैं। हमारा पहला लक्ष्य नॉकआउट के लिए क्वालीफाई करना था और साथ में हम अपने खेल में सुधार भी करना चाहते थे।
ईर्नेस्टो वाल्वर्डे
मैनेजर, बार्सिलोना

दीपिका ने जीता स्वर्ण और अंकिता ने रजत, भारत को मिला ओलंपिक कोटा

महाद्वीपीय क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट में हासिल की भारतीय तीरंदाजों ने सफलता

बैंकाक, प्रेट्र: भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने गुरुवार को यहां 21वीं एशियाई चैंपियनशिप से इतर आयोजित महाद्वीपीय क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंकिता भक्त ने रजत पदक हासिल किया। दीपिका ने अंकिता को एकतरफा फाइनल में 6-0 से मात दी। इन दोनों के इस महाद्वीपीय क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने से ही देश को व्यक्तिगत ओलंपिक कोटा हासिल हो गया था।

क्वालीफिकेशन के जरिये व्यक्तिगत स्थान के लिए तीन कोटा स्थान हासिल किए जा सकते थे और भारतीय तीरंदाजों ने शीर्ष वरीय दीपिका और छठी वरीयता प्राप्त अंकिता के शानदार प्रदर्शन की बदौलत बड़ा संदेश दिया, क्योंकि भारतीय तीरंदाज राष्ट्रीय संघ के निलंबन की वजह से बिना झंडे के तले प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। नंबर एक महिला तीरंदाज के रूप में उतरीं दीपिका ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए मलेशिया की नूर अफिसा अब्दुल हलिल को 7-2 से, ईरान की जाहरा नेमति को 6-4 से और स्थानीय प्रतिद्वंद्वी नरिसारा खुनहिरानचाइयो को 6-2 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई और ओलंपिक कोटा सुनिश्चित किया। दीपिका ने कहा, 'दिन की शुरुआत में हम थोड़ा सा नर्वस थे। वहां काफी तेज हवा भी चल रही थी। मैंने सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और खुद से कहा कि बस कर दो। अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूं।' स्थानीय प्रतिद्वंद्वी नरिसारा के खिलाफ फाइनल राउंड से पहले दीपिका ने अपने मंगेतर और टीम के साथ अतानु दास से 28 शूट करने का वादा किया था, लेकिन वह दो परफेक्ट 10 और एक नौ अंक के निशाने के साथ एक अंक से बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, 'हम अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहते थे। मैंने अतानु (मिक्स्ड टीम के साथ और मंगेतर) से वादा भी किया था कि मैं 28 शूट लगाऊंगी। उन्होंने मुझसे कहा था जाओ और शूट करो। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वह इसे समझते हैं और यह अच्छे से हो गया। अब हमें अगले साल विश्व कप के बर्लिन चरण से टीम बर्थ के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीद है।' दिन के अंत में दीपिका ने एक और एकतरफा मुकाबले में एनगुएट को 6-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरी ओर, अंकिता ने हांगकांग की लाम शुक चींग अदा को 7-1 से, वियतनाम की एनगुएन थी फुओंग को 6-0 से और कजाखिस्तान की अनास्तासिया बेनोवा को 6-4 से एवं भूटान की कारमा को 6-2 से हराकर ऑल इंडिया फाइनल सुनिश्चित किया।भारत के पास अब 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए पुरुष टीम वर्ग में और महिला स्पर्धा में व्यक्तिगत कोटा है। दीपिका, अंकिता और बोंबायाला ने तटस्थ झंडे के तले प्रतिस्पर्धा की। यह तीरंदाजी में भारत का दूसरा ओलंपिक कोटा है। इससे पहले तरुणदीप राय, अतानु दास और प्रवीन जाधव की पुरुष रिकर्व टीम ने इस साल विव चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहते हुए ओलंपिक कोटा हासिल किया था।

भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ● फाइल फोटो, ट्विटर

चौथे क्रम की परेशानी को दूर कर सकते हैं श्रेयस : प्रसाद

जेएनएन, नई दिल्ली: मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने कहा कि सीमित ओवरों के प्रारूप में श्रेयस अय्यर ने दो साल में अपने खेल में जो सुधार किया है उससे वह भारतीय क्रिकेट टीम की चौथे क्रम की परेशानी को दूर कर सकते हैं।

अय्यर ने नवंबर 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पदार्पण करने के बाद श्रीलंका के खिलाफ घरेलू मैदान में लगातार दो अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। 24 साल के इस खिलाड़ी ने इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में तीन वनडे खेले, लेकिन दो महीने बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। विश्व कप में भारतीय टीम का अभियान खत्म होने के बाद उन्हें इस साल अगस्त में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए फिर से चुना गया। प्रसाद ने कहा, 'अगर आपको याद हो तो हमने अय्यर को 18 महीने पहले (जब कोहली को विश्राम दिया गया था) वनडे टीम में शामिल किया था और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। दुर्भाग्य से हम उन्हें टीम में बरकरार नहीं रख सके। अय्यर ने हालांकि अपने खेल में काफी सुधार किया है, जिससे वनडे और टी-20 टीमों में चौथे क्रम की परेशानी से टीम को उबार सकते हैं।'

घरेलू प्रतियोगितओं में मुंबई का प्रतिनिधित्व करने वाले इस बल्लेबाज ने घरेलू और भारत-ए टीम के लिए रनों का अंबार लगाया।

कुलदीप को ज्यादा से ज्यादा मौके दें कोहली और शास्त्री : बांगर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने कप्तान विराट कोहली व कोच रवि शास्त्री से चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को टीम में ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाने की बात कही है। उनका कहना है कि वह एक मैच विजेता स्पिनर हैं और इस युवा गेंदबाज के साथ दोनों को खड़े रहना चाहिए।

बांगर ने कहा, 'मैं कुलदीप का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और स्ट्राइक रेट के लिहाज से वह वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। क्रिकेट के छोटे प्रारूप में भी अगर आप इंग्लैंड में जीते हुए मुकाबलों को देखें तो उन्होंने ऐसे वक्त पांच विकेट हासिल किए जब मैच हाथ से निकलता जा रहा था।' सिर्फ इस वजह से कि कुलदीप ने पिछले सत्र में आइपीएल के कुछ मुकाबलों में विकेट नहीं लिए, उन पर से भरोसा नहीं खोने वाला। उनके लिए आइपीएल का यह सत्र बहुत ही अहम होने वाला है। अगर वह अच्छा करते हैं तो फिर उन्हें बाहर रखना काफी मुश्किल होगा। टीम में ऑलराउंडर के होने को भी बांगर ने काफी अहम बताया। उनका मानना है कि रवींद्र जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो चार किफायती ओवर डाल सकते हैं और साथ ही पारी के आखिरी में बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं।

मैं भी असफलताओं से प्रभावित होता हूं : कोहली

नई दिल्ली: भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इतनी ज्यादा असफलताएं नहीं देखी हैं, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि वह इनसे प्रभावित नहीं होते। इसका हालिया उदाहरण भारत का इंग्लैंड में वनडे विश्व कप सेमीफाइनल मैच में हारना रहा, जिसमें टीम को न्यूजीलैंड ने 18 रन से शिकस्त दी। कोहली ने कहा, 'क्या मैं असफलताओं से प्रभावित होता हूं? हां, होता हूं। हर कोई होता है। अंत में मैं एक बात जानता हूं कि टीम को मेरी जरूरत है। सेमीफाइनल में मुझे लग रहा था कि मैं नाबाद लौटूंगा और अपनी टीम को इस मुश्किल दौर से निकाल कर लाऊंगा। लेकिन, हो सकता है कि वो मेरा अहंकार हो क्योंकि आप कैसे भविष्यवाणी कर सकते हो? आपके अंदर सिर्फ मजबूत अहसास हो सकते हैं या फिर इस तरह का कुछ करने की प्रबल इच्छाशक्ति।' वनडे और टेस्ट में क्रमशः 11500 और 7202 रन बनाने वाले कोहली अपने पीछे एक विरासत छोड़ना चाहते हैं जिसका अनुसरण आने वाले लोग करें। दायें हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा, 'मुझे हारना पसंद नहीं है। मैं बाहर आकर यह नहीं कहना चाहता था कि मैं ऐसा कर सकता था। जब मैं मैदान पर कदम रखता हूं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। जब मैं बाहर आता हूं, तो मैं पूरी तरह थका हुआ होना चाहता हूं। हम उस तरह की विरासत छोड़ना चाहते हैं कि आने वाले क्रिकेटर कहें कि हमें इस तरह से खेलना है।'

वीजा अवधि खत्म होने पर भी भारत में रुके हसन, लगा जुर्माना: बांग्लादेश के क्रिकेटर सैफ हसन वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रुके रहे, जिससे कारण उन्हें बुधवार को स्वदेश लौटते समय 21600 रुपये का जुर्माना देना पड़ा। हसन टेस्ट टीम के साथ वैकल्पिक सलामी बल्लेबाज के तौर पर भारत आए थे। अंगुली में चोट के कारण कोलकाता टेस्ट से बाहर बैठने वाले हसन के वीजा की छह महीने की अवधि खत्म हो गई थी। बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त तौफीक हसन ने कहा, ' उनके (हसन) वीजा की अवधि दो दिन पहले समाप्त हो गई और उन्हें एयरपोर्ट पर ही इसका अहसास हुआ। नियमों के अनुसार उन्हें जुर्माना भरना पड़ा। हम भारतीय उच्चायोग के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उनकी वीजा प्रक्रिया को जल्दी पूरा कर दिया और उन्हें लौटने की मंजूरी दे दी।'

सैमसन का चुनाव पंत के लिए खतरा : लक्ष्मण

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि विकेटकीपर ऋषभ पंत को टीम प्रबंधन ने जितना समय दिया है, उसमें उन्हें खरा उतरना होगा और अगर उन्होंने जल्द ही लय हासिल नहीं की तो संजू सैमसन उनकी जगह ले सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज की टीम में संजू सैमसन का चुना जाना पंत के लिए 'कड़ा संदेश' है कि प्रदर्शन करें या फिर टीम से बाहर होने के लिए तैयार रहे।

लक्ष्मण ने कहा कि पंत को काफी मौके मिले हैं और मुझे यकीन है कि टीम प्रबंधन ने उससे बात की होगी। खिलाड़ी को टीम प्रबंधन और चयन समिति के भरोसे को सही साबित करना होता है। दुर्भाग्य से पंत उस भरोसे पर खरे नहीं उतर रहे हैं लेकिन उनके पास 'एक्स' फैक्टर है। मैं अब भी मानता हूं कि वह शानदार बल्लेबाज हैं जो मैदान में आने के बाद बड़े शॉट खेलकर मैच का रुख मोड़ सकते हैं। अभी कुछ समय पहले तक पंत तीनों प्रारूपों में विकेटकीपर के तौर पर टीम की पहली पसंद थे लेकिन खराब फॉर्म के कारण टेस्ट टीम में उनकी जगह अनुभवी रिद्धिमान साहा ने ले ली। लक्ष्मण ने कहा कि एक बल्लेबाज के तौर पर वह उलझन में दिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह दबाव में हैं। आपने कई बार देखा है जब वह पूरे प्रवाह में खेलते हैं तो स्पिनरों के खिलाफ उनकी एक अलग मानसिकता और तकनीक दिखती है। मुझे लगता है कि वह अंतिम-11 में अपनी जगह बनाए रखने के लिए काफी दबाव में होंगे।

अगले साल टी-20 विश्व कप से पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सैमसन की जगह अब भी पंत ही पहली पसंद होंगे लेकिन महेंद्र सिंह धौनी भी शायद तब तक वापसी कर लें।

देश का नाम रोशन करने को मेहनत की : बजरंग

अगस्त में भारत के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी। उस समय वह विश्व चैंपियनशिप की तैयारियों में व्यस्त थे जिसकी वजह से यह पुरस्कार लेने के लिए नहीं आ सके थे। एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता बजरंग ने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। अनिल भारद्वाज ने बजरंग पूनिया से खास बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंशः

नई दिल्ली में गुरुवार को खेल मंत्री किरन रिजिजू से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ग्रहण करते पहलवान बजरंग पूनिया ● जागरण

साक्षात्कार

● जिस पुरस्कार के लिए आपने लंबे समय संघर्ष किया, वह आपको अब मिला है। कितनी खुशी है?

-यह सही है कि मैंने पिछले वर्ष पुरस्कार का दावा किया था लेकिन मैंने दावे के मुताबिक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया। देश का नाम रोशन करने के लिए संघर्ष किया। मेरे गुरु व बड़े भाई योगेश्वर दत्त ने कहा था कि सिर्फ पदक जीतने पर ध्यान रखो। देश के लिए पदक जीतने से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता।

● आपने कहा कि खेल रत्न पुरस्कार पाने का सपना पूरा हो गया है लेकिन यह अगस्त में पूरा हो गया था?

-राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं पुरस्कार ग्रहण नहीं कर पाया था। उन दिनों में विश्व चैंपियनशिप की तैयारी के लिए रूस में था और पुरस्कार लेने नहीं आ सका। अगस्त में घोषणा हो चुकी थी लेकिन अब पुरस्कार ग्रहण किया है तो खुशी व तमन्ना पूरी हुई। इसके लिए लंबा संघर्ष व मेहनत की है। क्योंकि यह पुरस्कार तभी मिलता है जब आप देश के लिए बड़े पदक जीत पाते हो।

● आपने जिम्मेदारी बढ़ने की बात कही, कौन सी जिम्मेदारी बढ़ गई?

-जब किसी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार मिलता है तो खेल प्रेमियों की उस खिलाड़ी से ज्यादा आशा बढ़ जाती है। खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार खेल रत्न है। अब कुश्ती प्रेमियों को मुझसे टोक्यो में पदक जीतने की आशा है। टोक्यो में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी बढ़ी है।

● तब और अब में क्या फर्क महसूस हो रहा है। यह पुरस्कार अगस्त में लेना था। आज विश्व चैंपियनशिप का पदक है और पुरस्कार भी है?

-पुरस्कार लेना हर खिलाड़ी का सपना होता है और मेरा भी था। उस समय देश के लिए पदक जीतने का लक्ष्य था और उसमें मैं कामयाब रहा था। सही कहा आपने, आज खुशी दोगुनी है। पदक जीतने के बाद पुरस्कार पा रहा हूं।

● आपके पिता का कहना है कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, उनका बेटा खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार हासिल करे?

-हर पिता का सपना होता है, उसका बेटा ऊंचाई और सम्मान हासिल करे। मेरे साथ मेरे पिता ने भी पुरस्कार का इंतजार किया और पुरस्कार से मेरे पिता के साथ कुश्ती प्रेमियों को खुशी है।

● 2016 के बाद आप राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नहीं खेले और इस बार नहीं खेल रहे, क्या कारण है?

-कारण एक ही है, दूसरे पहलवानों को मौका देना। राष्ट्रीय स्तर पर हम उन उभरते हुए पहलवानों को मौका दे सकते हैं जो आगे चलकर देश के लिए पदक जीत सकते हैं।

● कुश्ती के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सेना में भर्ती होने में कुश्ती के ही लोग शामिल हैं?

-मुझे नहीं पता कौन शामिल हैं लेकिन जो भी हैं वह कुश्ती की छवि को खराब कर रहे हैं। उन्हें रोका जाना चाहिए। पहलवानों ने मेहनत व त्याग कर दुनिया में देश का नाम रोशन किया है।

बजरंग पूनिया ने ग्रहण किया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

नई दिल्ली, जेएनएन: भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को यहां भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के मुख्यालय में गुरुवार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल मंत्री किरन रिजिजू ने उन्हें यह सम्मान देकर सम्मानित किया। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। 25 साल के पूनिया को कुश्ती में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता बजरंग विश्व चैंपियनशिप की तैयारियों के चलते 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों इस पुरस्कार को ग्रहण नहीं कर पाए थे। अब रिजिजू से बजरंग ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इसके साथ ही उन्हें 32 लाख 72 हजार रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा भारत के ट्रैक एवं फील्ड के एथलीट मुहम्मद अनस और गोला फेंक एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया जबकि एथलेटिक्स कोच मोहिंदर सिंह ढिल्लो ने द्रोणाचार्य पुरस्कार ग्रहण किया। मोहिंदर, तेजिंदर पाल सिंह तूर को प्रशिक्षण देते हैं और उनके मार्गदर्शन में ही तूर ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया है। इस मौके पर रिजिजू ने कहा, 'मैं आप सभी पुरस्कार ग्रहण करने वालों को बधाई देता हूं। आप सभी लोग अपना पूरा समय देश की सेवा करने में दे रहे हैं।'

सड़क सुरक्षा को लेकर मुहिम चलाना चाहते हैं गिल

विकास पांडेय, नई दिल्ली : ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 30 नवंबर और एक दिसंबर को एक्स-1 रेसिंग लीग का आयोजन होगा। रैली ड्राइवर गौरव गिल इसके जरिये ट्रैक रेसिंग की दुनिया में वापसी करते नजर आएंगे। टीम दिल्ली के लिए इस लीग में उतर रहे गिल मोटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार हासिल करने वाले भारत के पहले ड्राइवर हैं।

ट्रैक पर वापसी को लेकर गिल ने कहा कि रेसिंग की मेरी पृष्ठभूमि काफी मजबूत रही है इसलिए एक्स-1 वालों ने मुझे इस लीग के लिए बुलाया तो मैं मना नहीं कर पाया। ट्रैक प्रतियोगिताओं में भी मैं कई खिताब जीत चुका हूं। यह कुछ अलग करने का सही फैसला था। इस लीग में अलग-अलग तरह के ड्राइवर हैं इसलिए मैं इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित हूं। जोधपुर में इंडियन रैली चैंपियनशिप के दौरान गिल की कार की चपेट में आने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस मंजर को याद करते हुए गौरव ने कहा कि वह दौर मेरे जीवन का सबसे मुश्किल और डरावना दौर था। मैं दुआ करूंगा कि भविष्य में वैसा किसी के साथ ना हो। मैं सड़क सुरक्षा को लेकर मुहिम चलाना चाहता हूं।

मेरी कोशिश है कि भविष्य में ट्रैफिक पुलिस और भारतीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाऊं। वह झकझोर देने वाली घटना थी। रैली में सुरक्षा के इंतजाम पर गिल ने कहा कि इस खेल की प्रकृति ही ऐसी है जिसमें जोखिम है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। केरल में एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान एक वालंटियर एथलीट द्वारा फेंके गए भाला को उठाने जा रहा था लेकिन तभी दूसरे स्पर्धा के एक प्रतियोगी ने चक्का फेंका और वह उस वालंटियर को लगा जिससे उसकी मौत हो गई। अब आप इसे किसकी गलती कहेंगे।

मैनचेस्टर के मालिकों ने खरीदी मुंबई सिटी की 65 फीसद हिस्सेदारी

- मैनचेस्टर के मैनेजर पेप गॉडियोला मुंबई सिटी एफसी के मैनेजर के संपर्क में रहेंगे
- पहली बार कोई यूरोपियन क्लब बना भारतीय क्लब का हिस्सेदार

एक कार्यक्रम दौरान नीता अंबानी और फेरान सोरियानो। प्रेट्र

मुंबई, प्रेट्र : इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन मैनचेस्टर सिटी के स्वामित्व वाली कंपनी सिटी फुटबॉल ग्रुप (सीएफजी) ने गुरुवार को इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) फ्रेंचाइजी मुंबई सिटी एफसी की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी।

इस अधिग्रहण की घोषणा गुरुवार को सीएफजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फेरान सोरियानो और फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड एवं रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबानी ने की। इस अवसर पर नीता अंबानी ने कहा, 'यह एक ऐतिहासिक अवसर है। भारतीय फुटबॉल ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, यह उसका जश्न है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई सिटी एफसी को भारतीय फुटबॉल को इस ऐतिहासिक भागीदारी का फायदा मिलेगा।' मुंबई सिटी एफसी का घरेलू मैदान 8,000 की क्षमता वाला मुंबई फुटबॉल एरिना है। आइएसएल के छठे सत्र में टीम ने अब तक पांच मैच खेले हैं। सोरियानो ने कहा कि मैनचेस्टर सिटी के स्पेनिश मैनेजर पेप गॉडियोला मुंबई सिटी एफसी के मैनेजर के संपर्क में रहेंगे। इसके साथ ही पहली बार कोई यूरोपियन क्लब भारतीय क्लब का हिस्सेदार बना है।

अब मुंबई सिटी एफसी को ग्रुप की व्यावसायिक और फुटबॉल की जानकारियों का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही क्लब की पहुंच सीएफजी ग्लोबल कमर्शियल प्लेटफॉर्म तक होगी। सिटी फुटबॉल ग्रुप को मैनचेस्टर सिटी के स्वामित्व के लिए जाना जाता है। इस ग्रुप के पास अन्य फुटबॉल क्लबों में यूएस की न्यूयॉर्क सिटी, ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न सिटी एफसी, जापान के योकोहामा एफ मैरिनो, उरुग्वे के क्लब एटलेटिको टॉर्क, स्पेन के गिरोना एफसी और चीन के सिचुआन जिउनिउ एफसी शामिल हैं। सीएफजी के अब दुनिया भर में 13 कार्यालय और आठ फुटबॉल क्लब हैं। सीएफजी की स्थापना मार्च 2013 में हुई थी। इसके आठ क्लबों में 1500 से अधिक फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो हर साल करीब 2500 से अधिक मैच खेलते हैं।

मारूफ चाहती हैं पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैच खेले भारत

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान की महिला टीम की कप्तान बिसमाह मारूफ ने गुरुवार को कहा कि भारत को खेलों को राजनीति से अलग रखकर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैच खेलने चाहिए। बिसमाह ने निराशा जताई कि पाकिस्तान इस साल आइसीसी महिला चैंपियनशिप में भारत के साथ नहीं खेल सका। उन्होंने कहा कि भारत की टीम अच्छी है और हम उसके साथ खेलना चाहते थे। भारत को खेलों को सियासत से अलग रखना चाहिए।

मेरे साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में हुई नस्ली घटना से अब मैं बाहर आ चुका है।
– जोफ्रा आर्चर, तेज गेंदबाज, इंग्लैंड

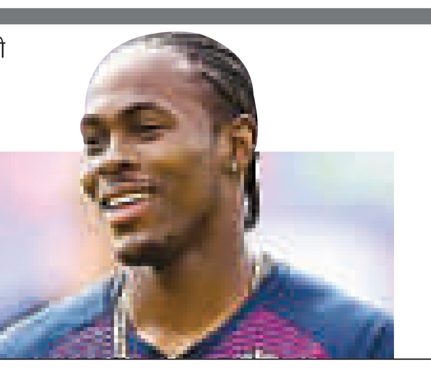

न्यूज गैलरी

श्रीकांत और सौरभ क्वार्टर फाइनल में

लखनऊ : पूर्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत और सौरभ वर्मा ने गुरुवार को यहां सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया लेकिन युवा लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स से बाहर ,हो गए। श्रीकांत ने हमवतन पी कश्यप को 18-21, 22-20, 21-16 से हराया। सौरभ ने हमवतन भारतीय अलाप मिश्रा को 21-11, 21-18 से पराजित किया। अब उनका सामना थाइलैंड के कुनालवत वितिदसार्न से होगा जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले बी साई प्रणीत को 21-11, 21-17 से हराया। 18 वर्षीय लक्ष्य भी अनुभवी सोन वान से हार गए। वान ने यह मैच 21-14, 21-17 से जीता। अजय जयराम को चीन के झाओ जुन पेंगे के हाथों तीन गेम तक चले मैच में 18-21, 21-14, 28-30 से हार का सामना करना पड़ा। अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की महिला डबल्स जोड़ी इंग्लैंड की चोले बिर्च और लॉरेन स्मिथ के खिलाफ पहले गेम के बाद ही मैच से हट गई। (प्रेट्र)

सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप आज से

जालंधर : तीन दिवसीय सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप यहां शुक्रवार से शुरू हो रही है जहां पहलवानों की नजरें आगामी दक्षिण एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई करने पर लगी होंगी। पुरुषों और महिलाओं की फ्री स्टाइल स्पर्धा में सात वर्गों में विजेताओं को दक्षिण एशियाई खेलों (सैग) में भारत के प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। पुरुषों के फ्री स्टाइल में 74 किग्रा में अमित धनकड़, सचिन राठी और प्रवीण राणा भाग लेंगे। इस वर्ग में भारत को अभी सुशील कुमार का विकल्प नहीं मिला है। महिला वर्ग में विनेश फोगाट (55 किग्रा), रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक (62 किग्रा), सीमा बिस्ला प्रमुख पहलवान होंगी। (प्रेट्र)

मैराज, गुरजोत निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्कीट में आगे

नई दिल्ली : ओलंपियन मैराज अहमद खान और पंजाब के गुरजोत सिंह ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरुवार को पुरुषों के स्कीट वर्ग के क्वालीफायर में चार दौर में सभी सौ निशाने सटीक लगाकर बढ़त बनाई। स्कीट निशानेबाजी में जूनियर वर्ग में पंजाब के राजवीर सिंह गिल शीर्ष पर रहे। वहीं गनीमत शेखों महिला और जूनियर महिला वर्ग में अग्रणी रही। ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके अंगद वीर सिंह बाजवा, स्मित सिंह, अमरिंदर सिंह चीमा और राजवीर ने 98 का स्कोर किया। (प्रेट्र)

पाकिस्तान को पस्त करने को तैयार भारत

डेविस कप ▶ सुमित, रामकुमार व पेस जैसे भारतीय खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की आस

सीनियर खिलाड़ियों के हटने से कमजोर पड़ी पाकिस्तानी टेनिस टीम

नूर-सुल्तान (कजाखिस्तान), प्रेट्र : मजबूत भारतीय टीम से उम्मीद है कि शुक्रवार से यहां शुरू होने वाले डेविस कप मुकाबले में वह कमजोर पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से पार कर लेगी जिसके नाटकीय परिस्थितियों के बाद मुकाबलों को तटस्थ स्थल पर आयोजित कराने का फैसला किया गया।

स्थल पर अंतिम समय तक अनिश्चितता बनी रही जिससे दोनों टीमों में खिलाड़ियों के चयन को लेकर संदेह रहा। आखिर में अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आइटीएफ) ने इस मुकाबले को नूर-सुल्तान में कराने का फैसला किया क्योंकि उसके स्वतंत्र पंचाट ने पाकिस्तान टेनिस महासंघ की समीक्षा की अपील ठुकरा दी थी। सुमित नागल, रामकुमार रामनाथन और अनुभवी लिएंडर पेस जैसे खिलाड़ियों की उपस्थिति से भारत के आसानी से जीतने की उम्मीद है जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी अब भी आइटीएफ फ्यूचर्स स्तर के टूर्नामेंट में छाप छोड़ने में जूझ रहे हैं। सीनियर खिलाड़ियों के हटने पाकिस्तानी कमजोर पड़ गई है। इस मुकाबले की विजेता टीम मार्च में क्रोएशिया में होने वाले 2020 में विश्व ग्रुप क्वालीफायर में जगह बनाएगी। वहीं, 46 वर्षीय पेस के लिए सबसे ज्यादा डबल्स जीत का अपना डेविस कप रिकॉर्ड बेहतर करने का मौका होगा जिसमें वह 43 जीत से शीर्ष पर हैं। यह रिकॉर्ड उन्होंने पिछले साल चीन के खिलाफ खेलते हुए हासिल किया था। रामकुमार शुक्रवार को मुहम्मद शोएब के खिलाफ मुकाबले की शुरुआत करेंगे जो आइटीएफ फ्यूचर्स टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में एक भी मैच नहीं जीते हैं। दूसरे सिंगल्स में नागल का सामना अब्दुल रहमान से होगा। शून्य से कम तापमान के कारण यह मुकाबला इंडोर हार्ड कोर्ट पर खेला जाएगा। शनिवार को मुकाबले के दूसरे दिन पेस और जीवन का सामना रिवर्स सिंगल्स में शोएब और हुजाएफा से होगा। अगर भारत 3-0 की अजेय बढ़त बना लेता है तब भी चौथा मुकाबला खेला जाएगा। टीमों के पास पांचवें मुकाबले को नहीं खेलने का विकल्प है।

नूर-सुल्तान में एक साथ भारत की डेविस कप टीम। फाइल फोटो, प्रेट्र

> पाकिस्तान की टीम में युवा खिलाड़ी हैं जो मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ खेलेंगे, उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने (पाकिस्तान) कहा कि वे फाइटर हैं और अंत तक लड़ेंगे। हम सूपड़ा साफ करने की कोशिश करेंगे।
> – रोहित राजपाल, गैर खिलाड़ी कप्तान, भारत

दो साल बाद टेनिस कोर्ट पर वापसी करेंगी सानिया

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने गुरुवार को कहा कि जनवरी 2020 में होने वाले होबार्ट अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट के जरिये वह मातृत्व अवकाश के बाद प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी करेंगी। 33 वर्षीय सानिया ने पिछली बार अक्टूबर 2017 में चीन ओपन में भाग लिया था। वह होबार्ट अंतरराष्ट्रीय में विश्व रैंकिंग में 38वें स्थान पर काबिज यूक्रेन की नाडिया किचेनोक के साथ जोड़ी बनाएंगी। सानिया ने पिछले साल अक्टूबर में बेटे इजहान को जन्म दिया।

सानिया ने कहा, 'मैं होबार्ट में खेलूंगी, इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खेलूंगी। मैं अगले महीने मुंबई में भी एक टूर्नामेंट (आइटीएफ महिला टूर्नामेंट) में खेलूंगी, हालांकि इस प्रतियोगिता में खेलना मेरी कलाई की चोट पर निर्भर करेगा लेकिन होबार्ट और ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जरूर खेलूंगी।' सानिया ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अमेरिका के राजीव राम के साथ मिक्स्ड डबल्स में जोड़ी बनाएंगी। सानिया ने कहा कि वह 2020 टोक्यो ओलंपिक का टिकट पाने की कोशिश करेंगी। हालांकि सानिया की लंबे समय बाद टेनिस कोर्ट पर वापसी आसान नहीं होने वाली है क्योंकि उन्हें अपनी लय बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

'टेनिस को अधर में छोड़ा, क्रिकेट होता तो मामला संसद में उठता'

▶ **पूर्व डेविस कप कप्तान भूपति ने कहा कि पाकिस्तान में टेनिस खेलने के मामले में टेनिस संघ और सरकार ने खिलाड़ियों को अधर में छोड़ा**

मुंबई, प्रेट्र : पूर्व डेविस कप कप्तान महेश भूपति ने गुरुवार को कहा कि भारत के टेनिस खिलाड़ियों ने जब डेविस कप मुकाबले के लिए पाकिस्तान की यात्रा के संबंध में सुरक्षा चिंता व्यक्त की तो टेनिस महासंघ और सरकार ने उन्हें अधर में छोड़ दिया। अगर क्रिकेट का मामला होता तो संसद में भी मामला उठता।

भूपति ने कहा, 'यह अनुचित है कि एआइटीए ने टीम का समर्थन नहीं किया और सरकार ने भी कुछ नहीं कहा इसलिए हर किसी ने हाथ खड़े कर लिए, जिससे दिखता है कि हमारे देश में टेनिस खेलों के कार्यक्रम में कितना महत्व रखता है। अगर सरकार में से किसी ने भी कहा होता कि पाकिस्तान जाना सुरक्षित नहीं है तो काम हो गया होता लेकिन कोई भी यह कहने को तैयार नहीं था। अगर भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाना होता तो सांसद संसद में खड़े होते और इसके बारे में कुछ न कुछ कहते लेकिन जब बात हमारी (टेनिस खिलाड़ियों) थी तो यह मायने नहीं रखता था।'

भूपति ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला अलग ही स्तर का होता है। पाकिस्तान के बनने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव है। पिछले दो दशक से किसी भी खेल की टीम ने वहां का दौरा नहीं किया था और अचानक से ही वे कह रहे हैं कि भारतीय टेनिस टीम को वहां जाना चाहिए। इसके खिलाफ फैसला लेने के लिए हर कोई खिलाड़ियों की आलोचना कर रहा है जो अनुचित है। सुरक्षा संबंधित चिंताओं के कारण डेविस कप के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से इन्कार के बाद अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआइटीए) ने भूपति को कप्तान के पद से हटा दिया था। हालांकि बाद में अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ ने सुरक्षा कारणों से यह मुकाबला पाकिस्तान से हटा दिया गया और अब यह शुक्रवार से कजाखस्तान के नूर सुल्तान में शुरू होगा।

भूपति ने यहां उस घटना को याद करते हुए कहा, 'मैं अब भी दैनिक रूप से खिलाड़ियों) के संपर्क में हूं। महासंघ ने मेरे साथ जो तरीका अपनाया, मैं उससे निराश था। जब वे मुझे कप्तान बनाना चाहते थे तो वे मुझसे बैठक के लिए हैदराबाद तक पहुंच गए थे। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, अगर वे समझते हैं कि मेरे हटने का समय आ गया है लेकिन शिष्टाचार के तहत कम से कम एक फोन तो कर सकते थे कि देखिये हम समझते हैं कि अब किसी नए को लाने का समय आ गया है। मैं इसका सम्मान करता लेकिन मुझे इस तरह का कोई फोन नहीं आया। ईमानदारी से कहूं तो जिस तरह से महासंघ पिछले 20 वर्षों में बर्ताव करता आया है, सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि भारतीय टेनिस में सभी से, उसे देखते हुए यह हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन कहीं न कहीं इससे निराशा होती है।' उन्होंने कहा, 'भारतीय टीम के लिए पाकिस्तान को दुनिया में कहीं भी हराना जरा भी मुश्किल नहीं है।'

इंग्लैंड के रग्बी कोच का बेटा न्यूजीलैंड टीम में

क्रिकेट डायरी

हैमिल्टन, एएफपी : ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। न्यूजीलैंड के पूर्व कोच और अब इंग्लैंड के सहायक रग्बी कोच जॉन मिशेल के बेटे डेरिल को हैमिल्टन में होने वाले टेस्ट के लिए चोटिल कोलिन डि ग्रैंडहोम की जगह क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। हाल में हुए रग्बी विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को मात दी थी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत हासिल की थी और अब उसकी निगाहें क्लीन स्वीप करने पर लगी हैं। उनके सीनियर बल्लेबाज रोस टेलर ने कहा कि दूसरे टेस्ट से पहले मौसम और पिच की स्थिति को देखकर ही उनका गेंदबाजी लाइन अप निर्धारित होगा।

अभ्यास सत्र के दौरान डेविड वार्नर। एएफपी

डे-नाइट टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव नहीं

एडिलेड, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट के लिए अपनी टीम में गुरुवार को कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उसने 'कंकशन सब्सीट्यूट' कैमरन बेनक्राफ्ट को रिलीज कर दिया। घरेलू टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ ब्रिसबेन में खेला गया पहला टेस्ट चार दिन के अंदर पारी और पांच रन से जीता था। स्विंग गेंदबाज माइकल नेसेर 12वें खिलाड़ी होंगे। बल्लेबाज बेनक्राफ्ट और तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए रिलीज किया गया है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ हार के करीब अफगानिस्तान

▶ **अफगानिस्तान की टीम ने दूसरी पारी में बनाए सात विकेट पर 109 रन**

▶ **वेस्टइंडीज के स्पिनर रहकीम कॉर्नवाल ने दूसरी पारी में झटके तीन विकेट**

जागरण संवाददाता, लखनऊ

अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हो रहे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ अफगानिस्तान पर हार का खतरा मंडरा रहा है। गुरुवार को वेस्टइंडीज ने दो विकेट पर 68 रनों से आगे खेलना शुरू किया। शमार्ह ब्रुक्स (111) की बेहतरीन शतकीय पारी के दम पर मेहमान टीम ने पहली पारी में 277 रन बनाए। ब्रुक्स ने 15 चौके व एक छक्का लगाया। जवाब में अफगानिस्तान ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक सिर्फ 109 रनों पर सात विकेट गंवा दिए। पहली पारी में सात विकेट लेने वाले रहकीम कॉर्नवाल दूसरी पारी में तीन विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा रोस्टन चेस ने भी तीन विकेट झटके।

अफगानिस्तान की ओर से दूसरी पारी में जावेद अहमदी ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने आउट होने से पहले 62 रनों की पारी खेलकर किसी तरह टीम को सौ रनों के पार पहुंचाया। वहीं, रहमत शाह और असगर अफगान खाता भी नहीं खोल सके। इन दोनों बल्लेबाजों को कॉर्नवाल ने अपना शिकार बनाया।

इस तरह से अफगानिस्तान 19 रनों की बढ़त बना चुका है, लेकिन उसके खाते में अब सिर्फ तीन विकेट और बचे हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज के लिए ब्रुक्स के अलावा कैंपवेल (55) और डाउरिच (42) ने भी अपना-अपना योगदान दिया। इन दोनों ने ब्रुक्स के साथ दो महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसकी बदौलत कैरेबियाई टीम 250 रनों का आंकड़ा पार करने में सफल रही।

विकेट लेने के बाद रहकीम कॉर्नवाल। एएफपी

विविध

जैन मुनि के सम्मान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा प्रतिनिधि

▶ **अमेरिका नहीं जा सकते, इसलिए राष्ट्रपति के एडवाइजर प्रोफेसर फीलिप जाधव आए**

▶ **जैन मुनि का सम्मान धार्मिक क्षेत्र में उनके की ओर से किए जा रहे कार्यों के लिए होगा**

उदय मंडलोई, देवास

मध्य प्रदेश में देवास जिले के पुष्पगिरी में शुक्रवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जैन मुनि प्रसन्न सागरजी को सम्मानित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्रतिनिधि भेजा है। पुष्पगिरि तीर्थ के संत पर्व सागरजी महाराज ने बताया कि ट्रंप की तरफ से उनके एडवाइजर प्रोफेसर फीलिप जाधव प्रसन्न सागरजी का सम्मान करेंगे। चूंकि प्रसन्न सागरजी अमेरिका नहीं जा सकते हैं, इसलिए प्रतिनिधि भेजा गया है। जैन मुनि का सम्मान धार्मिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए किया जा रहा है।

गौरतलब है कि महोत्सव में शुक्रवार को पहली बार चार मुनियों को एकसाथ आचार्यश्री की पदवी मिलेगी। आचार्यश्री पुष्पदंत सागरजी महाराज द्वारा मुनि प्रसन्न सागर, प्रमुख सागर, पुलक सागरजी और प्रणाम सागरजी महाराज को आचार्यश्री की पदवी दी जाएगी। इसके लिए सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक पांच सोने के कलश से मंगल क्रियाएं की जाएंगी।

कैलिफोर्निया की महारानी मारिया आमोर भी शुक्रवार को पुष्पगिरि पहुंचेंगी। इससे पहले उनकी बेटी इशा बेला यहां आई थीं। महारानी को भारतीय दूतावास से यहां आने की किन्हीं कारणों से अनुमति नहीं मिल सकी, इसी वजह से वह बिना सरकारी सुविधा के इंदौर होते हुए पुष्पगिरि तीर्थ पहुंचेंगी।

ग्वालियर में युवाओं ने जैन संतों के लिए बनाई चलित आहारशाला : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जैन संतों के आहार के लिए युवाओं ने चलित आहारशाला बनाई है। जैन समाज के युवा महेंद्र जैन और उनके साथियों ने श्री दिगंबर जैन जागरण युवा मंच ग्रेटर ग्वालियर की स्थापना कर चंदे की रकम से एक वैन खरीदी। वैन के अंदर रसोई का पूरा सामान रहता है। जैन संत दिन में एक बार सुबह ही आहार करते हैं, इसलिए महिलाएं सुबह पांच बजे ही वैन लेकर तय स्थान पर पहुंच जाती हैं। यह स्थान ऐसा होता है, जहां पर कुआं या बोरिंग का शुद्ध पानी उपलब्ध हो, क्योंकि जैन संत सिर्फ कुएं या बोरिंग का ही पानी पीते हैं। सुबह आठ बजे तक भोजन तैयार होता है और नौ बजे तक संतों को आहार कराया जाता है।

पीएफ घोटाला : ईओडब्ल्यू ने केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल से की पूछताछ

▶ **पावर कारपोरेशन और ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं संजय, ब्रोकर फर्मों से जुड़े कई खातों की भी चल रही है जांच**

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों के भविष्य निधि घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) के अधिकारियों ने आखिरकार पावर कारपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष संजय अग्रवाल से दिल्ली जाकर पूछताछ की है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात वरिष्ठ आइएएस अधिकारी संजय अग्रवाल वर्तमान में केंद्रीय कृषि सचिव हैं। सूत्रों का कहना है कि उनसे घोटाले से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल-जवाब किए गए हैं। ईओडब्ल्यू इसके साथ ही ब्रोकर फर्मों से जुड़े कई खातों की भी गहनता से जांच कर रही है। डीजी ईओडब्ल्यू डॉ.आरपी सिंह ने संजय अग्रवाल से दिल्ली में पूछताछ की पुष्टि की है।

ईओडब्ल्यू ने पीएफ घोटाले की जांच संभालते ही शक्ति भवन के दूसरे तल स्थित ट्रस्ट के कार्यालय में छानबीन की थी और कई अहम दस्तावेज कब्जे में लिए थे। जांच में सामने आया था कि 15 मार्च 2017 को निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से कोटेशन लिया गया था। अगले ही दिन 16 मार्च को दो और निजी कंपनियों से कोटेशन लिए गए थे और इसी दिन डीएचएफएल में भविष्य निधि की रकम निवेश किए जाने का अप्रूवल दे दिया गया था। 16 मार्च 2017 को ही तत्कालीन एमडी एपी मिश्र ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। 17 मार्च को डीएचएफसीएल को 18 करोड़ रुपये की पहली किस्त आरटीजीएस के जरिये दे दी गई थी।

ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया था कि 22 मार्च 2017 को ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में भविष्य निधि की रकम डीएचएफएल में निवेश किए जाने का अप्रूवल दिया गया था। पांच सदस्यीय बोर्ड की बैठक संबंधी जो दस्तावेज ईओडब्ल्यू के हाथ लगे थे, उसमें उप्र पावर कारपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष संजय अग्रवाल, एमडी एपी मिश्र, निदेशक वित्त सुधांशु द्विवेदी, सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता व निदेशक कार्मिक सत्यप्रकाश पांडेय (दिवंगत हो चुके) के हस्ताक्षर थे। जांच में ट्रस्ट बोर्ड की बैठक की नोटशीट में तारीख बदले जाने की बात भी सामने आई थी। ईओडब्ल्यू ने इसके बाद ही बोर्ड बैठक के सभी सदस्यों की भूमिका की जांच शुरू की थी। घोटाले से जुड़े तमाम तथ्यों को जुटाने के बाद ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने दिल्ली में संजय अग्रवाल से डीएचएफएल में पीएफ की रकम को निवेश करने के फैसले से जुड़े सवाल पूछे हैं। उनसे 22 मार्च 2017 व 24 मार्च 2017 को हुई बोर्ड की बैठकों व उनकी नोटशीट में किए गए हस्ताक्षरों को लेकर भी जानकारी की गई। बताया गया कि ईओडब्ल्यू के एसपी शकीलुज्ज्मा टीम के साथ दिल्ली गए थे और संजय अग्रवाल से पूछताछ की। संजय अग्रवाल के बयान विवेचना में शामिल किए जाएंगे। डीएचएफएल में पीएफ के अरबों निवेश किए जाने के दौरान पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष पद पर पहले संजय अग्रवाल और फिर आलोक कुमार रहे हैं। घोटाला सामने आने के बाद अध्यक्ष पद से हटाए जाने से पहले आलोक कुमार ने ही पूरे मामले की जांच कराकर एफआइआर दर्ज कराई थी। प्रकरण में ईओडब्ल्यू आरोपित सुधांशु द्विवेदी, एपी मिश्र, पीके गुप्ता, पीके गुप्ता के बेटे अभिनव गुप्ता व फर्जी ब्रोकर फर्म संचालक आशीष चौधरी को गिरफ्तार कर चुकी है।

चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

▶ **श्राइन बोर्ड के गठन के विरोध में उठाया यह कदम**

▶ **मुख्यमंत्री के समक्ष रखी तीर्थ पुरोहित समाज की बात**

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड सरकार के चारधाम श्राइन बोर्ड के गठन के निर्णय से चारधाम के पुरोहितों व हक-हकूकधारियों में उबाल है। उन्होंने सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध किया है। इस कड़ी में चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष आचार्य शिव प्रसाद ममगाईं ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। आचार्य ममगाईं ने कहा कि चारों धामों के हक हकूकधारियों पर किसी भी तरह की आंच आती है तो उन्हें अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रदेश सरकार ने बीते रोज कैबिनेट के जरिये प्रदेश में चारों धामों और इनके सहयोगी 51 मंदिरों को शामिल करते हुए चारधाम श्राइन बोर्ड के गठन का निर्णय लिया था। इसमें व्यवस्था यह की गई कि बोर्ड में चारों धाम के पुजारियों, वंशानुगत पुजारियों का भी प्रतिनिधत्व रहेगा और रावल समेत अन्य नियुक्तियां परंपरानुसार ही होंगी। दावा किया गया कि हक-हकूकधारियों के हितों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। सरकार के इस निर्णय को तीर्थ पुरोहितों ने छलावा बताया है। उन्होंने देहरादून में बैठक करने के बाद मीडिया के सामने अपना विरोध जताया।

उनका कहना है कि प्रस्तावित एक्ट में कई खामियां है जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। वहीं, चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगाईं ने भी तीर्थ पुरोहितों के समर्थन में मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने तीर्थ पुरोहितों का पक्ष रखा। आचार्य ममगाईं ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी कि मंदिरों में पूजन व आंतरिक कार्यों में कोई छेड़छाड़ न की जाए। धामों के पुजारियों की परंपरा को भी यथावत रखा जाए। इस पर मुख्यमंत्री की ओर से तीर्थ पुरोहितों को तीन दिसंबर तक का समय उपलब्ध कराने की बात कही गई।

आचार्य ममगाईं ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें तीन दिसंबर तक प्रस्ताव देने को कहा है। इसके बाद चारधाम श्राइन प्रबंधन बोर्ड विधेयक में संशोधन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहितों का पक्ष रखने के साथ ही मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भी उन्होंने सौंप दिया है।

आचार्य शिवप्रसाद ममगाईं। जागरण

उत्तराखंड सरकार की सख्ती, विदेश दौरे पर गए तो 15 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट

▶ **सरकारी खर्च पर योजनाओं और प्रशिक्षण के लिए विदेश जाते हैं अधिकारी**

विकास गुसाईं, देहरादून

उत्तराखंड के तमाम सरकारी विभागों के अधिकारी विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नाम पर विदेश जाते हैं, लेकिन इनके विदेश भ्रमण का फायदा न तो सरकार को मिलता है और न विभागों को। कारण यह कि अधिकांश अधिकारी विदेश दौरों के अपने अनुभवों की रिपोर्ट विभाग से साझा ही नहीं करते। अब शासन ने इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। शुरुआत स्वास्थ्य विभाग ने की है। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य ने देश के भीतर अथवा बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं में जाने वाले अधिकारियों को वापस आने के 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में इस समय तकरीबन 40 सरकारी महकमे हैं। ये सभी महकमे किसी ने किसी तरह से राष्ट्रीय योजनाओं से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा प्रदेश के विकास को अन्य राज्यों व विदेशों में संबंधित विभागों से जुड़ी योजनाओं के लिए भी अधिकारी प्रशिक्षण अथवा प्रारूप अध्ययन को जाते हैं। कुछ समय पहले यह बात बहुत तेजी से उठी थी कि अधिकारियों के विदेश दौरों का कोई फायदा विभागों को नहीं मिलता। इसका प्रमुख कारण विदेश दौरों से लौटने के बाद अधिकारियों द्वारा इसकी कोई रिपोर्ट न बनाना होता है।

यह स्थिति तब है, जब इस तरह के विदेश दौरों के लिए शासन इसी शर्त पर अनुमति देता है कि वह इस संबंध में विभागीय सचिव अथवा प्रभारी सचिव को रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। यह इसलिए, ताकि सरकारी कार्यों के साथ ही नई योजनाओं में उनके अनुभवों को लाभ उठाया जा सके। स्थिति यह रहती है कि न तो विदेश से आने के बाद अधिकारी रिपोर्ट बनाने के इच्छुक होते हैं और न ही शासन इसमें कोई रुचि दिखाता है।

अब शासन ने इस दिशा में सख्ती करनी शुरू की है। इसकी शुरुआत प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडेय ने की है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जारी आदेश में कहा है कि विभागीय अधिकारी देश और विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं व बैठकों में जाते हैं लेकिन वापस आकर कोई रिपोर्ट उच्च स्तर पर नहीं दी जाती।

इस कारण इन कार्यशालाओं व प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ राज्य को नहीं मिल पाता है। भविष्य में जो भी अधिकारी इस तरह के कार्यक्रमों में देश अथवा विदेश जाएंगे वे 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट उच्च स्तर पर सौंपेंगे।

फ्लिपकार्ट व मिंत्रा के कर्मचारी ही फर्जी कॉल सेंटरों को देते थे डाटा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

उप्र में नोएडा में पुलिस ने दो फर्जी कॉल सेंटर का साइबर सेल टीम ने भंडाफोड़ किया है। मौके से 45 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 22 पुरुष व 23 युवतियां शामिल हैं। सभी आरोपित कॉल सेंटर के प्रबंधक, टीम लीडर व कर्मचारी हैं। वे ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट व मिंत्रा के ग्राहकों का डाटा हासिल कर उनको लिंक भेजकर ठगी करते थे। कंपनी के कर्मचारी ही उन्हें ये डाटा उपलब्ध कराते थे। फर्जी कॉल सेंटर का मालिक दिलीप सरोज अभी फरार है।

एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि बुलंदशहर के एक व्यक्ति से ठगी की शिकायत गत दिनों मिली थी। जांच की गई तो पता चला कि ठगी का धंधा नोएडा के सेक्टर छह व सात में बने फर्जी कॉल सेंटर से संचालित किया जा रहा है। इसके बाद एसपी सिटी विनीत जायसवाल के नेतृत्व में साइबर सेल व नॉलेज पार्क कोतवाली प्रभारी बलजीत सिंह को कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करने के लिए लगाया गया।

टीम ने बुधवार रात छापेमारी कर दो कॉल सेंटरों से 45 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 16 वॉकी-टॉकी, 29 पैड मोबाइल, दो कम्प्यूटर, कीबोर्ड व माउस बरामद किया गया है। सभी आरोपित दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग जिले के रहने वाले हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपित एक हजार लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुके है। कॉल सेंटर के चार कर्मचारी पूनम, आकाश, कृष्णा व विकास की भूमिका मुख्य रहती थी।

कॉल सेंटर दो, मालिक एक : पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों फर्जी कॉल सेंटर का मालिक दिलीप सरोज है। वह दिल्ली के न्यू अशोक नगर का रहने वाला है। दिलीप के अलावा कॉल सेंटर संचालित करने में उसकी मदद करने वाला नंदन भी अभी फरार है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।

मौसम विशेष

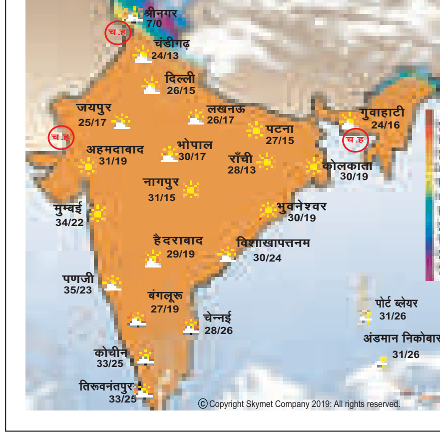

© Copyright Skymet Company 2019: All rights reserved.

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में वर्षा व बर्फबारी में कमी आऐगी। सुबह का तापमान पहाड़ों में शुन्य से नीचे रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान में बदलीयुक्त आसमान के साथ कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा होगी। दिल्ली सहिम मैदानी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। ठंड में और वृद्धि होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/22/व	अहमदाबाद	31/16/आंबा
कोलकाता	30/19/सा	बड़ौदा	32/17/सा
चेन्नई	29/22/व	नागपुर	30/14/व
हैदराबाद	29/18/आंबा	इन्दौर	28/19/व
बंगलूरू	26/19/सा	रांची	29/18/आंबा
त्रिवेन्द्रम	33/24/व	पटना	29/18/व
गुवाहाटी	24/16/सा	जमशेदपुर	31/20/आंबा
गंगटोक	06/-5/व	पुणे	31/22/सा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 29 नवंबर 2019
आजकल
16

फलस्तीन को अरब और यहूदियों के बीच बांटने की मंजूरी

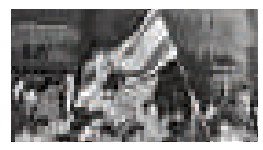

1947 में आज ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फलस्तीन को अरब और यहूदियों के बीच बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1948 में यहूदी राष्ट्र इजरायल का गठन हुआ था। मगर फलस्तीन ने बंटवारे की योजना को खारिज कर दिया था। तभी से हिंसा का दौर जारी है।

पहला व्यावसायिक रूप से सफल वीडियो गेम रिलीज हुआ

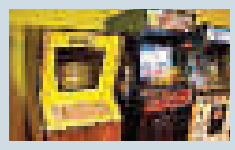

1972 में आज ही अमेरिकी वीडियो गेम डेवलपर अटारी ने दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से सफल वीडियो गेम पोंग रिलीज किया था। इसे एक आर्केड गेम के तौर पर विकसित किया गया था। आर्केड गेम्स को एंटरटेनमेंट मशीनों की तरह सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है।

शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को शत-शत नमन

शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म 1935 में आज ही शकरगढ़ (अब पाकिस्तान) में हुआ था। 1953 में नेशनल डिफेंस अकेडमी में प्रवेश लिया और पास होकर सेना में अधिकारी बने। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के सदस्य रहे। 1961 में उन्हें कांगो में विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया था। 5 दिसंबर, 1961 को उन्होंने 40 विद्रोहियों को मार गिराया और खुद भी शहीद हुए। मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। यह सम्मान पाने वाले वह एनडीए के पहले छात्र बने।

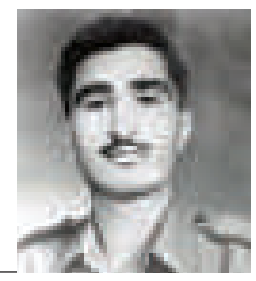

इधर-उधर की

प्लास्टिक की बोतलों से बना दी नौका

याओऊंडे, एजेंसी : मध्य अफ्रीकी देश कैमरून के इस्माइल इबोन ने समुद्र से बहकर तट पर आई प्लास्टिक की बोतलें जमाकर बॉटल-बोट बना दी। इस नौका में तीन लोग आराम से बैठकर मछली पकड़ सकते हैं। इस्माइल इबोन ने कैमरून के शहरों को प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में अपना सारा पैसा एक गैर लाभकारी संस्था में दान कर दिया है। यह संस्था प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करती है और उनसे मछुआरों के लिए ईको फ्रेंडली नौका में बनाती है। खास बात यह कि इबोन यह नौका बनाकर मुफ्त में मछली पकड़ने वालों को मुफ्त में दे देते हैं। इस नौका को बनाने में एक हजार बोतलें लगती हैं। इसका वजन 270 किलो तक होता है। इस नौका को बनाने में एक सप्ताह का समय लगता है। । पहले समुद्री तूफान में परीक्षण किया

शोध अनुसंधान

पौष्टिक आहार से टल सकती है भूलने की समस्या

संतुलित जीवनशैली अपनाने से कई समस्याओं से बचाव हो सकता है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम करने से उस स्थिति को धीमा किया जा सकता है, जिसका स्मृति पर असर पड़ता है। अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी फॉर मेडिसिन के शोधकर्ताओं के अनुसार, अक्सर ही चीजों को भूलना स्मृति में गिरावट का संकेत होता है। लेकिन स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से बुजुर्गों में ना सिर्फ हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है बल्कि याददाश्त में गिरावट को धीमा भी किया जा सकता है। इस तरह की जीवनशैली में नियमित व्यायाम और पौष्टिक आहार को शामिल किया गया है। यह निष्कर्ष 55 साल की उम्र के ऐसे 160 लोगों पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है, जो व्यायाम नहीं करते थे और स्मृति संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। -एएनआइ

शिशुओं को हृदय रोग से बचाने में स्तनपान मददगार

मां और शिशु दोनों के लिए स्तनपान लाभकारी माना जाता है। इससे शिशु की सेहत को लाभ होने के साथ ही कई समस्याओं से बचाव में मदद भी मिलती है। एक नए अध्ययन में पाया गया कि समय पूर्व जन्मे शिशुओं में स्तनपान के उपयोग से हृदय रोग से बचाव में मदद भी मिल सकती है। आयरलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन के शोधकर्ताओं के अनुसार, समय पूर्व जन्मे शिशुओं को जीवन में आगे चलकर हृदय संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इनमें छोटा हार्ट चेंबर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि अध्ययन से जाहिर होता है कि हृदय की संरचना पर मां के दूध का सुरक्षात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्तनपान से हृदय संबंधी रोग को दूर किया जा सकता है। यह निष्कर्ष समय पूर्व जन्मे 30 बच्चों पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। -प्रेट्र

वैज्ञानिकों ने खोजा सूर्य से 70 गुना बड़ा ब्लैक होल

- वैज्ञानिकों का दावा तारों की उत्पति से जुड़ी मौजूदा अवधारणों को चुनौती देती है यह खोज
- एलबी-1 रखा गया है नए ब्लैक होल का नाम, पृथ्वी से 15 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी पर है स्थित

हमारी आकाशगंगा में 10 करोड़ ब्लैक होल हैं। प्रतीकात्मक

बीजिंग, प्रेट्र : हमारा ब्रह्मांड कई अचरजों से भरा पड़ा है। इसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन कर आए दिन नई-नई जानकारियां देते रहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा में एक ऐसा ब्लैकहोल खोजा है जो सूर्य से 70 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह खोज तारों की उत्पति से जुड़ी मौजूदा अवधारणों को चुनौती देती है।

एक अनुमान के मुताबिक, हमारी आकाशगंगा में लगभग 10 करोड़ ब्लैकहोल हैं। इनका निर्माण बड़े तारों में विस्फोट से होता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक हिस्सा है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश की किरणें भी वहां से बाहर नहीं निकल पातीं। अब तक वैज्ञानिकों का मानना था कि एक स्टेलर ब्लैकहोल का द्रव्यमान सूर्य से 20 गुना अधिक नहीं होता है। इस ब्लैकहोल की खोज चाइना एकेडमी ऑफ साइंस स्थित नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेट्री ऑफ चाइना (एनएओसी) से जुड़ी एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने की है। वैज्ञानिकों का यह अध्ययन नेचर नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस ब्लैकहोल का नाम एलबी-1 रखा गया है। हमारे ग्रह से इस ब्लैक होल की दूरी 15 हजार प्रकाश वर्ष है।

एनएओसी के वैज्ञानिक लियू जेफिंग ने कहा, 'इतने द्रव्यमान का ब्लैकहोल हमारी आकाशगंगा में नहीं होना चाहिए क्योंकि एलबी-1 का द्रव्यमान अनुमानित से लगभग दोगुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अब व्याख्याकारों के सामने इस विशालकाय ब्लैकहोल के बारे में नए सिरे से अध्ययन करने की चुनौती होगी।

जेफिंग ने कहा, 'कुछ साल पहले तक स्टेलर ब्लैकहोल की खोज तभी होती थी जब वह साथी तारे से छोड़ी गई गैस को निगल लेते थे। इस प्रक्रिया से शक्तिशाली एक्स-रे का उत्सर्जन होता है और पृथ्वी से इसका पता लगाया जा सकता है।'

शोधकर्ताओं ने बताया कि हमारी आकाशगंगा में कई स्टेलर ब्लैक होल धीरे-धीरे खगोलीय पिंड को अपने भीतर समेटते हैं। ऐसे में 'एक्स-रे' का उत्सर्जन में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता। यही कारण है कि अब तक केवल दो दर्जन स्टेलर ब्लैक होल्स की ठीक से पहचान हो पाई है।

अल्कोहल के अणु घटा सकते हैं प्रदूषण

उम्मीद ▶ अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अध्ययन में आया सामने

पता लगाया कि किस तरह से होता है प्रदूषक कणों का निर्माण

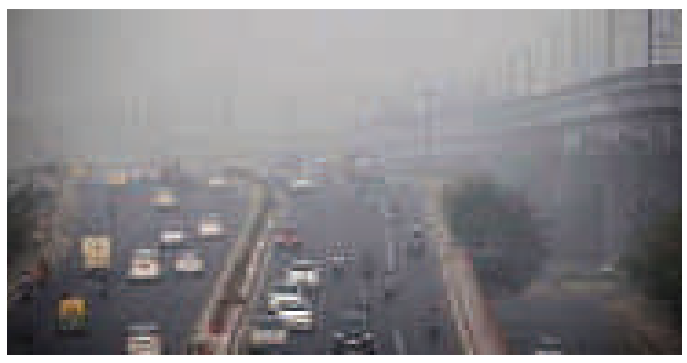

वायु प्रदूषण के कारण बीते दिनों राजधानी दिल्ली की हवा भी विषाक्त हो गई थी। फाइल

वाशिंगटन, प्रेट्र : वायु प्रदूषण वर्तमान में सबसे बड़ी वैश्विक समस्याओं में से एक है। दुनियाभर के वैज्ञानिक इससे निपटने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। इसी दिशा में अमेरिकी शोधकर्ताओं को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। एक अध्ययन के आधार पर उन्होंने दावा किया है कि वातावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद अल्कोहल के अणु प्रदूषण फैलाने वाले उन खतरनाक कणों के निर्माण को कम कर सकते हैं, जो धुंध का कारण बनते हैं। इस अध्ययन के आधार पर वायु प्रदूषण, मौसम और जलवायु से संबंधित अधिक सटीक मॉडल विकसित किए जा सकते हैं।

अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं इस अध्ययन में कई बातों पर फोकस किया। उन्होंने यह पता लगाया कि धुंध के अवयवों में मेथेनॉल किस प्रकार मिल जाता है। साथ ही इसके जरिये किस तरह सल्फर ट्राईऑक्साइड और बेहद सूक्ष्म प्रदूषक कणों (पीएम 2.5 और पीएम 10) के निर्माण को कम किया जा सकता है। बता दें कि ये प्रदूषक कण बेहद महीन होते हैं। इंसानों के बाल की मोटाई भी इन अतिसूक्ष्म कणों से 10 से 30 गुना अधिक होती है। ये प्रदूषक कण कितने खतरनाक होते हैं इसका पता लैंसेट नामक जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पीएम 2.5 के कारण केवल वर्ष 2015 में ही करीब 5.25 लाख लोगों को समयपूर्व जान गंवानी पड़ी थी।

अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किए गए ताजा अध्ययन को पीएनएएस नामक जर्नल में विस्तार से प्रकाशित किया गया है। अध्ययन में सामने आया है कि शुष्क और प्रदूषण की उस स्थिति में जब वातावरण में पर्याप्त मात्रा में अल्कोहल और सल्फर ट्राईऑक्साइड मौजूद होता है और पानी की मात्रा कम होती है, तब रासायनिक क्रिया जहरीले कणों का निर्माण कम कर देती है।

पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इस अध्ययन के सह-लेखक जोसफ एफ फ्रांसिस्को के मुताबिक, वर्तमान में हम पीएम 2.5 और पीएम 10 को लेकर चिंतित हैं क्योंकि ये प्रदूषक कण वायु की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं। बकौल जोसफ, वातावरण में मौजूद सल्फर ट्राईऑक्साइड पानी के अणुओं के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख घटक है। इसी क्रिया की वजह से वातावरण में कणों में वृद्धि और नेटवर्क संरचनाओं का निर्माण होता है। अध्ययन के दौरान हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि किस तरह से इन कणों के निर्माण को कम किया जा सकता है?

इस तरह किया शोध

शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर मॉडल और अणुओं के सिमुलेशन का उपयोग किया। इसमें सामने आया कि यदि वातावरण में अल्कोहल जैसे कि मेथेनॉल आदि वातावरण में पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है तो सल्फर ट्राईऑक्साइड उससे रासायनिक क्रिया करती है। इस रासायनिक क्रिया के चलते मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जो प्रदूषक कणों के निर्माण के लिए पर्याप्त चिपचिपा माहौल बनाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, चूंकि यह रासायनिक क्रिया, अल्कोहल को अधिक चिपचिपे यौगिक में परिवर्तित कर देती है, इसलिए शुरुआत में उन्होंने सोचा कि इसकी वजह से प्रदूषक कणों के बनने की प्रकिया को बढ़ावा मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल, वातावरण में मौजूद ज्यादातर अल्कोहल सल्फर ट्राईऑक्साइड के निर्माण में ही खर्च हो जाता है। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए इसकी बेहद कम मात्रा ही रह जाती है। हालांकि, यह रासायनिक क्रिया पीएम 2.5 और पीएम 10 के कणों के निर्माण को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। शोधकर्ताओं ने कहा, इस अध्ययन से हमें पता चला है कि एक रासायनिक क्रिया के जरिये दूसरी रासायनिक क्रिया को संतुलित कर सकते हैं। यदि किसी तरह हम वातावरण में अल्कोहल की मात्रा को बदलने में कामयाब हो जाएं तो प्रदूषक कणों के निर्माण को कम किया जा सकता है।

थ्री डी पैदल पथ

ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में कलाकारों के एक ग्रुप ने सड़कों पर थ्रीडी पैदल पथ बनाए हैं। सड़कों पर यह पथ पैदल चलने वालों के लिए होते हैं, किंतु वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नही करते। कला के जरिये इस ओर ध्यान आकर्षित करने का यह सकारात्मक कदम बताया जा रहा है। रायटर

ट्रैफिक से तंग व्यक्ति ने बनाया हेलीकॉप्टर

रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से तंग आकर इंडोनेशिया के एक शख्स ने अपना निजी हेलीकॉप्टर ही बना डाला। सुकाबुमी कस्बे के रहने वाले 42 वर्षीय जुजुन जुनैदी का सपना अब अपने निजी हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने का है। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े पुराने कलपुर्जों और स्क्रैप से हेलीकॉप्टर तैयार किया है, जो पेट्रोल से उड़ेगा। जुनैद ने वीडियो से बनाने की विधि सीखी है। करीब आठ मीटर लंबे इस हेलीकॉप्टर के निर्माण में 21 सौ डॉलर (करीब डेढ़ लाख रुपये) खर्च हो चुके हैं। हालांकि उनकी पत्नी येति हेलीकॉप्टर निर्माण पर होने वाले खर्च से परेशान हैं और उनका कहना कि यदि यह सिलसिला जारी रहा तो उनके पास खाने के लिए भी पैसे नही बचेंगे। जो भी है सभी जुजुन के जुनून और हौसले की तारीफ कर रहे हैं। एएफपी

अध्ययन

ब्रिटेन की एक्सेटर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया दावा, शार्क, पेंग्विन, कछुओं की इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग हो सकती है फायदेमंद

अपने परितंत्र की अहम जानकारियां दे सकते हैं समुद्री जीव

- शोधकर्ताओं ने 183 जीवों की प्रजातियों का किया अध्ययन
- इनसे मिला डाटा जलवायु परिवर्तनशीलता और मौसम की भी कर सकता है निगरानी

यह अध्ययन ग्लोबल चेंज बायोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। फाइल

लंदन, आइएएनएस : समुद्री परितंत्र के बारे में नई जानकारियां एकत्र करने के लिए शोधकर्ताओं ने एक नया तरीका सुझाया है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि शार्क, पेंग्विन, कछुए और अन्य समुद्री प्रजातियां इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग की मदद से इंसानों को समुद्र के बारे में कई अहम जानकारियां देने में मदद कर सकती हैं।

ब्रिटेन की एक्सेटर यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने कहा, 'कई समुद्री जीव ऐसे काम आसानी से कर लेते हैं, जिन्हें आम तौर पर इंसानों के लिए करना कठिन होता है। इसमें बर्फ के नीचे गोता लगाना, उथले पानी में तैरना या धाराओं के खिलाफ चलना जैसे काम शामिल हैं। ये सभी काम समुद्री जीवों के व्यवहार में शामिल रहते हैं। ऐसे में सेंसर से जरिये समुद्री परितंत्र के बारे में कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं।'

एक्सेटर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक डेविड मार्च ने कहा, 'हम समुद्र के बारे में बताने और सिखाने के लिए पशु-जनित सेंसर की क्षमता को उजागर करना चाहते हैं। हालांकि यह पहले से ही सीमित पैमाने पर हो रहा है, लेकिन इसमें अभी काफी गुंजाइश है।' उन्होंने कहा कि हजारों समुद्री जानवरों को विभिन्न प्रकार के अनुसंधान और संरक्षण उद्देश्यों के लिए टैग किया गया है। लेकिन वर्तमान में महासागरों से एकत्रित जानकारी का व्यापक रूप से जलवायु परिवर्तन और अन्य बदलावों को ट्रैक करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय ज्यादातर अनुसंधान जहाजों, ड्रोन और फ्लोटिंग सेंसरों द्वारा समुद्र की निगरानी की जाती है।

मार्च ने कहा, 'शोध के दौरान हमने 183 प्रजातियों का अध्ययन किया, जिसमें ट्यूना, व्हेल, शार्क और उड़ने वाले समुद्री पक्षी शामिल हैं। साथ ही हमने खराब सेंसर वाले क्षेत्रों में महासागर की सतह की पहचान करने के लिए फ्लोटिंग सेंसर से 15 लाख से अधिक माप बनाए हैं।

ग्लोबल चेंज बायोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि कछुए या शार्क द्वारा एकत्र किया गया डाटा वैश्विक जलवायु परिवर्तनशीलता और मौसम पर बड़े प्रभाव के साथ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी समुद्र की निगरानी बढ़ा सकते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि उनका काम पारिस्थितिकीविदों और समुद्र विज्ञानियों के बीच सहयोग के लिए आह्वान करता है।

फिल्म रिव्यू

कमजोर कहानी, दमदार एक्शन

कमांडो 3

निर्देशन : आदित्य दत्त
प्रमुख कलाकार : विद्युत जामवाल, अदा शर्मा, अंगीरा धर, गुलशन देवैया, राजेश तैलंग
अवधि : 2 घंटे 13 मिनट

सोशल मीडिया के प्रभाव ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींचा है। विपुल अमृतलाल शाह के निर्माण और आदित्य दत्त के निर्देशन में बनी 'कमांडो 3' में राष्ट्रवाद के मुद्दे को केंद्र में रखा गया है। इसमें सोशल मीडिया के प्रयोग से देश को आतंकी हमले से बचाने की कोशिश दिखाई गई है।

कहानी के अनुसार, दिवाली पर देश में बड़े आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए इंडियन स्पेशल फोर्स हरकत में आती है और अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह डोगरा (विद्युत जामवाल) को यह साजिश नाकाम करने का काम सौंपती है। करण को पता चलता है कि साजिशकर्ता बुराक अंसारी (गुलशन देवैया) लंदन में है। बुराक अपने संदेश वीडियो के जरिए भारत के लोगों तक भेजता है। उसकी तकरीरें सुनकर लोग धर्म परिवर्तन करने को तैयार होते हैं। उसे पकड़ने के लिए करण इंस्पेक्टर भावना रेड्डी (अदा शर्मा) के साथ लंदन जाता है। वहां पर ब्रिटिश अधिकारी मल्लिका सूद (अंगीरा धर) मिशन में उनकी मदद करती है। वहां बुराक को पकड़ने को लेकर हर मोड़ पर मुठभेड़ होती है, जिसमें सकरी गलियों से होकर बाइक चेजिंग से लेकर हाथापाई तक शामिल है। इस बार तकनीक का भी काफी उपयोग किया गया है।

कहानी में बुराक को पकड़ने का 33 दिन का काउंटडाउन दिया गया है, जो कहानी को रोमांचक बनाने में शुरू में कामयाब होता है। अतः फिल्म के शुरुआती हिस्से में पर्याप्त एक्शन है, लेकिन बाद में कहानी पर लेखक की पकड़ नहीं रहती। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की कार्यप्रणाली पर लेखकों को रिसर्च करने की जरूरत थी।

'कमांडो' सीरीज का दारोमदार विद्युत जामवाल के कंधों पर रहा है। वह एक्शन में हर बार कमाल करते हैं। इस बार भी उन्होंने एक्शन को रियल बनाए रखने की कोशिश की है। इस बार उनके साथ अदा शर्मा और अंगीरा धर भिन्न किरदारों में हैं। दोनों को एक्शन करते देखना अच्छा लगता है। दोनों के बीच नायक के प्रति प्रेम को लेकर प्रतिस्पर्धा दिखाने में लेखक-निर्देशक ने समय नहीं गंवाया है। खलनायक बने गुलशन देवैया बुराक अंसारी के तौर पर बर्बर दिखाए गए हैं, लेकिन वह प्रभावित नहीं करते हैं। उनके किरदार की गहराई में भी लेखक नहीं गए हैं। फिल्म में कुछ दृश्यों में हिंसक दृश्य और खून खराबा है। 'कमांडो 3' की दिक्कत यह है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे को कहानी में समुचित तरीके से पिरोया नहीं गया। सोशल मीडिया की ताकत का प्रयोग घटनाक्रम को विश्वसनीय नहीं बना पाता है।

फिल्म मुख्य रूप से लंदन में शूट की गई है। वहां की गलियों में बाइक पर फिल्माए गए चेजिंग शॉट, भवनों के नाम सेफ हाउस, बीआई हेडक्वार्टर देकर उसमें हॉलीवुड एक्शन फिल्मों की तरह रोमांच देने की कोशिश की गई है। मगर कमजोर कहानी इन कोशिशों पर पानी फेर देती है।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

कॉफी पीने से कम हो सकता है हृदय रोगों का जोखिम

लंदन, आइएएनएस : एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कॉफी पीने से मेटाबोलिक सिंड्रोम का खतरा कम हो सकता है। मेटाबोलिक सिंड्रोम कार्डियोवस्कुलर (हृदय संबंधी) समस्याओं के लिए जिम्मेदार होता है। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ कैटनिया के असिस्टेंट प्रोफेसर ग्यूसेप्प ग्रोस्सो ने कहा कि शोधकर्ताओं ने पोलिश और इतालवी समूहों के बीच अध्ययन कर यह पाया कि कॉफी में पाया जाने वाला पॉलीफेनोल्स से फेनोलिक एसिड और फ्लेवोनोइड्स का असर कम हो जाता है।

स्क्रीन शॉट

मुझे रिटायर हो जाना चाहिए : अमिताभ बच्चन

महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों अयान मुखर्जी निर्देशित फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग के लिए मनाली में हैं। बुधवार को मनाली पहुंचकर देर रात उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा, 'शांत... ताजगी का सार, सर्दी का एहसास, शुद्ध हवा। छोटे शहरों की सादगी हमेशा सर्वोच्च रही है। हम इनकी ईमानदारी और सादगी का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। निर्माणधीन और बनी सड़कों पर लगभग 12 घंटे कार से सफर करने के बाद एक नए माहौल और नए कमरे में ढलना और उसकी साज-सज्जा...। मुझे रिटायर हो जाना चाहिए... दिमाग कुछ सोचता है, उंगलियां कुछ और करती हैं। यह एक संदेश है।' इससे पहले अमिताभ ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन के जन्मदिन पर उनको याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, 'बाबूजी के जन्म का साल 1907 और 2019 के कैलेंडर एक जैसे हैं। बीते वर्षों में पिछले 13 वर्षों के कैलेंडर दिन और दिनांक के मामले में 2019 के जैसे थे। 1901, 1907, 1918, 1929, 1935 (जब 'मधुशाला' छपी), 1946, 1957, 1963, 1974, 1985, 1991, 2002, 2013।' उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर रामगोपाल वर्मा की फिल्म 'एंटर द गर्ल ड्रैगन' का टीजर साझा किया। इंडियन-चाइनीज को-प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म से पूजा भालेकर अपने अभिनय सफर का आगाज कर रही हैं।

हाइड्रोफोबिया के बावजूद रानी ने लिया तैराकी का प्रशिक्षण

रानी मुखर्जी आगामी फिल्म 'मर्दानी 2' में शिवानी शिवाजी रॉय नामक एक बेखौफ महिला पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगी। लेकिन उन्हें पानी में जाने से बहुत डर लगता था। इस डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। फिल्म के एक दृश्य में रानी को पानी में कुछ एक्शन सीन करने थे। यह पता चलने पर उन्होंने पहले फिल्म के निर्देशक गोपी पुथरन से सीन बदलने का आग्रह किया। गोपी ने उन्हें बताया कि ये फिल्म के जरूरी सीन हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। उसके बाद रानी के आग्रह पर तय किया गया कि इन दृश्यों को सबसे आखिर में फिल्माया जाएगा। अपने हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर से निपटने के लिए उन्होंने अनीस एडेनवाला से तैराकी का प्रशिक्षण लिया। रानी बताती हैं कि इस फिल्म की शूटिंग जून में ही पूरी हो गई थी, सिर्फ पानी में एक्शन वाले सीन का फिल्माया जाना ही बाकी था। पानी से डर के कारण उन्होंने तैराकी प्रशिक्षण शुरू करने में देर की, इसलिए फिल्म की शूटिंग में देरी हुई और शूटिंग सितंबर-अक्टूबर तक खिंच गई। अंततः रानी के तैराकी प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद उन दृश्यों को मुंबई से लगभग 85 किमी दूर खोपोली के एक तीस फीट गहरे पूल में शूट किया। दृश्य को वास्तविक दिखाने के लिए पूल को चंबल नदी की तरह तैयार किया गया था।

सोशल मीडिया को श्रद्धा कपूर नहीं मानतीं नकारात्मक

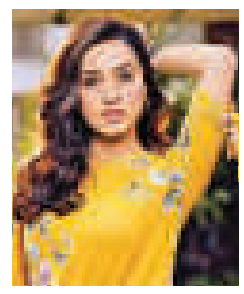

श्रद्धा कपूर की इस साल आई दोनों ही फिल्में 'साहो' और 'छिछोरे' बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। फिल्मों की सफलता से श्रद्धा काफी खुश और उत्साहित हैं। दोनों ही फिल्मों में उनका किरदार एक-दूसरे से काफी अलग था, लेकिन श्रद्धा ने दोनों के लिए ही खूब तारीफें बटोरीं। श्रद्धा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं और इसी बहाने उनके फैंस को उन्हें ऑफ द स्क्रीन देखने का मौका मिल जाता है। श्रद्धा सोशल मीडिया पर तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय भी रखती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में श्रद्धा ने सोशल मीडिया के पक्ष में अपने विचार रखे। श्रद्धा ने कहा, 'लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया नकारात्मक जगह है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे यहां से बहुत कुछ अच्छा मिला है। यह लोगों की ऐसी आवाज है, जहां कुछ भी फिल्टर नहीं होता है। हर किसी को सुने जाने का बराबर का मौका मिलता है और यही सबसे अच्छी बात है।' श्रद्धा वरुण धवन के साथ 'स्ट्रीट डांसर 3डी' में दिखाई देंगी। इसके अलावा 'बागी 3' में वह टाइगर श्रॉफ के अपोजिट दिखेंगी। दोनों ही फिल्में अगले साल की शुरुआत में सिनेमाघरों में दस्तक देंगी।

बहन शाहीन के जन्मदिन पर आलिया ने लिखी इमोशनल पोस्ट

आलिया भट्ट की बहन शाहीन ने गुरुवार को अपना 31वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर आलिया ने बेहद प्यारी-सी तस्वीर और उतना ही खूबसूरत कैप्शन पोस्ट किया है। आलिया ने लिखा है कि उन्हें अपनी बहन के लिए एक परफेक्ट बर्थडे कैप्शन लिखने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने लिखा, 'मैंने टाइप किया, फिर कैंसिल किया, फिर मैंने टाइप किया, फिर कैंसिल किया, और इसकी वजह यह है कि मैं शाहीन की तरह अच्छी राइटर नहीं हूं और जिस तरह की हम बातें करते हैं, वे किसी को समझ में नहीं आएंगी। जिस तरह का हमारा रिलेशनशिप है, उसकी भाषा मौजूद ही नहीं है।' शाहीन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि वह 12 साल की उम्र में डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं। धीरे-धीरे उनकी समस्या काफी बढ़ गई थी और फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें मदद लेनी चाहिए। डिप्रेशन से अपनी लड़ाई को लेकर उन्होंने एक किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले हैं।